गेर्हार्ड कोम : थियोडोर गाइगर

अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था

(सचित्र)

अनुवादक

कृष्ण चन्द्र

1965

आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-6

AMRIKI JANTA KI ARTHA-VYAVASTHA
(Hindi Version of *The Economy of the American People*)
by
Gerhard Colm : Theodore Geiger
Translated by
Krishan Chander

Rs 5 00

प्रकाशक
रामलाल पुरी, सचालक
आत्माराम एण्ड सन्स
काश्मीरी गेट, दिल्ली–6

शाखाएँ
हौज खास नई दिल्ली
चौडा रास्ता, जयपुर
विश्वविद्यालय क्षेत्र, चण्डीगढ
महा नगर, लखनऊ-6
रामकोट, हैदराबाद

मूल्य पाँच रुपये
प्रथम सस्करण

मुद्रक
युगान्तर प्रेस,
मोरी गेट
दिल्ली–6

निवेदन

संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत सघ आज संसार के दो सव से शक्तिशाली राष्ट्र है। दोनो की अर्थ-व्यवस्थाएँ परस्पर-विरोधी है। किन्तु अमेरिकी आर्थिक प्रणाली के आलोचक मार्क्सवादी भी यह स्वीकार करते है कि अमेरिका ही आज आर्थिक दृष्टि से सव से अधिक उन्नत राष्ट्र है और वे उसकी आर्थिक प्रणाली की कुछ विशेषताओ से सवक लेने का भी प्रयत्न करते है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की सव से वडी विशेषता यह है वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और आर्थिक उन्नति, दोनो का समन्वय करती है। सोवियत सघ ने भी निस्सन्देह आर्थिक क्षेत्र मे पिछले कुछ दशको मे असाधारण उन्नति की है, लेकिन इसके लिए उसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के वलिदान के रूप मे वहुत वडी कीमत चुकानी पडी है।

अर्थशास्त्रियो ने अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को प्रचलित पद्धति से किसी विशिष्ट वर्ग मे रखने का प्रयत्न किया है, लेकिन वह पूर्णतः सगत नही है। उसे न सर्वथा पूंजीवादी प्रणाली कहा जा सकता है और न सर्वथा समाजवादी। इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक के लेखको ने उसे 'अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था' के नाम से अभिहित किया है।

अमेरिका की आर्थिक उन्नति का सव से वड़ा कारण यह है कि वहाँ विभिन्न उपायो से उत्पादकता को वढाने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि कृषि और उद्योग, दोनो क्षेत्रो मे प्रवन्ध-कौशल को वहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की कुछ कमजोरियाँ भी हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा और तक्नीकी प्रशिक्षण की ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने उतना ध्यान नही दिया, जितना सोवियत संघ ने दिया। अव अमेरिका

इस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

प्रस्तुत पुस्तक सयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है, जो अमेरिकी अर्थ व्यवस्था के उपर्युक्त गुण-दोष के अलावा उसके आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं को विशद रूप मे प्रस्तुत करती है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को समझने के लिए इसकी उपयोगिता के कारण न केवल अमेरिका मे इसके दो सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, बल्कि स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषाओ मे भी इसका अनुवाद हो चुका है।

हमे विश्वास है कि इसका यह हिन्दी अनुवाद भी हिन्दी भाषियों को अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था को समझने मे सहायता देगा और पाठक भारत की वर्त्तमान मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के लिए उससे आवश्यक निष्कर्ष निकाल सकेगे।

प्रकाशक

पृष्ठभूमि

संयुक्त राज्य की नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन (राष्ट्रीय आयोजन संघ) की यह रिपोर्ट उसके कर्मचारी मण्डल द्वारा तैयार की गई अन्य रिपोर्टों से बिलकुल भिन्न प्रयोजन की पूर्ति करती है। ये रिपोर्टें आम तौर पर नीति-सम्बन्धी वक्तव्यो के लिए तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और विश्लेषण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है, ताकि हमारी समितियो मे कृषि, व्यवसाय, श्रम और विभिन्न पेशो के प्रतिनिधि उनका अध्ययन कर उन वक्तव्यो पर सहमत हो सके। परन्तु 'अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था' नामक यह प्रकाशन केवल जानकारी देने के लिए ही प्रकाशित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अमेरिकी प्रणाली के स्वरूप और भावी सम्भावनाओ का विश्लेषण कर यह बताना है कि कैसे हमारी निजी उद्यम वाली अर्थ-व्यवस्था उत्पादकता और रहन-सहन का इतना ऊँचा स्तर प्राप्त कर सकी है, क्योकि कम्युनिस्टो और अन्य समाजवादी भविष्यवक्ताओ की विनाश की भविष्यवाणियो के बावजूद वह जीवित रह सकी है, और उसकी वास्तविक समस्याएँ और भावी सम्भावनाएँ क्या है।

हम नेशनल प्लैनिंग एसोसिएशन के सदस्य हमेशा यह अनुभव करते रहे है कि विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमो के अन्तर्गत संयुक्त राज्य की यात्रा करने वाले विदेशी नेताओ, टैकनीशि-यनो और छात्रो के दलो के साथ अपने निरन्तर सम्बन्धो के कारण हमे इस प्रकार का एक अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए। अन्य देशो से आने वाले इन लोगो ने हमसे अनेक बार यह अनुरोध किया है कि हम अमेरिकी अर्थ व्यवस्था की जानकारी देने वाली एक पुस्तक प्रकाशित करे जो आसानी से उपलब्ध हो सके। हमारे अनेक अमेरिकी मित्रो ने

भी हमसे कहा है कि क्योंकि नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन के सदस्यो मे सभी वर्गो के प्रतिनिधि है, उसका अनुभव बहुत लम्बा है और वह एक निष्पक्ष और गर-राजनीतिक सस्था है, इसलिए हम इस प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत और प्रकाशित करने के लिए सबसे अधिक अच्छी स्थिति मे है।

इन कारणो से प्रेरित होकर नेशनल प्लैनिंग ऐसोसियेशन के ट्रस्टी-मण्डल ने यह रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। मण्डल यह जानता था कि यह काम आसान नही है और अन्य सगठनो और व्यक्तियो ने भी अनेक बार ऐसी रिपोर्टे तैयार करने के प्रयत्न किये है। लेकिन साथ ही हमने यह भी अनुभव किया कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन अनेक भिन्न-भिन्न पहलुओ से किया जा सकता है और यह सम्भव है कि नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन जिस दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करेगी, उससे दूसरे लोग अध्ययन न करे। इसके अलावा हमे इस तथ्य मे भी आगे बढने की प्रेरणा मिली कि हमारे कर्मचारी मण्डल मे से कुछ लेखक भी हैं जो हमारी योजना के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर सकते है।

इन लेखको मे से एक श्री गेरहार्ड कोम नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन के मुख्य अर्थशास्त्री है और साथ ही वह वाशिंगटन, डी० सी० के जॉर्ज वाशिगटन विश्वविद्यालय मे अर्थशास्त्र के प्राध्यापकीय व्याख्याता भी है। नेशनल प्लैनिक एसोसियेशन के कर्मचारी मण्डल मे शामिल होने से पूर्व और उसके बाद डा० कोम ने अनेक विदेशी अतिथिओ के समूहो के सन्मुख भाषण दिये है और उन्हे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी तथ्यो और समस्याओ की जानकारी दी है। यूरोप, एशिया और सयुक्त राज्य मे उन्होने जो अनुभव प्राप्त किये है, उनसे उन प्रश्नो की विशेष रूप से जानकारी हो गई है जिनका उत्तर अक्सर अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के विदेशी प्रेक्षक खोजना चाहते है।

दूसरे लेखक श्री थ्योडोर गाइगर नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन के

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग के प्रमुख है। उन्होने एक आर्थिक और सामाजिक इतिहासकार के रूप मे शिक्षा प्राप्त की है और खास तौर से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे एक अर्थशास्त्री के रूप मे अनुभव प्राप्त किया है। डा० गाइगर ने ऐतिहासिक और समाज-विज्ञान सम्बन्धी पहलुओ की दृष्टि से इस अध्ययन मे विशेष योग दिया और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओ को प्रस्तुत करने का मुख्य उत्तरदायित्व लिया।

नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन के सहकारी अर्थशास्त्री श्री मैनुएल हेल्जनर ने इन दोनो लेखको को बहुत अच्छी सहायता दी। उन्होने साख्यिकी सम्बन्धी आँकड़े देने के साथ-साथ अन्य अनेक रूपो मे भी इस अध्ययन मे सहायता दी।

नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन की संचालन समिति ने इस रिपोर्ट पर विचार-विनिमय किया और उसके बाद उसके प्रकाशन की अनुमति दी। श्रीमती डी० पार्कर ने इसकी पाडुलिपि को पठनीय रूप प्रदान किया, जिसके लिए हम उनके आभारी है। हम उन अनेक अमेरिकी और विदेशी मित्रो के प्रति भी कृतज्ञ है, जिन्होने प्रकाशन से पूर्व इस रिपोर्ट को पढ़ा और उस पर अपनी सम्मति दी।

एच० क्रिश्चियन सन
अध्यक्ष, नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन, ट्रस्टी मण्डल

प्रस्तावना

हाल के दशको मे औद्योगिकी (टैकनोलॉजी) मे जो भारी परिवर्तन हुए है, वे आज हर व्यक्ति को नजर आते है। आकाश मे उडते जेट विमान, घरो मे रखे टेलीविजन सेट, रसोई घरो मे इस्तेमाल किए जाने वाले बिजली और इलेक्ट्रानिकी के उपकरण, कारखानो मे प्रयुक्त स्वचालित नियन्त्रण यन्त्र और बिजलीघरो मे परमाणु शक्ति पैदा करने वाले प्रतिक्रियावाहक यन्त्र (रिएक्टर)—ये सभी वस्तुएँ, बल्कि और भी-बहुत सी वस्तुएँ आज हर व्यक्ति देख सकता है।

लेकिन इस बात की लोगो को उतनी जानकारी नही है कि हमारी आर्थिक प्रणाली मे भी भारी परिवर्तन होते रहे है। उन्नीसवी शताब्दी की पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था मे से एक नई अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था धीरे-धीरे विकसित होती रही है। इस अर्थ-व्यवस्था की पुरानी पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के साथ उतनी ही समानता है जितनी कि आज के जेट विमान की राइट बन्धुओ के प्रारम्भिक विमान के साथ। इसके बावजूद हमारी वर्त्तमान आर्थिक प्रणाली के सम्बन्ध मे बहुत-सी चर्चा इस ढग से की जाती है, मानो कोई परिवर्त्तन हुआ ही न हो। इसका कारण शायद यह है कि अधिकतर अमेरिकी लोग इन परिवर्तनो के मध्य मे रहते और काम करते हुए इतने अधिक व्यस्त रहे है कि उन्होने उनके महत्त्व पर या सभ्यता के विकास पर पडने वाले उनके महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर विचार ही नही किया।

इस विवरण का प्रयोजन हमारी नई आर्थिक प्रणाली की मुख्य विशेषताओ का वर्णन करना है। हम यहाँ यह बताने का प्रयत्न करेगे कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था किस ढग से चलती है, उसकी कौन-सी बडी सफलताएँ या कमजोरियाँ हैं, कौन-सी समस्याएँ अभी हल करनी है

सास्थानिक रचनाएं कैसी भी हो, क्योकि इसका सम्बन्ध हर सामाजिक और आर्थिक प्रणाली का विशिष्ट क्षमताओ के साथ है।

किंतु यथा-सम्भव अधिकतम उत्पादन और उपभोग ही किसी आर्थिक प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य नही होता। आर्थिक प्रणाली अपने आप मे कुछ अन्य अधिक बुनियादी सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यो की उपलब्धि का साधन है। अर्थ-व्यवस्था किसी ऐतिहासिक सस्कृति का अविच्छिन्न अग होती है और उससे किन विशिष्ट मूल्यो की उपलब्धि होती है, यह उस सस्कृति पर ही निर्भर है। हर समाज के लोगो मे अपने सामान्य उद्देश्यो के सम्बन्ध मे तो अक्सर मोटे तौर पर एक आम मतैक्य होता है, किन्तु आर्थिक साधनो के द्वारा सिद्ध किये जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यो के सम्बन्ध मे उनमे मतभेद रहते है—ये मतभेद उस समाज के अलग-अलग वर्गो के भिन्न-भिन्न हितो और परम्पराओ के कारण होते है।

जहाँ तक अमेरिका का सम्बन्ध है, अमेरिकी गणराज्य की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षो मे आर्थिक प्रणाली के उद्देश्यो के बारे मे परस्पर-विरोधी विचारो को लेकर राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध मे एक बडा विवाद चला। टॉमस जैफर्सन का मत था कि "जीवन, स्वतन्त्रता और सुख प्राप्ति का प्रयत्न" ही समाज के अन्तिम मूल्य है। उनका विश्वास था कि इन मूल्यो की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन स्वतन्त्र पारिवारिक फार्म और छोटे कारखाने है। उनके विरोधी अलेग्जेण्डर हैमिल्टन की धारणा थी कि अमेरिका अपनी आबादी को बढाकर उसकी शक्ति और दौलत से और अपने उद्योगो के विशाल विस्तार से ही एक महान् राष्ट्र बन सकता है। सौभाग्य से अमेरिकी लोगो ने कभी भी मजबूर होकर अपने आपको पूर्णत किसी एक उद्देश्य के साथ नही बाँधा। पिछली डेढ शताब्दी मे सयुक्त राज्य अमेरिका ने हैमिल्टन की कल्पना से भी कही अधिक राष्ट्रीय शक्ति और दौलत हासिल कर ली है और इसके लिए उसे जैफर्सन के व्यक्ति स्वतन्त्रता और उत्तरदायित्व के आदर्शों ‍का भी परित्याग नही करना पडा।

इन परस्पर-पूरक और साथ ही परस्पर-विरोधी आदर्शों की प्राप्ति के लिए चाहे कितनी ही लगन और व्यग्रता के साथ प्रयत्न किया गया हो, किन्तु उन्हे सामाजिक सस्थाओ के रूप मे मूर्त रूप देते हुए बहुत कट्टरता और सैद्धान्तिकता से नही, बल्कि व्यावहारिकता और लचकीलेपन से काम लिया गया। राष्ट्र के इतिहास मे सुधार की अनेक लहरें उठती रही है। किन्तु इन सबमे जैफर्सन और हैमिल्टन के उद्देश्यो मे एक सामजस्य कायम रहा, जो तत्कालीन सम्भावनाओ और सीमाओ का परिणाम था। अठारहवी शताब्दी के अन्तिम और उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे जैफर्सन के व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आदर्श के मूर्त रूप मे अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था छोटे-छोटे फार्मों वाली कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था थी। किन्तु बीसवी शताब्दी के मध्य मे ऐसी स्थिति आ गई कि कोई इक्के-दुक्के आदमी ही ऐसे होगे जो पुराने भूले-बिखरे दिनो की याद करते हो और फिर से कृषि-प्रधान समाज की स्थापना करना ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के उद्देश्य की प्राप्ति का साधन समझते हो।

आज भी जैफर्सन के स्वतन्त्रता और आत्म-निर्भरता के आदर्शों और हैमिल्टन के वैभव और शक्ति के आदर्शों की एक साथ प्राप्ति के लिए प्रयत्न जारी है, किन्तु आज उसके लिए सामाजिक सम्भावनाएँ और सीमाएँ बिलकुल भिन्न है। आज आर्थिक उन्नति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता सरकार के अथवा कुछ व्यक्तियो के हाथो मे बड़े पैमाने पर केन्द्रित रहे। किन्तु साथ ही स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत सत्ता की रक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि निश्चय और कार्रवाइयाँ करने का काम प्रधानत व्यक्तिगत रूप मे लोगो के हाथ मे रहे और उसका केन्द्रीकरण न हो। इसलिए आज यह आवश्यक है कि इन दोनो के बीच समन्वय स्थापित किया जाय।

यदि उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि का अर्थ समाज को मानवीय यन्त्रो का समाज बना देना हो, तो अमेरिकी लोग उसे अपना लक्ष्य स्वीकार

करने के लिए तैयार नही है और भविष्य मे भी वे इसके लिए कभी तैयार नही होगे। यदि मानव-समाज केवल ऐसे नर-नारियो का ही समाज बन जाय जो महज मशीने हो, तो चाहे ये मानवीय मशीने कम्युनिस्ट देशो की भाति सर्वशक्तिमान् राज्य (सरकार) के द्वारा सचालित हो और चाहे सर्वशक्तिमान् उद्योगपतियो द्वारा, जैसा कि उन्नीसवी शताब्दी की बन्धनहीन स्वतन्त्रता वाली पूंजीवादी प्रणाली के आज भी कायम रहने पर होता, दोनो मे कोई अन्तर नही होगा। अन्तिम विश्लेषण मे हम इस नतीजे पर पहुँचेगे कि अमेरिका की वर्त्तमान पीढी के सामने आज यह सवाल नही हे कि वह कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था को चुने या उद्योग-प्रधान अर्थ-व्यवस्था को, अथवा समाजवाद को चुने या पूंजीवाद को। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी समाज एक ओर आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रो मे बडे पैमाने के सगठन के लाभो का और दूसरी ओर व्यक्तिगत चयन की अधिकतम सम्भव प्राप्ति का परस्पर समन्वय कर सकता है ? अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की प्रवृत्तियो और भावी सम्भावनाओ पर पुन. दृष्टिपात करने का हमारा प्रयोजन इस निर्णायक प्रश्न का उत्तर खोजना ही है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर 'समाजवाद बनाम पूंजीवाद' के दृष्टिकोण से बार-बार विचार और अध्ययन किये जाने का परिणाम यह हुआ है कि यह निर्णायक प्रश्न बहुत विकृत हो गया है। इन अध्ययनो और विचार-विनिमयो मे दोनो पक्षो के लोग बहुत चरम-सीमा तक पहुँच जाते है। एक ओर, अमेरिका मे और अमेरिका से बाहर भी, ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की खूब तारीफ करते है किन्तु उनकी तारीफ इस गलत धारणा पर आधारित होती है कि वह पूर्ण स्वतन्त्र और बन्धन-हीन व्यापार के विशुद्ध आदर्श का मूर्त रूप है। उनका मत यह हे कि जब हर व्यक्ति और सगठन को अपने-अपने आत्म-हितो के साधन की पूर्ण स्वतन्त्रता मिल जाती है तो अधिकतम लोगो के अधिकतम हित का श्रेय स्वत. ही सुरक्षित हो जाता है। उनका ख्याल है। कि अन्याय और

अपर्याप्तताएं तभी पैदा होती है जब कि कोई दखलन्दाज सरकार समाज-व्यवस्था मे हस्तक्षेप कर उसके स्वतन्त्र और निर्बाध कार्य मे रुकावट डालती है और यदि सरकार ऐसा न करे और हर चीज को स्वतन्त्र छोड दे तो सब समस्याएँ स्वय समाप्त हो जाएँ।

दूसरी ओर मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, पर वह अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का जो चित्रण करता है या उसके लिए जो नुस्खा पेश करता है वह उपर्युक्त विचारधारा से भी कम सही है। मार्क्सवादी सिद्धान्त इस बात पर बराबर जोर देता रहा है कि अमेरिकी 'पूंजीवाद' के परिणाम-स्वरूप 'आम जनता' के कष्टो का निरन्तर बढते जाना अनिवार्य है, क्योकि धन-दौलत कुछ 'एकाधिकारवादी' पूंजीपतियो के हाथ मे अधिकाधिक केन्द्रित होती जाती है। लेकिन समस्त प्रमाण इसके विपरीत है। मार्क्सवादी अपने इस सिद्धान्त मे चिपटे हुए है कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था अन्त मे एक दिन खोखली होकर अवश्य ढह जाएगी, लेकिन अगर वह अभी तक ढही नही तो उसका कारण सिर्फ यह है कि अमेरिका ने विदेशी बाजारो पर कब्जे, विदेशो मे अपने पूंजी-निवेश और युद्धो के 'साम्राज्य-वादी' प्रयत्नो से कयामत के उस दिन को कुछ समय के लिए टाल दिया है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप और उसकी समस्याओं के इस हास्यास्पद चित्रण की विशुद्ध प्रचार कहकर उपेक्षा की जा [illegible] थी, किन्तु कठिनाई यह है कि संसार के अन्य देशो मे अनेक गैर-[illegible] बुद्धिजीवी भी, पूर्णत नही तो कम से कम अंशत, इस [illegible] से विश्वास करते है।

है कि मनुष्य अतिशयोक्तियो से और अपनी कमियो की ओर से आँखें फेरने की प्रवृत्ति से बिलकुल बच नही सकता और हम यह बात भी नि सकोच स्वीकार करते है कि हमारा एक प्रयोजन यहां यह बताना है कि हमारे ख्याल मे वह कौन-सी चीज है, जो अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियो मे जीवन को जीने योग्य बनाती है। फिर भी, अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की सम्भावनाओ पर गर्व करते हुए भी, हम उसकी कुछ कमियो और अवशिष्ट समस्याओ को स्वीकार करते है। अमेरिकी अर्थ व्यवस्था के सम्मुख अभी तक जो समस्याएँ विद्यमान है उन्हे और उनके समाधान के लिए उसकी अब तक की उपलब्धियो को जानना जरूरी है। अपनी प्रणाली की जो चीज हमे सबसे ज्यादा पसन्द है वह शायद यह है कि, जैसा कि सभी लोकतन्त्रीय देशो मे होता है, हर नागरिक की यह ज़िम्मेदारी है कि वह अपने देश की अर्थ-व्यवस्था की कमियो को पहचाने और उन्हे दूर करने के लिए प्रयत्न करे। सिर्फ इसी प्रक्रिया से अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था अपनी सम्भाव्यताओ की पूर्ति की दिशा मे अग्रसर हो सकती है।

विषय सूची

प्रथम भाग

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे उत्पादकता और उपभोग के उच्च स्तर के कारण

द्वितीय भाग

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की समस्याएँ और सभावनाएँ

प्रथम भाग

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता और उपभोग के उच्च स्तर के कारण

अमेरिका ने जिन उपायो से अपनी उत्पादकता को अभूतपूर्व स्तर तक पहुँचाया है और रहन-सहन का ऊँचा स्तर प्राप्त किया है, उसकी सीधी-सादी और सुस्पष्ट व्याख्या करना बहुत आनन्ददायक होगा। किंतु अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था एक जटिल मशीन की भाति पेचीदा है। उसका उत्पादन बहुत-से अलग-अलग हिस्सो पर ही निर्भर नही है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर है कि उनमे परस्पर समन्वय और सन्तुलन रहे। एक लोकतन्त्रीय देश मे एक-दूसरे से बहुत भिन्न भौगोलिक क्षेत्रो से तरह-तरह के दबाव और खिचाव पडते है, और सयुक्त राज्य मे विद्यमान विशिष्ट हितो वाले विविध वर्गों की भारी सख्या भी अनेक प्रकार के दबाव और खिचाव डालती रही है, फिर भी यह कुछ हद तक आश्चर्य की बात है कि इन से यह जटिल मशीन खड-खड नही हुई। इसमे तनिक भी सन्देह नही कि यह मशीन सिर्फ चलती ही नही रही, बल्कि इन वर्षो मे उसके ढाचे मे काफी बडा परिवर्त्तन हुआ है और उसकी सुचारुता मे सुधार और वृद्धि हुई है। प्रथम भाग मे हम यह बताने का प्रयत्न करेगे कि यह कैसे हुआ।

पहले अध्याय मे सयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशो में उत्पादन, आय और उपभोग के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार के तथ्य और आंकडे दिये गए है। इस सक्षिप्त सर्वेक्षण में दिये गए आकड़े अनेक पाठको को नये

या आवश्यक प्रतीत न हो, यह सम्भव है, किन्तु फिर भी सब मिलाकर वे अमेरिकी उत्पादकता के परस्पर-सम्बद्ध कारक-तत्वो को समझने के लिए प्रारम्भिक बिन्दु का काम दे सकते है।

दूसरे अध्याय से आठवे अध्याय तक दो प्रश्नो का उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है। पहला यह कि वे मुख्य-मुख्य कारक-तत्व कौन-से है जिन्होने अमेरिका की उत्पादकता को इतना बढाया है और अमेरिका के रहन-सहन के स्तर को इतना ऊँचा उठाया है। दूसरा यह कि भविष्य मे भी इन रुझानो के कायम रहने की क्या सम्भावनाएँ हैं। यह सारा विवेचन और अध्ययन प्राकृतिक साधन, श्रम, प्रबन्ध, अनुसधान और औद्योगिकी, पूंजी और सरकार आदि कारक-तत्वो द्वारा उत्पादकता की वृद्धि मे दिये जाने वाले योग पर केन्द्रित है और साथ ही इसमे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे इन तत्वो को प्रभावित करने वाले सस्थानो, प्रयोजनो और मूल्यो का भी विवेचन किया गया है।

प्रथम भाग का उद्देश्य सिर्फ यह बताना है कि इनमे से हरेक तत्व कैसे उत्पादकता की वृद्धि मे योग देता है—इसका उद्देश्य उनका समर्थन या आलोचना करना नही है। किंतु हम यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि हमे इनमे से किसी भी कारक-तत्व मे पूर्णता दिखाई नहीं दी। हरेक मे ही सुधार की गुजाइश और सम्भावना है। इन कमियो का सकेत हर तत्व के वर्णन मे दिखाई पडता है। किन्तु इन समस्याओ पर अपना विश्लेषण और साथ ही सरकारी और निजी नीतियो द्वारा उनके समाधान के लिए किये जा रहे उपायो का विवरण हमने द्वितीय भाग के लिए रख छोडा है।

1
कुछ तथ्य और आंकड़े

सयुक्त राज्य अमेरिका मे उत्पादन और उपभोग का स्तर कितना ऊँचा है और अन्य देशो की आर्थिक उपलब्धियों की तुलना मे उसकी क्या स्थिति है, इसकी जानकारी के लिए निम्न तथ्य दिये जा सकते है :—

* सयुक्त राज्य मे कुल उत्पादन इस समय सन् 1929 के भारी व्यावसायिक उत्कर्ष के वर्ष के उत्पादन से ढाई गुना है और यह आशा की जा सकती है कि अगले दस वर्षो मे वह इससे भी अधिक तेज गति से बढता रहेगा।
* पिछले 30 वर्षो मे प्रति मानव-घण्टा उत्पादन 2·5 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढता रहा है और औद्योगिक विधियो मे हो रहे नये-नये सुधारो को और अधिक तीव्र गति से अपनाने से भविष्य मे वृद्धि की यह दर और भी ऊँची होगी।
* अमेरिका मे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक क्षेत्र मे उठाये जाते है। और किसी भी देश में ये लाभ इतने व्यापक रूप मे नही उठाये जाते।
* सन् 1929 के बाद, यदि मूल्यो को स्थिर मान लिया जाय, तो प्रति व्यक्ति उपभोग मे 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वृद्धि की यह दर किसी भी अन्य देश से अधिक है।
* देश आज आर्थिक अस्थिरता का सामना करने के लिए पहले की अपेक्षा कही अधिक तैयार है।
* यद्यपि सयुक्त राज्य की आबादी सारे संसार की आबादी का कुल छ: प्रतिशत है फिर भी उसका औद्योगिक उत्पादन विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का एक तिहाई है।

ये कथन सामान्य कथन मात्र है। किन्तु अन्य ग्राकडो से यदि इनकी पुष्टि की जाय तो इनसे इस वात की कुछ झलक मिल सकती है कि अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था परिमाण की दृष्टि से कितनी विशाल है और अन्य देशो की अर्थ-व्यवस्थाओ से वह किन-किन वातो मे भिन्न है।

इन और वाद मे आने वाले आकडो की व्याख्या के सम्वन्ध मे कुछ चेतावनी देना उपयुक्त होगा। कुल आय और अर्जित आय, खाद्य सामग्री, आवास एव सयुक्त राज्य के रहन-सहन के स्तर के अन्य पहलुओ के सम्बन्ध मे जो आकडे दिये गए है वे 'औसत' अमेरिकी के आंकडे है। कुछ अमेरिकी लोगो की आर्थिक स्थिति इन औसत आकडो से प्रदर्शित स्थिति से भी वेहतर है, किन्तु दूसरी ओर कुछ अमेरिकी लोग औसत अमेरिकी लोगो से गरीव भी हैं। साथ ही उत्पादन और उपभोग के विभिन्न देशो के आँकडो की तुलना मे भी कुछ खतरा है। इन तुलनाओ से सयुक्त राज्य अमेरिका मे या अन्य देशो मे जीवन-स्तर की उन्नति या ह्रास की सही तस्वीर नही मिलती। फिर भी विभिन्न देशो के आकडो की तुलनाओ से अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के कुछ पहलुओ की झाँकी मिलती है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

आकडो और उनकी तुलनाओ पर वहुत अधिक भरोसा करने मे एक और भी गम्भीर वाधा है। उनसे सभी देशो मे विद्यमान महत्त्वपूर्ण और दूरगामी अप्रत्यक्ष विशेषताओ की सही झाकी नही मिलती। केवल धन-सम्बन्धी और भौतिक तुलनाएँ न तो उत्पादक प्रक्रियाओ द्वारा साधे जाने वाले आर्थिकेतर (नैतिक आदि) मूल्यो की और न उपभोग की विभिन्न किस्मो और स्तरो के गुणात्मक पहलुओ की पर्याप्त झाँकी दे सकती है। वस्तुओ और सेवाओ के उत्पादन और उपभोग का मूल्य वाजार दर के हिसाव से निकाल लेना ही आर्थिक गति-विधि के सम्पूर्ण सामाजिक महत्त्व को नही नाप सकता। उदाहरण के लिए यह सम्भव है कि एक वैज्ञानिक का अनुसन्धान सम्वन्धी कार्य जव तक चल रहा है तव तक उसका मूल्य वहुत ऊँचा न हो, लेकिन जव उसके अनुसन्धान और आविष्कार पूरे हो जाएँ तो वे भविष्य के लिए वहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो। चिकित्सा सवधी वहुत-सी खोजे ऐसी है जिनसे उनके अनुसन्धान कर्त्ताओ

को बहुत ही कम पैसा मिला है। यह बात आमतौर पर सभी जानते हैं कि अध्यापको के काम का समाज के लिए जितना महत्त्व है, उसकी तुलना मे उन्हे पैसा बहुत कम मिलता है, फिर भी आत्मार्पण की भावना से काम करने वाले अध्यापक छात्रो मे एक ऐसी उत्कण्ठा, कल्पना शक्ति और साहस की भावना पैदा करते है जो समाज को उन्नति और परिवर्त्तन की ओर ले जाती है। इसी प्रकार जो कलाकार अपनी कलाकृतियो को तुरन्त नही बेच देता, उसके कार्यों का मूल्य विशुद्ध पैसे की दृष्टि से बिलकुल शून्य होगा, भले ही वह राष्ट्र के सास्कृतिक जीवन मे अमूल्य योगदान कर रहा हो।

लेकिन आकडो के द्वारा दिये जाने वाले विवरणो मे इन त्रुटियों और अपर्याप्तताओ के बावजूद, कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण मात्रात्मक तुलनाएँ अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उपलब्धियो और साथ ही उसमे अभी तक विद्यमान कमियो के कारणो को समझने मे सहायता दे सकती हैं।

सयुक्त राज्य में हाल मे हुए परिवर्त्तन

पिछली एक पीढी मे अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था मे कुछ बहुत बडे उतार-चढाव आये है। सन् 1920 से प्रारम्भ दशक मे उसके व्यापार मे खूब उत्कर्ष और तेजी आई और उसके बाद 1930 से प्रारम्भ दशक मे जबर्दस्त मन्दी रही। उसके पश्चात् सन् 1940 से प्रारम्भ दशक मे उसकी अर्थ-व्यवस्था पहले युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था रही और फिर युद्ध समाप्त होने पर उसमे पुन परिवर्त्तन आये। सन् 1950 के बाद के दस वर्षों मे उसकी अर्थ-व्यवस्था का फिर विस्तार हुआ और हल्की-सी

घटा उत्पादन का, अधिक ऊँचा होना है। इस उत्पादकता की बदौलत

चार्ट 1

आर्थिक वृद्धि के सूचक

1929–1960 (1960 के मूल्यों के हिसाब से डालरों में)
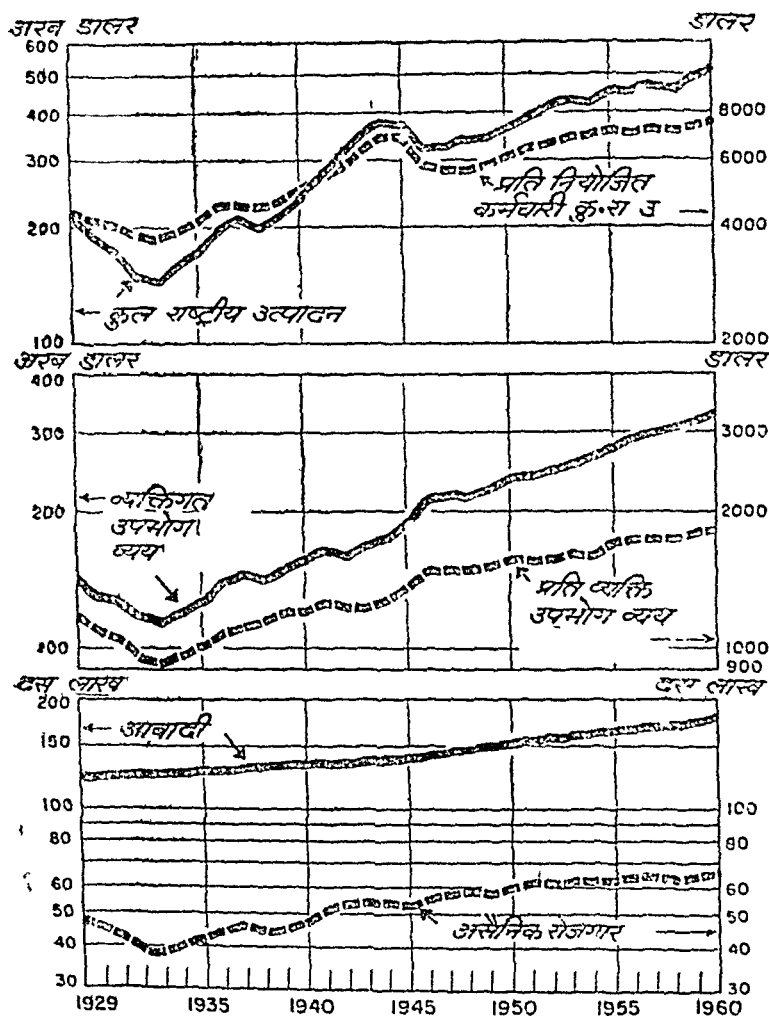
नोट:—देखें परिशिष्ट तालिका—1

ही अमेरिका इस समय उपलब्ध साधनो से वस्तुओ और सेवाओ का अधिकाधिक मात्रा मे उत्पादन कर सका है। यद्यपि सप्ताह के काम के घटे कम हो गए है तो भी इस ऊँची उत्पादकता के कारण ही अमेरिकी लोगो का उपभोग का स्तर ऊँचा बना हुआ है। और हाल के वर्षो मे अमेरिका मे जो आर्थिक विकास हुआ है और अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक स्थिरता रही है, उसका भी बडा कारण यह उत्पादकता ही है।

पिछले पचास वर्षों मे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता सब मिलाकर तीन गुनी हो गई है और सन् 1929 के बाद वह दुगुनी हुई है (देखिए परिशिष्ट तालिका 3)। इसका अर्थ यह है कि इन पचास वर्षों मे उत्पादकता मे वृद्धि की दर 2 2 प्रतिशत वार्षिक रही और सन् 1929 के बाद तो यह दर 2 5 प्रतिशत वार्षिक हो गई। किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की अवधि मे यह वार्षिक दर औसतन 3 प्रतिशत से भी अधिक रही है। इस वृद्धि का कारण निर्माण उद्योगो (मैन्यूफैक्चरिग इडस्ट्री) की उत्पादकता का काफी बढ जाना था। सन् 1947-49 के बाद निर्माण-उद्योगो मे प्रति मानव-घटा उत्पादन औसतन 3 5 प्रति-शत वार्षिक बढा है। इसी बीच कृषि की उत्पादकता भी बढती रही है, हालाकि अब भी वह निर्माण-उद्योगो की उत्पादकता से आधे स्तर पर है। पिछले दस वर्षों मे उसमे औसतन 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होती रही है।

उत्पादकता मे वृद्धि की दर हर उद्योग मे अलग-अलग है (देखिए परिशिष्ट तालिका 4)। उदाहरण के लिए कुछ खान उद्योगो मे हाल के वर्षो मे प्रति मानव-घटा उत्पादन बहुत थोडा-थोड़ा बढा है और तार उद्योग (टेलीग्राफ इडस्ट्री) मे प्रति कर्मचारी उत्पादन बढने के बजाय उल्टा कम हुआ है। इसके विपरीत रेयन, कृत्रिम रेशा, सीमेट और खाद्य पदार्थों को डिब्बा बन्द और सुरक्षित करने आदि के उद्योगो मे उत्पादकता न केवल अन्य अनेक निर्माण-उद्योगो की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढी है, बल्कि सब मिलाकर अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता वृद्धि का जो औसत है उससे भी वह अधिक है। इसके अलावा अधिक उत्पादकता वाले इन उद्योगो का आपेक्षिक महत्त्व भी

बढ गया है। कारण, मजदूरो की एक बडी सख्या कृषि से हटकर अधिक उत्पादकता वाले इन निर्माण-उद्योगो मे लग गई है जिससे सब मिलाकर अमेरिका का प्रति मानव-घटा उत्पादन और भी ऊँचा हो गया

चार्ट 2

कुछ चुने हुए उद्योगो मे प्रति घटा श्रमिक आय मे वृद्धि (1939-1960)
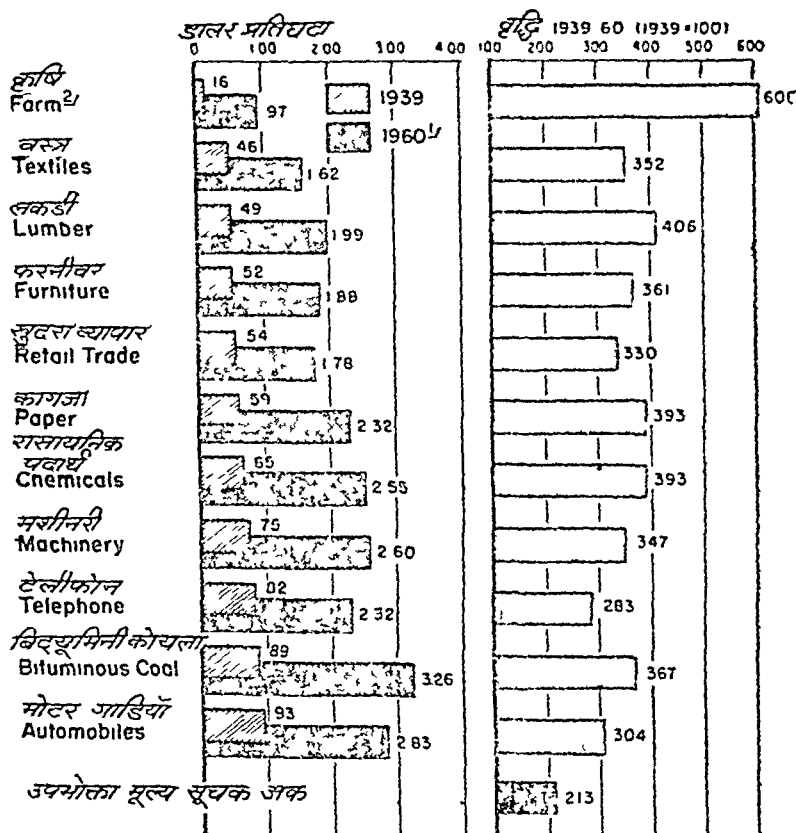
1. प्रारम्भिक

2 बिना भोजन और रिहायश के औसत प्रति घटा मजदूरी की दर जो औसत दैनिक मजदूरी की दर को काम के घटों से बाटकर निकाली जाती है।

है। इसलिए जहाँ उत्पादकता मे आम वृद्धि का अधिकतर कारण उत्पादन की विधियो मे औद्योगिकी (टैकनोलॉजी) और प्रवन्ध सम्बन्धी सुधार है, वहाँ उसका एक आशिक कारण यह भी है कि बहुत-से मजदूर कम उत्पादकता वाले उद्योगो से हटकर अधिक उत्पादकता वाले उद्योगो मे लग गए है।

अमेरिका के उपभोग सम्बन्धी ढाचे मे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन यह हुआ है कि लोगो मे अधिक समानता आने लगी है और अधिकाधिक लोग अधिकाधिक जीवन के आराम के साधनो का उपभोग करने लगे है। पहले जहाँ अपेक्षाकृत कम अमेरिकी लोगो के हाथो मे बहुत बडी मात्रा मे धन-दौलत केन्द्रित थी, वहाँ अब आय का वितरण अधिक व्यापक क्षेत्र मे होने लगा है। उदाहरण के लिए, सन् 1929 मे अमेरिका मे खर्च करने या बचाने के लिए उपलब्ध कुल आय का 33 8 प्रतिशत भाग देश के कुल 5 प्रतिशत लोगो के हाथो मे आया। इन 5 प्रतिशत व्यक्तियो की गिनती सर्वाधिक आय वाले वर्ग मे थी। सन् 1952 मे इसी सर्वोच्च आय-वर्ग के लोगो को देश की कुल उपलब्ध आय का केवल 15 2 प्रतिशत भाग मिला और सन् 1952 के बाद पिछले कुछ वर्षो मे इस स्थिति मे कोई विशेष परिवर्त्तन नही हुआ है (देखिए परिशिष्ट तालिका 5)। इसका एक आशिक कारण 1920 और 1930 के दशकों की तुलना मे कहीं अधिक ऊँचे सम्पदा शुल्क और आयकर है। किन्तु आय के इस अधिक व्यापक और अधिक समान वितरण का इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि कम आय वाले सभी वर्गो की आय मे अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई। रोजगार के अवसरो के बढने और श्रमिको और प्रबन्धको के सम्बन्धो मे सामूहिक सौदेबाजी के अधिकाधिक प्रभावकारी ढग से लागू होने और सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के स्तर निर्धारित किये जाने का परिणाम यह हुआ है कि कम मजदूरी पाने वाले वर्गों की आय भी बढकर अधिक मजदूरी पाने वाले वर्गों की आय के निकट आ गई है।

पूर्व कम आय वाले परिवार के मुखिया को, अगर वह रोजगार पर लगा होता, आज की अपेक्षा काम अधिक घंटे करना पड़ता था और उसे मज़दूरी कम मिलती थी। उस समय परिवार का कामचलाऊ निर्वाह तभी हो पाता था जबकि उसके कई सदस्य पूरे समय के या कुछ समय के रोज़गार पर लगे रहते। उस समय समस्या यह थी कि पूरे समय के काम के अनेक धन्धो मे मूल वेतन की दरे नीची थीं। किन्तु सन् 1930 के दशक के बाद से अमेरिकी श्रमिको की प्रति घंटा औसत आय काफी बढ गई है—खासकर उन उद्योगो मे जिनमे मज़दूरी की दरे अपेक्षाकृत नीची थी। उदाहरण के लिए सन् 1939 से 1960 तक उपयोग्य वस्तुओ के मूल्य सूचक अक मे जहाँ दुगुने से कुछ ही अधिक वृद्धि हुई, वहाँ मजदूरी की दरे फार्मो मे युद्ध-पूर्व के स्तर से छ गुनी हो गई और कपड़ा मिलो मे साढे तीन गुनी बढ गई। अधिक ऊँची मजदूरी की दरो वाले उद्योगो मे भी मज़दूरियाँ काफी बढी। उदाहरण के तौर पर, मोटर-निर्माण-उद्योग मे औसत मजदूरी 204 प्रतिशत और टेलीफोन-उद्योग मे 183 प्रतिशत बढ गई। आज यह स्थिति है कि पूरे समय काम करने वाले करीब-करीब सभी श्रमिको को इतनी आय अवश्य है कि वे अपना निर्वाह भली भाति कर सके और बहुत-से श्रमिक तो इससे भी अधिक कमा लेते है। इसके अलावा जीविकोपार्जन की क्षमता के नष्ट हो जाने की दशा मे लोगो को सरकार से भी सामाजिक सहायता और बीमा-लाभो की प्राप्ति होती है और प्राइवेट उद्योगो की पेंशन योजनाओ और प्राइवेट कल्याण सगठनो से भी लाभ प्राप्त होता है।

कम आय वाले परिवारो की सख्या बराबर घट रही है, इसका आभास इस बात से मिलता है कि सन् 1929 मे जहाँ 2,000 डालर से कम व्यक्तिगत आय वाले परिवारो की सख्या कुल अमेरिकी परिवारो की सख्या का 32 प्रतिशत थी, वहाँ सन् 1960 मे वह घटकर 13 प्रतिशत रह गई। फिर भी सयुक्त राज्य अमेरिका मे भी यह समस्या है कि इसके कुछ इलाके अल्पविकसित हैं और अलग-अलग क्षेत्रो मे आय और उत्पादन के स्तर अलग-अलग हैं। कुछ अल्पविकसित इलाको मे सरकारी

और गैर-सरकारी नीतियाँ विकास को वढाने में सफल सिद्ध हुई हैं। ऐसा एक क्षेत्र टैनेसी घाटी क्षेत्र है, जो अनेक राज्यों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र मे 1929 में प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय सारे अमेरिका की औसत प्रति व्यक्ति आय से 49 प्रतिशत कम थी, किन्तु विकास कार्यो के फलस्वरूप 1960 मे वह इस औसत से केवल 36 प्रतिशत नीची रह गई। फिर भी दक्षिण के अनेक क्षेत्रो मे प्रति व्यक्ति आय देश के अन्य क्षेत्रो की तुलना मे वहुत कम है।

किन्तु आय के वितरण के आकड़े इस वात को पूरी तरह प्रकट नही करते कि किस प्रकार मोटर गाड़ी आदि आधुनिक जीवन के आराम और सुख-सुविधा के साधन अधिकाधिक व्यापक क्षेत्र मे वितरित हो रहे है। सन् 1949 मे कुल अमेरिकी परिवारो मे से 51 प्रतिशत ऐसे थे, जिनके पास एक मोटर गाडी थी और 3 प्रतिशत ऐसे थे जिनके पास दो या दो से अधिक मोटरें थी। सन् 1960 तक ये दोनो अनुपात बढ कर क्रमश. 77 और 13 प्रतिशत हो गए। यद्यपि अधिक धनी लोग आज भी दूसरो से अधिक विलासितापूर्ण और शानदार मोटर गाडी रख सकते है, किन्तु कैडिलक गाडी और फोर्ड गाड़ी रखने की क्षमताओं में उतनी असमानता नही है जितनी कि एक गाड़ी रखने की क्षमता और अक्षमता मे है।

आवास के क्षेत्र मे बेहतर जीवन-स्तर का और भी अधिक प्रमाण मिलता है। सरकार के आवास कार्यक्रमो के फलस्वरूप अमेरिका के लाखो परिवारो के लिए उससे भी बेहतर मकान खरीदना सम्भव हो गया है, जैसा कि वे इन कार्यक्रमो के विना अपनी निज की सामर्थ्य से खरीद पाते। औसत अमेरिकी परिवार अपने मकानों के स्वयं मालिक है। सन् 1940 में 43 6 प्रतिशत गैर-कृषिजीवी परिवार अपने निज के मकानों मे रहते थे। सन् 1960 तक यह अनुपात बढकर 62 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा समस्त अमेरिकी परिवारों मे से 89 प्रतिशत के पास टेलीविज़न सैट और 95 प्रतिशत के पास एक से अधिक रेडियो सैट थे।

रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने वाली और भी कई बातें हैं।

सरकारी गति-विधियाँ, जिनमे सघीय, राज्यीय और स्थानीय—तीनों प्रकार की गति-विधियाँ शामिल है आज जनता को अनेक आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराती है, जैसे कि शिक्षा, समाज कल्याण, जन-स्वास्थ्य, पार्क और अन्य मनोरजन सुविधाएँ आदि। पहले मुख्यत धनी लोग ही अपने बच्चो को उच्च शिक्षा दिला सकते थे। यद्यपि सयुक्त राज्य आज भी उस स्थिति से बहुत दूर है जिसमे कि उच्च शिक्षा केवल छात्र की योग्यता पर ही निर्भर हो, फिर भी विश्वविद्यालयी शिक्षा का असाधारण विस्तार हो गया है। मोटे तौर पर हमारे तमाम हाई स्कूल पास छात्रो मे से 40 प्रतिशत कालेजो या विश्वविद्यालयो मे पढते हैं, हालाकि इनमे से आधे ही अपनी शिक्षा डिग्री प्राप्त करने तक जारी रख पाते है। सन् 1960 मे 18 से 24 वर्ष तक की आयु के अमेरिकी तरुणो मे से लगभग 17 प्रतिशत कालेजो या विश्वविद्यालयो मे भरती थे, जब कि सन् 1900 मे यह अनुपात 3 प्रतिशत से भी कम था। एक और उदाहरण लीजिये एक पीढी पहले आज की अपेक्षा बहुत ही कम अमेरिकी लोग छुट्टी मनाने या मनोरजन के लिए यात्रा कर सकने की स्थिति मे थे किन्तु आज अधिकतर अमेरिकनो को सवेतन अवकाश मिलता हे और वे मनोरजन या आमोद-प्रमोद के लिए इतनी बडी सख्या मे इधर-उधर जाते है कि उनकी छुट्टी की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए एक बडा सेवा-उद्योग ही स्थापित हो गया है। चिकित्सा और चिकित्सालय सेवाओ को भी अधिकाधिक अमेरिकी लोगो के लिए सुलभ करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और इस बात का कोई ख़याल नही किया जाता कि वे उसके लिए पैसा चुका सकते है या नही।

इस प्रकार सयुक्त राज्य मे अनेक तत्त्वो ने मिलकर जीवन की सुख-सुविधाओ को बढाने और उनका अधिक समान वितरण करने मे योग दिया है ताकि कम आय वाले लोग भी उन्हे प्राप्त कर सके। ये तत्त्व है—आय के वितरण मे विद्यमान असमानता मे वास्तविक कमी, आय और उपयोग के स्तरो मे आम वृद्धि और सरकारी कार्यक्रमो और सार्वजनिक सेवाओ मे वृद्धि।

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर यह भय व्यापक रूप से फैल गया

था कि युद्धोत्तर कालीन व्यापारिक उत्कर्ष और तेजी के बाद कहीं सन् 1930 के दशक की भाँति फिर जबर्दस्त और व्यापक बेरोजगारी न पैदा हो जाय। किन्तु यह भय निर्मूल सिद्ध हुआ और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था निरन्तर विकसित होती रही, सिर्फ कुछ थोड़े-से समय के लिए ही उसमे रुकावट पड़ी। हाल के वर्षों मे आर्थिक अभिवृद्धि की गह गति कुछ धीमी पड़ गई है और बारह वर्षों की अवधि में चार बार मन्दी आई है। ये मन्दियाँ बहुत हल्की थी और बहुत कम समय तक रही; किन्तु उन्होने वृद्धि की गति को मन्द अवश्य किया है। यही नहीं, बल्कि बेरोजगारी भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है।

चार्ट 3.

उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1946–60)

(1947-49=100)
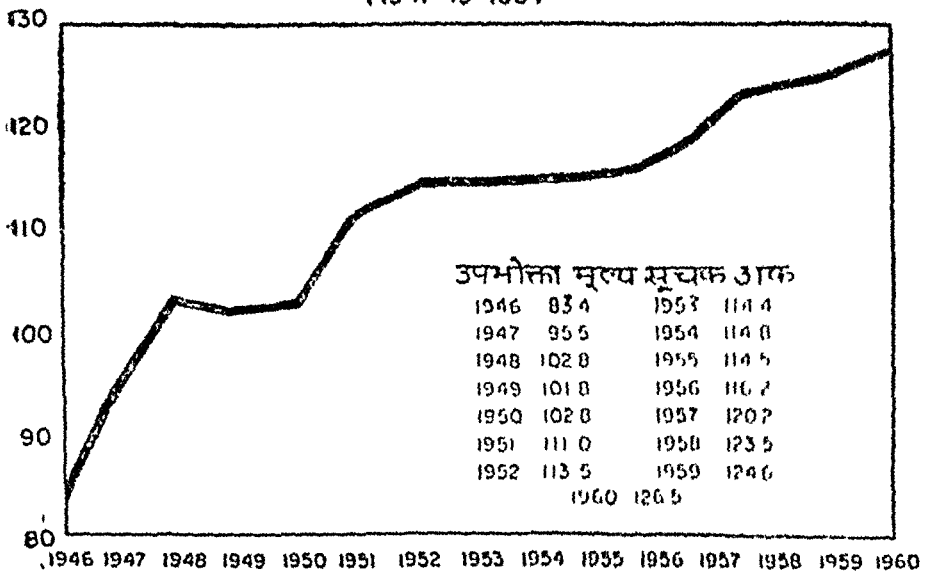
किन्तु पिछले दशक की बेरोजगारी उससे पहले के जमाने की बेरो-जगारी से भिन्न किस्म की है। इस बेरोजगारी का अर्थ पूर्णतः आभा-ग्रस्त हो जाना नहीं है। इस दशक में पहले के मन्दियों के जमाने की भाँति व्यक्तिगत निराशा और हताशापूर्ण कठिनाइयाँ नहीं आईं, वैसे अमेरिका अच्छी तेजी के दिनों में भी बेरोजगारी के भार...

न-कुछ वृद्धि अनुभव करता रहा है। खास कर, बेरोज़गारी, कुछ ऐसे इलाको मे, जो मन्दी के पुराने मरीज रहे है, और जहाँ रोजगार के अवसर अधिकतर उन्ही उद्योगो तक सीमित रहे है, जिनमे ह्रास हो रहा है, एक गम्भीर समस्या बन गई है। वह अपेक्षाकृत पुराने और बूढे कर्मचारियो, अश्वेतो (नीग्रो) और बेहुनर और कम शिक्षित नौजवानो के लिए भी एक समस्या रही है। इस तरह की विशिष्ट बेरोज़गारी पिछले दशक मे अधिक बढी है किन्तु गैर सरकारी और सरकारी सस्थानो द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने की जोरदार कोशिशे की जा रही है। सरकार ने क्षेत्र पुर्नविकास प्रशासन के नाम से एक नया सस्थान स्थापित किया है जो मन्दी के शिकार अवकसित क्षेत्रो के विकास की समस्याओ पर ध्यान देता है। इसके साथ ही बेरोजगार होने वाले श्रमिको के पुनर्वास और उन्हे नये कामो का पुन प्रशिक्षण देने की सुविधाओ की ओर भी ध्यान दिया ज रहा है। श्रमिको के वेतन इतने ऊँचे रहे है कि उनमे से बहुत-से स्वल्पकालिक बेरोजगारी के दिनो के लिए कुछ पैसा अपने वेतनो मे से बचाकर सुरक्षित रख सके है। इसके अतिरिक्त 60 प्रतिशत से अधिक बेरोजगार व्यक्ति अपना रहन-सहन का स्तर कायम रखने के लिए सरकार से मिलने वाला बेरोजगारी बीमे का लाभ प्राप्त करते है। कुछ मजदूर यूनियने और कुछ बडी फार्मे अपने बेरोजगार सदस्यो और कर्मचारियो को पूरक आय भी प्रदान करती है। बेरोजगार मजदूर जानते है कि सरकार रोजगार के स्तर को निरन्तर ऊँचा बनाये रखने और बढाने की नीति से बधी हुई है और इसलिए वह रोजगार के नये-नये अवसर पैदा करने के लिए बराबर कोशिश कर रही है।

पिछले अनुभव के आधार पर कुछ प्रेक्षको ने यह मत प्रकट किया है कि तीव्र गति से बढते आर्थिक विस्तार से या तो काफी आर्थिक अस्थिरता आयेगी या वस्तुओ की कीमते बढेगी। द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध दोनो के बाद—यानी युद्धोत्तरकालीन वर्षो मे—कीमते वास्तव मे ही काफी तेजी से बढी और हाल के वर्षो मे भी सयुक्त राज्य अमेरिका और ससार के और बहुत-से देशो मे कीमतो मे वृद्धि जारी रही है। यद्यपि 1951 के वसन्त से 1960 के अन्त तक कीमतों

मे वृद्धि बहुत अधिक विक्षुब्ध कर देने वाली ही रही, तो भी उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अभी तक इस समस्या का समाधान नही किया जा सका कि सब लोगो को रोजगार देने वाली और मूल्यो को स्थिर रखने वाली अर्थ-व्यवस्था कैसे स्थापित की जाय।

सयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऐसे सुदीर्घ काल का उपभोग किया है जिसमें उसके यहाँ रोजगार उत्पादन और वस्तुओ की खपत का स्तर न सिर्फ ऊँचा रहा है, बल्कि उसमे बराबर वृद्धि भी होती रही है। किन्तु हाल के वर्षो मे उत्पादन और रोजगार मे वृद्धि की रफ्तार सन्तोषजनक नही रही। इसके अलावा इस बात का कोई पक्का भरोसा नही है कि भविष्य में गम्भीर आर्थिक उतार-चढाव नही आएँगे। इस तरह का भरोसा कर लेना वैसा ही गलत होगा, जैसा कि 1930 से प्रारम्भ दशक की मन्दी के वर्षो मे यह भय मान लेना गलत था कि अब अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे अनिश्चित काल तक मन्दी ही जारी रहेगी। सरकार, व्यापारी, मजदूर और आम अमेरिकी लोग स्पष्ट रूप मे यह महसूस करते है कि आर्थिक अभिवृद्धि को दृढता से कायम रखने और रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए अधिक प्रभावकारी उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएँ

विभिन्न देशो के रहन-सहन के आँकडो की तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकी लोग दूसरो की अपेक्षा न केवल वस्तुओ और सेवाओ का अधिक उपभोग करते है, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभो मे भी वे अन्य देशो के लोगो की अपेक्षा अधिक समान हिस्सा बँटाते है। फिर भी जीवन-स्तर के कुछ विशिष्ट पहलुओ—उदाहरण के लिए भोजन मे कैलोरियो की मात्रा, मकान और पुरुषो की औसत आयु (जीवन की आशा)—की दृष्टि से तुलना करने पर एक या अधिक औद्योगिक देशो का स्थान सयुक्त राज्य से ऊपर रहता है। और यदि इन तुलनात्मक आकडो को जिनमे कुछ कम विकसित देशों की अपेक्षा सयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान ऊँचा रहता है, हर देश की विकास की स्थिति

चार्ट 4

उपलब्ध आहार की मात्रा कैलोरियो मे 1958–59
(प्रति व्यक्ति प्रति दिन कैलोरियाँ)
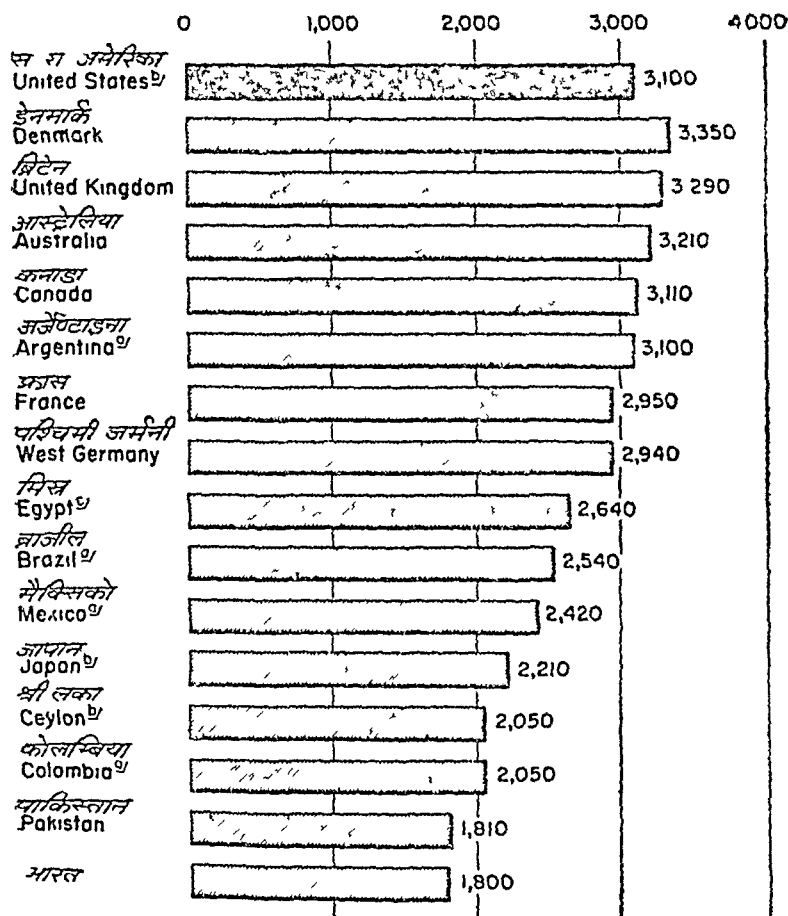
a) 1957
b) 1957
c) 1957—58

पर विचार किये बिना स्वीकार कर लिया जाय, तो वे अन्य देशो की वास्तविक आर्थिक उपलब्धियो को बहुत फीका कर देते है। इसलिए वास्तविकता पूर्ण अध्ययन और मूल्याकन के लिए यह जरूरी है कि उन समस्याओ, कठिनाइयो और बाधाओ को भी ध्यान मे रखा जाय, जिनका कम विकसित देशो को अपने प्रति-व्यक्ति उत्पादन और उपभोग मे मामूली-सी वृद्धि के लिए भी सामना करना पडता है और जिन पर विजय पाये बिना वे अपना यह स्वल्प-सा लक्ष्य भी पूरा नही कर सकते।

फिर भी यदि सयुक्त राज्य और अन्य देशो मे लाभयुक्त रोजगार पर लगे हर व्यक्ति के पीछे उत्पादन की और कुल आबादी के हर व्यक्ति के पीछे उपभोग की तुलना पैसों मे की जाय तो हम देखेंगे कि सयुक्त राज्य मे इन दोनो का स्तर यूरोप के अनेक देशो के स्तर से दो से तीन गुना तक ऊँचा और दूसरे बहुत-से देशो के स्तर से आठ से दस गुना तक ऊँचा है। यदि पैसो के बजाय भौतिक वस्तु की दृष्टि से ये तुलनाएँ की जाएँ तो भी यही असमानताएँ नजर आएँगी। इस उदाहरण के लिए लोगो के आहार के तत्वो की तुलना की जाय तो यह प्रतीत होगा कि ससार की 60 प्रतिशत के लगभग आबादी ऐसे इलाको मे रहती है, जहाँ खाद्योत्पादन वहाँ के हर व्यक्ति को 2,200 कैलोरी भी प्रतिदिन उपलब्ध नही करा सकता, जबकि अधिकतर स्थानो की परिस्थितियो की दृष्टि से पोषक तत्वो की यह मात्रा न्यूनतम वाछनीय या उससे भी कम है।

सयुक्त राज्य मे और ससार के अन्य अधिक उद्योग सम्पन्न देशो मे लोगो को पोषण की आवश्यकता से भी अधिक आहार मिल जाता है, जब कि अधिकाश कम विकसित देशो मे कैलोरियो की दृष्टि से पोषक आहार की मात्रा आवश्यक या वाछनीय मात्रा से कम रहती है। इसका अभिप्राय यह नही है कि सयुक्त राज्य मे अल्पपोषण या आहार की कमी जैसी चीज़ है ही नही; लेकिन यह बात जरूर सही है कि अमेरिका मे पोषण की पर्याप्तता का स्तर संसार के और बहुत-से क्षेत्रो के स्तर से काफी ऊँचा है।

भौतिक जीवन-मान की दूसरी तुलना विभिन्न देशो की आवास

सबधी परिस्थियो की तुलना मे दृष्टिगोचर होती है। सयुक्त राज्य मे यूरोप और लैटिन अमेरिका के अनेक भागो की अपेक्षा प्रति-व्यक्ति घर 10 से 50 गुना तक अधिक है। अन्य बहुत-से देशो की तुलना मे यह संख्यात्मक अन्तर इससे भी अधिक बडा है और स्वच्छता सम्बन्धी सुवि-

चार्ट 5

उपलब्ध रिहायशी मकान
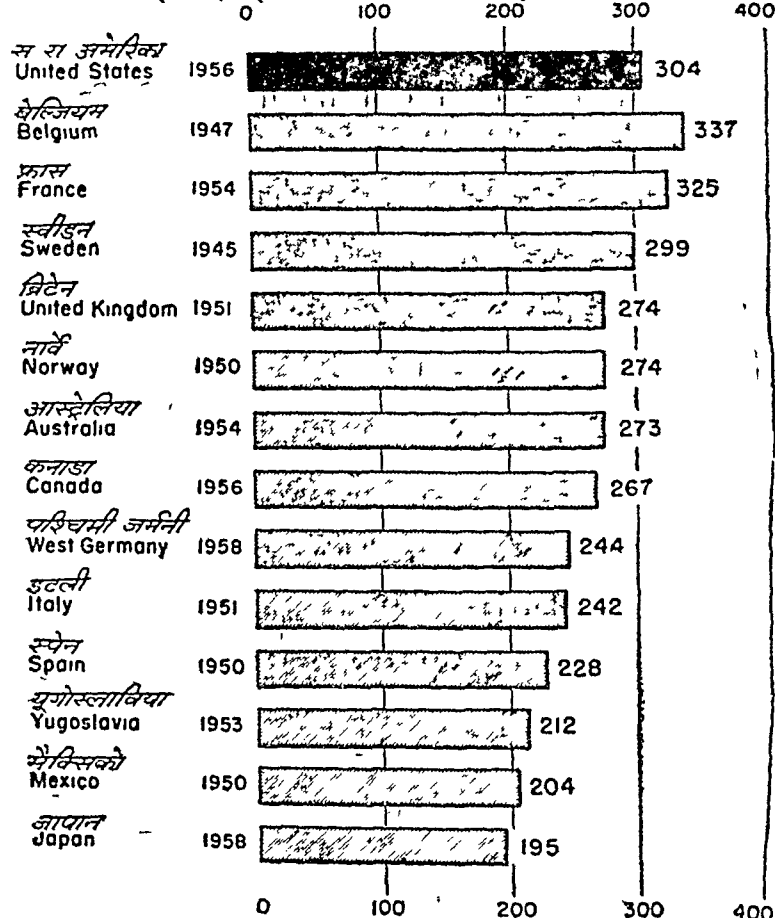
धाओं, रोशनी, पानी और मनोरजन के स्थान की दृष्टि से जो गुणात्मक अन्तर है, उसका तो कहना ही क्या। लेकिन इससे यह अर्थ निकालना

चार्ट 6

जन्म के समय पुरुषों की जीवन की आशा
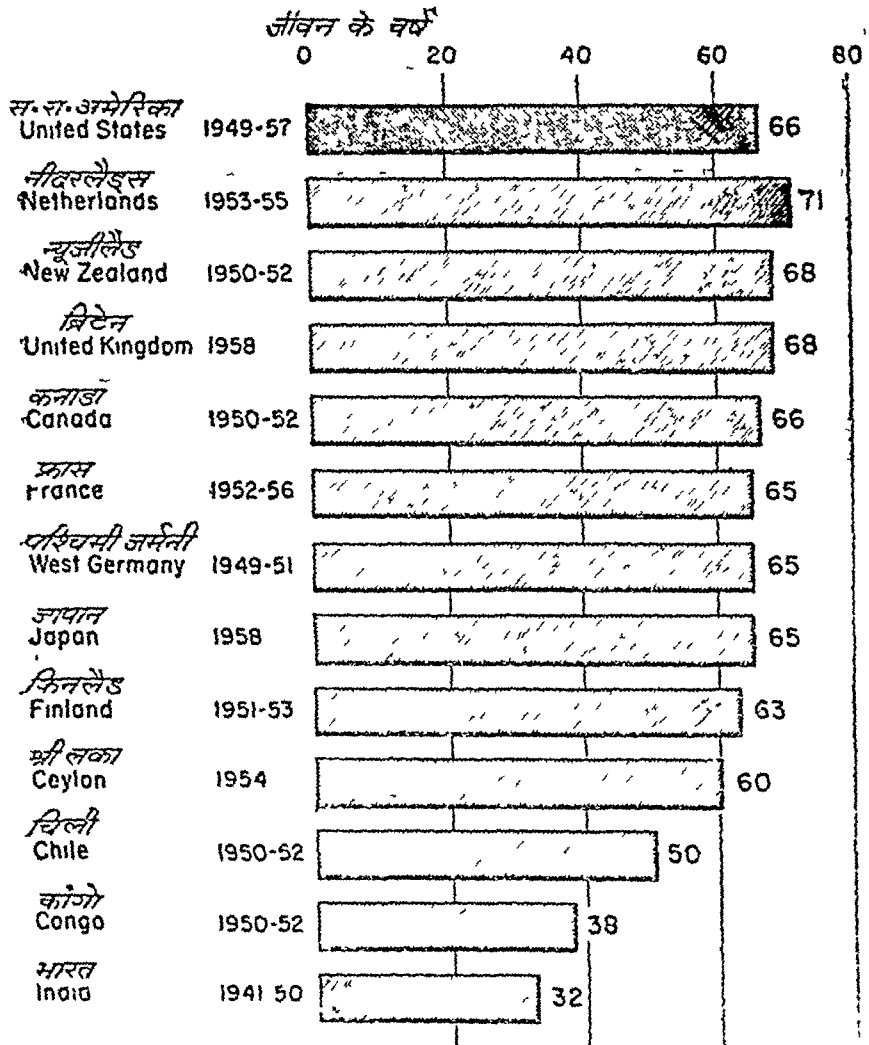
कि सयुक्त राज्य मे भीड भरी और गन्दी रिहायशी बस्तियाँ है ही नही, आकडो के धोखे मे पडना है।

आय के स्तर विषयक आंकडे अपने आप मे पूर्ण रूप से यह सिद्ध

नही करते कि सयुक्त राज्य और अन्य देशो मे मजदूरी के स्तरो मे कितनी असमानता है। एक ही वस्तु के मूल्य-स्तर और उपभोग के ढाचे अलग-अलग देशो मे अलग-अलग है। इस अन्तर के बावजूद सयुक्त राज्य एव अनेक यूरोपीय देशो मे औसत मजदूरी की क्रय-शक्ति का अनुमान लगाने के प्रयत्न किये गए है। यह हिसाब लगाया गया है कि विभिन्न प्रधान खाद्य पदार्थों को खरीदने लायक पैसा कमाने के लिए किस देश में मजदूरो को कितने घण्टे काम करना पडता है। इस हिसाब से यह मालूम हुआ है कि यूरोप के अनेक अधिक उद्योग सम्पन्न देशो मे भी एक वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए औसत मजदूर को सयुक्त राज्य के औसत मजदूर की अपेक्षा चार या पाँच गुना अधिक समय तक काम करना पडता है। (देखिए परिशिष्ट तालिका 8)।

जब हम औसत जीवन-आशा की दृष्टि से तुलना करते है तो रहन-सहन के स्तर के ये अन्तर और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की उन्नति से लोगो की औसत आयु मे सर्वत्र वृद्धि हुई है, तो भी ये औसत आयु अलग-अलग देशो मे अलग-अलग है। कुछ कम विकसित देशो मे लोगो के जीवन का औसत-विस्तार अधिक उद्योग-सम्पन्न देशो के लोगो के जीवन के औसत विस्तार से बहुत कम होता है। लोगो की जिन्दगी के कम या अधिक होने का यह अन्तर बहुत हद तक आराम के साधनो के अन्तर के कारण होता है, बशर्ते कि आराम के साधनो का अर्थ केवल मोटर-गाडी और टेलीफोन ही न समझा जाय बल्कि उसमे डाक्टर, चिकित्सा-सुविधा, सार्वजनिक स्वच्छता और विश्राम का समय आदि भी शामिल किये जाएँ।

सारांश

इस अध्याय मे दिये गए आकडे, यद्यपि वे सक्षेप मे और मोटे तौर पर दिये गए है, इस बात को काफी हद तक पुष्ट करते है कि अमेरिका मे उत्पादकता और उपभोग के स्तर ऊँचे है और हाल के दशको मे

उनमे काफी वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के परस्पर-सम्बद्ध कारणो के बारे में लोगो को काफी जानकारी नही है। अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था पर विचार करते हुए कुछ कारणों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और कुछ पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। इस जटिल आर्थिक तन्त्र के अधिक महत्त्वपूर्ण भागो पर अगले अध्यायो मे विचार करते हुए हम यह देखेंगे कि हर भाग क्या काम करता है, उन सबका एक-दूसरे के साथ कैसे समन्वय है और क्या अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था मे उत्तरोत्तर अभि-वृद्धि जारी रखने के लिए उनमे से कुछ मे कुछ परिवर्त्तन करने की आवश्यकता है।

2

प्राकृतिक साधन

आमतौर पर कहा जाता है कि जो देश ऊँचे जीवन-स्तर का उपभोग करता है, उस पर प्रकृति की अवश्य विशेष कृपा रही होगी। क्या सयुक्त राज्य अमेरिका के बारे मे यह बात सही है? क्या अमेरिका की जलवायु इतनी अनुकूल है, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है और खनिज स्रोत इतने समृद्ध है कि सयुक्त राज्य का अधिक आबादी वाला और अधिक उत्पादक राष्ट्र होना अनिवार्य हो?

सयुक्त राज्य की दूर तक फैली सीमाओ के भीतर समशीतोष्ण कटिबन्ध के प्राय सभी किस्म के मौसम पाये जाते है—गर्म, सर्द, नम, खुश्क और इनके बीच के। सब मिलाकर सयुक्तराज्य का जलवायु अन्य कई देशो के, उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप के, अपेक्षाकृत हल्के जाडो और हल्की गर्मियो के मौसम के मुकाबले मे, अधिक देर तक और अधिक कडी मेहनत का काम करने के लिहाज से अच्छा नही है। फिर भी इसमे सन्देह नही कि उष्णकटिबन्ध के अनेक देशो की तुलना मे वह कडी शारीरिक मेहनत करने के लिए अधिक अच्छा है। लेकिन मौसम के इस सामान्य प्रभाव को यदि छोड दिया जाय, तो अमेरिका का मौसम यहाँ की कृषि के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

कृषि के साधन

इसमे तनिक भी सदेह नही कि अमेरिका की कृषि की उत्पादकता इस समय बहुत ऊँची है, लेकिन इसका कारण यहाँ की भूमि का असाधारण तौर पर उपजाऊ होना और मौसम का अनुकूल होना है, यह एक गम्भीर सदेह का विषय है।

अपने विकास के प्रारम्भिक युगो मे तो अमेरिकी कृषि को उपजाऊ-

पन्न और अनुकूल मौसम के लाभ प्राप्त थे। उस समय सारा प्रदेश खुला था, खेती के लिए चाहे जितनी भूमि उपलब्ध हो सकती थी, जमीन उपजाऊ तत्त्वो से भरी हुई थी, क्योंकि उस पर पहले कभी खेती नही हुई थी, दूर-दूर तक घास के हरे-भरे मैदान और घने जगल थे जो ज़मीन के भीतर नमी को क़ायम रखते थे और उसका क्षरण नहीं होने देते थे। उस समय वहाँ भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की प्रवृत्ति ससार के अधिक सघन आबाद भागो की अपेक्षा कम थी। कारण, जब किसी एक जगह खेती करने पर जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती तो किसान उसे छोडकर नई जमीन पर खेती करने के लिए आगे बढ जाते। नई जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर नये सिरे से आबाद होने मे खर्च भी अधिक नही पडता था। किसान के परिवार के पास यदि खेती के कुछ थोडे-से सादे औजार, बीज और कडी मेहनत करने की आकाक्षा होती तो वह आसानी से अपना नया घर आबाद कर सकता था। लेकिन इस अच्छी और गहरी मिट्टी के बावजूद किसान अपने परिवार की अन्न-वस्त्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त अनाज और कपास आदि पैदा नही कर सकता था। उदाहरण के लिए सन् 1820 मे सयुक्त राज्य मे एक कृषि-मजदूर केवल चार ही व्यक्तियो की आवश्यकता के लिए उत्पादन कर सकता था।

लेकिन यह स्थिति बहुत पहले ही बदल चुकी है। आज एक कृषि-मजदूर लगभग तीस व्यक्तियो की अन्न-वस्त्र की आवश्यकताओ के लायक अनाज और कपास आदि पैदा कर लेता है। अच्छी कृषि-भूमि की कीमते ऊँची है और बराबर चढ रही है और बडे-बड़े फार्मो की आवश्यकता और आकाक्षा बढ़ती जा रही है। एक अमेरिकी को आज एक सफल कृषक बनने के लिए केवल जमीन खरीदने के लिए ही काफी पैसा लगाने की आवश्यकता नही है, बल्कि खेती के यन्त्र, उत्कृष्ट किस्मो के बीज, अच्छी नस्ल के पशु, उर्वरक, कीटाणु-नाशक दवाएँ, भूमि-सरक्षण और सिचाई के साधनो पर भी काफी पैसा लगाने की जरूरत होती है। उनके उपयोग के लिए उसमे प्रवन्ध-सम्बन्धी और

तकनीकी योग्यता भी होनी चाहिए। अधिक उत्पादन की उसकी क्षमता बहुत हद तक दूसरे लोगो के काम पर भी निर्भर है—यानी वह रासायनिक पदार्थ, मशीनरी, बिजली का सामान और ट्रैक्टर आदि आवश्यक वस्तुओ और औजारो के कारखानो मे काम करने वालो, कृषि-उत्पादनो के अनुसन्धान-कर्त्ताओ एव वितरको और उसे हर समय नई उत्पादन-विधियो और तकनीकी पद्धतियो की जानकारी देते रहने वालो के काम के साथ बधी हुई है।

खासकर पिछले पच्चीस वर्षो मे, कृपि सम्बन्धी उत्पादकता मे काफी वृद्धि हुई है और उसका कारण फार्मों मे काफी बडी मात्रा मे धन का निवेश (इन्वेस्टमेट) और तकनीकी विधियो मे द्रुत गति से सुधार है। सयुक्त राज्य की अधिकाश फसलो मे प्रति एकड उपज सन् 1940 से प्रारम्भ दशक के शुरु वर्षो की अपेक्षा आज अधिक हैं। प्रति एकड उपज मे वृद्धि से भी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रति कृषक उत्पादन मे वृद्धि है। प्रति-मानव-घटा कृषि उत्पादन आज सन् 1940 की तुलना मे तीन गुना और सन् 1929 की तुलना मे लगभग चार गुना हो गया है। अमेरिका मे कृषि-मजदूरो की सख्या ससार के कुल मजदूरो की सख्या का 1 5 प्रतिशत है, किन्तु उसका कृषि-उत्पादन ससार के कुल कृषि-उत्पादन का 16 प्रतिशत है। प्रति मानव उत्पादन, प्रति एकड उत्पादन, उपज की किस्म, फार्मो का विस्तार, उनमे किया गया पूंजी का निवेश, फार्मो के कर्मचारियो का जीवन-स्तर या किसी भी अन्य दृष्टि से तुलना करने पर मालूम यह होगा कि अमेरिकी कृषि मे हाल के वर्षो मे असाधारण परिवर्तन हुए हैं।

जहाँ एक ओर ये दूरगामी परिवर्त्तन होते रहे हैं, वहाँ अमेरिका की कृषि की एक बुनियादी विशेषता ज्यो की त्यो अपरिवर्त्तित रही है। अमेरिकी कृषि मे पारिवारिक फार्मों का, जो वहाँ की एक परम्परागत वस्तु रही, अब भी प्रधान स्थान है। यह अमेरिका के लिए बहुत लाभकारी बात है, क्योंकि प्राइवेट पारिवारिक फार्मों मे काम करने के ९ जितना प्रोत्साहन मिलता है, उतना और किसी भी प्रकार के

फार्मो मे नही मिलता। इसी प्रकार नये-नये तकनीकी अनुसन्धान करने और उनसे लाभ उठाने की प्रवृत्ति भी अमेरिकी लोगो के लिए नई नही है। पिछले सौ वर्षो मे अमेरिका की सघीय और राजकीय सरकारो ने कृषि-अनुसन्धान, कृषि-शिक्षा और कृषकों की कौशल-वृद्धि के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किये है। कृषको और उनकी हर नई पीढी को शिक्षा-प्राप्ति और शिक्षा सेवाओ के पहले से अधिक अवसर मिलते रहे है। उन्हे कृषि सम्बन्धी हाई स्कूलो, कालेजो और प्रयोग केन्द्रो मे अध्ययन करने का और सरकारी विशेषज्ञो से तथा फार्मो से उपज खरीदने और उन्हे उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ मुहैया करने वाले व्यापारियो की व्यक्तिगत सलाह से लाभ उठाने का मौका मिला है। वे फार्मो के सगठनो मे भाग लेते है। उन्हे कृषि सम्बन्धी सभी कार्यो के विषय मे कितनी ही पुस्तिकाएँ, पत्रिकाएँ और बुलेटिन आदि मुफ्त या नाममात्र के मूल्य पर वितरित किये जाते है। इन सभी चीजों ने पारिवारिक फार्मो की उत्पादकता और लाभकारिता बढाने और उनसे कृषको मे सन्तोष पैदा करने में योग दिया है।

इसमे सन्देह नही कि अब भी मौसम, जमीन और स्थलाकृति के कारण हर फार्म पर कुछ-न-कुछ प्रतिकूल असर पड़ता है और किसी-किसी वर्ष और किसी-किसी इलाके में यह असर बहुत अधिक प्रतिकूल भी होता है। फिर भी तीन अन्य कारण ऐसे है जो अमेरिकी कृषि की उत्पादकता को बढाते है और उन पर इन प्राकृतिक विपर्ययो का बहुत असर नही पडता, क्योकि इन कारणो का मौसम और भूमि की मूल उर्वरा शक्ति से सीधा सम्बन्ध नही है। ये तीन कारण है: पारिवारिक ढग के फार्म; पारिवारिक ढंग के फार्मो का अपेक्षाकृत बड़ा होना; और इन पारिवारिक फार्मों मे नई-नई तकनीकी विधियो का अधिकाधिक उपयोग और बहुत अधिक पूँजी का निवेश।

सयुक्त राज्य की वर्तमान कृषि-पद्धति और उसके कृषकों के बारे मे बहुत-से लोगो की धारणाएँ वास्तविकता से बहुत दूर है। कुछ लोग यह समझते है कि संयुक्त राज्य में कृषि का धन्धा बहुत सीधा-सादा है और कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के और मामूली-सी

पूँजी से कृषि का धन्धा अपना सकता है। दूसरी ओर इससे ठीक उल्टा विचार रखने वाले लोग भी है जो यह समझते है कि यहाँ पारिवारिक फार्मों का अन्त हो रहा है और उनकी जगह बड़े-बड़े सयुक्त फार्म बन रहे है और उन्ही के कारण यहाँ अन्न और कपास आदि का उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ रहा है। ये दोनो सर्वथा परस्पर-विरोधी धारणाएँ सत्य से बहुत दूर है। अन्य देशो के लोगो मे अमेरिकी-कृषि व्यवसाय के बारे मे सही जानकारी न होने का एक कारण भी है। सन् 1959 की कृषि सम्बन्धी जनगणना मे अमेरिका के 37 लाख फार्मों का जो विवरण दिया गया है, वह बहुत विविधतापूर्ण है। ये फार्म विस्तार की दृष्टि से एक एकड से लेकर दस हज़ार एकड तक की और वार्षिक उपज की बिक्री के लिहाज से पचास डालर से लेकर दस लाख डालर से भी अधिक तक की विविध श्रेणियो मे बाटे जा सकते है। इन फार्मों मे पैदा होने वाली फसलो और पाले जाने वाले पशुओ मे भी बडी विविधता है। इनमे यान्त्रिक औज़ारो और भाडे पर रखे जाने वाले मजदूरो के उपयोग की दृष्टि से ही नही और भी बहुत-सी दृष्टियो से असमानता और विविधता है।

सन् 1959 की जनगणना के विवरण मे एक औसत अमेरिकी फार्म की तस्वीर मिलती है। और साथ ही आर्थिक दृष्टि से उनका वर्गीकरण करके उनका परस्पर एक-दूसरे से अन्तर भी बताया गया है। पहला अन्तर यह है कि कुछ फार्म 'व्यापारिक' है और कुछ नही है। व्यापारिक फार्म वे हैं जो सारे समय चलने वाले फार्म है और आर्थिक दृष्टि से उन्हे छ वर्गों मे बाटा गया है। छोटे-से-छोटे फार्म की वार्षिक उपज की बिक्री 50 डालर और बडे फार्मों की अधिकतम वार्षिक उपज की बिक्री 40 हजार डालर या इस से भी अधिक है। 'व्यापारिक' श्रेणी मे न आने वाले फार्म वे है जिनमे सारे वर्ष काम नही होता अथवा जो लोगो ने अपने निवासस्थानो पर ही बनाये हुए हैं। इन फार्मों के मालिक वर्ष मे 100 या इससे भी अधिक दिन फार्मो से बाहर काम करते है और उनकी फ़ार्मो से बाहर के काम की आमदनी फ़ार्मों की आमदनी से अधिक है। इस श्रेणी मे ऐसे फार्म भी आते है जिनके मालिको की आयु

65 वर्ष से अधिक होती है और उनके वार्षिक उत्पादन की बिक्री 2500 डालर से अधिक नही होती ।

सन् 1959 मे सारे वर्ष चलने वाले व्यापारिक फ़ार्मो मे से 80 प्रतिशत की वार्षिक उत्पादन की बिक्री 2500 डालर से 40,000 डालर तक थी, जबकि तमाम व्यापारिक फार्मो मे से कुल 4 प्रतिशत ही ऐसे थे जिनकी वार्षिक उपज की बिक्री 40,000 डालर से अधिक थी । फिर भी इन चार प्रतिशत बडे फार्मो के वार्षिक उत्पादन की बिक्री सयुक्त राज्य के कुल कृषि-उत्पादनो का एक चौथाई थी ।

यदि एक औसत अमेरिकी व्यापारिक फार्म की तस्वीर खीची जाय तो वह इस प्रकार होगी कृषक परिवार के पास 320 एकड के लगभग भूमि होगी जिसमे से 40 प्रतिशत मे फसल बोयी जाती होगी उसकी 33,000 डालर की पूँजी जमीन और फार्म की इमारतो मे, 4,000 डालर की मशीनरी मे और 3,600 डालर की पशुओ मे लगी हुई होगी । मशीनो और मजदूरो को भाडे पर रखने मे उसका 1,000 डालर और व्यय होगा । और इसके बाद उसके वार्षिक उत्पादन का विक्रय मूल्य 7,500 डालर होगा ।

इस औसत दर्जे के फार्म मे बिजली और बहते पानी का उपयोग न केवल उसके कामो को अधिक सुचारू ढग से चलाने मे सहायक होता है, बल्कि कृषक परिवार के घरेलू काम भी उससे अधिक अच्छी तरह हो सकते है, परिवार के लोग अधिक स्वस्थ जीवन बिता सकते है और उन्हे विश्राम का समय भी अधिक मिलता है (अमेरिका के 97 प्रतिशत से अधिक फार्म बिजली का उपयोग करते हैं) टेलीफोन और रेडियो उन्हे पत्र-पत्रिकाओ मे छपने वाले समाचारो और अन्य ज्ञातव्य बातो की जानकारी देते रहते है । यदि कोई टेलीविजन स्टेशन आसपास हो तो कृषक-परिवार की बैठक मे एक टेलीविजन सैट भी होता है । सचार और परिवहन के साधनो मे सुधार के कारण कृषक बाजारों के रुख के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है । कृषक परिवार के पास वाहन होने से उसके सदस्य शैक्षणिक, सास्कृतिक और सामाजिक अवसरो का अधिक लाभ उठा सकते है ।

औसत अमेरिकी फार्म का वर्णन करने से भी अधिक कठिन काम यूरोप या एशिया के औसत फार्मों के साथ उसकी तुलना करना है। ससार के अन्य भागो मे एक कृषक परिवार के पास अपेक्षाकृत कम कृषि योग्य भूमि होती है। उदाहरण के लिए, बेल्जियम मे मोटे तौर पर तीन चौथाई फार्म २.५ एकड से भी कम भूमि वाले है। फार्म इतने छोटे होने पर उनके काम मे बहुत कुशलता नही आ सकती और न मशीनरी का अधिक उपयोग हो सकता है। लेकिन फार्म छोटे होने के कारण इनमे कृषक परिवार अधिक उत्पादन के लिए सघन कृषि करता है। यही कारण है कि अमेरिका मे कुछ फसलो का प्रति एकड उत्पादन ससार के अन्य भागो के प्रति एकड उत्पादन की तुलना मे कम है। इसलिए यह सम्भव है कि विभिन्न देशो के फार्मों के औसत परिमाणो की तुलना से सयुक्त राज्य और अन्य अनेक देशो के पारिवारिक फार्मों की विशेषताओ की सही तुलना न हो सके।

कुछ फार्म इतने बडे होते है कि उनमे मजदूरी पर मजदूर रखने पडते है और यह देखा गया है कि कुछ किस्मो के फार्म उत्पादन मे स्वय परिवार के लोगो द्वारा किये जाने वाले श्रम की अपेक्षा मजदूरो का यह श्रम कम कुशल होता है। किन्तु फिर भी सयुक्त राज्य मे अधिकतर बडे पारिवारिक फार्म भी उन्नत कृषि विधियो और साधनो के कारण बाहर के बहुत कम मजदूर रखकर स्वय परिवार के सदस्यो द्वारा ही चलाये जा सकते हैं। फार्मों मे श्रम की बचत करने वाले साधनो के अधिकाधिक उपयोग से यह मालूम हो जाता है कि किस प्रकार अमेरिकी पारिवारिक फार्म का सचालन मानवीय हस्त-श्रम की गतिविधि के बजाय एक तकनीकी गतिविधि बन गया है। उदाहरण के लिए सन् 1959 मे 75 प्रतिशत व्यापारिक फार्मों मे ट्रैक्टर और 59 प्रतिशत मे मोटर-ट्रैक्टर इस्तेमाल होते थे। यही बात इस प्रकार भी समझी जा सकती है कि फार्मों मे 1959 मे 30 लाख घोडे या खच्चर थे, जबकि 1920 मे उनकी सख्या 250 लाख थी।

तालिका 1

कृषि जोतो का परिणाम और वर्गीकरण—1950

देश	औसत कृषि जोत (हैक्टेयरो मे)	एक हैक्टेयर से कम की जोते (प्रतिशत)	दस हैक्टेयर से कम की जोते (प्रतिशत)
सयुक्त राज्य अमेरिका	122 3	1[1]	28[4]
बेल्जियम	1 9	75	95
कनाडा	113 1	[2]	4[5]
कोस्टारिका	42 1	अनुपलब्ध	54
डेनमार्क	17 5	1	46
एल साल्वेडोर	8 8	40	89
फिनलैंड	33 3	44[3]	84
पश्चिमी जर्मनी	10 9	14	76
होण्डुरास	16 1	10	75
जापान	1 6	67	99.5
नीदरलैंड्स	5 7	41	82
नार्वे	20 2	46	94
फिलिपाइन	3 5	19	94
उरुग्वे	199.7	अनुपलब्ध	26

सन् 1950 और 1959 के बीच व्यापारिक फार्मो मे ग्रेन कम्बाइन मशीने 47 प्रतिशत और कॉर्न पिकर मशीने 75 प्रतिशत बढ़ी। इसी प्रकार दूध दुहने, गांठे बाँधने, फसल काटने आदि की मशीने भी काफ़ी

1. 1·2 हैक्टेयर से कम की जोतें। (हैक्टेयर—2·47 एकड़)
2. ·5 प्रतिशत से कम।
3. 2 हैक्टेयर से कम की जोतें।
4. 11·7 हैक्टेयर से कम की जोतें।
5. 4 हैक्टेयर से कम की जोतें।

बढी । इस प्रकार फार्मो मे कृषि के अधिकाधिक यान्त्रिकीकरण से खेती के लिए मजदूरो की आवश्यकता कम हो गई है और वे निर्माण-उद्योगो और सेवा-व्यवसायो मे काम कर सकते है।

तालिका 2

संयुक्त राज्य मे फार्मों की संख्या मे परिवर्तन की निर्देशिका

वर्ग	1930	1940	1950	1959
कुल फार्म	100	97	86	59
व्यापारिक फार्म	100	89	70	46
बडे[1] (पहले वर्ग के)	100	93	80	80
मध्यम[2] (दूसरे वर्ग से पाँचवे वर्ग तक के)	100	85	66	45
छोटे[3] (छठे वर्ग के जिनकी वार्षिक बिक्री 250 डालर से 1200 डालर तक है)	100	110	89	47
गैर-व्यापारिक फार्म (कुछ समय चलने वाले या घरो पर स्थापित)	100	137	166	130

पिछले 25 वर्षो मे फार्मो की उत्पादकता मे वृद्धि होती रही है, लेकिन उनकी सख्या कम हो गई है पर सख्या मे कमी होने से भी जोत-भूमि मे कमी नही हूई । इसका अर्थ यह है, कि कुछ लोग कृषि का धन्धा छोडकर दूसरे कामो मे लग गए और उनकी जमीने बड़े फार्मों ने उनसे लेकर अपनी जमीनो मे मिला ली । सन् 1959 से पूर्व 25 हजार डालर से कम वार्षिक बिक्री वाले फार्मों की और 1959

* 1959 की और उससे पहले के वर्षों की परिभाषाएं एक-सी नहीं हैं।

1 25 हजार डालर या अधिक, की वार्षिक बिक्री (1959 में 40 हजार या अधिक की)

2 1200 से 25 हजार डालर तक की वार्षिच बिक्री (1959 में 2500 से 40 हजार डालर तक की)।

3 250 से 1200 डालर तक की वार्षिक बिक्री (1959 में 50 डालर से 2500 डालर तक की।

में 40,000 डालर से कम वार्षिक बिक्री वाले फार्मों की सख्या बहुत तेजी से गिरी है। फिर भी बड़े पैमाने पर काम करने वाले फार्मों की संख्या मे उतनी तेजी से कमी नही आयी, हालाकि इनमे ऐसे फार्मो की सख्या बहुत कम है जो बडी-बडी कम्पनियो या वेतन-भोगी प्रबन्धकों द्वारा चलाये जाते है और यह एक महत्त्वपूर्ण बात है।

अमेरिका मे कृषि की उत्पादकता निरन्तर बढ रही है, अतः यह आशा है कि फार्मो मे कृषि-मजदूरो की सख्या कम हो जाने पर भी कुल कृषि-उत्पादन मे वृद्धि ही होगी। कृषि सम्बन्धी रोजगारो का महत्त्व 1860 के दशक के गृह-युद्ध से पूर्व ही कम होने लगा था और अब बीसवी शताब्दी मे भी यही स्थिति है। पिछले बीस वर्षो मे यद्यपि कृषि उत्पादन ड्योढे से भी अधिक हो गया है तो भी फार्मो मे रोजगार पर लगे कृषि-मजदूरो की सख्या 35 प्रतिशत घट गई है और यह सम्भावना है कि वह भविष्य मे और भी घटेगी। हालाकि सयुक्त राज्य की आबादी बढने से अन्न की माँग बढेगी तो भी आशा यही है कि इस सख्या मे निरन्तर कमी होगी। कारण यह है कि अगले एक दशक मे,

चार्ट 7

फार्मो में काम करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अनुपात
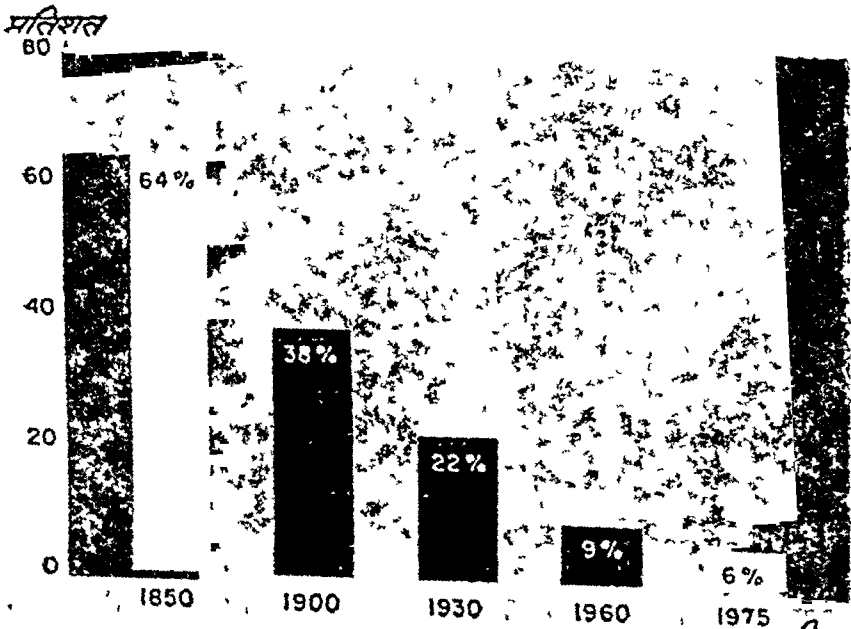
कम से कम कुछ मुख्य पदार्थों के बारे मे कृषि की उत्पादकता देश की आन्तरिक माँग से ज्यादा बढ जाएगी। इसके अतिरिक्त माँग मे होने वाली अधिकतर वृद्धि ऊँचे दर्जे के खाद्य पदार्थों की माँग मे होगी। इसलिए इन पदार्थों को तैयार करने, डिब्बों मे बन्द करने और वितरण करने के लिए जरूर अतिरिक्त श्रमिको की आवश्यकता होगी, किंतु कृषि के काम के लिए नही। इस प्रकार फार्मों मे काम करने वाले लोगो की प्रतिशतता मे भी कमी की सम्भावना है।

यद्यपि अमेरिका मे कृषि से भिन्न व्यवसायो की उत्पादकता की अपेक्षा कृषि व्यवसाय की उत्पादकता का स्तर नीचा है, फिर भी अमेरिकी फार्मों मे काम करने वाले व्यक्तियो की उत्पादकता हमारी अपनी आन्तरिक माँग से अधिक है। यह एक विचित्र तथ्य है कि अमेरिका जैसे अत्यधिक उद्योग-सम्पन्न देश मे, कृषि उत्पादन भी अपनी आवश्यकता से इतना अधिक होता हो कि वह उसका दस प्रतिशत निर्यात के लिए निकाल सके। कृषि-उत्पादन की यह ऊँची सामर्थ्य दोनो विश्व-युद्धो के बाद विशेष रूप से उपयोगी और महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि युद्ध के कारण ससार के अनेक भागो मे खाद्य पदार्थों की बहुत कमी हो गई थी। यदि ससार की आबादी बढने से अति सघन आबादी वाले किसी देश मे अन्न की कमी गम्भीर समस्याएँ पैदा कर दे तब अमेरिका की इस ऊँची उत्पादकता का महत्त्व भविष्य मे भी बना रहेगा। सयुक्त राज्य का 'शान्ति के लिए अन्न' कार्यक्रम इस समस्या के समाधान के लिए ही बना है।

इस प्रकार सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी कृषि का उत्पादकता का स्तर इतना ऊँचा होने का कारण यहाँ का असाधारण रूप से अनुकूल मौसम या असाधारण तौर पर उर्वरा भूमि ही नही है, बल्कि इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ के अपेक्षाकृत बडे पारिवारिक ढग के फार्मों मे प्रति व्यक्ति उत्पादन का स्तर ऊँचा है, और यह ऊँचा स्तर अनेक कारणो के सम्मिश्रण का परिणाम है—जैसे कि हर व्यक्ति का अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग रहकर अधिक श्रम करना, तकनीकीज्ञान, ऊपरी देखरेख पर कम व्यय और बहुत बडे पैमाने पर यान्त्रिकीकरण।

खनिज सम्पदा

सयुक्त राज्य को जिस विशाल ऐतिहासिक विकास ने ससार का सबसे अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बना दिया है, उसमे उसकी कोयला, तेल और अन्य खनिज सम्पदाओ एव जल और लकडी आदि प्राकृतिक साधनो के प्राचुर्य ने महत्त्वपूर्ण योग दिया है। लेकिन कुछ चीजो को छोडकर बाकी प्राकृतिक साधनो की दृष्टि से यह स्थिति अब बदल गई है। अब अमेरिका के उद्योगो मे केवल देश के भीतर उत्पन्न कच्चे माल की ही भारी माँग नही है, बल्कि वे अन्य देशो से भी यह माल मगाते हैं। इस स्थिति का एक परिणाम यह भी हुआ कि अमेरिका मे अब ऐसी कृत्रिम वस्तुओ की शोध करने और उन्हे तैयार करने के लिए बहुत बडा प्रयत्न किया जा रहा है, जो प्राकृतिक वस्तुओ का स्थान ले सके। ये वस्तुएँ प्रभूत मात्रा मे पाई जाती है और उन्हे कुछ प्रक्रियाओं की सहायता से अधिक बेहतर उपयोग के लायक बनाया जा सकता है।

विभिन्न कच्ची सामग्रियो को उपयोगी वस्तुओ मे परिणत करने मे सहायता देने वाले महत्त्वपूर्ण कारणो मे से एक यह है कि अमेरिका मे सस्ती शक्ति (एनर्जी) पैदा करने वाले अनेक साधन प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है, खास तौर से कोयला। सयुक्त राज्य मे कोयला एक ऐसी महत्त्वपूर्ण कच्ची सामग्री है जिसका प्राकृतिक भडार अब भी उसकी [illegible] मे [illegible] है। [illegible] के दशको मे ईंधन के रूप मे कोयले की [illegible] जिस रफ्तार से [illegible] रही है, यदि वही रफ्तार भविष्य मे भी जारी रहे तो भी सयुक्त राज्य मे कोयला सौ वर्ष या उससे भी [illegible] पर्याप्त मात्रा मे मिलता रहेगा, [illegible] उसका उत्पादन- [illegible]। [illegible] सयुक्त राज्य मे [illegible] उत्पादन [illegible] उत्पादन [illegible] किया है, [illegible] कि उसका कोयले [illegible] के कुल प्राकृतिक भडार [illegible] है।

[illegible] उपार्जित [illegible] ससार [illegible] मे [illegible] सबसे [illegible]। [illegible] कोयला (बिटुमिनि-

नस कोल) जमीन के नीचे एक हजार फुट से कम की गहराई मे ही मिल जाता है, जब कि ब्रिटेन और जापान मे वह इससे भी कही अधिक नीचे जाकर मिलता है और कुछ खानें तो चार हजार से पाँच हजार फुट तक गहरी है। इसके अलावा अमेरिका के कोयले के उत्पादन का लगभग एक तिहाई भाग तो जमीन की ऊपरी तह मे ही प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए जमीन के नीचे खुदाई का काम करने की जरूरत ही नही पडती। प्रकृति के इन लाभो एव खानो की ऊँची उत्पादकता के कारण सयुक्त राज्य के अनेक हिस्सो मे उद्योगो को वहुत-से अन्य देशो की तुलना मे सस्ता ईंधन प्राप्त हो जाता है।

किन्तु जब हम सयुक्त राज्य मे निर्मित वस्तुओ के कुल उत्पादन व्यय को दृष्टि मे रखकर विचार करते हैं तो सयुक्त राज्य मे कोयले के सस्तेपन का लाभ, अपने आप मे काफी वडा होने पर भी, वहुत वडा प्रतीत नही होता। वस्तुओ के उत्पादन-व्यय मे अन्य कच्चे माल, श्रम, प्रबन्ध और पूंजी का भी हिस्सा होता है और उन सब पर विचार करना पडता है। निर्माण-उद्योगो मे एक औसत वस्तु को तैयार करने मे ईंधन का खर्च मोटे तौर पर चार प्रतिशत होता है। लेकिन जिन उद्योगो मे ताप या पावर का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है, उनमे ईंधन पर व्यय अधिक होना स्वाभाविक है। इसके अलावा और अधिक औद्योगिक विकास के लिए शक्ति के सस्ते स्रोतो की उपलब्धि का महत्त्व अधिकाधिक वढना सम्भव है। ससार की जनसंख्या जैसे-जैसे वढती जाती है और औद्योगिक उन्नति अधिकाधिक हो रही है, वैसे-वैसे हमारी पृथ्वी के कच्चे माल के प्राकृतिक स्रोतो का अधिकाधिक दोहन किया जा रहा हैं। इसके परिणामस्वरूप अब ऐसी कच्ची सामग्रियो का इस्तेमाल जरूरी हो गया है जो कम आसानी से उपलब्ध होती है या घटिया श्रेणी की है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कच्चे माल की जगह पर इस्तेमाल करने के लिए कृत्रिम वस्तुओ का भी धीरे-धीरे विकास किया जा रहा है। घटिया किस्म के प्राकृतिक कच्चे माल को इस्तेमाल करके सुधारने और कृत्रिम कच्चा माल तैयार करने के परिणामस्वरूप प्रति उत्पादित

वस्तु पर शक्ति (एनर्जी) का औसत व्यय अधिक बढ गया है।

कोयला एवं बहुत-सी कृषि-जन्य कच्ची सामग्रियो को छोडकर, शेष प्राकृतिक कच्ची सामग्रियो की खपत देश के आन्तरिक उत्पादन से अधिक बढ गई है और भविष्य मे वह और भी बढेगी। पचास वर्ष पूर्व यह स्थिति थी कि सयुक्त राज्य की कृषि-जन्य वस्तुओ से भिन्न 15 प्रतिशत प्राकृतिक कच्ची सामग्रियाँ अन्य देशो को निर्यात की जाती

चार्ट 8

कुछ चुने हुए देशो मे ईंधन की लागत
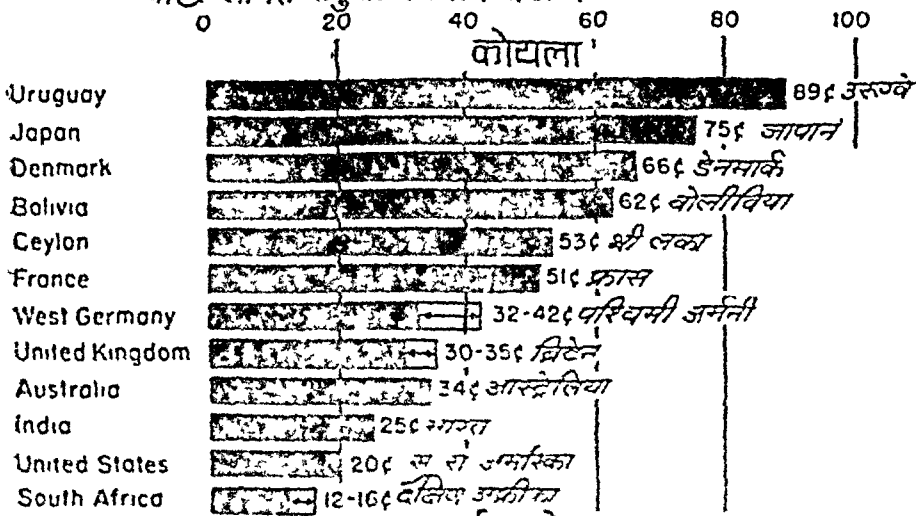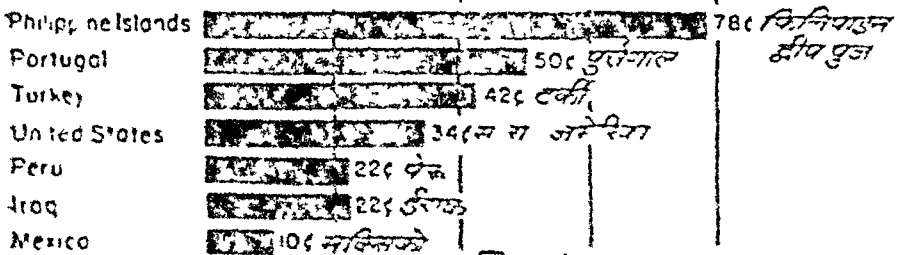
थी। आज यह प्रतिशत आधी रह गई है और बहुत-सी कच्ची सामग्रियो का काफी मात्रा मे आयात आवश्यक हो गया है और वह निरतर बढ रहा है। अमेरिकी उद्योगो ने हाल के वर्षो मे कृषि-जन्य वस्तुओ और सोने को छोडकर अपनी शेष कच्ची सामग्रियो का 10 प्रतिशत अन्य देशो से आयात किया है और यह अनुमान किया जाता है कि अगले बीस वर्षो मे विदेशी कच्चे माल पर यह निर्भरता बढती ही जाएगी। ऐसी कच्ची सामग्रियो की सूची बहुत बडी है, जिनकी सयुक्त राज्य मे होने वाली उपलब्धि का 50 प्रतिशत अन्य देशो से आयात करना पडता है। इस सूची मे से कुछ वस्तुएँ पृष्ठ 37 पर तालिका 3 मे दी गई है।

एक और प्राकृतिक सम्पदा, जो पहले सयुक्त राज्य मे प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध थी, अब चिन्ता का विषय बन गई है। इस समय सिंचाई और व्यक्तिगत एव औद्योगिक कामो के लिए पानी का जिस गति से उपयोग किया जा रहा है, उसे भविष्य मे सयुक्त राज्य की निरन्तर विस्तृत हो रही अर्थ-व्यवस्था मे तब तक कायम नही रखा जा सकेगा, जब तक कि उसके उत्पादन और अधिक उचित उपयोग के लिए बेहतर व्यवस्था न कर ली जाय। इसके लिए काफी बडी मात्रा मे धन लगाकर ऐसी व्यवस्थाएँ करनी पडेगी, जिनसे एक बार प्रयुक्त किये गए पानी को इकट्ठा कर और वैज्ञानिक प्रक्रियाओ से सुधार कर पुन प्रयोग के लायक बनाया जा सके। यही नही, पानी को दूर-दूर तक पहुँचाने का प्रबन्ध और भविष्य मे आगे चलकर समुद्र के खारी और नमकीन पानी को नमक-रहित करके उपयोग मे लाने की व्यवस्था की भी जरूरत होगी। पानी की उपलब्धि और समुचित उपयोग की समस्या पर सयुक्त राज्य मे अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखे तो अमेरिका के विविध और प्रचुर प्राकृतिक साधनो ने अतीत मे बहुत-से आव्रजको को अमेरिका के तट की ओर आकृष्ट किया है और इन प्राकृतिक साधन-सम्पदाओ ने अमेरिका के द्रुत आर्थिक विकास मे बहुत महत्त्वपूर्ण योग भी दिया है। सयुक्त

तालिका 3

संयुक्त राज्य में उपलब्ध कुछ कच्ची सामग्रियों का अन्य देशों से आयातित प्रतिशत भाग—1959

कच्ची सामग्री	प्रतिशत	कच्ची सामग्री	प्रतिशत
खाद्य पदार्थ		**लकड़ी और कागज़**	
केला	100	कच्चा कार्क	100
कहवा (कॉफी)	100	अखबारी कागज	73
चाय	100	**अलौह खनिज और धातुएँ**	
ट्यूना मछली	61	रांगा (टीन)	100
कच्चा रबड़, गोंद, बिरोजा		निकल	91
लाख और चपड़ा	100	बॉक्साइट और एल्युमीनियम	84
प्राकृतिक रबड़	100	सीसा	61
वानस्पतिक उत्पादन		जस्त	57
नारियल और नारियल का तेल	100	**अधात्वीय खनिज**	
क्वेब्रैको का सत	100	अभ्रक	95
वस्त्र-रेशा		ऐस्बैस्टस	94
जूट (पटसन)	100	फ्लोरस्पार	75
कच्चा रेशम	100	**लौह धातुएँ और खनिज**	
सीसल और मैनिला	100	क्रोम[1]	90
कच्ची ऊन	57	मैंगनीज खनिज	87
दीर्घ तन्तु रेशे की रुई	52	टंगस्टन	61

1. 1958 के आंकड़े

राज्य मे औद्योगिकीकरण का जो उफान आया उसने प्रकृति के इस अक्षय भण्डार का नई-नई वस्तुएँ तैयार करने और यहाँ के निवासियो का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिए उपयोग किया। लेकिन इन प्राकृतिक साधनो से सम्पन्न होने पर भी, अमेरिकी उद्योग अन्य देशो की तुलना मे अब अधिक अच्छी और लाभ की स्थितियो मे नही हैं, क्योकि कोयले को छोडकर शेप सब प्राकृतिक साधनो का भण्डार धीरे-धीरे क्षीण होता जा रहा है। जैसे-जैसे सारे ससार मे प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर ऊँचा होता जाएगा, वैसे-वैसे कच्चे माल की माँग भी बढती जाएगी। अगर यह आशा न हो कि कुछ दुर्लभ खनिज पदार्थो की कमी की पूर्ति उनके स्थान पर उपयोग के लिए नये पदार्थ खोजकर कर ली जाएगी तो कुछ महत्त्वपूर्ण औद्योगिक कच्ची सामग्रियो की भविष्य मे उपलब्धि की स्थिति वास्तव मे ही बहुत निराशापूर्ण हो जाएगी।

सारांश

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का उत्पदकता का स्तर ऊँचा होने का मुख्य कारण मौसम का अनुकूल होना, जमीन का असाधारण तौर पर उपजाऊ होना या खनिज और अन्य कृषि-भिन्न प्राकृतिक सम्पदाओ का प्राचुर्य नही है। प्राकृतिक साधनो का प्राचुर्य सहायता अवश्य करता है, किन्तु अकेला नही, अन्य कारक तत्त्वो के साथ मिलकर।

3

श्रम

जनता ही किसी राष्ट्र की सब से बडी आर्थिक सम्पत्ति होती है। प्राकृतिक साधन-सम्पदा के प्राचुर्य का अपने आप मे कोई अर्थ नही, जनता के साथ मिलकर ही उस का कुछ अर्थ होता है। किसी देश की उन्नति और विकास तभी अधिक सम्भव है, जबकि उस देश की जन-शक्ति और प्राकृतिक साधनो का परस्पर समन्वय और सतुलन के साथ विकास किया जाय।

सयुक्त राज्य इस लिहाज से भाग्यशाली है कि उसे प्रकृति ने अपनी बढती हुई जन-सख्या के पालन-पोषण के लिए साधन-सम्पदा प्रदान की है। औद्योगिक विकास ने जैसे-जैसे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध किये, वैसे-वैसे ससार के अन्य भागो से अधिकाधिक लोग इस नये देश मे अपने श्रम और कौशल अर्पित करने के लिए आने लगे। इस प्रकार एक ओर श्रमिक शक्ति की वृद्धि ने और दूसरी ओर प्राकृतिक साधन-सम्पदा और उद्योगो के विकास ने मिलकर सयुक्त राज्य मे प्रति व्यक्ति आय का ऊँचा स्तर स्थापित करने मे योगदान किया।

तालिका 4

आवादी की घनता और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय

देश	आवादी की घनता[1]	प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (अमेरिकी डालरों में)
सयुक्त राज्य अमेरिका[2]	48	2,722
कनाडा	5	1,983
स्विटजरलैंड	324	1,510
आस्ट्रेलिया	3	1,424
ब्रिटेन	547	1,272
फ्रास	209	1,146
पश्चिमी जर्मनी	543	1,140
नीदरलैंड्स	893	६98
इटली	417	578
दक्षिण अफ्रीका	30	412
क्यूबा	148	389
जापान	641	375
मैक्सिको	43	293
ब्राजील	20	210
टर्की	87	167
फिलिपाइन	209	166
श्रीलका	375	131
नाइजीरिया	96	79
भारत	314	74
बर्मा	77	53

1 प्रति वर्गमील आवादी (1959 में) ।

2 अलास्का और हवाई भी सम्मिलित है ।

का ऊँचा स्तर मुख्यत· उनकी अन्य देशों से आयातित कच्चे माल से तैयार माल बनाने की क्षमता का परिणाम है। और इस तैयार माल का बडा भाग उन्हे फिर अन्य देशो को निर्यात करना पडता है।

श्रमशक्ति की रचना

सयुक्त राज्य की जनसख्या इस समय 18 करोड 20 लाख है और हाल के वर्षो मे वह 1.8 प्रतिशत वार्षिक की रफ्तार से बढती रही है। सन् 1960 मे सयुक्त राज्य की सक्रिय असैनिक श्रम शक्ति (श्रम जीवियो की सख्या) 7 करोड 20 लाख थी, जिनमे से लगभग 4 करोड 70 लाख पुरुष और 2 करोड 50 लाख स्त्रियाँ थी। इस असैनिक मानव शक्ति का लगभग 25 प्रतिशत निर्माण उद्योगो मे, 20 प्रतिशत वितरण, थोक और खुदरा व्यापार मे, लगभग 10 प्रतिशत कृषि में, लगभग 15 प्रतिशत सरकारी सेवाओ मे और करीब 30 प्रतिशत खानो, भवन आदि के निर्माण और अन्य धन्धो मे लगा हुआ है।

यद्यपि श्रमजीवी वर्ग मे 16 वर्ष से लेकर 65 वर्ष से भी ऊपर की आयु तक के लोग है, फिर भी अधिक बडी सख्या 20 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लोगो की है। बाल-श्रम (बच्चो से मजदूरी कराना) की बुराई का सयुक्त राज्य मे एक प्रकार से खात्मा कर दिया गया है। यह केवल बाल-श्रम विरोधी कानूनो का ही परिणाम नही, बल्कि अधिकतर राज्यो मे इस आशय के नियम बनने का भी परिणाम है कि 15 या 16 वर्ष की आयु तक के बच्चो को नियमित रूप से स्कूल मे उपस्थित होना होगा। इस प्रकार 15 या 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे स्कूलो मे पढाई के दिनो मे केवल अश-कालिक श्रम कर सकते है। उनके लिए पूरे समय काम करना गर्मियो की छुट्टियो के दिनो मे ही सम्भव है। श्रमजीवियो की उम्र के पैमाने मे जो लोग सबसे ऊपर आते है, यानी बूढे हैं, उन्हे बुढापे की पेन्शन और व्यक्तिगत सुरक्षा की पहले से अधिक सुविधाएँ दी जाती हैं, जिनमे वृद्धावस्था की सहायता, पेन्शन योजनाएँ और प्राईवेट बीमा आदि शामिल हैं। इनका परिणाम

यह होता है कि बहुत-से श्रमजीवी अधिक उम्र हो जाने पर स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ अधिक उम्र के व्यक्ति, यह अनुभव करते हैं कि बुढापे मे सहायता देने की ये सब योजनाएँ उन्हे काम के अवसरो से वचित करती है, हालाकि उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा होता है कि वे काम करते रह सकें। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप आज आदमी मे पहले से अधिक लम्बी आयु तक अशकालिक (पार्ट टाइम) या पूर्णकालिक (फुल टाइम) काम करने की क्षमता आ गई है, फिर भी अमेरिका की श्रम सम्बन्धी व्यवस्थाओ मे उसके अनुरूप परिवर्तन नही किया गया है तथापि श्रमजीवी वर्ग मे स्त्रियो की, खासकर अधिक आयु की विवाहित स्त्रियो की, सख्या काफी बढ गई है।

अमेरिका के श्रमजीवी वर्ग की एक बडी विशेषता उसकी बहुजातीय विविधता है। प्रारम्भ मे अमेरिका की आबादी अन्य महाद्वीपो से यहाँ आकर बसे लोगो की थी। उसके बाद भी उसका एक खासा भाग बाहर से आकर बसे लोगो और उनके बीवी-बच्चो का रहा है। यद्यपि सन् 1920 के दशक से कानून बनाकर अमेरिका मे बाहर से बडे पैमाने पर आप्रवासियो के आगमन को रोक दिया गया है, फिर भी सन् 1950 की जन-गणना मे यह देखा गया कि सयुक्त राज्य की कुल गोरी आबादी की चौथाई सख्या बाहर से आकर बसे लोगो और इनके अमेरिका मे उत्पन्न बच्चो की थी। इसी तरह इस जन गणना मे सयुक्त राज्य की कुल गोरी श्रमिक सख्या का तिहाई ऐसे ही आप्रवासी लोगो का था (देखिए परिशिष्ट तालिका 9)। यद्यपि आबादी की यह बहुजातीय विविधता सयुक्त राज्य की ही विशिष्टता नही है, तथापि यहाँ के आर्थिक विकास मे उसका योग महत्त्वपूर्ण रहा है। भिन्न-भिन्न देशो और भिन्न-भिन्न सास्कृतिक पृष्ठभूमियो से आये आप्रवासी लोगो के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यताएँ और हुनर आये। यही नही, ये लोग एक नई दुनिया मे अपने लिए जगह बनाने का दृढ सकल्प भी ।कर आये।

अमेरिकी श्रम शक्ति की एक और विशेषता भी है जो उसकी

उत्पादकता को वहुत वढाती है। यह विशेषता है सयुक्त राज्य का भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तृत होना और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के एक विशाल भाग मे फैला होना। यदि एक व्यक्ति न्यूयार्क से सानफ्रासिस्को तक यात्रा करे तो 2,500 मील का लम्बा सफर करने पर भी उसे कही सयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सीमा को लाघना नही पड़ेगा। लेकिन अगर यूरोप मे उसे लिस्वन से मास्को तक इतना ही लम्बा सफर करना पड़े तो उसे सात राष्ट्रो की सीमाओ को पार करना होगा, आठ तरह की मुद्राओ का उपयोग करना पड़ेगा। आज के जमाने मे उसे एक 'लौह-आवरण' को भी भेदना पडेगा।

महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक संयुक्त राज्य के वसे होने का परिणाम यह है कि उसके निवासी और श्रमजीवी वे-रोक टोक इधर से उधर आ-जा सकते है, जब कि यूरोप मे यह वात इतनी आसान नही रही। इसका एक और लाभ यह हुआ कि जैसे-जैसे आवादी की वृद्धि और अर्थ-व्यवस्था का विकास हुआ, वैसे-वैसे लोगो को फैलने के लिए नये-नये इलाके मिलते रहे। यूरोप मे पिछले दस वर्षो मे विभिन्न देशो की आवादियो के घटने-वढने का मुख्य कारण पूर्वी यूरोपीय देशो की आवादियो मे हुई स्वाभाविक वृद्धि और उनका एक देश से दूसरे देश मे जाना था, जवकि सयुक्त राज्य के विभिन्न घटक राज्यो मे आवादियो के घटने-वढने का कारण देश के भीतर ही लोगो का एक राज्य से दूसरे राज्यो मे आना-जाना था।

कर अधिक उत्पादकता वाले और अधिक मजदूरी वाले कामों में जाने की सर्वदा प्रेरणा दी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका में उत्पादकता का स्तर इतनी तेज़ी से ऊँचा कैसे हो गया जबकि अन्य

चार्ट 9

संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी
क्षेत्रवार विभाजन 1880 और 1960
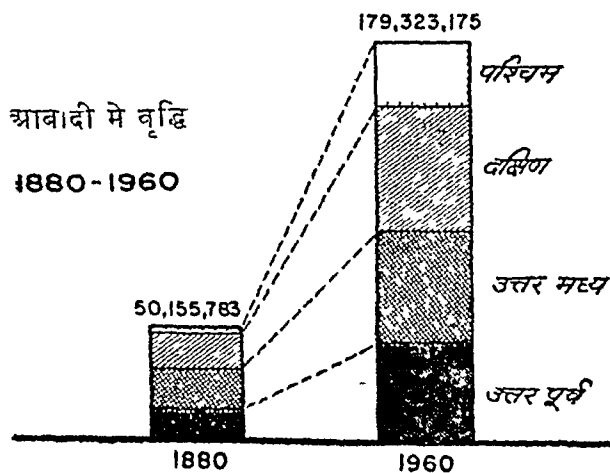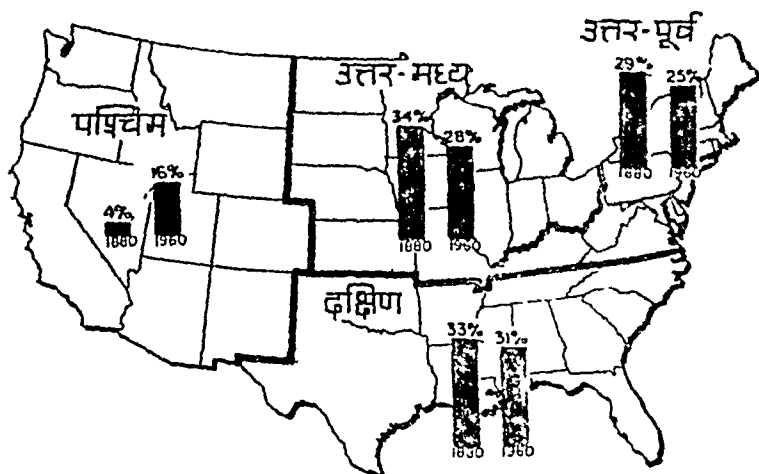
देशो मे, उत्पादन के औद्योगिक तरीके वैसे ही होने पर भी वह उतना ऊँचा नही हुआ।

अमेरिका और कुछ अन्य देशो के श्रमिको की उत्पादकता मे जो अन्तर है उसका कारण यह नही है कि उनके श्रमिको को योग्यताओ मे अन्तर है। हर देश की अपनी कुछ अलग ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है जिनसे उनके श्रमिको की क्षमताओ, कौशलो और हुनरो मे फर्क होता है। उदाहरण के लिए स्कैण्डिनेवियायी देशो की भाति समुद्र तटवर्ती देशो के लोग बहुत अच्छे नाविक और मछुवे होते है, क्योकि एक तो वे समुद्रतट के नजदीक रहते है और दूसरे आबादी बढने पर स्थल पर जीवन के जिन साधनो की उन्हे पर्याप्त उपलब्धि नही हो सकती, उन्हे प्राप्त करने के लिए उन्हे सागर मे जाना पडता है। इसी तरह यूक्रेन के किसान के लिए गेहूँ की फसल पैदा करना उतना ही स्वाभाविक है, जितना, कि कन्सास के किसान के लिए क्योकि दोनो प्रदेशो की समतल भूमि और महाद्वीपीय जलवायु गेहूँ पैदा करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है।

अमेरिकी श्रमजीवियों का स्वास्थ्य और प्रशिक्षण

परिपक्व श्रमजीवी को शारीरिक दृष्टि से सबल और स्वस्थ बनाये रखने के लिए सभवत सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उसे अच्छी खुराक मिले, रहन-सहन की अच्छी परिस्थितियाँ मिले और बचपन तथा जवानी मे उसे काफी ताजा हवा और मनोरजन के साधन उपलब्ध होते रहे हो। हाल के दशको मे अधिक अच्छी और पोपक खुराक विकसित करने और सभी आयु-वर्गो के अमेरिकी श्रमिको को अधिक स्वस्थ जीवन-परिस्थितियाँ और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा मे काफी प्रगति हुई है। इससे श्रमिको की शारीरिक शक्ति और काम करने की सामर्थ्य मे वृद्धि हुई है और परिणामत उससे उनकी उत्पादकता (उपादन सामर्थ्य) बढी है।

लेकिन इस का अर्थ यह नही समझा जाना चाहिए कि अमेरिकी

लोगो की स्वास्थ्य की स्थिति मे अब और किसी सुधार की ज़रूरत या गुजायश नही है। यह अनुमान लगाया है कि लगभग 2 प्रतिशत मानव घटे ऐसी अस्थायी दुर्घटनाओ या बीमारियो के कारण, जिनका श्रमिक के व्यवसाथ से कोई सम्बन्ध नही हैं, बरबाद हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओ, देख-भाल और अनुसधान को जारी रखने की अभी आवश्यकता है। स्वास्थ्य के जिस अग की ओर हाल के वर्षो मे अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, यद्यपि वह भी पर्याप्त नही है, वह है मानसिक स्वास्थ्य—यानी यह समस्या कि किस प्रकार लोगो के शरीर के साथ-साथ उनके मन को भी स्वस्थ रखा जाय। द्वितीय विश्व-युद्ध मे सयुक्त राज्य मे सेना ने 25 प्रतिशत से भी अधिक उम्मीदवारो को सेना मे लेने से इसलिए इन्कार कर दिया कि उनमे सैनिक सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम शारीरिक योग्यता का अभाव था। इसके अलावा 5 प्रतिशत अन्य उम्मीदवार शिक्षा या मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी योग्यताओ की कमी के कारण अस्वीकृत कर दिये गए। अकेली ये दोनो बाते ही यह साबित करने के लिए काफी है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओ मे सुधार की अभी बहुत आवश्यकता है।

जैसे-जैसे कारखानो और दफ्तरो मे नयी-नयी आधुनिक औद्योगिक विधियाँ अपनायी जाने लगेगी, वैसे-वैसे औसत कर्मचारियो की प्रतिभा, शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तर को ऊँचा उठाने की जरूरत भी बढती जाएगी। यह बात शायद सही है कि यूरोप का श्रमजीवी विशिष्ट परम्परागत शिल्पो की दक्षता और हुनर मे और अमेरिकी श्रमजीवी सामान्य दक्षता और सूझ-बूझ मे आगे बढा हुआ है। इस प्रकार अमेरिकी श्रमिक आधुनिक स्वचालित मशीनो के काम को झटपट आसानी से सीख लेता है, किन्तु इस समय ऐसे अमेरिकी कर्मचारियो की सख्या बहुत कम है जिन्हे सूक्ष्म काम वाले उद्योगो का प्रशिक्षण और दक्षता हो।

'सयुक्त राज्य मे हर व्यक्ति के लिए, न केवल प्राथमिक स्कूलो मे

चार्ट 10

प्रति डाक्टर देशवासियों की संख्या—1957

स रा अमेरिका	United States	800
आस्ट्रिया	Ausfria	610
पश्चिमी जर्मनी	West Germany	730
न्यूजीलैण्ड	New Zealand	750
कनाडा	Canaaa	950
ब्रिटेन	United Kingdom	1030
स्वीडन	Sweden	1180
मिस्र	Egypt	2900
बोलीविया	Bolivia	4000
भारत	India	5100
पाकिस्तान	Pakistan	15,400
नाइजीरिया	Nigeria	40,000
इंडोनेसिया	Indonesia	102,000
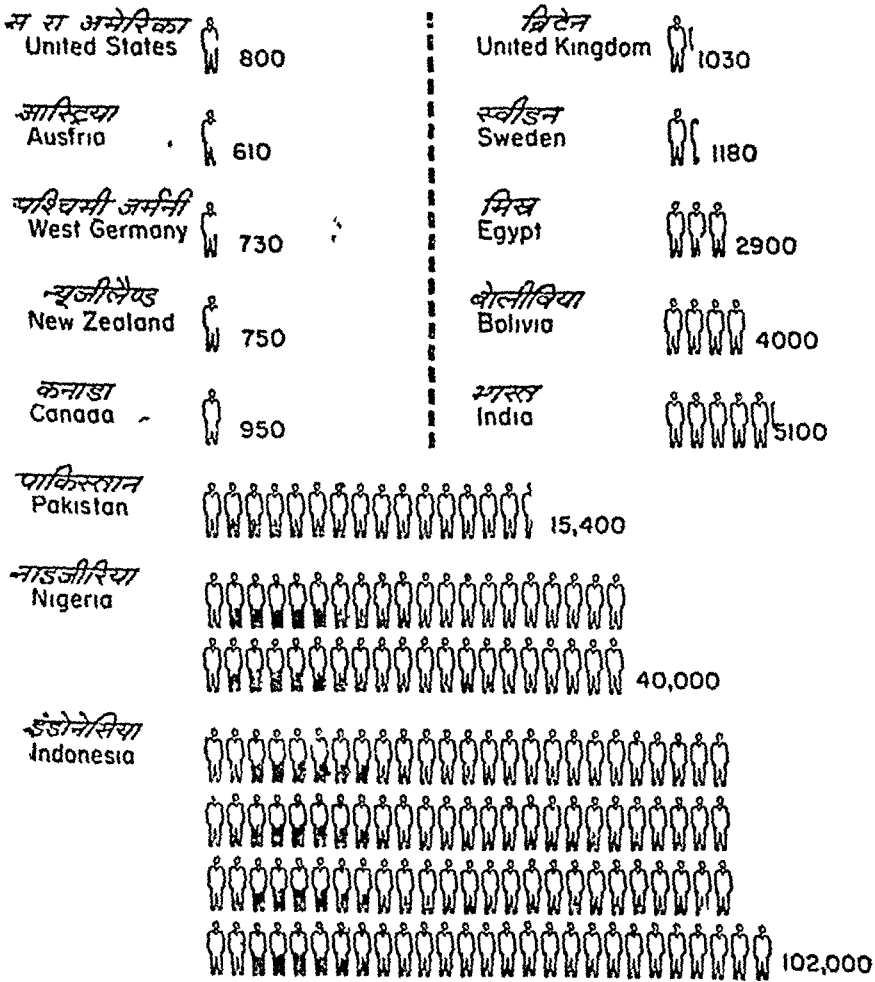
= 1000 निवासी

बल्कि माध्यमिक स्कूलो मे भी नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है और अनेक शहरो मे कालेज और विश्वविद्यालय स्तर तक भी नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। सयुक्त राज्य के स्कूलो मे भर्त्ती की अधिक प्रतिशतता से माध्यमिक और उच्च माध्ममिक स्कूलो की शिक्षा की अद्वितीयता के

बारे मे पता चलता है तथा बच्चो की स्कूल आयु से ही कालेजो और स्कूलो की बढती हुई विशाल सख्या का पता चलता है। सन् 1960 मे सयुक्त राज्य के कुल असैनिक श्रमिको मे से आधे ऐसे थे जिन्होने कम से कम चार साल की हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली थी। सन् 1940 और 1960 के बीच ऐसे श्रमिको की सख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई जो कम से कम चार वर्ष की कालेज की शिक्षा पूरी कर चुके थे। फिर भी इस समय सयुक्त राज्य मे शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ इतनी नही हैं कि छात्रो की बढती हुई सख्या को प्रभावकारी ढग से शिक्षा दे सके और आधुनिक औद्योगिक विधियो के प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी कर सके। सयुक्त राज्य ने अपनी इस कमी को अनुभव किया है और वह उसे पूरा करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर रहा है। अन्य अनेक उद्योग सम्पन्न अथवा कम विकसित देश भी अपनी शिक्षा-पद्धतियो और शिक्षा के स्तर को आज के युग की आवश्यकताओ के अनुरूप ढालने के लिए दृढ सकल्प के साथ अग्रसर हो रहे हैं।

किन्तु शिक्षा की स्थति के सम्बन्ध मे विभिन्न देशो से प्राप्त आकडे अपने आप मे इस बात का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए काफी नही है कि उनके श्रमिको की प्राप्त प्रशिक्षण की स्थिति क्या है (देखिये परिशिष्ट तालिका 10)। उदाहरण के लिए यूरोप के अनेक भागो मे ऐसे लोगो की विधिवत् शिक्षा, जिन्हे बाद मे श्रमिक बनना होता है 14 या 15 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है अर्थात् वे केवल आठ या नौ वर्ष तक ही स्कूल मे पढ पाते हैं। वहाँ अनेक बच्चो को प्राथमिक (प्राइमरी) शिक्षा समाप्त करके ही किसी रोजगार मे लग जाना पडता है, क्योकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नही होती और वे माध्यमिक स्कूल की फीस नही चुका सकते। किन्तु फिर भी बहुत-से देशो मे, जहाँ बच्चो को प्राथमिक शिक्षा के दौरान मे पर्याप्त तकनीकी शिक्षा नही मिल पाती, उन्हे प्रशिक्षु (एप्रेण्टिस) के रूप मे रखकर काम सिखाने की और व्यावसायिक प्रशिक्षिण के लिए अलग कक्षाएँ चलाने की व्यापक व्यवस्था की जाती है, ताकि अधिक उत्पादक श्रम-शक्ति

तयार की जा सके ।

उदाहरण के लिए जर्मनी मे परिपक्व प्रशिक्षुओ (एप्रेन्टिसी) को अधिक उन्नत प्रशिक्षण और तालीम देने के लिए तकनीकी सस्थाएँ (फाखशुलेन) खोली जाती है । इग्लैण्ड मे जूनियर तकनीकी स्कूल तरुण श्रमिको को खास-खास उद्योगो और व्यवसायो के लिए तैयार करते है। सोवियत सघ मे विशिष्ट प्रशिक्षण के स्कूल (तेकनिकम) खोले गए हैं जो सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के लिए चार-वर्षीय पाठ्यक्रम चलाते है। ये स्कूल आम सार्वजनिक स्कूलो मे दी जाने वाली न्यूनतम शिक्षा से आगे की शिक्षा देते है और साथ ही सैद्धान्तिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते है। यूरोप मे व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूलो और प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रमो का मुख्य प्रयोजन आधुनिक कारखानो की जटिल मशीनो के कौशलपूर्ण सचालन और रख-रखाव के लिए आवश्यक दक्ष श्रमिको और अर्ध-पेशेवर टैकनीशियनो को तैयार करना होता है। सयुक्त राज्य मे ऐसे स्कूलो की सख्या अपेक्षाकृत कम है ।

सयुक्त राज्य मे इस तरह का तकनीकी प्रशिक्षण स्कूलो मे देने के बजाय कारखानो मे ही देने की पद्धति का सहारा अधिक लिया जाता है। अनेक कारखानो और औद्योगिक संस्थानो ने ऐसे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये है जिनके द्वारा वे अपने यहाँ नये आधुनिक ढग के काम सभालने के लिए कर्मचारियो को प्रशिक्षित कर तैयार करते है। ये कार्यक्रम अतिरिक्त अध्ययन कार्यक्रम नही समझे जाते, बल्कि कर्मचारी को अपने काम की शिक्षा देने के कार्यक्रम के ही अविछिन्न अग समझे जाते है। कारखाने मे काम करते-करते प्रशिक्षा देने के इन कार्यक्रमो का मुख्य प्रयोजन 'तेकनिकमो' और 'फाखशुलेन' की तरह अर्ध-

कार कर्मचारियो की माँग बढने से यह सभव है कि यहाँ ऐसी तकनीकी शिक्षा पर अधिकाधिक जोर दिया जाने लगे जो पूरे इजीनियरो के पाठ्य-क्रम के स्तर पर न पहुँचने पर भी आज के व्यावसायिक प्रशिक्षण से ऊँचे दर्जे की हो।

इस प्रकार, यह सम्भव है कि अमेरिका का श्रमिक वर्ग अन्य अनेक देशो के श्रमिको की तुलना मे अधिक स्वस्थ और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो भी यह नही कहा जा सकता कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता एव अधिक अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण ही अन्य देशो के श्रमिको की तुलना मे उनकी अधिक उत्पादकता का एकमात्र कारण हैं। उत्पादकता के इस अन्तर के और भी महत्त्वपूर्ण कारण है।

श्रमिको का रवैया

सयुक्त राज्य मे श्रमिको की कोई ऐसी विशिष्ट अभिवृत्ति नही है जिसे समग्र रूप से अमेरिकी श्रमिको का रवैया कहा जा सके। इसके विपरीत यहाँ श्रमिको के विभिन्न वर्गो के अलग-अलग रवैये है। जो श्रमिक हाल मे अन्य देशो से आकर अमेरिका मे वसे है, उनके और अमेरिका मे ही उत्पन्न श्रमिको के विचारो और मतो मे अन्तर है, अलग-अलग क्षेत्रो के श्रमिक विचारो मे एक-दूसरे से अलग-अलग है, और गोरे तथा काले श्रमिको मे भी विचार-भेद है। इसी प्रकार के और भी अन्तर है। फिर भी अमेरिकी श्रमिको के भिन्न-भिन्न प्रकार के रवैयो मे कुछ सामान्य लक्षण पाये जा सकते है। ये सामान्य लक्षण अधिकतर ट्रेड यूनियनो (श्रमिक सघो) के उद्देश्य और कार्यो के सम्बन्ध मे उनके विचारो मे पाये जाते हैं।

सयुक्त राज्य के 7 करोड 20 लाख श्रमजीवी-वर्ग मे से सिर्फ 1 करोड 80 लाख के लगभग यूनियनो के सदस्य है। किन्तु निर्माण-उद्योगो मे यूनियनो के सदस्यो की सख्या उनके कुल श्रमिको की आधी के लगभग होती है। एक आम अमेरिकी ट्रेड यूनियन एक ऐसा सगठन है जिसका उद्देश्य श्रमिको को अच्छे वेतन और अच्छे काम की

परिस्थितियाँ दिलाना होता है। यह एक सर्वथा स्वतन्त्र सगठन है, जिसकी स्थापना या नियन्त्रण मे सरकार या मालिकों का कोई हाथ नही होता।

अन्य देशो मे, खासकर मध्य यूरोप के देशो मे, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो ट्रेड यूनियनो का विकास श्रमिक आन्दोलन का केवल एक भाग ही रहा है—राजनीतिक दल, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ और सास्कृतिक एव खेल सगठन उसके अन्य अग थे। इन देशो मे श्रमिक आन्दोलन के इतना व्यापक होने का कारण यह था कि इन देशो के श्रमिको का, बल्कि दूसरो का भी, यह खयाल था कि वे एक सर्वथा अलग वर्ग है और बाकी समाज, यानी उच्च वर्ग, समाज के वरदानो मे उन्हे हिस्सा नही देता, और इसीलिए उन्हे अपने लिए एक अलग सास्कृतिक और आर्थिक जीवन का विकास करना चाहिए।

इसके विपरीत अमेरिकी श्रमिक अपने आप को एक पृथक् वर्ग या राष्ट्र के शेष वर्गो से अलग नही समझता। वह सिर्फ यह मानता है कि श्रमजीवी होने के नाते उसके कुछ विशिष्ट आर्थिक हित है और उन्हे वह एक शक्तिशाली श्रमिक सगठन के जरिये सक्रिय रूप से पूरा करना चाहता है। लेकिन इन अव्यवहित और विशिष्ट उद्देश्यो को छोड़ दिया जाय, तो अन्य अमेरिकी नागरिको की भाति वह भी अपने लिए चाहे जिस राजनीतिक दल, चर्च या अन्य सगठन को चुन सकता है। इस चुनाव मे उसके व्यवसाय या उसकी आर्थिक स्थिति से किसी भी तरह की बाधा नही आती। सयुक्त राज्य मे लोगो के सामाजिक सम्बन्धो का आधार बहुत कुछ यह होता है कि कोई व्यक्ति मूलत किस राष्ट्र से या किस प्रकार की संस्कृति से वहाँ आया है, वह किस धर्म मे आस्था रखता है अथवा किस प्रदेश और किस इलाके का वह रहने वाला है। इसका आधार यह उतना नही होता कि उत्पादन की प्रक्रिया मे उसकी क्या स्थिति है।

यद्यपि अमेरिकी मजदूर श्रमिक आन्दोलन को जीवन की सर्व-समावेशी पद्धति नही मानता तो भी वह यह जरूर चाहता है कि उसकी ट्रेड

यूनियन उसके आर्थिक हितो के लिए जबर्दस्त सघर्ष करे। सन् 1930 के दशक के वाद से यूनियनो की सदस्य सख्या मे असाधारण वृद्धि हुई है और यूनियनो ने श्रमिको को अधिक वेतन, काम के घटो मे कमी और इसी प्रकार के और अनेक लाभ प्रदान कराये है। यद्यपि औसत अमेरिकी श्रमिक को जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन से कही अधिक वेतन मिलता है तो भी वह भविष्य मे अधिकाधिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। जव उसे अवसर मिलता है तो वह काम के घटो के वाद भी अतिरिक्त काम करता है, क्योकि इस अतिरिक्त काम के लिए उसे नियमित काम के घटो की अपेक्षा ड्योढी मजदूरी मिलती है। कुछ उद्योगो मे, जहाँ कि काम के साप्ताहिक घटे घटाकर कुल 35 कर दिये गए है, श्रमिक अपना नियमित काम करने के वाद फालतू समय मे दूसरी जगह अश-कालिक काम ले लेते है, हालाकि उन्हे उक्त उद्योगो के नियमित काम से ही काफी आमदनी हो जाती है।

सयुक्त राज्य मे भी, अन्य सभी देशो की भाति, जहाँ कि श्रमिको को अपने अभ्युदय के लिए प्रयत्न करने की स्वतन्त्रता है, मजदूरो और मालिको मे झगडे होते रहते है। पिछले दो दशको मे श्रम-सम्वन्धो मे सुधार होने के कारण, सामूहिक सौदेवाजी और पच-निर्णय से अनेक विवादो का निबटारा होता रहा है। इसका यह अर्थ नही है कि इन वर्षों मे हडताले हुई ही नही है, लेकिन यह जरूर सही है कि जो हडताले हुई, उनमे श्रमिक आन्दोलन के प्रारम्भिक युग की भॉति कटुता और हिसा नही थी। सन् 1956 से 1960 तक की अवधि मे मजदूर-मालिक विवादो के कारण काम बन्द होने से कुल मानव-दिनो मे से औसतन एक प्रतिशत का भी तिहाई भाग ही नष्ट हुआ। सयुक्त राज्य मे यह स्थिति अन्य देशो की, जहाँ मजदूरो को हडताल करने का अधिकार है, स्थिति से भिन्न नही है (देखिये परिशिष्ट तालिका 11)।

अमेरिकी श्रमिक यह समझते है कि श्रम के ठेके मे मालिक दूसरा पक्ष है, इसलिए वे उनसे अच्छी से अच्छी शर्तें अपने लिए प्राप्त करने का प्रयत्न करते है। लेकिन साथ ही वे यह भी महसूस करते है कि यूनि-

यादी तौर पर मालिको के और उनके हित एक ही है और जिस उद्योग या व्यवसाय मे वे काम करते है वह उन्हे ऊँचे वेतन और अन्य लाभ तभी दे सकता है, जबकि वह खूब फले-फूले और उन्नति करे। उनके इस रवैये के महत्त्व को दृष्टि मे रखकर प्रबन्धक लोग श्रमिको के लिए काम की अच्छी परिस्थितियाँ बनाए रखने के लिए काफी पैसा खर्च करते और मेहनत करते है। श्रमिको के लिए काम की अच्छी शारीरिक और मानसिक परिस्थितियाँ पैदा कर बहुत-से उद्योगो ने प्रति व्यक्ति उत्पादन बढा लिया है और ऐसे उद्योगो की सख्या अब बराबर बढ रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक कारखानो मे श्रमिको ने यह भावना विकसित कर ली है कि बढिया किस्म की चीज तैयार करना उनके लिए शिल्पिक गर्व की वस्तु है और अनेक मामलो मे उन्होने प्रबन्ध के सुधार मे भी सक्रिय और रचनात्मक दिलचस्पी ली है। राष्ट्रीय आयोजन सघ (नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन) ने कई मामलो का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट मे यह निष्कर्ष प्रकट किया है कि श्रमिक और मालिक, दोनो की ओर से पारस्परिक हित और सहयोग का रुख अपनाये जाने से न सिर्फ बहुत-से विवादो को सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा हल करने मे मदद मिली है, बल्कि उससे श्रमिको को उत्पादन के कामों मे सुधार के लिए अधिक दिलचस्पी लेने का प्रोत्साहन मिलने से उनकी उत्पादकता भी बढी है।

है जिससे कुछ उद्योगो मे श्रमिको की सख्या तो बढ जाती है, परन्तु उत्पादन मे उसके अनुरूप वृद्धि नही होती। जिस जमानेमे बेरोजगारी बडे पैमाने पर रही है, खासकर सन् 1930 के दशक मे, भवन-निर्माण, परिवहन और मनोरजन सम्बन्धी उद्योगो मे इस प्रकार का श्रम का अपव्यय बहुत हुआ है। किन्तु पिछले दशक मे, जबकि रोजगार का स्तर बहुत ऊँचा रहा है, इस प्रकार की अपव्ययकारी प्रवृत्तियाँ बहुत घटी हैं, हालाकि उनका पूरी तरह अन्त नही हुआ है।

सब मिलाकर अमेरिकी श्रमिको ने अब यह अनुभव कर लिया है कि उत्पादकता मे वृद्धि केवल वास्तविक वेतन मे वृद्धि के लिए ही जरूरी नही है, बल्कि वह आर्थिक अभिवृद्धि को जारी रखने के लिए भी आवश्यक है। फिर भी यूनियनो के नेताओ ने इस बात पर निरन्तर बल दिया है कि प्रबन्धको की और सरकार की नीतियाँ ऐसी होनी चाहिएँ जिनसे नई तकनीकी विधियो के फलस्वरूप श्रमिको को रोज़गार बदलने मे कठिनाइयाँ न हो और सब लोगो को पूरा रोजगार मिल सके। उनका यह बल देना उचित भी है। अन्य देशो के जिन श्रमिक नेताओ ने अमेरिका मे आकर स्थिति का अध्ययन किया है, आधुनिक और नवीनतम तकनीकी विधियो के प्रति, जिनमे स्वचालित यन्त्रो का उपयोग भी शामिल है, अमेरिकी श्रमिको के इस रुख को देखकर आश्चर्य प्रकट किया है।

साराश

सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी श्रमिको की उत्पादकता मे वृद्धि का कारण सिर्फ ऐसी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ ही नही है जो उनकी विविधता और सफलता को प्रभावित करती है। वह श्रमिको की शारीरिक श्रम करने की सामर्थ्य, उनकी तालीम और प्रशिक्षण एव काम, आराम और नई औद्योगिक विधियो के प्रति उनके रवैये पर भी निर्भर है। अमेरिका श्रमिको का यह रवैया अमेरिकी उद्योगो मे प्रति मानव-घटा उत्पादन मे वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। किंतु इसके महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद, विभिन्न देशो मे श्रमिको की उत्पादकता की जो विभिन्नता पाई जाती है, उसकी व्याख्या के लिए केवल यही पर्याप्त नही है।

4

व्यावसायिक प्रबन्ध

पिछले पचास वर्षो मे अमेरिकी आर्थिक जीवन के किसी भी अन्य पहलू मे उतने बुनियादी परिवर्त्तन नही हुए जितने कि व्यावसायिक प्रबन्ध के कार्य और स्वरूप मे हुए हैं। ये परिवर्त्तन नि सन्देह अमेरिकी उत्पादकता मे तीव्र वृद्धि का एक बडा कारण हैं। यह शायद बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सोवियत रूस के नेताओ ने अनेक बार इस बात पर जोर दिया है कि साम्यवादी देश सयुक्त राज्य अमेरिका मे उत्पादन के प्रबन्ध की विधियो से बहुत कुछ सीख सकते है। किन्तु साथ ही वे मार्क्सवादियो का यह सिद्धान्त हमेशा दोहराते रहे हैं कि उत्पादन के 'अराजकतापूर्ण' सगठन मे एक के बाद एक सकट पैदा होते रहेगे और अन्तत. एक दिन उनसे पूंजीवादी प्रणाली का अन्त हो जाएगा।

साम्राज्य खड़े किये। ये लोग 'कठोर व्यक्तिवादी' थे और अक्सर प्रति-स्पर्धात्मक सघर्ष मे पूरे जोर से उतरते थे। इन लोगो ने विशाल सम्पदाओ का सग्रह किया, अक्सर एकाधिकार वाले (मोनोपलिस्टिक) तरीके अपनाये और जनता की आलोचना के लक्ष्य वने। यह आलोचना खास तौर से उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम और वीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक दशको मे खूब जोर-शोर से हुई, क्योकि उन दिनो इन तथा-कथित 'लुटेरे सामन्तो' के पास सम्पत्ति और ऐश्वर्य के ढेर लग गए थे और वे खूब शान और ठाठ से खर्च करते थे, जवकि किसान कृषि-जिन्सो की कम कीमतो के कारण, और अन्य देशो से आकर बसे मजदूर कम मजदूरी और काम की खराब और असुरक्षित परिस्थितियो के कारण, अत्यधिक सकटग्रस्त थे। इन विशाल औद्योगिक साम्राज्यो की सार्वजनिक आलोचना का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने अनेक कम्पनियो को मिलाकर वनाये गए वडे-वडे ट्रस्टो पर रोक लगाने के कानून और अन्य नियामक उपाय अपनाये। यद्यपि इन कानूनो ने अनेक आपत्तिजनक हरकतो पर रोक लगा दी किन्तु इन औद्योगिक और वित्तीय उद्यमो के निर्माण से अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के विकास मे जो योग मिला था उसमे कोई रुकावट नही पडी। इनमे से वहुत-से लोगो की दूर तक कल्पना करने की प्रतिभा और उत्कृष्ट आत्म लाभ की भावना सृजनात्मक और विनाशात्मक, दोनो प्रकार की थी। उन्होने छोटे-छोटे किसानो, अभिजात वर्ग के वागान मालिको और छोटे पैमाने पर काम करने वाले दस्तकारो के राष्ट्र को एक महान् और समृद्ध औद्योगिक ताकत मे परिनत कर दिया जिसका विस्तार महाद्वीप-व्यापी था और महत्त्व विश्वव्यापी।

यह एक विचित्र वात है कि आधुनिक व्यावसायिक प्रबन्ध पर चर्चा और विचार करते हुए कुछ लोग एक तरह से यह स्वीकार करके चलते है कि हमारा अब भी उन्नीसवी शताब्दी के उन लुटेरे सामन्तो से साबिका पड रहा है। मौजूदा अमेरिकी आर्थिक प्रणाली के आलोचक मार्क्सवादी ही नही, दूसरे लोग भी इसी प्रकार की बाते लिखते और कहते है। यही गलती अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के कुछ प्रशसक भी करते है, हालाकि

उसका कारण बिलकुल उलटा होता है। वे इन पुराने कठोर व्यक्तिवादियों की, जो अब लुप्त हो गए है और जिनके वर्त्तमान उत्तराधिकारी प्रबन्धकों ने सगठनात्मक अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व और जन-मत की चिन्ता करने के मामले मे सर्वथा भिन्न किस्म के पैमाने अपनाये हैं, स्वकेन्द्रित उपक्रमी प्रवृत्ति और उद्यमशीलता की सराहना करते है, जैसे कि वे अब भी हमारे बीच विद्यमान हो।

छोटे और बड़े व्यवसायों की विशेषताएँ

आज के अमेरिकी आर्थिक क्षेत्र के दृश्य पर एक सरसरी नजर डालने से भी आदमी के मन पर यही छाप पडेगी कि यहाँ उत्पादन और वितरण मुख्यत बडी-बडी व्यावसायिक कम्पनियो के हाथ मे है। किन्तु अधिक सावधानी से विचार करने पर यह मालूम होगा कि बडी कम्पनियो का महत्त्वपूर्ण स्थान अवश्य है, किन्तु उनका प्राधान्य नही है। जून, 1959 को समाप्त कर-वर्ष मे सयुक्त राज्य मे लगभग दस लाख सक्रिय कम्पनियाँ थी, जिन्होने आय-कर के लिए अपनी आमदनी के हिसाब दाखिल किये। इनमे से करीब 2200 कम्पनियाँ ऐसी थी जिनकी परिसम्पत्तियाँ (ऐसेट) पाँच करोड डालर से अधिक की थी। इन 2200 वृहत्तर कम्पनियो की परिसम्पत्तियाँ और शुद्ध आय, दोनो समस्त अमेरिकी व्यावसायिक कम्पनियो की कुल परिसम्पति और शुद्ध आय का 62 प्रतिशत थी, लेकिन समस्त अमेरिकी कम्पनियो की कुल वार्षिक बिक्री मे इन कम्पनियो का हिस्सा 40 प्रतिशत ही था। इन आँकडो से जहाँ यह पता लगता है कि इन 2200 विशाल कम्पनियो का स्थान महत्त्वपूर्ण है, वहाँ यह भी मालूम होता है कि अमेरिका मे ऐसी कम्पनियों की सख्या भी बहुत बडी है जिनकी गिनती विशाल कम्पनियो मे नही की जा सकती।

अमेरिका एक ऐसे समाज का स्वप्न देख रहा है, जिसमे कोई भी साहसी और सूझ-बूझ वाला व्यक्ति, जिसमे प्रतिभा भी हो और हिम्मत भी, व्यवसाय स्थापित कर सके और स्वय अपना मालिक बन सके।

तालिका न० 5

1958-59 के कर-वर्ष मे विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों की कम्पनियो द्वारा दिये गए कम्पनी आय-कर के विवरण

विवरणो की सख्या हजारो मे		कुल परिसम्पत्तियाँ %	%	कुल प्राप्तियाँ %	शुद्ध आय %
10 लाख डालर से कम परिसम्पत्ति वाली कम्पनियाँ	867 0	87 6	10 7	28 8	9 8
10 लाख से 5 करोड डालर तक की परिसम्पत्ति वाली कम्पनियाँ	58 4	5 9	27 3	30 2	27 8
5 करोड या अधिक परिसम्पत्ति वालो कम्पनियाँ	2 2	2	62 0	40 0	61 9
योग	927 6	93 7	100 0	99 0	99 6
जिन कम्पनियो की परिसम्पत्ति 0 थी या बताई नही गई	62 7	6 3	—	1 0	4
कुल योग	990 3	100 0	100 0	100 0	100 0

आज किसी के लिए भी यह सम्भव नही है कि वह अकेला इस्पात सयत्र, मोटर कारखाना या तेल-शोधक कारखाना खडा करने के लिए आवश्यक साधन जुटा सके। किन्तु उद्योग, व्यापार और सेवाओ की दूसरी ।ख .। मे छोटे या मध्यम व्यवसाय स्थापित करने के लिए काफी

अवसर है। यद्यपि आँकडो से यह निष्कर्ष पूरी तरह नही निकलता तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि हाल के कुछ दशको मे छोटे व्यावसायिक उद्यमो की सख्या मे कोई विशेष कमी नही हुई है।

किन्तु लाभ सम्बन्धी आँकडो को देखने से यह ज्ञात होता है कि आर्थिक उतार-चढावो का असर बहुत बडी कम्पनियो के बजाय छोटी कम्पनियो पर अधिक पड़ता है और निवेश की गई पूँजी या शेयरो की सख्या की दृष्टि से औसतन छोटी कम्पनियो की लाभ की दर बडी कम्पनियो की लाभ की दर की अपेक्षा कम होती है। लाभदर कम होने का कम से कम एक आशिक कारण यह अवश्य है कि इन छोटी कम्पनियो के मालिक अक्सर अपने शेयरो के लाभाश (डिविडेड) के रूप मे जो लाभ लेते है, उससे भी अधिक बडा लाभ प्रबन्धक की हैसियत से अपने या अपने परिवार के लोगो के लिए ले लेते है।

इस बात पर काफी विवाद रहा है कि बडे व्यवसायो का काम अधिक कुशलता और दक्षता से चलता है या छोटे व्यवसायो का। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है कि बडी कम्पनियाँ आवश्यक वित्त की व्यवस्था अधिक आसानी से कर सकती है और उनमे अनुसन्धान और विकास कार्यों एव विज्ञापन के लिए खर्च करने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि इन कम्पनियो का कारोबार बहुत विशाल और फैला हुआ होने के कारण उनमे दफ्तरी नौकरशाही बहुत चलती है और लचीलापन

करने की आवश्यकता है।

पिछले कुछ वर्षों मे छोटे और मध्यम व्यवसायो की कठिनाइयो को देखने से इस कथन की निश्चय ही पुष्टि होती है कि वे अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, खासकर उधार-प्राप्ति की कठिनाई के समयो मे, धन प्राप्त करने मे वडी कठिनाइयो की अपेक्षा अधिक मुश्किल अनुभव करते है। स्वभावत ही उधार देने वाले सस्थान, खासकर बैंक, वडे उधार लेने वालो को, जो बहुत समय से उनसे उधार लेते रहे हे और जिनके पास काफी वडी परिसम्पत्तियाँ है, उधार देते समय प्राथमिकता देते है। किन्तु इस बात को छोड दे तो भी छोटे व्यवसायो की कठिनाई का एक कारण यह भी है कि उन्हे अपने पूंजी के आन्तरिक स्रोतो—मूल्य ह्रास निधि और अवितरित लाभ आदि—से पर्याप्त धन नही मिलता, जबकि वडे व्यवसायो की बहुत-सी वित्तीय आवश्यकता इन स्रोतो से ही पूरी हो जाती है।

किन्तु छोटे व्यवसायो की कुछ विशेषताएँ ऐसी भी है जो वडी कम्पनियो की इस लाभपूर्ण स्थिति को बहुत कुछ बराबर कर देती है। अधिक प्रसिद्ध छोटी कम्पनियो की सफलता और वडी एव सम्पन्न कम्पनियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता का कारण यह है कि उनकी कार्य सचालन विधि मे लचकीलापन होता है और उनके प्रबन्धको मे विविध प्रकार के कार्य कर सकने की क्षमता और योग्यता होती है। छोटी कम्पनियाँ अनेक नये औद्योगिक क्षेत्रो मे, उदाहरणार्थ इलैक्ट्रानिकी, यन्त्रो को स्वचल (ऑटोमैटिक) बनाने के उपकरणो, नियन्त्रित मिसाइलो के कुछ पुर्जो और सामग्रियो एव अन्य प्रकार के प्रतिरक्षा-सम्बन्धी कार्यों मे, तकनीकी प्रगति मे आगे रही है। इसके अलावा अनेक नई चीजो के विकास से, उदाहरणार्थ टेप-नियन्त्रित मशीनी औजारो और कम महँगे इलैक्ट्रानिक गणक यन्त्रो (कम्प्यूटर) से, मध्यम दर्जे के उद्योगो के लिए भी स्वचल विधियाँ अपनाना सम्भव हो गया है। जिन व्यवसायो मे वित्त की प्राप्ति, अनुसन्धान और ज्ञापन बहुत महत्त्वपूर्ण नही है, उनमे व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की

क्षमता का निर्णय इस बात से नही होता कि सम्बद्ध व्यवसाय छोटा है या वडा। लेकिन साथ ही यह बात भी स्वीकार की जानी चाहिए कि हाल के वर्षो मे अधिकतर नये और कल्पनापूर्ण साहसिक कार्यो का श्रेय वडे व्यवसायो को ही रहा है। उदाहरण के लिए ट्राजिस्टरो का आविष्कार एक वडी कम्पनी की प्रयोगशाला मे हुआ था। किन्तु मूल आविष्कारक से लाइसेस लेकर उसके उत्पादन की विधियाँ विकसित करने और उन्हे क्रियान्वित करने का श्रेय छोटी और वडी दोनो प्रकार की कम्पनियो को है।

चार्ट 11

कर अदा करने से पूर्व औसत वार्षिक लाभ की दर विभिन्न परिसम्पत्तियो वाली अमेरिका निर्माता कम्पनियों (शेयर होल्डरों के शेयरो पर प्रतिशत लाभ)
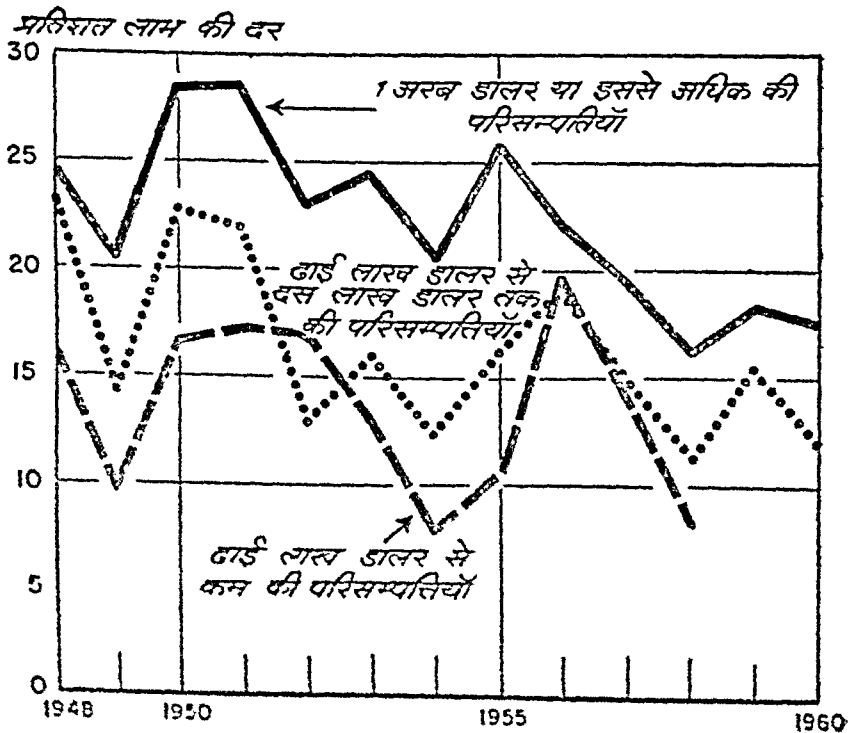
यद्यपि छोटे और वडे व्यावसायिक सस्थानो का साथ-साथ अस्तित्व ही उत्पादकता मे वृद्धि का एक मात्र कारण नही है, तो भी यह जरूर

कहा जा सकता है कि उसके विना यह असाधारण वृद्धि सम्भव न होती। इस कथन का अभिप्राय यह नही है कि सयुक्त राज्य मे वडे और छोटे व्यवसायो का मौजूदा मिश्रण ही सर्वोत्तम सम्भव मिश्रण है। वास्तविकता यह है कि वित्तीय दृष्टि से अधिक अच्छी स्थिति मे होने के कारण बडी कम्पनियो ने अनेक वार छोटी कम्पनियो के विकास मे वाधा डाली है। यह वाधा न डाली जाती तो ये छोटी कम्पनियाँ उनके साथ अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा कर सकती थी।

प्रतिस्पर्धा की मात्रा

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे वडे व्यवसायो की वृद्धि से प्रतिस्पर्धा (कॉम्पीटीशन) का स्थान एकाधिकार (मोनोपली) ले लेगा, यह भय सत्य सिद्ध नही हुआ। अमेरिका मे अन्य औद्योगिक राष्ट्रो की अपेक्षा अधिक वडी कम्पनियो के अस्तित्व का कारण सिर्फ यह है कि अमेरिकी उद्योग अपेक्षाकृत अधिक वडे क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं। फिर भी सारे महाद्वीप के वाजार की जरूरत पूरी करने के वावजूद, बल्कि अशत इसी कारण से, अमेरिकी उत्पादको मे किसी भी अन्य देश के उत्पादको की अपेक्षा अधिक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है।

कभी-कभी लोग यह वात भूल जाते है कि जिन उद्योगो मे थोडे-से ही वडे उत्पादक है उनके और ऐसे उद्योगो के, जिनमे सैकडो या हजारो छोटे उत्पादक है, प्रतिस्पर्धा अधिक होगी। इसके अलावा, एक ही वस्तु के विभिन्न उत्पादको की प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ मूलत एक ही काम मे आने वाली विविध वस्तुओ मे—उदाहरणार्थ सूती कपडे और कृत्रिम रासायनिक धागे से बने कपडे मे—भी प्रतिस्पर्द्धा हो जाती है। कुछ क्षेत्रो मे यह एक विचित्र विरोधाभासपूर्ण स्थिति है कि जब तक उनमे छोटे-छोटे उत्पादक थे तब तक उनमे परस्पर इतनी प्रति-स्पर्धा नही थी किन्तु अब उनमे बड़े-बड़े उत्पादक आ गए तो प्रतिस्पर्धा खूब वढ गई। यह वात खास तौर से खुदरा व्यापार के क्षेत्र में पायी जाती है और इसकी वृद्धि का कारण कुछ हद तक यह है कि न केवल

मोटरो की संख्या बढ जाने के कारण लोग कही भी जाकर वस्तुएँ खरीद सकते है बल्कि टेलीफोन और डाक से आर्डर देकर भी सामान मँगा सकते है।

भण्डार शृखला (चेन स्टोर) डाक से सामान का आर्डर देने और बट्टा-घरो (डिस्काउण्ट हाउस) की प्रणाली स्थापित होने और सारे राष्ट्र मे विज्ञापन करने की पद्धति अपनायी जाने से पूर्व बहुत-सी छोटी खुदरा बिक्री की दुकाने, जिन्हे कुछ खास चीजो के व्यवसाय मे विशिष्टता प्राप्त होती थी, इस बात का लाभ उठाती थी कि ग्राहको के लिए उनका स्थान अन्य दुकानो के स्थानो की तुलना मे अधिक सुविधाजनक है। इस प्रकार वे अपनी प्रतिद्वन्द्वी दुकानो से इस आधार पर प्रतिस्पर्धा नही करती थी कि उनके माल की कीमत कम है, या किस्म बढिया है, या उनकी उधार माल देने की शर्ते आसान है, बल्कि इस आधार पर करती थी कि जिस जगह वे स्थापित है, वह ग्राहको के लिए अधिक सुविधाजनक है। आज भी अनेक देशो मे यही स्थिति है। किन्तु संयुक्त राज्य मे आज मूल्यो के आधार पर प्रतिस्पर्धा खूब चल रही है। उदाहरण के लिए सेफवे, ए० एण्ड पी० आदि खाद्य पदार्थो की बडी-बडी भण्डार शृङ्खलाओ मे आज उस जमाने से कही अधिक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है, जब कि उनकी स्थापना से पहले की छोटी-छोटी दुकाने अपने स्थानीय और बँधे हुए ग्राहको की सेवा किया करती थी। बिक्री की मात्रा मे बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण मूल्यो की प्रतिस्पर्धा बहुत उग्र हो गई है और इस प्रतिस्पर्धा की वजह से खुदरा व्यापार मे मुनाफे की गुंजायश घट गई है। इस प्रतिस्पर्धा से ग्राहको के सामने बहुत अधिक किस्मो की चीजे आने लग गई है, जिनमे से वे अपने मन के मुताबिक चीज छाँट सकते है। इससे खरीदारों की सुविधाएँ भी बढी है और कम खर्च पर उन्हे दुकानो मे अधिक सुविधाएँ भी प्राप्त होने लगी है।

अन्य क्षेत्रो मे भी नई-नई तकनीको के विकास से और प्रतिस्पर्धा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनी रहने से कीमतो पर ऐसे दबाव पड़

रहे हैं जिनसे उनका रुख नीचे की ओर रहे। मोटर और टेलीविजन सैट इसके प्रमुख उदाहरण है। इन क्षेत्रो मे नई औद्योगिक तकनीको के विकास से पहले की अपेक्षा अधिक बडे कारखानो की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है और जब कारखाने बडे होते है तो उन पर ऊपरी खर्चे भी अधिक आते है। परिणाम यह होता है कि उनमे इजीनियरी, पूंजीगत सामग्री, विज्ञापन और सामान्य प्रशासन का खर्च उनके कुल खर्च का अधिक बडा भाग होता है, जबकि उनके उत्पादन मे प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल और श्रम का हिस्सा कुल खर्च का कम भाग होता है। इसलिए इन उद्योगो को अधिक बडे पैमाने पर काम करने की प्रेरणा मिलती है। उनके उत्पादन पर ऊपरी खर्चों समेत जितनी लागत आती है, उससे जरा भी अधिक मूल्य पर अगर उनकी एक भी वस्तु बिके तो उनके कुल मुनाफे मे वृद्धि और कुल घाटे मे कमी आती है। इन प्रोत्साहनो को देखते हुए यह बात शायद आश्चर्यजनक है कि जैसे ही इन उद्योगो मे उत्पादन की क्षमता जरा-सी भी बढती है, वैसे ही कीमतें इतनी क्यो नही गिर जाती कि उनमे एकदम गडबड और अराजकता-सी पैदा हो जाय। इसका उत्तर यह है कि मूल्य-नीति निर्धारित करते समय उद्योगो के प्रबन्धक केवल तात्कालिक प्रतिफल (या तात्कालिक न्यूनतम हानि) को ही नहीं देखते, बल्कि उसके दूरगामी प्रभाव को भी देखते हैं। हर फर्म सिर्फ यही नही देखती कि उसके उत्पादन की कीमत ऊपरी खर्चों सहित कुल लागत से ऊँची रहे, बल्कि वह यह भी देखती है कि एक निश्चित अवधि मे उसकी यथासम्भव अधिक बिक्री हो।

बडी अमेरिकी कम्पनियो मे परस्पर प्रतिस्पर्धा खूब है, इसका अर्थ यह नही कि यहाँ किसी खास क्षेत्र मे किसी एक कम्पनी या कम्पनियो का एकाधिकार है ही नही और वे उससे मनमाने मूल्यो का फायदा नही उठाती, और न ही इसका यह अर्थ है कि कम्पनियो को अपने बडे-बड़े सघ बनाकर एकाधिकार स्थापित करने की प्रवृत्ति की ओर सजग रहने की अब कोई जरूरत नही है। यद्यपि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का एक भाग—रोज़गार और उत्पादन, दोनो की दृष्टि से—विकेन्द्रित और

छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगो के क्षेत्र मे ज्यादा है, तो भी कुछ उद्योगो मे केन्द्रीकरण काफी मात्रा मे है और वह चिन्ता का विषय बना हुआ है। उद्योग के बडा होने का अर्थ—जिसका हम ग्यारहवे अध्याय मे अधिक विस्तार से विवेचन करेगे—आर्थिक शक्ति का केन्द्रित हो जाना है। परन्तु आर्थिक शक्ति का यह केन्द्रीभूत होना आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से बुरा ही होगा, यह जरूरी नही है, क्योकि शक्ति का उपयोग जैसे समाज के लिए अहितकर हो सकता है, वैसे ही रचनात्मक भी हो सकता है। अमेरिका की नीति यह है कि इसके हानिकर उपयोग को रोका या निरुत्साहित किया जाय और इसके रचनात्मक पहलू को प्रोत्साहन दिया जाय।

व्यावसायिक प्रबन्ध के स्वरूप में परिवर्तन

बडी कम्पनियो द्वारा आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्त्वपूर्ण सरक्षता व्यावसायिक प्रबन्ध के स्वरूप मे परिवर्त्तन है। पिछले बीस वर्षो मे बडे और छोटे, दोनो प्रकार के उद्योगो मे व्यावसायिक प्रबन्ध के स्वरूप मे परिवर्त्तन हुआ भी है। यह महज सयोग ही नही है कि आज हमे व्यवसाय के क्षेत्र मे रॉकफेलर, कारनेगी, ऐस्टर और वेंडरबिल्ट जैसे नाम कम सुनाई देते है, और जनरल मोटर्स, जनरल इलैक्ट्रिक, स्टैंडर्ड ऑयल और अमेरिकन टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ आदि नाम अधिक सुनने को मिलते है। यह सच है कि आज भी कुछ व्यक्ति ऐसे है जिन्होने विशाल सम्पत्तियाँ सचित कर ली है, किन्तु वे अपवाद है, और आय-कर और सम्पदा-कर आदि की ऊँची दरो को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपवाद ही रहेगे। आज अधिकतर बड़े व्यावसायिक सस्थान ऐसे लोगो के हाथो मे है जिन्हे आम लोग नाम से शायद ही जानते हो।

व्यावसायिक प्रबन्ध का एक पेशे के रूप मे अपनाया जाना अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की हाल की शायद सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। इस नये पेशे के लोग अपने पूर्ववर्त्तियो के समान न तो शान-शौकत से रहते है

और न उतने कठोर व्यक्तिवादी हैं। ये लोग प्रायः अपनी कम्पनियो के वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, न कि उनके मालिक। हाल के दशकों मे कम्पनियो के प्रवन्ध विभाग के शीर्षस्थ व्यक्तियो का चुनाव अधिकाधिक इस आधार पर किया जाता रहा है कि उन्हें तकनीकी ज्ञान और क्रय-विक्रय का अनुभव कितना है। पहले की तरह उनके वित्तीय अनुभव को उतना महत्त्व नही दिया गया। आधुनिक व्यवसाय-अधिकारी व्यवसाय-प्रशासन विद्यालयो मे प्रशिक्षण प्राप्त होने के कारण दफ्तर और कारखाना, दोनो जगह व्यावहारिक विज्ञान और नई तकनीको के उपयोग के महत्त्व को समझते है, क्योकि वे जानते है कि इससे वे दोनो जगह काम की सुचारुता और क्षमता वढा सकते है, प्रतिस्पर्धा का मुकावला कर सकते हैं और श्रम तथा सामग्री की लागत मे वृद्धि को निष्प्रभाव करने का उपाय निकाल सकते है। वे शेयर होल्डरो, श्रमिको और ग्राहको के प्रति, और सवसे वढकर स्वय कम्पनी के प्रति, अपने उत्तरदायित्व को समझते है ताकि कम्पनी एक स्थायी सस्थान के रूप मे दीर्घकाल तक कायम रह सके।

कम्पनी के भीतर प्रवन्ध विभाग टीम की भावना और सहयोग से काम करने की उपयोगिता को महसूस करता है और यह भी अनुभव करता है कि कर्मचारी सघो के साथ प्रबन्धको के सम्वन्ध ऐसे होने चाहिएँ जो दोनो के लिए परस्पर लाभकारी और हितावह हो। आज के व्यावसायिक प्रबन्धको की व्यक्तिगत उन्नति उनकी अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि पर निर्भर होती है, इसलिए वे भी यह भली भाँति जानते है कि यदि ग्राहको, प्रतिस्पर्धियो और आम जनता मे उनकी कम्पनी की ख्याति होगी तो उससे कम्पनी के माल की विक्री मे और उसे अच्छे कर्मचारियो की प्राप्ति मे वहुत योग मिलेगा। आज जल्दी से जल्दी अधिक लाभ उठाना उतना महत्त्वपूर्ण नही माना जाता जितना कि ऐसी व्यवस्था करना जिससे कम्पनी का अपने उद्योग मे प्रतिष्ठित स्थान बन जाय और वह दीर्घ काल तक लाभ उठाती रह सके।

सहयोग और सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायित्वपूर्ण ढग से काम करने

को आवश्यकता की अनुभूति बढ जाने से अमेरिकी व्यवसायों मे साहस और उद्यम की प्रवृत्ति मे कोई कमी नही आयी है। इसके विपरीत व्यावसायिक कम्पनियाँ बडे पैमाने पर उत्पादन करने लग गई है। इसका अर्थ यह है कि वे कम मुनाफा लेकर अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करती हैं और राष्ट्र के बाजार मे उन्होने अपना जो क्षेत्र बना लिया है, उसे कायम रखने की, और सम्भव हो तो बढाने की भी कोशिश करती है। इसका अर्थ यह है कि वे बडे पैमाने पर और नये-नये आकर्षक तरीको से विज्ञापन करती और अपनी बिक्री को बढाने का प्रयत्न करती है और साथ ही नई और अधिक परिष्कृत वस्तुओं के उत्पादन की एव वितरण की नई-नई विधियो का विकास करती है। इस प्रकार दूर-दूर तक फैले बाज़ार, राष्ट्रव्यापी विज्ञापन के साधन, आमदनियो मे वृद्धि और उनका लोगो मे बटवारा और बडी-बडी कम्पनियो की स्थापना—इन सबने मिल कर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी है जिनमे प्रबन्ध मे निरन्तर सुधार करना और उत्पादन एव बिक्री की विधियो मे उन्नति करना आवश्यक है।

प्रबन्धको और सचालको (डायरेक्टरो) की व्यक्तिगत पसन्द या नापसन्द आदि के आधार पर व्यावसायिक पूंजी-निवेश (कैपिटल इन्वेस्टमेंट) विषयक निश्चय किये जाते है। यद्यपि बाजार के मूल्य सम्बन्धी सकेतो का आज भी महत्त्व है, फिर भी इनके प्रति व्यावसायिक लोगो की प्रतिक्रियाएँ दीर्घकालिक लाभ की आशाओ पर अधिक और तात्कालिक बिक्री की सम्भावनाओ पर कम, अवलम्बित रहती है, जब कि पहले यह स्थिति नही थी।

हाल के वर्षों मे बहुत-से उद्योगो मे अनेक प्रकार की फर्मों ने समूची अर्थ-व्यवस्था के विकास की सम्भावनाओ के बारे में बहुत कुछ एक ही जैसी मान्यताएँ अपनायी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत-सी फर्मों के निवेश सम्बन्धी कार्यक्रम आमतौर पर एक-दूसरे के बहुत अधिक अनुकूल है और उनमे तालमेल है। औद्योगिक विस्तार को जारी रखने के बारे मे सम्भावनाओ और दृष्टिकोण की इस समानता का एक लाभ नि सन्देह हुआ है और वह यह कि उद्योगो के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए व्यवसायो मे अधिक पूंजी का निवेश किया गया है और उसके स्तर मे और भी अधिक वृद्धि होती जा रही है। इस विस्तार और आधुनिकीकरण ने उत्पादकता मे वृद्धि की है और समूची अर्थ-व्यवस्था को ही उन्नत और विकसित किया है।

इस नई किस्म के व्यावसायिक प्रबन्ध की एक विशेषता और भी है और वह यह कि वह परिवर्त्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियो के साथ समझौता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और इस सम्बन्ध मे वह व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। प्रबन्धको मे पुराने दकियानूसी और अपरिवर्त्तनशील कट्टर या विशुद्ध तार्किक सिद्धान्तो के परित्याग के लिए हमेशा तैयार रहने की जो प्रवृत्ति है उसी के कारण वे समूची अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से परिवर्त्तमान परिस्थितियो के साथ शीघ्रता से समजन कर लेते है। प्रबन्धक लोग कारखाने और दफ्तर मे नई और अधिक उत्पादक विधियो को विकसित करने और अमल मे लाने के लिए तैयार रहते है, इसीलिए वे अपने अधिकारी वर्ग के लिए

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने मे दिलचस्पी लेते है और इजीनियरी, औद्यो-गिकी और व्यवसाय-प्रबन्ध सम्बन्धी स्कूल खोलते है। किन्तु शिक्षा और प्रशिक्षण से उत्पादकता मे वृद्धि तभी होगी, जबकि सिखाने और सीखने को कोई उपयोगी चीज मौजूद हो। इसीलिए उत्पादकता वृद्धि मे वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसन्धान का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन अनुसन्धानो के बिना अच्छे से अच्छे व्यवसाय प्रबन्धक भी वे सफलताएँ और परिणाम नही दिखा सकते थे, जो अब तक उन्होने दिखाये है।

सारांश

अमेरिकी सामाजिक और आर्थिक जीवन मे कम्पनियो के एक महत्त्वपूर्ण सस्था के रूप मे विकसित होने के फलस्वरूप व्यावसायिक प्रबन्ध की कला भी लगभग उतनी ही आगे बढ गई है, जितनी कि कारखाने मे औद्योगिक तकनीक विकसित हुई है। कम्पनी प्रबन्धको के इस नये वर्ग द्वारा अपनाये जाने वाले रुख और तरीको का महत्त्व अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की सफलता के लिए अधिकाधिक बढता जाएगा।

5
अनुसन्धान और औद्योगिकी

अमेरिकी दार्शनिक जॉर्ज सेंटायना ने 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है' कहावत से भी अधिक गहराई मे जाकर कहा था कि प्राचुर्य को आविष्कार का जन्मदाता कहा जाना चाहिए। जो देश या जाति अपनी मौलिक या आर्थिक परिस्थितियो के भारी दवाव के कारण अपनी सीमित प्रतिभा, कल्पना और औजारो को लेकर उनके सहारे जैसे-तैसे जीवन-यापन करती है, वह प्रगति नही कर पाती और करती भी है तो अत्यन्त मन्द गति से। यही कारण है कि सभ्यता का अधिकतर प्रारम्भिक उत्कर्ष एशिया और अफ्रीका की धन-धान्यपूर्ण हरी-भरी नदी घाटियो मे हुआ और वे छोटी-छोटी घुमक्कड जनजातियाँ, जिन्हे यह भी मालूम नही था कि उन्हे अगले वक्त का खाना क्या, कहाँ और कव मिलेगा, वे सस्कृति के विलकुल आदिम स्तर से आगे नही वढ सकी। इसमे सन्देह नही कि प्राचुर्य ही अमेरिका मे भी अनुसन्धान और औद्योगिकी (टैक-नोलॉजी) की उन्नति का एक प्रधान कारण और साथ ही प्रधान परि-णाम था।

व्यावहारिक और मूल विज्ञान

आज किसी भी आधुनिक देश का वुनियादी या व्यावहारिक विज्ञान की प्रतिमा और उपलब्धियो पर एकाधिकार नही है। अमेरिकी लोग मूल विज्ञान के अनुसन्धानो के परिणामो को व्यवहार मे लाने और उनसे औद्योगिक क्षेत्र मे नई विधियो को अपनाने मे विशेष रूप से आगे रहे है, भले ही ये आविष्कार या अनुसन्धान अमेरिका मे हुए हो या अमेरिका से वाहर। कई वैज्ञानिक खोजे ऐसी है, जो हुई तो अमेरिका से वाहर किन्तु उनका व्यावहारिक उपयोग सबसे पहले अमेरिका मे हुआ, क्योकि

जिन देशो मे वे खोजें हुई, उनके बाजार इतने छोटे और प्रतिस्पर्धाहीन थे कि वे अपने उत्पादन और उत्पादन-विधियो मे बार-बार परिवर्तन का खर्च नही उठा सकते थे। उदाहरण के लिए मोटर निर्माण के क्षेत्र मे कई महत्त्वपूर्ण आविष्कार पश्चिमी यूरोप मे हुए, किन्तु जर्मन, ब्रिटिश और फ्रासीसी उत्पादक, जिनके यहाँ मूलत: ये आविष्कार हुए थे और जिन्होने उनके औद्योगिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम नमूने तैयार किये थे, अमेरिकी मोटर-निर्माताओ से दस या इससे भी अधिक वर्ष बाद उन्हे अपने कारखानो मे प्रयोग मे ला सके।

नई-नई विधियो के आविष्कार और प्रयोग की यह प्रवृत्ति ही अमेरिकी उत्पादकता और वैज्ञानिक अनुसन्धान और उसके व्यावहारिक उपयोग के बीच सम्बन्ध की कुजी है। आज इन दोनो के सम्बन्ध का लाभ केवल औद्योगिक या कृषि क्षेत्र मे ही नही उससे भी अधिक व्यापक क्षेत्र मे उठाया जा रहा है। इसकी बदौलत चिकित्सक और दातो के डाक्टर आधुनिक ढग के नये उपकरणो का, लाड्रियाँ चलाने वाले कपड़े धोने, सुखाने और इस्त्री करने की स्वचलित मशीनो का, और गृहिणियाँ घर की सफाई करने वाली वैक्यूम मशीनो और बर्तन साफ करने वाली बिजली की मशीनो का लाभ उठा रही है। यही नही और भी बीसियों वर्गों के लोग औद्योगिक क्षेत्र की वैज्ञानिक और औद्योगिकी सम्बन्धी उन्नति का लाभ प्राप्त कर रहे है।

इसके अलावा आधुनिक अनुसन्धान और औद्योगिकी की पहुँच उत्पादन की भौतिक प्रक्रियाओ से भी आगे तक है और उनका असर व्यवसायों के सगठन और प्रशासन पर भी पडता है। अमेरिकी उद्योगो मे बड़े पैमाने पर सामूहिक उत्पादन की नई विधियो के प्रारम्भ होने से पूर्व ही यह अनुभव कर लिया गया था कि जिस तरह नये औजारो और नई मशीनों के उपयोग से उत्पादकता बढाई जा सकती है, वैसे ही उत्पादन की प्रक्रियाओ को कौशलपूर्ण ढग से सगठित करके भी उसे बढाया जा सकता है। कुछ समय बाद यह भी महसूस किया गया कि यदि श्रमिकों के काम की परिस्थितियाँ अच्छी हो तो उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी

उत्पादन की प्रक्रिया मे सघर्ष कम होगा। हाल के वर्षो मे प्रबन्धको और श्रमिक सगठनो, दोनो के द्वारा किये गए अनुसन्धानात्मक अध्ययनो के फलस्वरूप इन सिद्धान्तो को आम तौर पर स्वीकार कर लिया गया है और उन्हे व्यवहार मे लाकर उत्पादकता मे वृद्धि भी की जा सकी है।

यद्यपि सामाजिक विज्ञानो का भी उत्पादकता मे वृद्धि के लिए बहुत महत्त्व है, तो भी भौतिक विज्ञानो की अपेक्षा उनकी उन्नति अधिक कठिन रही है। इसका एक कारण यह है कि सामाजिक विज्ञानो का स्वरूप ही भौतिक विज्ञानो से भिन्न है—सामाजिक विज्ञानो मे एक तो कारण तत्वो की सख्या बहुत अधिक होती है, दूसरे उनमे नियन्त्रित ढग से प्रयोग और परीक्षण करने की गुजायश कम होती है और तीसरे उनमे नैतिक मूल्य सम्बन्धी निर्णयो की उपेक्षा नही की जा सकती। लेकिन इस कठिनाई का एक कारण यह भी है कि सामाजिक विज्ञानो के क्षेत्र मे अनुसन्धान के लिए सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रो से पर्याप्त वित्तीय सहायता नही मिलती।

वैज्ञानिक और औद्योगिकी सम्बन्धी अनुसन्धानो के परिणामो को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र मे प्रयुक्त करना बहुत कुछ विज्ञान की मूल खोजो पर निर्भर है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र मे अधिकतर महान् मूल आविष्कार यूरोप मे या यूरोपीय परम्पराओ मे प्रशिक्षित वैज्ञानिको के हाथो हुए है।

इसका अर्थ यह नही है कि अमेरिकी लोगो ने दर्शन और विज्ञान के क्षेत्रो मे महत्त्वपूर्ण योग नही दिया है। जबसे बैंजमिन फ्रैंकलिन ने अपने उदाहरण से यह साबित किया कि शुद्ध और प्रयुक्त विज्ञान की प्रतिभा और व्यावहारिक बुद्धि एव राजनीतिज्ञता का एक ही व्यक्ति मे समन्वय सम्भव है, तभी से अमेरिकी लोग भी इन क्षेत्रो मे योगदान करते आये हैं। एक और उदाहरण भी लिया जा सकता है—आज की आधुनिक औद्योगिक टैकनोलॉजी अमेरिकी वैज्ञानिक एली व्हिटने की इस सैद्धान्तिक कल्पना का ही मूर्त रूप है कि मशीनो के पुर्जो मे परस्पर परिवर्तन किया जा सकता है। फिर भी पिछले सौ वर्षों मे सगठित रूप मे बुनियादी

वैज्ञानिक अनुसन्धान अमेरिका मे उतना सघन नही हुआ, जितना कि यूरोपीय देशो मे।

अमेरिका का मूल अनुसन्धान मे पीछे रहना यह बताता है कि अमेरिका और यूरोप के मूल और प्रयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी रवैयो मे अन्तर है। उदाहरण के लिए फ्रास, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस (जारशाही और कम्युनिस्ट दोनो) की विज्ञान अकादमियो मे नियुक्ति, शुद्ध अनुसन्धान मे अपना जीवन अर्पण करने वाले नर-नारियों के लिए, सर्वोच्च सम्मान समझी जाती है। इस प्रकार अकादमिशियन बनने की आकाक्षा और ध्येय ने यूरोप की वैज्ञानिक उन्नति को बहुत प्रोत्साहन दिया है। लेकिन अमेरिका मे इन विज्ञान अकादमियो की समकक्ष सस्थाओ को यूरोप की इन सस्थाओ के बराबर मान्यता, सहायता और ऊँचा स्थान नही मिला है। यूरोप मे वैज्ञानिक और अध्यापक को जो प्रतिष्ठा मिलती है वह अमेरिका मे प्राय एक सफल व्यवसाय अधिकारी को, खासकर स्वय अपने परिश्रम से बने व्यक्ति को, मिलती है।

अमेरिका के वैज्ञानिक उन्नति संघ की परिषद् ने हाल में अपनी एक रिपोर्ट मे कहा था कि "सयुक्त राज्य मे मूल विज्ञान की उन्नति प्रयुक्त (व्यावहारिक) विज्ञान की उन्नति के साथ कदम मिलाकर चलती प्रतीत नही होती।" मूल विज्ञान की इस उपेक्षा का जो मुख्य कारण आमतौर पर बताया जाता है, वह यह है कि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसन्धान के काम मे लगे हुए व्यक्तियो और उनके लिए पैसा लगाने वालो, दोनो का मानसिक रुझान व्यावहारिक उपयोग की ओर होता है। दूसरे विश्व युद्ध के दिनो मे अमेरिकी वैज्ञानिको ने शस्त्रास्त्रो के विकास का काम करने की सरकार की पुकार की ओर ध्यान दिया; युद्ध के बाद उनमे से बहुत-से प्रतिभाशाली वैज्ञानिको और इजीनियरो ने सरकारी सेवा छोड दी। अधिकतर सृजनात्मक और सफल अनुसन्धानकर्त्ता प्राय औद्योगिक सस्थानो की प्रयोगशालाओ की ओर आकृष्ट होते जिनमे प्रयुक्त विज्ञानो पर सारा ध्यान केन्द्रित किया जाता है। वे सरकार या [illegible] की अपेक्षा 'शुद्ध' वैज्ञानिक अनुसन्धान करने

सस्थाओ की ओर आकृष्ट नही होते ।

आज सयुक्त राज्य मे अनुसन्धान और विकास पर होने वाले सारे खर्च का 10 प्रतिशत से भी कम भाग प्रकृति की बुनियादी प्रक्रियाओ के अनुसन्धान और वैज्ञानिक सिद्धान्तो के निर्धारण और परीक्षण मे लगाया जाता है। सयुक्त राज्य मे मूल वैज्ञानिक अनुसन्धान मे अपेक्षाकृत कम दिलचस्पी और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षाकृत कम धन के व्यय पर अमेरिकी वैज्ञानिको और अमेरिकी सरकार की चिन्ता वरावर बढती रही है ।

ऐसी स्थिति मे हाल के वर्षों मे रूस ने वैज्ञानिक अनुसन्धान मे जो असाधारण उन्नति की है उसने अमेरिकी को वहुत वडा आघात पहुँचाया है और उसी के कारण यहाँ शिक्षा और अनुसन्धान की प्रणाली और उसके सम्बन्ध मे अमेरिकी लोगो के बुनियादी रुख पर सम्पूर्ण रूप से पुनर्विचार को और भी वल मिला है। यह सम्भव है कि इस पुनर्विचार का असर हमारी शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरो पर पडे, प्राथमिक, माध्यमिक और व्यावसायिक स्कूल और विश्वविद्यालय आदि सभी उससे प्रभावित हो और मूल अनुसन्धान को और अधिक वल और प्रोत्साहन मिले ।

विज्ञान और औद्योगिकी के विकास मे अमेरिकी लोगो की आस्था इतनी गहरी है कि इस क्षेत्र मे अपनी कमज़ोरी की गम्भीर चुनौती को वे किसी भी तरह दर-गुजर और नजरन्दाज नही करेगे। लेकिन एक ख़तरा भी है कि इस कमी को दूर करने की जल्दबाजी मे कही अमेरिकी लोग तकनीकी शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान और गणित को बहुत सकुचित अर्थ मे न लेने लगे। इन क्षेत्रो मे सृजनात्मक उपलब्धियाँ केवल तकनीक और बारीकियो के अध्ययन पर ही नही, बल्कि इन विज्ञानो के सैद्धातिक और दार्शनिक पक्षो पर भी निर्भर है, वल्कि यह बात और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। और इन सैद्धान्तिक और दार्शनिक पक्षो की जड समग्र रूप से सस्कृति के अधिक व्यापक और उर्वरक प्रभावो मे गहराई तक धॅ.ी रहती है। जहाँ सास्कृतिक परम्परा समृद्ध और विविधतापूर्ण

तकनीकी उन्नतियो और नवीन वैज्ञानिक सुधारो का परिणाम भी है और कारण भी ।

तालिका 6

सयुक्त राज्य के 11 चुने हुए उद्योगो[1] की प्रयोगशालाएँ और उनमे काम करने वाले कार्यकर्त्ता—1945-1960

	1945	1950	1955	1960 (अनुमान)	प्रतिशत वृद्धि 1945-60 (अनुमान)
प्रयोगशालाओ की सख्या	1,855	2,414	3,760	5,600	200
वैज्ञानिक और इजीनियर	50,560	70,182	1,19,641	2,08,500	310
सहायक कार्यकर्त्ता	70,544	87,547	1,41,256	2,10,000	200
प्रयोगशालाओ के कुल कार्यकर्त्ता	1,21,104	1,57,729	2,60,897	4,18,500	245

उद्योगो, सरकार और शिक्षा सस्थाओ मे जैसे-जैसे अधिकाधिक वैज्ञानिको और इजीनियरो की नियुक्तियाँ हुई है, वैसे-वैसे अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी कार्यो पर खर्च भी बढता रहा है । यद्यपि शुरू के वर्षो के आकडे हाल के वर्षो के आकडो की भाति पूर्णत सही नही है, तो भी यह अनुमान लगाना अनुचित नही होगा कि 1946 से 1953 तक उद्योगो

1. इन उद्योगों में लगभग 85 प्रतिशत वैज्ञानिक कार्यकर्त्ता लगे हुए हैं ।

मे अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी कार्य दुगुने हो गए है। और सन् 1953 के बाद से वे फिर तिगुने हो गए है। सन् 1953 मे अनुसन्धान और विकास पर कुल आनुमानिक खर्च 5 अरब डालर से अधिक था और युद्धोत्तर वर्षो की औसत वार्षिक वृद्धि के दर से सन् 1961 मे उसे 14 या 15 अरब डालर हो जाना चाहिए। दूसरे शब्दो मे सयुक्त राज्य की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 3 प्रतिशत इस समय अनुसन्धान और विकास पर खर्च हो रहा है।

सन् 1959-60 मे अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी सारे खर्च का दो-तिहाई सघीय सरकार ने दिया, हालाकि वास्तविक काम का कुल 20 प्रतिशत ही सघीय विभागो और सस्थाओ द्वारा किया गया। सरकार के अधिकाश अनुसन्धान और विकास के कार्य प्राइवेट सस्थाओ के द्वारा कराये गए। इस प्रकार मोटे तौर पर सारे अनुसन्धान और विकास कार्य का तीन चौथाई काम प्राइवेट उद्योगो ने किया। लेकिन इस पर हुए खर्च का केवल 50 प्रतिशत ही उन्होने अपने धन मे से किया, शेष 50 प्रतिशत सघीय सरकार ने दिया।

तालिका 7

अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी व्यय का प्रतिशत वितरण

	वित्तीय साधन		अनुसन्धान—कार्य	
	अनुसन्धान और विकास	बुनियादी अनुसन्धान	अनुसन्धान और विकास	बुनियादी अनुसन्धान
संघीय सरकार	64	56	15	19
उद्योग	33	26	75	30
कालेज और विश्वविद्यालय	2	12	8	44
मुनाफा न कराने वाली अन्य सस्थाएँ	1	6	2	7
	100	100	100	100

सरकार द्वारा या सरकारी पैसे से प्रतिरक्षा सम्बन्धी (सैनिक) वैज्ञानिक अनुसन्धान और विकास का एक बडा हिस्सा देर-सवेर शांति कालीन असैनिक कार्यों मे प्रयुक्त होने लगता है। यही कारण है कि युद्ध काल मे हुए वैज्ञानिक अनुसन्धान और विकास कार्यों के फलस्वरूप अब हम सयुक्त राज्य मे तथाकथित 'दूसरी औद्योगिक क्रान्ति' (सैकण्ड टैकनोलॉजिकल रेवोल्यूशन) देख रहे है।

औद्योगिक अनुसन्धान मे योग देने वाला एक वडा कारण द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद निगम कर (कॉर्पोरेट टैक्स) मे भारी वृद्धि है। निगम कर का हिसाब लगाते हुए अनुसन्धान ओर विकास सम्वन्धी खर्चों को आमतौर पर व्यावसायिक व्यय मानकर कर से मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार अधिक साहसी कम्पनियाँ इस प्रकार के कामो पर अपना व्यय बढा देती है, जिन पर उन्हे अपने पास से अधिक पैसा न लगाकर टैक्स मे से बचायी हुई रकम लगाने की सुविधा मिल जाती है।

अनुसन्धान और विकास पर अमेरिकी उद्योगो द्वारा अधिकाधिक धन का व्यय किया जाना इस बात का प्रमाण है कि वे सयुक्त राज्य की-सी गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ-व्यवस्था मे उत्पादकता-वृद्धि के लिए उसके महत्त्व को अनुभव करने लगे है। औद्योगिक तकनीको के विकास से प्रति मानव घण्टा उत्पादन मे भी वृद्धि होती है और साथ ही मजदूरी मे भी तदनुसार वृद्धि की जा सकती है। इसके प्रतिलोम की दृष्टि से कहा जाय तो यह भी कह सकते है कि जब मजदूरो की मजदूरी की दर बढ जाती है तब खर्च को घटाने के लिए ऐसी तकनीकी विधियाँ निकालनी पडती है जिनसे मानवीय श्रम की बचत की जा सके। आमतौर पर जिन देशो मे मजदूरो की सख्या बहुत बडी और मजदूरी की दर अपेक्षाकृत कम होती है, उनमे श्रम की बचत करने के तरीके निकालने के लिए प्रोत्साहन नही मिलता। किन्तु कुछ मामलो मे अन्य कारणो से इन देशो मे नई तकनीको के विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है। पुराने तरीक़ो मे सुधार और नये तरीको का आविष्कार कर पुराने तरीको से निर्मित वस्तु की अपेक्षा अधिक अच्छी और बेहतर किस्म की

वस्तु तैयार की जा सकती है। उदाहरण के लिए पुराने ढंग के तेल शोधक कारखानो मे जो गैसोलिन (विमानों मे प्रयुक्त पेट्रोल) तैयार किया जाता था, वह बिल्कुल एक-सा नही होता था और बार-बार प्रयोगशालाओ मे नमूनो की परीक्षा करके और उसके आधार पर विभिन्न पैमाने वाले गैसोलिनो को मिलाकर सही चीज तैयार की जाती थी, परन्तु नये और स्वचालित तेलशोधक कारखानो मे यह कठिनाई नही है, उनमे एक-सा गैसोलिन स्वय तैयार होता जाता है। इस प्रकार सयुक्त राज्य मे जो नई औद्योगिक विधियाँ मजदूरी की ऊँची दर के कारण श्रम की बचत के लिए निकाली गई है, वे अन्य देशो मे मजदूरी की दर अपेक्षाकृत नीची होने पर भी इसलिए अपनायी जाती है कि उनसे उत्पादित माल की किस्म अच्छी होती है।

लेकिन यह जरूरी नही है कि औद्योगिक तकनीकी विधियो में सुधार मानव के लिए हितकारी ही हो। अठारहवी और उन्नीसवी शताब्दियो मे जो नई शिल्पिक पद्धतियाँ निकाली गई उन्होने दस्तकारी को खत्म कर दिया और अक्सर उनके परिणामस्वरूप मानवीय श्रम की प्रतिष्ठा घटी और हाथ से काम करने वाले शिल्पी सृजनात्मक काम के आनन्द से वचित हो गए। किन्तु बीसवी शताब्दी मे स्वचालित और स्वनियन्त्रित मशीनो और औद्योगिक विधियो के आविष्कार का यह लाभ हुआ कि कारीगरो को पुरानी परम्परागत विधियो मे जो समय और हाथ और दिमाग की ताकत लगानी पडती थी, उसमे काफी बचत हुई। इस तरह यान्त्रिकीकरण से, और खासकर हाल मे हुए स्वचालित विधियो के क्रमिक विकास से श्रम की प्रतिष्ठा और उसमे सृजन के आनन्द की पुन. स्थापना हुई है, हालाकि यह प्रतिष्ठा और आनन्द औद्योगिक युग से पहले के समाजो मे प्रचलित श्रम की प्रतिष्ठा और आनन्द से भिन्न है। आज श्रमिक मशीन का गुलाम नही रहा, वह उत्पादन-प्रणाली का अधीक्षक और रक्षक बन गया है।

सारांश

आधुनिक अनुसन्धान गतिशील आर्थिक प्रक्रिया का हृदय है।

इसकी बदौलत उत्पादन अधिक और उत्कृष्ट किस्म का होता है और लागत मे वृद्धि के बावजूद अन्त मे वह सस्ता पडता है। सयुक्त राज्य मे नई औद्योगिक विधियो के विकास और प्रयोग ने अमेरिकी श्रमिक की उत्पादकता बढाने मे मदद की है। इनमे से बहुत-सी नई औद्योगिक विधियाँ अन्य देशो से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है और कुछ विधियाँ बडे पैमाने पर बिक्री का, जो अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ है, परिणाम भी हे और उसका कारण भी। वैज्ञानिक और औद्योगिक तकनीको के क्षेत्र मे होने वाली यह उन्नति, चाहे उसका उद्गम अमेरिका हो या कोई अन्य देश, अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे उत्पादकता को बढाती रहेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक तकनीको की यह उन्नति केवल इसी बात पर निर्भर नही होगी कि उसके लिए सुप्रशिक्षित वैज्ञानिक और कुशल टैकनीशियन अधिकाधिक सख्या मे उपलब्ध होते या नही, बल्कि शुद्ध बुनियादी विज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग के अध्ययन और अनुसन्धान के लिए पर्याप्त धन और साधनो की उपलब्धि भी उसके लिए उतनी ही आवश्यक और महत्त्वपूर्ण होगी। साथ ही इस बात की बडी आवश्यकता है कि अमेरिकी शिक्षा-प्रणाली के उद्देश्यो पर पुनर्विचार किया जाय और अध्ययन की विषय-वस्तु और अध्यापन की विधियो मे सुधार किया जाय।

पूँजी

श्रमिको का कौशल, प्रबन्ध-व्यवस्था की दक्षता और नई औद्योगिक विधियों का विकास उत्पादन और उत्पाकता मे वृद्धि के लिए तभी पूर्णत लाभकारी हो सकते है, जब कि आवश्यक सयन्त्र और साधनो के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो। यदि पूंजी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो तो उससे उत्पादकता मे वृद्धि होती है और जब उत्पादकता बढ जाती है तो वह उद्योग के भीतर से ही नई पूंजी को जन्म देती है और वह पूंजी फिर उत्पादकता को बढाती है। इस प्रकार पूंजी की पर्याप्त मात्रा मे उपलब्धि आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है और इसका प्रतिलोम स्वभावत यह होगा कि जो देश अपना आर्थिक विकास तेजी से करना चाहते है उनके मार्ग मे पूंजी की कमी सबसे बडी बाधा है। इन देशो के समक्ष यह कठिन समस्या खडी हो जाती है कि जो थोडा-सा उत्पादन बढता है उसकी आय कैसे बाँटे। उसका कितना अश आम लोगो की माँग की पूर्ति मे, कितना सार्वजनिक (सरकारी) कार्यक्रमो की बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति मे लगाये और कितना अश उत्पादक उद्योगो की पूंजी बढाने के लिए।

विदेशी पूंजी का योगदान

सयुक्त राज्य को भी अपने औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक दौर में, अन्य अल्पविकसित देशो की भाँति अपनी पूंजी की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए न केवल अपने आन्तरिक वित्तीय साधनो को खर्च कर डालने के बजाय पूंजी के रूप मे निवेश (इन्वेस्ट) करना पडा बल्कि अन्य देशो से भी पूंजी को आकृष्ट करना पड़ा। अन्य देशों

भाँति अमेरिका मे भी आन्तरिक स्रोतो से उपलब्ध पूंजी अन्य देशो से आयातित पूंजी की अपेक्षा मात्रा से भी अधिक थी और उस पर भरोसा भी अधिक किया जा सकता था। लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध तक अमेरिका के विकास मे विदेशी पूंजी का, खासकर प्राइवेट पूंजी का, महत्त्वपूर्ण स्थान था। सन् 1914 मे सयुक्त राज्य मे लगी विदेशी पूंजी 7 अरब डालर की थी, जिसकी क्रय शक्ति चालू मूल्यो के हिसाब से 35 अरब डालर की थी (देखिये परिशिष्ट तालिका 17)। यही नही, प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व अमेरिका के आर्थिक विकास मे विदेशी पूंजी का योगदान केवल 7 अरब डालर ही नही था, क्योकि कुछ पूंजी जो इस 7 अरब डालर मे शामिल नही है, पहले ही अमेरिका ने सम्बद्ध देशो को वापस लौटा दी थी। इसके अतिरिक्त ७ अरब डालर की इस राशि मे विदेशी पूंजी-निवेशको को अमेरिका मे अपने पूंजी-निवेश पर हुआ आशिक या पूर्ण नुकसान शामिल नही है, हालाकि नुकसान की यह रकम भी अमेरिका मे ही लग गई थी और उससे अमेरिका मे बहुत-से उत्पादक मयन्त्रो और अन्य साधनो का निर्माण हो गया था। उदाहरण के लिए विदेशी पूंजी से खुली कई रेल कम्पनियाँ अमेरिका मे दिवालिया हो गई, जब कि उनकी रेले बाकायदा अमेरिका मे चलती रही। इस प्रकार दिवाला निकल जाने पर उनकी पूंजी अमेरिका मे ही रह गई।

सन् 1914 के बाद सयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विकास मे प्राइवेट विदेशी पूंजी का योगदान पहले से बहुत कम हो गया। यह समस्या भी बहुत महत्त्वपूर्ण नही रही कि उद्योगो से होने वाले लाभ को खर्च करने के लिए लोगो मे वितरण कर दिया जाय या पूंजी के रूप मे पुन निविष्ट किया जाय। आज सयुक्त राज्य मे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, दोनो का स्तर इतना ऊँचा है कि लोगो का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिए उनकी क्रय-शक्ति बढाई जा सकती है, सरकारी कार्यक्रमो मे धन लगाया जा सकता है और प्राइवेट उद्योगो, व्यवसायो और कृषि मे भी पूंजी के रूप मे उसका निवेश

किया जा सकता है। दर असल, अमेरिका मे इस समय कुल उत्पादन इतना अधिक है कि उससे देशवासियो की उपभोग और पूंजी-निवेश की आवश्यकताओ को कोई गम्भीर नुक्सान पहुँचाये विना सरकार के प्रतिरक्षा और वैदेशिक सहायता के कार्यक्रम को भी काफी ऊँचे स्तर पर रखा जा सकता है।

आन्तरिक पूंजी के स्रोत

हाल के दशको मे सयुक्त राज्य मे कुल वचत इतनी रही है कि वह न केवल अपनी वढती हुई आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताएँ पूरी कर सकती थी, वल्कि उससे अन्य देशों को पूंजी का निर्यात भी किया जा सकता था। इन दशको मे पूंजी की कुछ कठिनाई सिर्फ तभी पैदा हुई जव सरकार को युद्ध के दिनो मे वहुत वडी मात्रा में वाजार से ऋण लेना पडा था जव हाल के वर्षो मे अमेरिका मे वहुत वडी मात्रा मे उद्योग-व्यवसाय और कृषि आदि मे पूंजी के निवेश का जवर्दस्त दौर आया। किन्तु यह सम्भावना भी ध्यान मे रखने योग्य है कि एक ही समय मे कुछ कामो के लिए पूंजी प्रचुर मात्रा मे उपलव्ध हो सकती है और कुछ के लिए वह वहुत दुर्लभ भी हो सकती है। पूंजी के वाजार की स्थिति का वारीकी से अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार की वचतो और निवेशो पर एक नजर डालना जरूरी है।

सयुक्त राज्य मे पूंजी निर्माण का वित्तीय स्रोत विभिन्न प्रकार की वचते हैं—व्यक्तिगत, सन्थागत, कम्पनियो की और सरकारी। अमेरिकी विकास के प्रारम्भिक दौर मे उत्पादक निवेश के लिए अधिकतर पूंजी धनी व्यक्तियो और परिवारो की वचत से प्राप्त होती थी। यद्यपि व्यक्तिगत वचत का आज भी वहुत महत्त्व है, तो भी हाल के दशको मे अन्य किस्मो की वचतें भी तीव्र गति से वढती रही हैं और आज वे कुल वचत के आधे से काफी अधिक हैं।

सन् 1920 और सन् 1950 मे प्रारम्भ दशको के अन्तिम वर्षों की यदि परस्पर तुलना की जाय तो यह परिवर्तन सहज मे ही समझा जा

सकता है। यह परिवर्तन आप लोगों की व्यक्तिगत बचतो मे विशेष रूप से नज़र आता है। आज आम लोगो के पास नकदी और बैंको मे जमा रकम की शक्ल मे मौजूद व्यक्तिगत बचत कुल प्राइवेट (गैर सरकारी) बचत के प्रतिगत अनुपात की दृष्टि से चौगुनी हो गई है और वह पूंजी-निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही किस्तो पर की गई खरीद और मकान गिरवी रखकर लिये गए ऋणो की अदायगी के लिए भी आम लोग पहले से काफी अधिक रकम चुकाते हैं। पहले यह स्थिति थी कि कोई भी व्यक्ति तब तक मोटर, घरेलू सामान या कपडा आदि नहीं खरीद सकता था, जब तक कि उसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए उसने पैसा न बचा लिया है। लेकिन आज लोग सामान खरीद पहले लेते हैं और फिर उसकी कीमत किस्तो मे आहिस्ता-आहिस्ता चुकाते रहते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं कि पहले आम लोगो की बचत शेयरो और सिक्यूरिटियो मे अधिक लगी होती थी, परन्तु आज उसमे कमी हो गई है। पहले इनमे लगी व्यक्तिगत बचत की मात्रा कुल प्राइवेट बचत का 39 प्रतिशत थी, जबकि आज वह सिर्फ 6 प्रतिशत है।

हाल के दशको मे प्राइवेट और सरकारी सस्थागत कार्य-क्रमो की पूंजी-निवेश निधियो मे भी बहुत वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए प्राइवेट व्यवसायो के बीमो और श्रमिक कल्याण निधियो से, ट्रेड यूनियनों और मुनाफा न कमाने वाले अन्य सगठनो एव सरकार के बीमा और पेन्शन कार्यक्रमों के द्वारा निवेश के लिए काफी पूंजी उपलब्ध हो जाती है। इन संस्थागत बचतो से न केवल अमेरिकी परिवारो की बहुत बड़ी सख्या को दुर्घटना, हारी-बीमारी, रिटायरमेंट, मृत्यु आदि की अवस्थाओ मे काफी लाभ प्राप्त हो जाते हैं, बल्कि प्रतिवर्ष पूंजी के रूप मे निवेश के लिए जो बहुत बडी रकम आवश्यक होती है, उसका भी एक बडा हिस्सा उपलब्ध हो जाता है। इन सस्थाओ के ज़रिये आम अमेरिकी श्रमिको और मध्यम-आय वर्ग के लोगो की व्यक्तिगत बचत पूंजी-निवेश के लिए अप्रत्यक्ष रीति से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, सन् 1960 के अन्त . प्राइवेट पेन्शन योजनाओ की ही करीब 50 अरब डालर की राशि

पूंजी के रूप मे विभिन्न स्थानो पर लगी हुई थी—इसका 80 प्रतिशत से अधिक भाग व्यावसायिक कम्पनियो के शेयरों और बाडो के रूप में लगा हुआ था—और उसमे 5 अरब डालर वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही थी। इस प्रकार करोडो अमेरिकी लोगो को अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक कम्पनियो के शेयरो के स्वामित्व का लाभ पहुँच रहा है। यह लाभ लाभाश (डिविडेड़) और शेयरो की मूल्य वृद्धि के रूप मे मिलता है। बहुत-सी ट्रेड यूनियनो ने भी व्यावसायिक कम्पनियो के शेयरो मे तथा अन्य विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक उद्यमो मे पूंजी लगाई हुई है।

पूंजी-निर्माण के लिए व्यावसायिक कम्पनियो की बचते तीसरा बड़ा स्रोत है। कुल प्राइवेट बचतो की तुलना मे प्रतिशत की दृष्टि से व्यावसायिक कम्पनियो की बचत का अनुपात प्रायः हमेशा एक ही रहा है। व्यवसायो मे पूंजी-निवेश और पूंजी के विस्तार के लिए यह स्रोत बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसके महत्त्व का पता व्यवसायिक कम्पनियो की कुल बचत (मूल्य ह्रास के लिए काटी गई रकमे और अवितरित लाभ) और कुल निविष्ट पूंजी के अनुपात से लग सकता है।

हाल के वर्षों मे व्यवसायो मे पूंजी-निर्माण मे कम्पनियो की अवितरित लाभ को राशि का हिस्सा उतना नही रहा, जितना कि उनकी मूल्य ह्रास निधि का। इसका कारण यह है कि 1947-49 के काल के बाद से जब कि अमेरिकी उद्योगो मे स्थित पूंजी परिसम्पत्तियो (फिक्सड कैपिटल एसैट) का स्तर बहुत नीचा था, कारखानो के सयन्त्रों और मशीनो आदि मे बहुत बडी मात्रा मे पूंजी लगी है। सन् 1954 के बाद से मूल्य-ह्रास निधियाँ और भी वढी है क्योकि कर का हिसाव लगाने के लिए मूल्य-ह्रास की छूट की सीमा काफी उदारता से बढ़ा दी गई थी। सन् 1960 मे अवित्तीय कम्पनियो की कुल बचते 30·3 अरब डालर की थी, जब कि उस वर्ष उन्होने लगभग उतनी ही, यानी 30·8 अरब डालर की रकम सयन्त्रो और मशीनो आदि मे लगाई। इस प्रकार उद्योगो के विस्तार और उन के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी उनके आन्तरिक स्रोतो से ही उपलब्ध हो जाती है।

तालिका 8

प्राईवेट वचतों का विवरण (वार्षिक औसत)

	1926-29		1957-60	
कुल अतिरिक्त वृद्धि	अरब डालर	प्रतिशत	अरब डालर	प्रतिशत
व्यक्तिगत वचतें	7 7	65 7	14 0	42 3
नकद और जमा (वचत और ऋण शेयर सहित)	1 0	8 6	12·4	37 6
प्राइवेट सिक्यूरिटियाँ (शेयर और बॉंड)	4 6	39 3	1 9	5 7
अन्य शुद्ध वचतें[1]	2 1	17 8	—0 3	—1·0
सस्थागत वचतें	1 7	14·6	10 9	33 0
प्राइवेट वीमा और पेन्शन निधियाँ	1 5	12 8	·6	26 0
सरकारी वीमा और पेन्शन निधियाँ	2	1 8	2 3	7 0
कम्पनियो की वचत[2]	2 3	19 7	8 2	24 7
कुल प्राइवेट वचत	11·7	100 0	33 1	100 0

1 इसमें लोगोंके पास मौजूद सरकारी सिक्यूरिटियाँ और अन्य स्थायी परिसम्पत्तियाँ भी शामिल हैं, किन्तु इसमें से उनकी देनदारियाँ और मूल्यह्रास की रकमें निकाल दी गई है।

2 व्यावसायिक कम्पनियों द्वारा सुरक्षित निधि में रखा गया अवितरित मुनाफा।

स्वय अपने साधनो मे वित्त की व्यवस्था करने के लाभ भी है और हानियाँ भी। लाभ यह कि उद्योगों के साहसी, प्रतिभाशाली और कल्पनाशील प्रबन्धको को उससे कार्य की अधिक स्वतन्त्रता रहती है। यदि उद्योग-व्यवसाय के प्रबन्धको को ऋण देने वाली संस्थाओ और द्रव्य-बाजार को अपने हर काम का व्योरा देना पडे और इस तरह उन्हे काम की पूरी स्वतन्त्रता न रहे तो उनमे नये विकास-कार्य करने और नई

तालिका 9

कम्पनियों की निधियो[1] के स्रोत और उनके उपयोग (वार्षिक औसत)

	1947-49		1957-60	
	अरब डालर	प्रतिशत	अरब डालर	प्रतिशत
स्रोत—कुल योग	22 6	100·0	38·2	100 0
आन्तरिक—योग	16·8	74 3	28 8	75·4
मूल्य-ह्रास	6·2	27 3	20 9	54 7
अवितरित लाभ	10 6	47·0	7 9	20 7
बाह्य—योग	5 8	25 7	9 4	24·6
कुल नई शेयर पूंजी	4 9	21·7	7 9	20 7
अन्य देनदारियो मे परिवर्तन	0 9	4·0	1·5	3 9
उपयोग—कुल योग	23 1	100·0	37 5	100 0
कुल कार्यकारी पूंजी	5 4	23 3	6·4	17·2
सयन्त्र और मशीने आदि	17 4	75 4	26 6	78 8
अन्य परिसम्पत्तियाँ	3	1 3	1·5	4 0
असंगित (स्रोत उपयोग के कम)	—·5			

1. इसमें बैंक, बचत और ऋण एसोसियेशनें, बीमा कम्पनियाँ और निवेश कम्पनियाँ शामिल नहीं है।

औद्योगिक विधियो को अपनाने की गति बहुत मन्द रहेगी। दूसरी ओर कुछ हानि भी सम्भव है क्योकि यदि ऋण के रूप मे पूंजी देने वाले बाहर के लोगो का कोई नियन्त्रण न रहे तो प्रबन्धको की इस स्वतन्त्रता के फलस्वरूप कुछ अपव्यय भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत-से छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यवसाय अपनी निज की बचतो से अपनी नई पूंजी की आवश्यकताएँ बहुत कम ही पूरी कर सकते हैं। इस हानि के बावजूद अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे उत्पादकता की गति मे वृद्धि और विस्तार मे कम्पनियो द्वारा अपने लिए स्वय अपने आन्तरिक स्रोतो से ही पूंजी की व्यवस्था ने भारी योग दिया है।

पूंजी का उपयोग

हाल के वर्षो मे सयुक्त राज्य मे व्यक्तिगत बचत का स्तर बहुत ऊँचा रहा है। किन्तु साथ ही लोगो द्वारा बचत की गई राशि के स्वयं अपने ही लिए उपयोग का स्तर भी बहुत ऊँचा रहा है। उदाहरण के लिए सन् 1960 मे उपभोक्ताओ पर दुकानो का उधार माल का कर्ज 4 अरब डालर बढ गया। इसके अलावा उपभोक्ताओ ने अपने पारिवारिक मकान गिरवी रखकर इस वर्ष 11 अरब डालर का और अतिरिक्त क़र्ज लिया। दूसरी ओर सब मिलाकर इस वर्ष उपभोक्ताओं ने अपनी व्यक्तिगत बचतो के रूप मे 23 अरब डालर की राशि व्यावसायिक पूंजी-निवेश के लिए (इसमे रिहायशी मकानो का निर्माण भी शामिल है) शेयरो की खरीद की शक्ल मे और सघीय और राज्यीय सरकारों और स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाओ को स्कूलो, सडको और अन्य सार्वजनिक निर्माण-कार्यो के लिए उनकी सिक्यूरिटियो की खरीद की शक्ल मे दी। फिर भी यदि अमेरिकी उद्योग अपने विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रमो के लिए अधिकतर वित्त व्यवस्था अपनी ही बचत से न कर पाते तो उपलब्ध पूंजी के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि की गति को कम कर देती। बचत की रकमो के उपयोग और पूंजी-निवेश की गति को दृष्टि मे रखते हुए यह कल्पना रना असगत नही है।

कुल बचतो का एक बडा भाग उपभोक्ता स्वय अपने लिए आवश्यक वस्तुएँ किस्तो पर खरीदने या अपने लिए मकान बनवाने पर खर्च कर देते हैं, यह सही है, लेकिन इसका अर्थ यह नही समझा जाना चाहिए कि बचतो का यह भाग उत्पादकता को बढाने मे कोई योग नही देता। यदि उपभोक्ताओ को किस्तो पर स्थायी और टिकाऊ सामान खरीदने के लिए देने को यह बचत की रकम न होती तो टिकाऊ उपभोग्य सामग्रियो की बडे पैमाने पर बिक्री का बाजार न रहता। साथ ही यदि वाजिब शर्तों पर मकानो को गिरवी रखकर पर्याप्य कर्ज न मिल सकता तो पिछले वर्ष प्राइवेट धन से बने 13 लाख नये मकान बनकर खडे न हो पाते और न इमारती सामान और घर की सजावट की सामग्री के लिए ही एक विशाल बाजार बन पाता। बडे पैमाने पर वस्तुओ की बिक्री होने पर ही बहुत-सी नई तकनीकी उत्पादन विधियो को उद्योगो मे अपनाना सम्भव होता है।

सारांश

7

शासन

यह बात आम तौर पर स्वीकार की जाती है कि प्राकृतिक साधन, श्रमिको की दक्षता, प्रबन्ध-कौशल, नई-नई तकनीकी विधियो को अपनाने का प्रयत्न और पूंजी का अपेक्षाकृत प्राचुर्य—ये चीजे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की ऊँची उत्पादकता के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन एक बात के सम्बन्ध मे लोगो मे मतैक्य नही पाया जाता और वह है शासन की नीतियाँ और कार्यवाहियाँ। कुछ लोग ऐसे है जो शासन की उन्नीसवी सदी की कल्पना से ही चिपके हुए है। उनका खयाल है कि सरकार को उत्पादकता मे सिर्फ इतना ही योग देना चाहिए कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये रखे और शिक्षा, स्वास्थ्य, सडको और स्वच्छता के क्षेत्रो मे आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराती रहे। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे है, जो कहते है कि उत्पादन के साधनो पर अमुक सीमा तक सरकार का नियन्त्रण रहना चाहिय, बल्कि कुछ लोगो की राय मे ये साधन सरकार के स्वामित्व मे रहने चाहिएँ, और कुछ लोगो का मत है कि सरकार को ही उनका सचालन करना चाहिए।

किन्तु सयुक्त राज्य मे शासन (सरकार) की कार्य पद्धति विचारधारा की इन दोनो चरम सीमाओ मे से किसी का भी स्पर्श नही करती। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था प्रधानत निजी (गैरसरकारी) उद्योगो द्वारा गठित है, फिर भी सरकार उस पर महज पहरेदारी का ही काम नही करती। अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि साहसी, गतिशील और उत्तरदायित्व की भावना से युक्त प्राइवेट उद्यम और रचनात्मक एव दूरदर्शितापूर्ण सरकारी नीतियो मे कोई असगति नही है, बल्कि दोनो एक-दूसरे के साथ खूब निभते है। इस प्रणाली के अन्तर्गत आर्थिक प्रक्रिया पर शासन के तानाशाही नियन्त्रण के बिना ही उत्पादकता मे वृद्धि की जा सकती है

और उसका स्तर निरन्तर ऊँचा उठता जा रहा है और साथ ही जनता का रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा हो रहा है। यहाँ आर्थिक कल्याण की प्राप्ति अमेरिकी की अपरिहार्य लोकतन्त्रीय स्वतन्त्रता के साथ पूर्णतः सगत रही है। इन मूल्यो मे, जिनमे परस्पर विरोध की सम्भावना निहित है, परस्पर समन्वय सिर्फ इस लिए सम्भव हुआ है कि सरकार द्वारा उठाये गए कदम प्राइवेट उद्योग-व्यवसाय और उपभोक्ताओ को काटने के वजाय उनके पूरक रहे हैं।

यहाँ यह भेद स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि शासन के भी तीन स्तर हैं—सघीय, राज्यीय और स्थानीय, और इन तीनो स्तरो के शासन की भी तीन अलग-अलग शाखाएँ हैं—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस त्रिपक्षीय प्रणाली का जन्म औपनिवेशिक शासन के दिनों मे हुआ था। वाद मे जव क्रान्ति के दौरान मे और उसके वाद राज्यो के सविधान वनाये गए और सन् 1789 मे सघीय सविधान वनाया गया तव उनमे भी उसे पूर्ण रूप मे समाविष्ट कर लिया गया। किन्तु इन तीनो स्तरो और इन तीनो शाखाओ के परस्पर सम्वन्ध तव से वैसे ही नही चले आ रहे, उनमे वदलती हुई आवश्यकताओ के अनुसार परिवर्त्तन होते रहे हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सघीय सरकार की जिम्मेदारियाँ और उसमे भी राष्ट्रपति की ज़िम्मेदारियाँ, ऐसी समस्याएँ पैदा होने पर वरावर वढती रही हैं, जो राज्यीय या स्थानीय शासन की क्षमता से वाहर थी और जिनके लिए कार्यपालिका द्वारा पहल की जाने और व्यापक प्रशासनिक कदम उठाये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार इस दौरान मे, खास कर हाल के दशको मे, राष्ट्रपति और ससद् (काग्रेस) के सम्वन्धो, सघीय सरकार और राज्यीय एव स्थानीय सरकारो के सम्वन्धो तथा सरकारी और गैर-सरकारी ज़िम्मेदारियो के सम्वन्धो मे वहुत परिवर्त्तन हुआ है।

आज सरकार का, अन्य सभी आधुनिक देशों की भाँति, अमेरिका में भी जन-जीवन मे वहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह जनता की अनेक प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है और उनके वदले में जनता तरह-तरह

के करो के रूप मे अपनी आय की एक निश्चित प्रतिशत मात्रा उसे देती है। तालिका 10 मे यह बताया गया है कि किस देश मे आय का कितने प्रतिशत भाग करो के रूप मे सरकार के पास जाता है।

सयुक्त राज्य मे सरकार की गति-विधियाँ आर्थिक प्रक्रिया को अनेक विभिन्न रूपो मे प्रभावित करती हैं। इनमे से कुछ सरकारी नीतियो और कार्यक्रमो का उद्देश्य कृषि, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन और वित्त के क्षेत्रो मे प्राइवेट उद्यमो को सहायता और सरक्षता प्रदान करना है। उसकी अन्य प्रवृत्तियो मे अनेक प्रकार के ऐसे नियमो और प्रतिबन्धो को लागू करना शामिल है, जिनका प्रयोजन श्रमिको और उपभोक्ताओ के और छोटे किसान, बेरोजगार, विकलाग और बूढे आदि

तालिका 10

सन् 1960 मे शासन के सभी स्तरो पर[1] विभिन्न देशो मे अदा किये गए कुल कर राष्ट्रीय आय के प्रतिशत अनुपात मे (प्रारम्भिक अनुमान)

सयुक्त राज्य	26 2
फ्रास	35 4
आस्ट्रिया	32 8
पश्चिमी जर्मनी	32 6
नार्वे	30 7
नीदरलैंड्स	30 3
इटली	30 0
ब्रिटेन	29 7
डेनमार्क	24·1
बेल्जियम-लक्सम्बर्ग	23 8
पुर्त्तगाल	17 0

1. इसमें सामाजिक बीमे के रूप में काटी गई राशियाँ भी शामिल है।

इसी प्रकार के अन्य दुर्बल और अल्पाधिकारी वर्गों के, अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। इनमे से बहुत-सी सरकारी प्रवृत्तियाँ दीर्घ काल से चली आ रही है और राजनीतिक प्रशासनों (सरकारो) के बदलते रहने पर भी जारी रही हैं।

प्राकृतिक साधनों का विकास

सयुक्त राज्य के इतिहास मे सरकार हमेशा ही कृषि और अन्य प्राकृतिक साधनो के विकास मे सक्रिय रही है। सघीय सरकार की सार्वजनिक भूमि नीति ने अमेरिकी कृषि के विस्तार मे बहुत महत्त्वपूर्ण योग दिया। सन् 1862 मे जो वासभूमि अधिनियम (होमस्टैड ऐक्ट) बना था, उसने ऐसे हर व्यक्ति को जो किसी एक ही स्थान पर घर बनाकर पाँच वर्ष तक रहा हो और खेती-वाडी करता रहा हो, 160 एकड भूमि प्रदान की। उसी वर्ष मौरिल अधिनियम भी बना जिसके अन्तर्गत सारे राष्ट्र मे कालेजो और कृषि-प्रयोग क्षेत्रो के लिए जमीनें दी गई। जैसा कि हमने देखा है, सरकार की सहायता से चलने वाली प्रशिक्षण, अनुसन्धान और सूचना-प्रसारण की इन सुविधाओ ने कृषि की उत्पादकता को बढाने मे महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। इसके अलावा, इन्होने सयुक्त राज्य सरकार के कृषि विभाग की विस्तार-सेवाओ के लिए बुनियाद तैयार की। यह सेवा किसानो को कृषि सम्बन्धी नई-नई विधियो को अपनाने मे सहायता देती है। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रमो की एक नई श्रृङ्खला, जिसका सम्बन्ध कृषि-जिन्सो के मूल्यो को स्थिर रखने के उपायो, उत्पादन सम्बन्धी नियन्त्रणो और फालतू जिन्सों को निबटाने के तरीको से था, दोनों विश्व-युद्धो के मध्यवर्त्ती वर्षों में प्रारम्भ हुई। ये कार्यक्रम अन्य सरकारी कार्यक्रमो की अपेक्षा अधिक विवाद का विषय थे। इन विभिन्न कार्यक्रमो का उद्देश्य विश्व के आर्थिक परिवर्त्तनो, तकनीकी क्षेत्र मे हुई उन्नति, मन्दियो और युद्धो के कारण कृषि-उत्पादनो की उपलब्धि और माँग मे पैदा असन्तुलन को दूर करना था। ये नीतियाँ और कार्यक्रम उपलब्धि और माँग मे अधिक सन्तुलन

स्थापित करने एव कृषि-जिन्सो के मूल्यो और कृपको की आय को स्थिर रखने मे सफल हुए हैं या असफल, इस विषय पर आज तक विवाद चला आ रहा है। कानूनन कृषि-क्षेत्र मे कमी कर के फालतू कृषि-उत्पादन को रोकने की नीति ने किसानो को अपनी अवशिष्ट भूमि मे ही अधिक उपज करने के लिए प्रोत्साहन दिया और फलत. कुछ हद तक वह कृषि-क्षेत्र मे तकनीकी विधियो के विकास और कृषि की उत्पादकता-वृद्धि मे सहायक सिद्ध हुई।

अन्य प्राकृतिक साधनो का सरक्षण और विकास भी सरकार की चिन्ता के मुख्य विपय रहे हैं और उसने अनेक प्रकार से उन्हे पूरा करने का प्रयत्न किया है। जहाँ तक संरक्षण का सम्बन्ध है, सरकार की नीतियो और कार्यो ने राष्ट्र की मूल्यवान् वन सम्पदा की रक्षा की है और नये वृक्षारोपण से उसे वढाया है और साथ ही पीने, खेतो को सीचने, उद्योगो मे इस्तेमाल करने और अनेक मनोरजन सम्बन्धी प्रयोजनो के लिए जलोपलब्धि का विस्तार, रक्षा और शोधन किया है।

अपने बहूद्देश्यक जल-कार्यक्रमो के एक अङ्ग के रूप मे सरकार ने जल-विद्युत् का इतना विकास किया है कि आज सयुक्त राज्य मे उत्पादित आधी से अधिक जल-विद्युत् का स्वामित्व सरकार के हाथ मे है। इसी प्रकार सरकार न केवल परमाणु शक्ति के विकास मे, बल्कि सौर शक्ति, शिला-तेल (शेल ऑयल) के निष्कर्षण और कोयले के हाइड्रोजनीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानो मे भी सक्रिय रही है। पेट्रोलियम उत्पादको को कर सम्बन्धी बहुत-सी रियायते दी गई हैं ताकि वे इस आवश्यक ईधन और रासायनिक कच्चे माल का उत्पादन बढाएँ। ताँबा, चाँदी, यूरेनियम आदि अनेक धातुओ के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार ने करो मे रियायत, अधिदान (बाउटी), तटकर सम्बन्धी सरक्षण, सामरिक महत्त्व की वस्तुओं के भण्डारण के लिए खरीद आदि उपाय अपनाये है। किन्तु सहायता के इन उपायो मे से कुछ का आर्थिक दृष्टि से औचित्य सन्दिग्ध प्रतीत होता है।

उद्योगों को प्रोत्साहन

परिवहन के विभिन्न प्रकार के साधनो के विकास और सचालन मे सरकार की सहायता ने केवल उत्पादकता मे प्रत्यक्ष सहायता ही नही दी है, वल्कि अनेक प्राकृतिक साधनो के विकास को प्रोत्साहन भी दिया है। रेलो के प्रारम्भ से पूर्व आन्तरिक परिवहन सड़को और नहरो पर अवलम्बित रहता था जिनमे से अधिकतर सघीय और राज्यीय सरकारो के अनुदानो, अनुपूर्त्तियो (सब्सिडीज) या कर सम्बन्धी रियायतो की सहायता से बनी। बहुत-सी रेलो के निर्माण मे भी इसी प्रकार की सहायता दी गई। अकेले सन् 1850 से 1871 तक सघीय और राज्यीय सरकारो ने 18 करोड 30 लाख एकड भूमि रेल कम्पनियो को मुफ्त प्रदान की और उसी का परिणाम है कि आज सयुक्त राज्य मे मुख्य रेलो का विशाल जाल फैला हुआ है। ट्रक और बस परिवहन के उद्योगो को भी, जो अपेक्षाकृत नये है, सघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो द्वारा बनाई गई और सभाली जा रही 30 लाख मील लम्बी सडको से बहुत सहायता मिली है। हाल मे ही सघीय सरकार ने एक नया सडक कार्यक्रम बनाया है जिस मे विभिन्न राज्यो से गुजरने वाली 41,000 मील लम्बी ऐसी सीधी सडके बनायी जाएँगी, जिन पर एक साथ चार गाड़ियाँ चल सकेगी और जिन्हे दूसरी सडके कही नही काटेगी। इस कार्यक्रम पर अगले 10 वर्षों मे 33 अरब डालर खर्च होगा जिसका 90 प्रतिशत भाग सघीय सरकार देगी।

सन् 1845 से समुद्री जहाजरानी उद्योग को डाक ले जाने के लिए सरकार से विशेष अनुपूर्त्ति मिल रही है। हाल मे ही प्राइवेट जहाजरानी कम्पनियो को जहाजो के निर्माण और संचालन के लिए करो मे कुछ रियायते और अनुपूर्त्तियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त कानून के द्वारा यह अनिवार्य व्यवस्था करके, कि वैदेशिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य देशो को भेजा जाने वाला 50 प्रतिशत माल अमेरिकी जहाजो मे ढोया जाएगा, प्राइवेट जहाजरानी को कुछ और भी अप्रत्यक्ष सहायता दी गई है। व्यापारिक हवाई परिवहन उद्योग को भी डाक ले जाने के

लिए दी जाने वाली अनुपूर्ति, विमान विकास ठेको, सरकारी हवाई अड्डो पर विमानो की देखरेख और स्थलीय सुविधाओं और हवाई यातायात नियन्त्रण प्रणालियो के रूप मे सरकारी सहायता दी गई है।

सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम श्रमिकों की उत्पादकता बढाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान करते है। कर्मचारियो के स्वास्थ्य और शिक्षा की वृद्धि मे अनिवार्य योग देने के साथ-साथ, सरकार के कई समाज-कल्याण कार्यक्रम भी हैं, जो उनकी कार्यकुशलता बनाये रखने मे सहायक होते हैं। इसका एक उदाहरण पुन:-प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत उन श्रमिको को प्रशिक्षण दिया जाता है जिनका कौशल नई स्वचालित मशीनो के अधिकाधिक उपयोग या अन्य कारणो से पुराना पड गया है। सरकार द्वारा श्रमिको को इच्छानुसार ट्रेड यूनियनें गठित करने और सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार की गारण्टी दी जाने से भी श्रमिको का उत्साह बढता है। यद्यपि सयुक्त राज्य मे सामूहिक सौदेबाजी विशुद्ध रूप से मजदूरो और मालिको के बीच का मामला है, तो भी यदि सरकार से प्रार्थना की जाय तो वह मध्यस्थता, आपसी सुलह और पंच-निर्णय के लिए सेवाएँ प्रदान करती है।

प्रबन्धको और व्यापारिक उद्यमो को सरकार द्वारा दी जाने वाली अनेक सेवाएँ अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान करती है। इनमे सबसे महत्वपूर्ण अनेक प्रकार की साख्यिकी और सूचना सम्बन्धी सेवाएँ है। इस प्रकार की पथप्रदर्शक सेवाएँ प्रबन्धको को न केवल बाजारो के दीर्घकालिक विकास का पहले से अनुमान लगाने मे सहायता देती हैं, बल्कि उन्हे रोजमर्रा के कामो, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और विकास मे भी मदद देती है। यद्यपि आर्थिक परिस्थितियो और उनकी भावी सम्भावनाओ के मूल्याकन के लिए आवश्यक कुछ महत्त्वपूर्ण आकडो और सामग्रियो का अब भी अभाव है, उदाहरण के लिए बचतो और उपभोक्ताओ के खर्च के बारे मे पर्याप्त आकडे उपलब्ध नही है, तो भी सरकारी सस्थाएँ जो कुछ भी जानकारी उद्योग और व्यवसाय को मुफ्त दे रही हैं, वह अमेरिकी व्यवसाय-प्रणाली के सफल सचालन के

लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। उद्योग-व्यापार को दी जाने वाली सरकारी सहायता का दूसरा उदाहरण है मानक कार्यालय (ब्यूरो ऑफ स्टैण्डर्डस) द्वारा दी जाने वाली सहायता जिससे अनेक नये और पुराने उत्पादनो के मानक निर्धारित किये जाते है। एक अन्य मोर्चे पर भी सरकार सहायता देती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धो की स्थापना और वृद्धि एवं निर्णय के लिए बाजार तैयार करने मे सक्रिय भूमिका अदा करने के साथ-साथ वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियो मे भी हिस्सा लेती है, जिससे प्राइवेट अमेरिकी व्यवसायो को विदेशी ग्राहक प्राप्त करने मे प्रोत्साहन मिलता है।

पिछले दो दशको मे सरकार ने वैज्ञानिक अनुसन्धान और नई औद्योगिक विधियो के विकास मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सहायता दी है उसने खास तौर से अमेरिकी उत्पादकता को बढाने मे बहुत बडा योग दिया है। जिस नई उद्योग-विद्या (टैकनोलॉजी) की बदौलत आज अमेरिका मे तथाकथित 'दूसरी औद्योगिक क्रान्ति' सम्भव हो रही है, वह इलेक्ट्रानिकी, कृत्रिम और नई वस्तुओ का निर्माण, स्वचालित गणक यन्त्रो और नियन्त्रण उपकरणो का आविष्कार और परमाणु शक्ति आदि क्षेत्रो मे प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयोजनो के लिए सरकार की दिलचस्पी का ही परिणाम है। किन्तु सरकार ने असैनिक किस्म के भी ऐसे अनेक अनुसन्धान कार्यक्रम चलाये हैं या उनके लिए धन दिया है, जिन्होने प्रकृति मे पाये जाने वाले विपुल साधनो के नये या अधिक कौशलपूर्ण उपयोगो की खोजकर प्रमुख उद्योगो मे महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रियाएँ पैदा की है। यहाँ तक कि जब कोई अनुसन्धान कार्यक्रम विशुद्ध रूप से प्राइवेट उद्योगो द्वारा ही चलाया जाता है, तब भी कर सम्बन्धी अनुकूल व्यवस्थाओ के द्वारा सरकार का प्रोत्साहन उसमे मौजूद रहता ही है।

पूँजी की उपलब्धि मे वृद्धि

सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम पूंजी की उपलब्धि को बढाने में भी सहायता देते हैं। प्रारम्भ मे सरकार ने कृषि के लिए, ऋण की सुविधाएँ

देना शुरू किया था, लेकिन सन् 1930 से प्रारम्भ दशक के मन्दी के वर्षो मे प्राय सभी प्रकार के व्यवसायो के लिए सरकार ऋण देने लगी।

सन् 1930 के दशक मे गृह-निर्माण के लिए धन की सहायता देने का जो कार्यक्रम सरकार ने प्रारम्भ किया था वह अब स्थायी कार्यक्रम बन गया है। यह सरकारी नीति और प्राइवेट व्यवसाय के पारस्परिक सहयोग का एक विशिष्ट उदाहरण है। प्राइवेट ठेकेदार मकान बनाते हैं और उनके लिए धन का प्रबन्ध उन्हे गिरवी रखकर करते है। लेकिन गिरवी रखने की शर्ते क्या हो, बीमा और गारण्टी कार्यक्रमो के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मकान किस किस्म के हो और इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था से बनाये जाने वाले मकानो का स्टैण्डर्ड क्या हो, इन सब बातो मे सरकार का स्पष्ट निर्णायिक प्रभाव रहता है। सघीय आवास प्रशासन और भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास प्रशासन मामूली-सा शुल्क लेकर प्राइवेट गृह-निर्माण के लिए गारण्टी और बीमा करके सहायता प्रदान करते है और कृषि के अलावा शेष आवासगृहो का 40 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा की गई इस गारण्टी और बीमे के आधार पर गैरसरकारी पैसे से बनता है। कृषि ऋण प्रशासन और कृषक आवासगृह प्रशासन लोगो को कृषि-भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने, उसे सुधारने, फार्मों मे रिहायशी मकान या अन्य इमारते बनाने और फार्मो को चलाने के लिए ऋण के रूप मे सहायता देते है।

सरकार के समस्त ऋण कार्यक्रमो के महत्त्व को इस तथ्य से आका जा सकता है कि 31 दिसम्बर, 1960 को लोगो से सरकारी ऋणो की वसूली की बकाया रकम 21 अरब 90 करोड डालर थी, जो सभी प्रकार के कुल प्राइवेट ऋणो का 4 प्रतिशत थी। इसके अलावा सरकार ने जिन ऋणो का बीमा या गारण्टी की हुई थी उनकी मात्रा भी 70 अरब डालर यानी कुल प्राइवेट ऋणो का 13 प्रतिशत और थी। सघीय जमाखाता बीमा निगम (फेडरल डिपोजिट इन्शोरेन्स कार्पोरेशन) आदि कुछ अन्य सगठन स्थापित करके अमेरिका मे ऋण व्यवस्था को और भी सुदृढ कर दिया गया है। यह निगम 10,000 डालर प्रति खाता तक बैंको मे

जमा रकमो का बीमा करता है।

पूर्ण रोजगार और आर्थिक अभिवृद्धि की समुन्नति

सन् 1946 मे रोजगार अधिनियम पास कर सरकार पर यह जिम्मेदारी डाली गई थी कि वह 'रोजगार, उत्पादन और क्रयशक्ति को उच्चतम स्तर तक' समुन्नत करने की नीति निर्धारित कर क्रियान्वित करे। यद्यपि सरकारे अमेरिका के समूचे इतिहास मे अर्थ-व्यवस्था के कुछ खण्डो को समुन्नत करती रही है किन्तु इस अधिनियम से आम और समग्र आर्थिक अभिवृद्धि और स्थिरता की नीति अपना कर एक नई जिम्मेदारी सरकार पर डाली गई। लेकिन इस नीति का अर्थ उद्योग-व्यवसाय, श्रमिक वर्ग या उपभोक्ताओं के निश्चयो मे किसी तरह का हस्तक्षेप करना नही है—यह नीति सरकार के मौजूदा अधिकार के भीतर ही सामान्य वित्तीय और आर्थिक उपायो और अन्य कार्यक्रमो के द्वारा परिचालित की जाती है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे सरकार क्या हिस्सा लेती है, इसका सर्वोत्तम अनुमान राष्ट्रीय आर्थिक लेखे या राष्ट्र के आर्थिक बजट से लगाया जा सकता है। इन बजटो का अध्ययन करने से मालूम होगा कि सन् 1929 मे जहां संघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो के बजटो की कुल राशि, चालू डालर मूल्य के हिसाब से, कुल राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत थी, वहाँ 1960 मे वह बढकर 27 प्रतिशत हो गई। इन 27 प्रतिशत मे सरकार द्वारा की गई माल की समस्त खरीद, सरकारी कर्मचारियो को दिये गए वेतन और किसानो, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्तियो, भूतपूर्व सैनिको और सरकारी बॉण्डधारियो को दी जाने वाली रकमे भी शामिल है। सरकारी गारण्टियो या बीमो के द्वारा सहायता-प्राप्त लेन-देन—उदाहरणार्थ संघीय आवास प्रशासन द्वारा मकान गिरवी रख कर दिये गए ऋण—अर्थ-व्यवस्था के प्राइवेट खण्ड मे होते रहे है। इसलिए यदि इन लेन-देनो को भी शामिल कर लिया जाय, तो इसका अर्थ यह होगा कि आर्थिक बजट अमेरिकी अर्थ-

तालिका 11

राष्ट्र के 1929, 1960 और 1970के बजट

(राजस्व प्राप्तिओं और राजस्व व्यय का मुख्य-मुख्य क्षेत्रो मे प्रतिशत विभाजन)

आर्थिक वर्ग	1920 वास्तविक आय	1920 वास्तविक व्यय	1960 वास्तविक आय	1960 वास्तविक व्यय	1970 आनुमानिक आय	1970 आनुमानिक व्यय
उपभोक्ता (स्वायत्त आय और उपभोग व्यय)	79·6	75·7	69 8	65·2	68 8	62 9.
व्यापार (अवतरित आय और आन्तरिक निवेश)	11 0	15·5	10·3	14·5	9 9	15·2
शुद्ध विदेशी निवेश	—	0·7	0 3	0·6	0 1	0 7
सरकार (अन्तरण, व्याज और अनुपूर्त्तियो महित)	10·7	9 7	27·5	27 2	27 7	27·5
(अन्तरण, व्याज और अनुपूर्तियो को निकाल कर)	1·6	1·6	7 3	7·3	6·5	6·5
सरकार (शुद्ध प्राप्तियाँ और सामान और सेवाओ की खरीद)	9·1	8·1	20·2	19 9	21 2	21·2
आकडो सम्बन्धी अशुद्धि	+0 3		—0·6	—0·2		
कुल राष्ट्रीय आय	100 0	100 0	100·0	100 0	100 0	100·0

नोट : चालू डालर मूल्य के हिसाब में आंकड़ों के लिए देखिये परिशिष्ट तालिका 20 ।

व्यवस्था पर सरकार के प्रभाव को उस अंश तक कम प्रदर्शित करता है, क्योकि ये लेन-देन उसमे शामिल नही है।

सरकारी कार्यवाही के प्रति रवैया

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था गतिशील है और उसके विभिन्न प्रमुख वर्गों के आपसी सम्बन्ध निरन्तर बदलते रहते है, इसलिए यह सम्भव है कि किसी समय सरकार अर्थ-व्यवस्था मे बहुत कम भाग ले रही हो अथवा बहुत अधिक भाग ले रही हो—और यह भी हो सकता है कि एक ही समय मे किसी विशिष्ट क्षेत्र मे वह बहुत अधिक काम करने की दोषी हो और दूसरो मे बहुत कम काम करने की। इस प्रकार सरकार की किन्हीं विशिष्ट नीतियो और कार्यक्रमो को लेकर मतभेद और विवाद की हमेशा गुंजायश है। लेकिन हितो और विचारो के ये भेद लोकतन्त्र का सार-तत्व है।

यह महत्त्वपूर्ण बात है कि ये मतभेद आमतौर पर दूर होते रहते हैं और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की मूल आर्थिक परम्पराएँ इन विवादो की लपेट मे नही आती। उदाहरण के लिए सयुक्त राज्य के किसी भी महत्त्व-पूर्ण राजनीतिक दल या वर्ग ने उद्योगो के राष्ट्रीयकरण की हिमायत नहीं की। वास्तव मे, व्यवसायी वर्ग और श्रमिक वर्ग, दोनो ही राष्ट्रीय-करण के विरोधी रहे है। दोनो ही यह अनुभव करते है कि राष्ट्रीयकरण से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नष्ट हो जाएगी और यदि दोनो पक्ष सरकार द्वारा बनाये गए नियमो और विनियमो के अन्तर्गत वेतन, काम के घटे और काम की परिस्थितियो के बारे मे परस्पर सौदेबाजी के लिए स्वतन्त्र रहे तो दोनो पक्षो का आर्थिक हित अधिक अच्छी तरह समुन्नत हो सकता है।

सयुक्त राज्य आर्थिक क्षेत्र मे स्वतन्त्र उद्यम और सरकारी उत्तर-दायित्व के सर्वोत्तम समन्वय के लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि सरकार कभी-कभी शक्तिशाली आर्थिक हितो के दवाव मे आ जाती है और ऐसा लगता है कि उसकी नीतियाँ और कार्य-

क्रम कुछ थोड़े-से सविशेषाधिकार (प्रिविलेजड) व्यक्तियो को लाभ पहुँचाने के लिए ही बनाये गए हैं। दूसरी ओर कुछ लोगो का खयाल यह है कि सरकार कभी-कभी अर्थ-व्यवस्था मे इतना अधिक उग्र और हस्तक्षेपपूर्ण रुख अपनाती है कि निजी उद्यम की स्वतन्त्रता और ओजस्विता खतरे मे पड़ जाती है। अब ऐसा लगता है कि सयुक्त राज्य एक ऐसी स्थिति मे पहुँच रहा है जिस में न तो व्यवसायी, श्रमिक और कृषक वर्ग का और न ही सरकार का मुख्य प्रभाव रह जायेगा। हरेक क्षेत्र शक्तिशाली और गतिशील है और सभी यह महसूस करते हैं कि यदि उनमे से किसी ने भी कोई ऐसा काम करने की चेष्टा की जो आम जन-कल्याण पर बुरा असर डालेगा, तो उसे दबा दिया जाएगा। इस स्थिति का एक महत्त्व-पूर्ण परिणाम यह हुआ है कि इन सभी वर्गो मे पारस्परिक विश्वास बढा हैं और इस विश्वास के फलस्वरूप व्यवसाय प्रबन्धको, श्रमिको, कृषको, विभिन्न पेशो के लोगो और सरकारी प्रशासको का हौसला बढा है और उसने अमेरिकी उत्पादकता मे महत्त्वपूर्ण योग दिया है।

सारांश

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता को बढाने मे सरकार के योग-दान के विभिन्न पहलुओ से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि उसके आर्थिक लेन-देन का अधिकतर भाग लोगो के निजी अभिक्रम और चयन का परिणाम है, तो भी सयुक्त राज्य मे आर्थिक क्षेत्र मे पूर्ण बन्धन-हीन व्यापार नीति यानी सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण स्वतन्त्रता नही है। सरकार का उत्तरदायित्व—जो आहिस्ता-आहिस्ता अनेक प्रकार के परीक्षण और गलतियाँ करने के बाद एक निश्चित रूप धारण कर सका है—यह है कि वह अर्थ-व्यवस्था के लिए उन साधनो, सेवाओ, प्रोत्साहनो और नियम-विनियमो को प्रस्तुत करे जिनके बिना निजी म वाली अर्थ-व्यवस्था न तो स्वय अच्छी तरह चल सकती है और न का आम हित साधन कर सकती है। वास्तव मे ऊपर जो उदाह-दिये गए हैं, उनसे निकलने वाला निष्कर्ष केवल सयुक्त राज्य के लिए

ही नही अन्य देशो के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। वह निष्कर्ष यह है कि आर्थिक प्रक्रिया के कुछ पहलुओ में सरकार का सक्रिय और बुद्धिमत्तापूर्ण भाग लेना एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था के लिए, जो बुनियादी तौर पर निजी उद्यम वाली अर्थ-व्यवस्था है, असगत नही है, बल्कि बीसवी शताब्दी के मध्य मे जैसी परिस्थितियाँ है, उनमे वह निजी उद्यमो के प्रभाव ढंग से काम करने के लिए अनिवार्य भी है।

8

मूल्य और संस्थाएँ

अमेरिकी उत्पादकता के उच्च स्तर के प्रमुख कारणो का जो विवरण हमने दिया है उससे यह अब भी स्पष्ट नही होता कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था, मात्रा को छोडकर अन्य वातो मे, अन्य पश्चिमी लोकतन्त्रीय देशो की अर्थ-व्यवस्था से क्यो भिन्न है। वह उनसे भिन्न है इससे तो इन्कार किया ही नही जा सकता। अन्य देशो से अमेरिका मे आने वाले अनेक लोगो का कहना है कि वे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की अनेक विशेषताएँ देखकर चकित रह गए। उसकी गतिशीलता, प्रतिस्पर्धात्मकता, आय का अपेक्षाकृत अधिक समान और न्यायपूर्ण वितरण, उसका लचकीलापन और सूझ-बूझ देखकर उन्हे वहुत आश्चर्य हुआ।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था सम्वन्धो और मूल्यो की उस अधिक व्यापक प्रणाली का, जिससे सव मिलाकर अमेरिकी समाज का निर्माण हुआ है, एक अविच्छिन्न अग है। आर्थिक और आर्थिकेतर तत्वो के अन्त सम्वन्ध बहुत जटिल है। किन्तु इन सम्बन्धो के एक अत्यधिक सरल और आत्मगत दृष्टि से किये गए वर्णन से भी उन अमेरिकी अभिवृत्तियो और परम्पराओ का कुछ सकेत मिल जाएगा, जिनमे अमेरिकी आर्थिक गतिविधियो मे अन्तर्हित भावना का पता चल सकता है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता के उच्च स्तर की व्याख्या करने वाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्वो मे इन मूल्यो का स्थान है।

अमेरिका मे एक नई शुरूआत

ऐतिहासिक दृष्टि से देखे तो अमेरिका की एक मूल अभिवृद्धि वह ` राइनहोल्ड नीबूर ने 'एक नई शुरूआत' की आशा कहा है। । विचार को उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे गोएते ने इन शब्दो मे

व्यक्त किया था :

> अमेरिका, तुम हो भाग्यशाली
> हमारे इस पुराने महाद्वीप से।
> नही तुम्हारे पास भग्न दुर्ग
> नही विदीर्ण असिताश्म स्तम्भ।
> तुम जी सकते हो वर्त्तमान मे,
> नही बाँध सकते है तुमको
> आशाहीन अवरोधक द्वन्द्व
> या व्यर्थ-सी गुजरी स्मृतियाँ
> गये पुराने बीते युग की।

गोएते ने सिर्फ इस सुस्पष्ट सत्य की ओर ही सकेत नही किया था कि जिस समय सर्वप्रथम यूरोपीय उपनिवेशी अमेरिका के तट पर गए थे उस समय अमेरिका एक सर्वथा अक्षत प्रदेश था और इन उपनिविशियों को अपने आप को वहाँ पहले से ही विद्यमान किन्ही परम्पराओ और प्रथाओ के अनुकूल नही बनाना पड़ा। उसका अभिप्राय यह भी था कि जो लोग एक के बाद एक अमेरिका मे बसने के लिए जा रहे है, वे अपनी निज की संस्कृतियों के उन पहलुओ को अपने पीछे ही छोड़कर जा सकते हैं, जिन्हे वे अपने लिए सबसे अधिक अवरोधक समझते है।

राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट का भी एक अन्य प्रसग में एक बार कहा गया यह प्रसिद्ध कथन है कि "सभी अमेरिकी आप्रवासी या उनके वंशज है।" कुछ लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध आते थे—ये लोग औपनिवेशिक युग के गुलाम और करारबद्ध कर्मचारी थे। किन्तु प्रारम्भिक आगन्तुकों से लेकर वर्तमान आप्रवासियों तक अधिकतर आदमी स्वेच्छा से ही यहाँ आते थे। ये लोग अपनी उन परम्पराओं को, जो अर्थहीन हो गई थीं, अपने पुराने देशों में छोड़कर नये रवैयों, नये रीति-रिवाजों और नई परम्पराओं को विकसित करने और अपनाने का साहस लेकर आये थे। अमेरिका ने इन लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक नया अवसर प्रदान किया।

कुछ लोगो के लिए यह नई शुरुआत मुख्यत धार्मिक या राजनीतिक थी और कुछ के लिए वह मुख्यत. सामाजिक और आर्थिक शुरुआत थी। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे थे जिनके लिए यह शुरुआत इनमे से विभिन्न प्रयोजनो के या कुछ सर्वथा नये प्रयोजनो के मिश्रण के रूप मे थी। जो लोग धार्मिक अत्याचारो से बचने की इच्छा से आये थे उनके लिए यहाँ आने का प्रयोजन यह आशा थी कि अन्तत इस नई बस्ती मे धार्मिक पूजा की पूरी स्वतन्त्रता स्थापित होगी। जो लोग स्व-शासन की आकाक्षा लेकर आये थे उन्होने अमेरिकी उपनिवेशो मे स्थानीय शासन की और फिर प्रतिनिधि शासन की नई सस्थाओ का विकास किया। और अन्त मे, जो लोग आर्थिक स्वतन्त्रता और अपनी सामाजिक स्थिति मे सुधार की इच्छा मन मे लेकर आये थे, उनमे ऐसी व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाएँ पैदा हुई जो वशानुगत सामाजिक और पारिवारिक स्थिति या कानूनी और आर्थिक निर्योग्यताओ (डिसेबिलिटी) की सीमाओ का बन्धन स्वीकार करने के लिए तैयार नही थी।

इस प्रकार पिछले 350 वर्षों मे जो लोग अमेरिका के तट पर आकर उतरे उनकी प्रधान आकाक्षा यह थी कि वे यहाँ ऐसे नये समाज का निर्माण कर सकेंगे अथवा यहाँ उन्हे ऐसा समाज बना-बनाया मिलेगा जिसमे स्वावलम्बी और जिम्मेदार व्यक्ति स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सकेगा। यह स्वतन्त्र जीवन पुराने परम्परागत समाजो और उनकी पहले से ही निर्धारित और बधी-बधायी पद-सोपान प्रणाली (हायरार्की) की सीमाओ मे जकडा हुआ नही होगा। यह सही है कि अमेरिका मे भी धार्मिक एकरूपता, केन्द्रीकृत अल्पतन्त्रीय शासन प्रणाली (ओलिगार्की), सामन्ती भूमि पट्टेदारी और वाणिज्यकीय व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिबन्ध कायम करने की अनेक कोशिशे की गई। किन्तु अन्त मे धार्मिक विविधता और समानता सार्व मताधिकार और विकेन्द्रित स्थानीय शासन, व्यावसायिक उद्यम की स्वतन्त्रता और समुचित सामाजिक सचलता की ही विजय हुई।

प्रारम्भिक अमेरिकी परिस्थितियाँ

इस स्पष्ट और विशिष्ट विकास में इस बात से भी सहायता मिली कि अमेरिका मे आने वाले नये लोगों के लिए एक विशाल भूखण्ड खुला पडा था जो गैर-आबाद था और जिससे उनके लिए जीवन की नई शुरूआत के लिए भौतिक साधन उपलब्ध थे। यदि धार्मिक एकरूपता, सत्तावादी शासन प्रणाली या अनुचित प्रतिबन्धयुक्त आर्थिक व्यवस्था थोपने की कोई कोशिश की जाती तो जो लोग उससे असन्तुष्ट होते या उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध न कर पाते वे उस प्रदेश को छोड़कर अमेरिकी महाद्वीप के विस्तीर्ण खुले और गैर-आबाद भूखण्ड मे किसी और प्रदेश की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते ताकि वहाँ फिर जीवन की नई शुरूआत कर सके। वास्तव मे लोगो के फैलने के लिए इतने विशाल भूखण्ड की उपलब्धि और उनके प्रसार की सम्भावनाओ के कारण ही अनेक बार इस प्रकार के प्रतिबन्ध थोपने के प्रयत्न छोड़ देने पड़े।

लोगो मे सिर्फ आबाद फार्मों और कस्बो की सीमा से परे नये गैर-आबाद इलाको मे फैलने का उद्यम ही नही था, बल्कि देश के आबाद इलाको मे भी उन्हे हमेशा ऐसी नई-नई दिशाएँ और क्षेत्र मिलते रहते थे जिनमे वे अपने आर्थिक उद्यम का विस्तार कर सकते थे। विस्तार का यह क्षेत्र आज भी विद्यमान है और उपक्रमी और साहसी लोग उसका लाभ उठा सकते है। आज भी व्यक्ति अपनी प्रकृति और अनुभव के अनुसार अपने लिए जीवन की नई शुरूआत करने के लिए किसी नये क्षेत्र को ढूढ सकता है।

किन्तु अतीत मे भौगोलिक दृष्टि से विस्तीर्ण गैर-आबाद क्षेत्र मे फैलने की सम्भावनाओ ने एक विशिष्ट अमेरिकी चरित्र के विकास को प्रभावित किया। नये आबाद प्रदेशो के लिए आवश्यक जीवन-पद्धति ने कुछ ऐसे चरित्र लक्षणो और सामाजिक अभिवृत्तियो को प्रोत्साहित किया जिन्होने अमेरिका मे 'एक अच्छे समाज' की निश्चित कल्पना लोगो के मन मे पैदा की। एक ओर नये इलाको के जीवन के खतरो, कठिनाइयो और सकटो का सफलतापूर्वक सामना करने की आवश्यकता ने **लोगो में**

स्वावलम्बन, सूझबूझ, व्यावहारिकता और विविध प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा की। दूसरी ओर पारस्परिक सहायता और सामाजिक सहयोग की प्रवृत्ति को भी बढावा मिला क्योकि जमीन को खेती के लिए साफ करना, घर बनाना, परिवहन की सुविधाओ की व्यवस्था करना, और समाज को मानवीय और प्राकृतिक शत्रुओ से बचाना—ये सब काम ऐसे थे जो अकेले किसी एक व्यक्ति या परिवार के बस के नही थे। इसके अलावा प्रारम्भिक स्थानीय शासन सस्थाएँ कायम करने और क़ानून और व्यवस्था की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी भी आमतौर पर स्वयं वहाँ आबाद अधिवासियो की ही थी। इनसे विकेन्द्रित आधार पर फ़ैसले करने की प्रवृत्ति और लोकतन्त्रीय ढग के राजनीतिक जीवन को प्रोत्साहन मिला।

लेकिन सिर्फ नये-नये गैर-आबाद सीमावर्त्ती क्षेत्रो की परिस्थितियो ने ही अमेरिकी लोगो मे इन विशिष्ट चरित्रो और सामाजिक अभिवृत्तियो को जन्म नही दिया, बल्कि न्यू इग्लैड और वर्जीनिया की विशिष्ट 'विचारधाराओ' ने भी इसमे महत्त्वपूर्ण योगदान किया। न्यू इग्लैण्ड की प्यूरिटनवादी विचारधारा, मैक्स वेबर के शब्दो मे, प्रधानत 'प्रोटेस्टैट आचारशास्त्र और पूंजीवादी भावना' की उपज थी। जो व्यक्ति कठोर श्रम और मितव्ययिता के गुणो से आर्थिक क्षेत्र मे सफलता प्राप्त कर लेता था, वह यह समझता था कि वह उन थोडे-से भाग्यशाली व्यक्तियो मे से है जो मुक्ति के लिए चुने गए हैं। यद्यपि इस विचारधारा के धार्मिक पहलू का अठारहवी शताब्दी के आखिरी चरण मे अन्त हो गया, तथापि इसके मूल मे जो बुनियादी रवैया था वह न्यू इग्लैड के 'याकीवाद' के रूप मे बना रहा। इस याकीवाद की विशेषताएँ थीं स्वावलम्बन, अन्तर्भावनाशीलता, प्रतिस्पर्धात्मक विचक्षणता और उद्यमशीलता।

अमेरिकी चरित्र के निर्माण मे वर्जीनिया का योगदान था अमेरिका की परिस्थितियो मे यूरोपीय प्रबोध के सिद्धान्तो का समन्वय कर उन्हें अपनाना। थामस जैफर्सन और जेम्स मैडिसन जैसे वर्जीनियाई विचारकों

के चिन्तन और लेखन मे यह विचार प्रकट किये जाते थे । इनमे मानवीय तर्क बुद्धि की शक्ति, सामाजिक प्रगति और सुधार की सम्भाव्यताओ और व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न के अधिकारो पर बल दिया जाता था । किन्तु वर्जीनिया के इन दार्शनिको ने रूसो की इस भ्रान्त धारणा को कभी स्वीकार नही किया कि हर मनुष्य प्रकृत्या अच्छा है और उसमे पूर्णता को प्राप्त करने की क्षमता है । इसके विपरीत उनके विचार होब्स और लॉक के इस सिद्धान्त के अधिक निकट थे, और उन्होने यह चेतावनी भी दी, कि मानवीय आवेशो मे विनाश की क्षमता भी है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और समानता एव राजनीतिक सत्ता और सामाजिक व्यवस्था के बीच समुचित सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए । लेकिन बाद मे उन्नीसवी शताब्दी की समाज की वैभवशालिता और सफलता ने इन धारणाओ को व्यापक बनाया और वृद्धमूल किया कि मानवीय तर्क बुद्धि से कोई भी वस्तु परे नही है और व्यक्ति तथा समाज का एक दिन पूर्णता को प्राप्त करना अनिवार्य है । आज के अमेरिकी चरित्र मे, जो तत्वत. आशावादी और तर्कवादी है, ये विश्वास महत्त्वपूर्ण तत्व बन गए है ।

कुछ अन्य प्रभावो ने भी अमेरिकी समाज को एक निश्चित शक्ल अख्तियार करने मे सहायता दी । इनमे से एक प्रभावकारी तत्व था पारस्परिक सहिष्णुता । यह सहिष्णुता अत्यन्त आवश्यक थी, क्योकि इसके बिना इतनी विभिन्न प्रकार की सस्कृतियो, धर्मों और जातियो के लोग आपस मे सफलतापूर्वक सहयोग नही कर सकते थे, जो एक तत्वत. लोकतन्त्रीय समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य था । इसके अलावा अमरीका एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है और अन्य देशो की अपेक्षा अधिक आत्मनिर्भर है । इस तथ्य ने भी इसे ससार का सबसे बडा निर्यात व्यापार देश बनाने मे सहायता दी । इन तथा कुछ अन्य तत्वो ने मिलकर अमेरिकी समाज को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया ।

अमेरिका की देशज विशिष्टताओं का प्रभाव

इस प्रकार अमेरिकी समाज मे प्रारम्भ से ही कुछ-न-कुछ यह विशेषता रही कि वह अतीत के बजाय वर्तमान और भविष्य की ओर दृष्टि रखता था। उसकी प्रवृत्ति विरासत मे पाई हुई प्रथाओ और अमूर्त सिद्धान्तो के बजाय वर्तमान स्थिति के तथ्यो के आधार पर विचार और कर्म करने की थी। उसका यह गहरा विश्वास था कि तर्कपूर्ण विचार और मानवीय कर्म व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओ को हल कर सकते है। वह समूह और व्यक्ति के हितो मे प्रतिस्पर्धा होने पर उनमे समझौता या निभाव करने के लिए उत्सुक रहता था। सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर अमेरिकी समाज आशावादी, क्रियात्मक, तर्कवादी, उन्मुक्त मन से हर विषय पर विचार करने वाला और सहकारी भावना से युक्त रहा है। उसने अन्तर्भावना के साथ निष्ठापूर्वक काम करने की प्रवृत्ति, भौतिक कल्याण, तकनीकी कौशल, व्यक्तिगत लचकीलेपन और सामाजिक एव भौगोलिक गतिशीलता को हमेशा मूल्यवान समझा है। इन मूल्यो ने अमेरिका की आर्थिक सफलता मे योग दिया है और इस सफलता ने इन मूल्यो को समृद्ध बनाया है।

अमेरिकी चरित्र की ये विशेषताएँ हमेशा लाभकारी ही नही रही। जहाँ एक ओर इन विशेषताओ के कारण अमेरिकी लोग ऐसी बहुत-सी समस्याओ से, जिन्होने अन्य देशो के लोगो को परेशान किया, बच सके या उनका समाधान कर सके, वहाँ उन्होने उनके लिए कुछ परेशानियाँ और कठिनाइयाँ भी पैदा की। उदाहरण के लिए जहाँ अतीत की उत्कण्ट भावना के अभाव ने अमेरिकी लोगो को घिसे-पिटे विचारो और पुरानी तकनीकी पद्धतियो के बन्धन से मुक्त किया, वहाँ उसने बहुत-से अमेरिकी लोगो मे उन लोगो के प्रति ईर्ष्या भी पैदा की जिनके भीतर अपनी एक सुदीर्घ और अविच्छिन्न ऐतिहासिक परम्परा की स्थायी चेतना है। इसी प्रकार जहाँ एक ओर मानवीय तर्क-बुद्धि की शक्तिशालिता और सामाजिक उन्नति की अनिवार्यता के विश्वास ने अमेरिकी विज्ञान और उद्योग विद्या को प्रेरित किया है और अमेरिकी समाज मे न्याय और जन-

कल्याण को समुन्नत किया है, वहाँ दूसरी ओर कभी-कभी उसने अमेरिकी लोगो मे यह अनुचित और घातक बेफिक्री भी पैदा की है कि अमेरिका विज्ञान और उद्योग-विद्या मे दूसरो से आगे है, इसलिए उन्हे किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नही है। उसने अमेरिकी लोगो को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र मे देश की आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय यथार्थताओ को सही रूप मे हृदयगम करने से रोका है और यही कारण है कि कभी-कभी हमने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रो मे कुछ काम निहायत ना-समझी के किये और जरूरत से ज्यादा नैतिकता के चक्कर मे पडे। और आखिरी बात यह कि जहाँ एक ओर अमेरिकी व्यक्तियो और समूहों मे परस्पर सहयोग करने और सामुदायिक जीवन मे रचनात्मक रूप से भाग लेने की वृत्ति ने विभिन्न सस्कृतियो, जातियो, वफादारियो और दिलचस्पियो के बावजूद इस बहुविध समाज को एकता के बन्धन मे बाँधे रखा वहाँ दूसरी ओर उसका एक नुकसान भी हुआ और वह यह कि व्यक्ति पर समाज के एक स्वीकृत ढाचे को अगीकार करने के लिए काफी दबाव पडा।

इन अमेरिकी अभिवृत्तियो ने, हालाकि वे बहुत प्रत्यक्ष नही है और उनके अच्छे-बुरे दोनो पहलू है, व्यवसाय और कृषि के प्रबन्ध की प्रणाली को, श्रमिको की काम के प्रति आत्मार्पण की भावना को और सरकार की नीतियो को प्रभावित करने मे महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया है। कुछ अतिशयोक्ति होने पर भी, यह बात कही जा सकती है कि बहुत-से अन्य औद्योगिक देशो मे प्रबन्धक लोगो की सबसे पहली भावना यह रहती है कि यथासभव उत्पादन की पुरानी पद्धति और ढाँचे को ही जारी रखा जाय और उसमे परिवर्तन तभी किया जाय जबकि उससे बहुत अधिक लाभ की असन्दिग्ध आशा हो। इसके विपरीत अमेरिकी प्रबन्धक पुरानी परिचित पद्धतियो और ढाँचो से चिपटे रहने के बजाय उनमे परिवर्तन करना अधिक पसन्द करते है। अमेरिका मे श्रमिक और किसान भी अन्य देशो के लोगो की अपेक्षा नई तकनीकी विधियो को अपनाने और आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अधिक तैयार रहते है। इसी तरह

किसी एक सिद्धान्त के प्रति कठमुल्लापन के अभाव और व्यावहारिकता की प्रबल भावना ने सरकार को भी ऐसी नीतियाँ अपनाने के लिए, जो आर्थिक उन्नति के लिए हितकारी हो, और ऐसी नीतियाँ बदलने या त्यागने के लिए, जो अनावश्यक और पुरानी हो गई हो, प्रेरित किया है।

हाल मे ही प्रकाशित एक रिपोर्ट मे अमेरिकी उत्पादकता के अध्ययन के लिए अन्य देशो से आये कुछ दलो के निष्कर्ष सक्षेप मे दिये गए है। इस रिपोर्ट मे अनेक विदेशी प्रेक्षको का मत इस प्रकार प्रकट किया गया है। "अमेरिका आने से पूर्व हम लोगो का खयाल था कि अमेरिका मे उत्पादकता का स्तर ऊँचा होने का कारण मशीने और यन्त्र है। लेकिन अब हमने यह अनुभव किया है कि प्रबन्धक, इजीनियर और श्रमिक सभी इस दृष्टि से सोचते है कि प्रति मानव-घटा उत्पादन बढाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से सोचने पर हर व्यक्ति उत्पादन-वृद्धि मे अपना सर्वोतम योग दे सकता है।"

सभ्यता के इतिहास मे ऐसे युग शायद ही कभी आये होंगे, और आये भी होगे तो बहुत कम, जिनमे कि जीवन की परिस्थितियाँ इतनी तेजी से और इतनी अधिक बदली हो, जितनी कि बीसवी सदी मे बदली है। वैज्ञानिक और औद्योगिकी के क्षेत्रो मे असाधारण उन्नति, प्राय सभी देशो मे प्रगति की आकाक्षाओ मे क्रान्ति, विचारधाराओ और आदर्शवादो के मौजूदा सघर्ष और आधुनिक युद्ध पद्धति की अभूतपूर्व विनाशक क्षमता—इन सब ने मिलकर लोकतन्त्री सरकारो को भी अधिकाधिक शक्ति अपने हाथ मे केन्द्रित करने को बाध्य कर दिया है। फिर भी अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली ने, अपने आधारभूत मूल्यो और सस्थाओ की बदौलत, अपनी निर्णय और कर्म की विकेन्द्रित और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को मूलत अक्षुण्ण रखते हुए इन परिवर्तित परिस्थितियो के अनुसार अपने आपको ढाल लिया है। यह सही है कि आज बीसवी शताब्दी मे जीवन की परिवर्तमान परिस्थितियो के कारण अमेरिकी लोगो के सामने ऐसे विकल्प बहुत कम रह गए है जिनमे से वे अपने लिए किसी अनुकूल

विकल्प को चुन सकते हो। किन्तु फिर भी एक अमेरिकी को, चाहे वह उत्पादक हो या निवेशक (इन्वेस्टर) या उपभोक्ता अपने भाग्य का निर्धारण करने की काफी स्वतन्त्रता है।

सारांश

सयुक्त राज्य के निजके सामाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक, और धार्मिक तत्वो ने उसके आर्थिक स्रोतो के विकास और उपयोग को समुन्नत किया है, लोगो मे परिवर्तन और नई तकनीकी पद्धतियो को स्वीकार करने की भावना उत्पन्न की है और आर्थिक प्रक्रिया मे सरकार को एक विशिष्ट रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया है। ये चीज़े अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था को सप्राण बनाने वाली 'भावना' के बड़े और अनिवार्य अग हैं। इस भावना के कारण ही हमारे युग के केन्द्रीकरण और सत्ता-वाद के प्रबल दबावो के बावजूद अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था अपनी विशिष्ट गतिशीलता, लचकीलेपन और काफी हद तक व्यापक न्याय और समानता को कायम रख सकी है। पिछले अध्यायो मे वर्णित अधिक प्रत्यक्ष आर्थिक तत्वों के अलावा अमेरिकी समाज के विशिष्ट मूल्यो और संस्थाओ ने भी अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता के स्तर को ऊँचा उठाने में सहायता दी है। ये मूल्य और सस्थाएँ अब भी मौजूद हैं और उनका स्थायित्व हमारे मन मे यह विश्वास पैदा करता है कि आगामी वर्षों में भी उत्पादकता मे वृद्धि जारी रहेगी और अगले दशक की आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ रचनात्मक और लोकतन्त्रीय ढग से हल की जा सकेंगी।

भाग 2

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की समस्याएँ और सम्भावनाएँ

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे अधिकतर उत्पादक—श्रमिक और प्रबन्धक, दोनो—उद्योगविद्या और प्रबन्ध कला की नवीनतम उन्नत विधियो के उपयोग से सृजनात्मक सफलताएँ प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। यद्यपि अमेरिकी लोग इस स्थिति पर गर्व कर सकते हैं तो भी वह सर्वथा निर्दोष नही है। अपनी रिपोर्ट के इस भाग मे हम इसके असन्तोषकारक होने के कुछ कारणो की ओर सकेत करेंगे और साथ ही यह भी बताएँगे कि उन्हे दूर करने के लिए क्या नीतियाँ अपनाने का प्रस्ताव किया गया है।

अमेरिकी समाज मे स्वभावत बद्धमूल आत्मालोचन और समाज-सुधार की क्षमता को पूरी तरह हृदयगम नही कर सके है।

अमेरिका के इतिहास मे एक के बाद एक सुधार की जो अनेक लहरें आयी है, वे किन्ही अमूर्त्त-सिद्धान्तो की प्रेरणा का परिणाम नही थी, बल्कि वे कुछ खास दुरुपयोगो और वास्तविक त्रुटियो को दूर करने की इच्छा का परिणाम थी, जिनका अमेरिकी समाज के लोकतत्रीय और व्यक्तिवादी आदर्शो के साथ मेल नही था। और फिर ये सुधार हमेशा एक ही स्रोत से उद्भूत नही हुए।

सुधार के इन युगो मे देश भर मे विभिन्न वर्गों, समूहो और राजनीतिक दलो मे तरह-तरह के और हमेशा बदलते रहने वाले गठबन्धन हुए और उनके फलस्वरूप सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रो मे बहुत-सी सफलताएँ प्राप्त की गईं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियो मे ही नही, उनके पूर्ववर्त्ती राजनीतिक दलो मे भी हमेशा दो वर्ग रहे, एक उदार और दूसरा अनुदार। इनके अलावा अन्य दल, जिनमे ये दो वर्ग नही थे, अपने कार्यक्रमो के कुछ अशो मे सिर्फ तभी सफलता प्राप्त कर सके जब कि उन्होने या तो इन दो बडे राजनीतिक दलो मे से किसी एक के साथ गठबन्धन किया या उनमे से किसी मे विलीन हो गए। लेकिन अक्सर उनके अस्तित्व ने डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टियो को सुधार सम्बन्धी कानूनो की वकालत के लिए प्रोत्साहन अवश्य दिया।

इन सुधारो और परिवर्तनो के समर्थको मे विविध प्रकार के लोगो के होने के कारण सुधार के युगो मे हुए अधिकतर परिवर्त्तन विभिन्न विचारो के बीच समझौते द्वारा मध्यमार्ग निकालकर ही किये गए। एक ओर अमेरिकी लोगों का यह व्यापक विचार है कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति के लिए समान अवसर मिलने चाहिएँ। उनका मत है कि व्यक्ति की और समाज की स्थितियो को सुधारना सम्भव भी है और उचित भी और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जनता को अपनी स्थिति मे सुधार करने के लिए सहायता दे और उसके लिए अवसर प्रदान करे। दूसरी ओर अमेरिकी लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए

भी बहुत चिन्तित है, उनका विश्वास है कि सरकार जनता की सहायक है, मालिक नही और जो भी सुधार होना हो, वह मुख्यत: स्वय जनता की इच्छा और प्रयत्न का ही परिणाम होना चाहिए। अभिप्राय यह कि अमेरिकी समाज मे सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बीच जो सृजनात्मक सघर्ष चल रहा है उसीके फलस्वरूप अत्यधिक केन्द्रीकृत सत्तावादी सस्थाओ का सहारा लिये बिना भी अमेरिकी लोग इतने अधिक लाभ प्राप्त कर सके है।

अमेरिका मे सबसे पहला बडा सुधार-आन्दोलन सन् 1800 से 1840 तक की अवधि में हुआ। दो राष्ट्रपतियो, जैफर्सन और जैकसन ने इस लोकतन्त्रवादी आन्दोलन का नेतृत्व किया, इसलिए उनके नामो पर ही इस आन्दोलन का नाम 'जैफर्सोनियन डेमोक्रेसी' और 'जैकसोनियन डेमोक्रेसी' रखा गया। 'जैकसोनियन डेमोक्रेसी' कुछ अधिक उग्र सुधारवादी आन्दोलन था। यद्यपि इन दोनो मे कुछ अन्तर था, फिर भी उनका कुल सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र मे वास्तविक या सम्भावित समानता की और राजनीतिक प्रक्रिया मे अमेरिकी लोगो के अधिकतर वर्गो को हिस्सा देने के उद्देश्यो की उपलब्धि हो सकी। इस आन्दोलन की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सफलताएँ ये थी: सार्विक मताधिकार, विधायको और न्यायाधीशो का जनता द्वारा चुनाव, राज्यो और स्थानीय स्वशासन सस्थाओ के शासनो पर जनता के नियन्त्रण को बढाने के लिए राज्यो के सविधानो मे संशोधन, और सारे देश मे नि शुल्क शिक्षा का आरम्भ। किसानो और शहरी श्रमिको ने जैफर्सन और जैकसन के इन लोकतन्त्रवादी आन्दोलनो को समर्थन प्रदान किया था, इसलिए उन्होने भी कुछ आर्थिक सुधार चाहे। इसके फलस्वरूप किसानो को ये लाभ प्राप्त हुए सरकार के पास पश्चिम की जो जमीन थी उनके वितरण की नीति अधिक उदार कर दी गई, उन्हे सस्ती ब्याज-दर पर ऋण आसानी से मिलने लगा, शुल्क दर मे कमी और अन्य ऐसे सरकारी-उपाय अपनाये गए जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय और देश के आन्तरिक व्यापार की शर्ते कृषि-उत्पादको के लिए अधिक अनुकूल होती थी।

श्रमिको को, खासकर उत्तर-पूर्व के नव-स्थापित कारखानो मे काम करने वाले श्रमिको को भी काफी लाभ प्राप्त हुआ। उन्हे राज्यीय और स्थानीय शासनो के उन कानूनो को रद्द कराने और न्यायालयो के उन फैसलो को उलटवाने मे सफलता मिल गई, जो उन्हे ट्रेड यूनियने बनाने और हडताल करने से रोकते थे।

सन् 1840 से प्रारम्भ दशक के आखिरी वर्षों मे दास-प्रथा के प्रश्न को लेकर आन्दोलन छिडा और उससे राजनीतिक पार्टियो और उनके कार्यक्रमो का फिर नये सिरे से गठन होने लगा। इस आन्दोलन के फल-स्वरूप राजनीतिक दलो का जो नया पुनर्गठन हुआ वह अपने आप मे सुधार का एक बडा प्रयत्न था। इसकी नाटकीय घटनाओ ने आने वाले गृह-युद्ध और पुनर्निर्माण युग मे देश के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक जीवन मे एक बडा परिवर्त्तन किया। ये वर्ष सिर्फ इसीलिए स्मरणीय नही है कि इनमे दास-प्रथा का अन्त हो गया, बल्कि इनमे रिपब्लिकन दल के पुनर्निर्माण आन्दोलन ने देश के आर्थिक और राज-नीतिक जीवन मे नीग्रो लोगो को पूर्ण और समान हिस्सा दिलाने—बल्कि देश के कुछ भागो मे एकमात्र उन्ही को ही हिस्सा दिलाने—का जबर्दस्त प्रयत्न किया, हालाकि वह सफल नही हुआ। सन् 1875 तक उत्तर मे निर्माण-उद्योगो (माल तैयार करने वाले उद्योग) का प्राधान्य हो गया था और पश्चिम मे लोगो को रहने और जोतने के लिए मुफ्त वासभूमि देने की नीति और महाद्वीप के आरपार रेलो का नया जाल बिछने से किसान, पशु पालक और खनक लोग धडाधड फैलने और आबाद होने लगे थे। इसके मुकाबले मे सयुक्त राज्य का दक्षिणी भाग बहुत समय तक आर्थिक दृष्टि से गतिहीन रहा और उस गतिहीनता की स्थिति से वह अगली शताब्दी के आरम्भ मे कही निकल सका। इन घटनाओ ने अनेक पुरानी समस्याओ को पुनर्जीवित कर दिया और नई समस्याएँ खडी कर दी और उनसे नये सुधार आन्दोलन के लिए सामग्री तैयार हो गई।

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सन् 1870 से प्रारम्भ दशक

से लेकर 1930 से प्रारम्भ दशक तक एक के बाद एक जो बहुत-से सुधार आन्दोलन हुए उनमे बहुत-सी बातें समान थी और उन सब की प्रक्रिया एक प्रकार से एक ही सम्मिलित प्रक्रिया थी। सुधार सम्बन्धी इन प्रयत्नो को राजनीतिक आन्दोलन के रूप मे सगठित करने की मुख्य प्रेरणा सबसे पहले पश्चिम के किसानो से मिली। बाद मे अन्य असन्तुष्ट वर्ग भी उनके साथ आ मिले। शुरू-शुरू के पोपुलिस्ट और प्रोग्रेसिव दल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दलो के उदार गुट और उनके अधिक उग्र पूर्ववर्त्ती दल या उनकी शाखाएँ—इन सबका बुनियादी ध्येय एक ही था कि उन अमेरिकी लोगो को अधिक सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण प्रदान कराया जाय, जो 1930 से प्रारम्भ दशक के 'नई नीति' (न्यू डील) युग मे 'विशेपाधिकार-वचित' (अण्डर प्रिविलेज्ड) कहलाते थे।

'विशेपाधिकार-वचित' शब्द की व्याख्या हर वर्ग और हर दशक मे अलग-अलग की जाती थी। उत्तर और मध्य-पश्चिम के औद्योगिक क्षेत्र मे मुख्यत औद्योगिक श्रमिक ही 'विशेपाधिकार-वचित' कहे जाते थे। प्रारम्भ मे सभी श्रमिको को इनमे गिना जाता था, किन्तु बाद मे मुख्यत बड़े पैमाने पर सामूहिक उत्पादन करने वाले और अन्य असगठित उद्योगो के मजदूर ही जिनके हितो का प्रतिनिधित्व यूनियनें नही करती थी, इन मे गिने जाने लगे। कृषि-प्रधान पश्चिम मे इस वर्ग मे किसान गिने जाते थे, मुख्यत वे किसान जो अपने पारिवारिक फार्म चलाते थे और यह अनुभव करते थे कि उन्हे अपनी उपज का वाजिब मूल्य नही मिलता और इसलिए वे उचित आय से वचित रहते है। दक्षिण मे, जो राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय था, प्रारम्भ मे असन्तुष्ट वर्ग मे छोटे गोरे किसान थे, लेकिन सन् 1930 से प्रारम्भ दशक मे स्थिति बदल गई और दक्षिण के नीग्रो लोगो की असन्तोषजनक स्थिति दक्षिणी राज्यो से बाहर ही नही, स्वयं दक्षिणी राज्यों मे भी चिन्ता का विषय बन गई। पहाडी राज्यो मे आन्दोलन कर्त्ता वहाँ के महत्त्वपूर्ण खान उद्योग थे, जो अलौह धातुओं के मूल्य बहुत अधिक गिरते ही सहायता

की माँग करते थे। इसी प्रकार प्रशान्त महासागर के तटवर्ती इलाको में व्यापारी, किसान और उपभोक्ता, सभी मिलकर यह आन्दोलन करते रहे कि उन्हे परिवहन और बिजली की सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

सुधार आन्दोलन करने वाले आम तौर पर दो तरह के कानून चाहते थे। एक तरह के कानूनो से वे 'विशेषाधिकार-वचित' लोगो के कुछ अधिकार सरकार से लागू कराना, या अधिक शक्तिशाली समूहो के अन्यायपूर्ण और अवाछनीय कामो को रुकवाना चाहते थे। इसका एक स्मरणीय उदाहरण सन् 1930 के दशक का श्रम-प्रबन्ध कानून है, जिसने न केवल श्रमिको के अपने आपको सगठित करने और अपनी पसन्द की ट्रेड यूनियन के द्वारा सौदेबाज़ी करने के अधिकार को वैध ठहराया, बल्कि इन अधिकारो को लागू करने के लिए एक सरकारी तन्त्र की स्थापना की। सामाजिक क्षेत्र मे सुधार के लिए आन्दोलन का उदाहरण वह सघीय कानून है, हालांकि वह अभी आशिक रूप मे ही सफल हुआ है, जिसके अन्तर्गत नीग्रो लोगो और अन्य जातीय तथा धार्मिक अल्पसख्यक वर्गों के साथ सभी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। रेल के किराये-भाडे की दरो आदि के नियमन और उद्योग-व्यवसायो के बड़े-बडे एकाधिकार वाले सघो के निर्माण को रोकने के लिए बनाये गए कानून भी सुधार आन्दोलन के उदाहरण है।

दूसरी तरह के कानून वे थे जिनका उद्देश्य ऐसे वर्गों के, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी या जिनकी आर्थिक सौदेबाजी की शक्ति स्वभावत बहुत कम थी, आय के स्तर को ऊँचा उठाने या उनके कल्याण के लिए सरकारी कार्यक्रम प्रारम्भ कराना था। इस श्रेणी के कानूनो मे मजदूरी की दर और काम के घण्टो के बारे मे निर्मित कानून, बुढापे और मृत्यु की दशा मे श्रमिक और उसके भरण-पोषण के लिए बीमे का कानून, गन्दी बस्तियो के उन्मूलन और अल्प-आय वर्ग के गृह-निर्माण के लिए सघीय सहायता का कानून, और इसी प्रकार खास-खास ...र्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सघीय, राज्यीय या स्थानीय ...ारा धन व्यय करने के कानून उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किये

जा सकते हैं।

यह अनवरत आत्मालोचन और उसके फलस्वरूप अमेरिकी समाज मे हुए ये सुधार मार्क्सवादियो के इन दोनो कथनो का पूर्णतः खण्डन करते है कि स्वतन्त्र उद्यम वाले समाज मे 'आम जनता के कष्टों' मे निरन्तर वृद्धि होगी और इस प्रकार के समाज मे सरकार केवल 'सत्ताधारी वर्ग की कार्यकारी परिषद्' से अधिक कुछ नही है। औद्योगिक क्षेत्र के मुखियाओं और बडी-बड़ी कम्पनियो की राजनीतिक और आर्थिक सत्ता मार्क्सवादी सिद्धान्त मे जितनी बडी और विशाल समझी जाती है, वास्तव मे वह उतनी बडी नही है। न केवल लोकप्रिय सुधार आन्दोलनों ने, जिनकी जडे कृषक और श्रमिक वर्ग मे बहुत गहरी थी, इस सत्ता को नियन्त्रित किया है, बल्कि एक-दो पीढियो के भीतर स्वय उद्योगपति ही ऐसी स्थिति मे पहुँच गए जब कि उन्होने अमेरिकी प्रणाली की सस्थात्मक खामियो को अनुभव किया और उन्हे दूर करने मे हिस्सा लेने लगे।

इसमे सन्देह नही कि कुछ ऐसे व्यक्ति, और छोटे किन्तु शोर मचाने मे तेज, समूह हमेशा रहे जिन्होने हर सुधार का जोरो से विरोध किया। कुछ सुधारो के उद्देश्यो और तरीको को लेकर भी विवाद हुए। इन मतभेदो से सिर्फ इतना ही हुआ कि काफी व्यापक रूप से आवश्यक और वाछनीय समझे जाने वाले परिवर्तनो की गति कुछ मन्द हुई, किन्तु वे उन्हे रोक नही सके। इस के अलावा अमेरिकी समाज मे ऐसा कोई बड़ा वर्ग नही था, जो परिवर्तन और सुधार का पूर्णत और बुनियादी तौर पर विरोधी रहा हो। सत्ता सभी बड़े सामाजिक वर्गों मे इस प्रकार बट गई कि देर-सवेर सभी बढते हुए सामाजिक न्याय और कल्याण मे हिस्सेदार होने लगे।

अमेरिकी समाज के सभी बडे वर्गों के लिए इस बात की परख का मौका 1930 के दशक की मन्दी के समय आया, कि वे परिवर्तन को वास्तव मे स्वीकार करते है या नही और उनमे व्यावहारिक सुधार की क्षमता है या नही। इस मन्दी मे बिक्री कम होने और परिसम्पत्ति के आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होने से व्यापारियो को लकवा-सा मार

कृषको के हाथ से उनके फार्म और बाजार निकलने लगे; श्रमिको के सामने अन्तहीन प्रतीत होने वाली बेरोजगारी का भूत मुंह बाये खडा हो गया, घरो के मालिक अपने घरो से बेदखल होने लगे और जिन लोगों ने कौडी-कौडी कर पैसा जोडा था उनकी बैंको मे जमा रकमे और बीमा पालिसियाँ देखते-देखते बैंक और बीमा कम्पनियाँ फेल होने से साफ होने लगी—इन सब आघात पहुँचाने वाली घटनाओ ने लोगो मे निराशा, मायूसी और गुस्सा पैदा कर दिया। कुछ समय तक सघीय और राज्यीय सरकारे भी कुछ नही कर सकी। उन्होंने सिर्फ लोगो से अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कहा, हालाकि वह बिलकुल बेकार था, या अपना खर्च घटा दिया अथवा कर बढा दिये, जिससे न चाहते हुए भी वस्तुओ की माँग उलटे और भी कम हो गई। इन सब सकटो के फलस्वरूप कुछ प्रेक्षक यह भविष्यवाणी करने लगे कि सयुक्त राज्य भी जल्दी ही फासिस्ट इटली, नाजी जर्मनी या कम्युनिस्ट रूस के ढग पर तानाशाही देश बन जाएगा। लेकिन अमेरिकी लोगो की एक सर्वथा नगण्य सख्या ही ऐसी थी जो ऐसे क्रान्तिकारी वामपक्षी या दक्षिण पक्षी सपने मन मे सजो रही थी।

यद्यपि अमेरिकी लोग बहुत निराश और भयभीत हो गए थे तो भी अधिकाश लोगो की दिलचस्पी समूची आर्थिक और सामाजिक प्रणाली के आमूलचूल पुनर्गठन के बजाय ऐसे तात्कालिक कदम उठाने मे थी जिनसे मन्दी के कुछ विशिष्ट प्रभाव दूर किये जा सके। उदाहरण के लिए किसानो ने यह माँग की कि कृषि-जिन्सो की कीमतो को स्थिर रखने के लिए कदम उठाये जाएँ और उन्होने फसल गिरवी रख कर जो मियादी कर्जे लिये है, उनकी मियाद बढा दी जाय। श्रमिको ने माँग की कि ऐसे नये सरकारी निर्माण कार्य खोले जाएँ जिनसे उन्हे रोजगार मिले और बेरोजगारी बीमा किया जाय एव बेरोजगारी की दशा मे उन्हे राहत दी जाय। जिन लोगो ने अपने मकान बनाने के लिए मकानों पर बन्धक-ऋण लिये थे उन्होने अपने मकानो को बचाने के लिए गारण्टियाँ चाही और जिन लोगो ने अपना पैसा बचाकर बैंको मे जमा

कराया था, उन्होंने संघीय सरकार से, जमा-खाते का बीमा करने और शेयर-बाजार पर नजर रखने की माँग की।

यह सच है कि सरकारे आर्थिक मन्दी के स्वरूप को पूरी तरह समझ नही सकी और उसके लिए उन्होने पुराने घिसे-पिटे उपाय ही अपनाये और अपने पहले के पूर्वग्रह ही कायम रखे जिसका परिणाम यह हुआ कि सन् 1930 से प्रारम्भ दशक के अन्त तक बडे पैमाने पर देश मे बेरोजगारी बनी रही। लेकिन मन्दी के प्रभावों का पूर्णत. अन्त होने मे देरी जरूर लग गई तो भी "नई नीति' के वर्षों मे कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक सुधारो के आन्दोलन, जो गृह-युद्ध के बाद के वर्षों मे बराबर अधूरे चलते आ रहे थे, कामयाब और पूर्ण हो गए।

सन् 1930 के दशक की मन्दी का प्रभाव इतना जबर्दस्त था कि लोगो ने ठोस सुधारो की आवश्यकता को बहुत उत्कट रूप मे अनुभव किया और इन सुधारो का विरोध बहुत कमजोर हो गया। नतीजा यह हुआ कि पहले जिन सुधारो को असम्भव समझा जाता था, वे बडी द्रुत गति से सम्पन्न हो गए। इसके अलावा यदि सन् 1940 और सन् 1950 के दशको मे काफी बड़ी आर्थिक उन्नति न हुई होती तो ये सुधार आन्दोलन सफल न हो पाते। एकदम मन्दी की स्थिति से पुन. आर्थिक अभिवृद्धि के युग के आगमन का परिणाम यह हुआ कि लोगो के वेतनो और आमदनियो मे बहुत बड़ी वृद्धि हुई। यदि आर्थिक अभिवृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय मे वृद्धि न होती तो वेतनो और आमदनियो मे भी इतनी वृद्धि कभी न हो पाती। आमदनियो की वृद्धि का एक परिणाम यह हुआ कि सीमित राष्ट्रीय आय के वितरण के प्रश्न को लेकर जो बहुत-से कटु विवाद उठ सकते थे, उनसे सयुक्त राज्य बच गया।

इस प्रकार अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था एक द्रुत विकास की प्रक्रिया में से गुजरती रही है—और यह विकास कभी-कभी तो इतना द्रुत हुआ है कि उस समय जो समस्याएँ बहुत तात्कालिक और विकट प्रतीत होती थी, वे एकदम स्थिति बदल जाने से निरर्थक हो गई और उनका स्थान बाद के जमाने की नई समस्याओ ने ले लिया। आर्थिक क्षेत्र की कुछ नीतियाँ

कृषको के हाथ से उनके फार्म और बाजार निकलने लगे; श्रमिको के सामने अन्तहीन प्रतीत होने वाली बेरोजगारी का भूत मुंह बाये खडा हो गया, घरो के मालिक अपने घरो से बेदखल होने लगे और जिन लोगो ने कौडी-कौडी कर पैसा जोडा था उनकी बैंको मे जमा रकमें और बीमा पालिसियाँ देखते-देखते बैंक और बीमा कम्पनियाँ फेल होने मे साफ होने लगी—इन सब आघात पहुँचाने वाली घटनाओ ने लोगो मे निराशा, मायूसी और गुस्सा पैदा कर दिया। कुछ समय तक सघीय और राज्यीय सरकारे भी कुछ नही कर सकी। उन्होने सिर्फ लोगो से अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कहा, हालाकि वह बिलकुल बेकार था, या अपना खर्च घटा दिया अथवा कर बढा दिये, जिससे न चाहते हुए भी वस्तुओ की माँग उलटे और भी कम हो गई। इन सब सकटो के फलस्वरूप कुछ प्रेक्षक यह भविष्यवाणी करने लगे कि सयुक्त राज्य भी जल्दी ही फासिस्ट इटली, नाजी जर्मनी या कम्युनिस्ट रूस के ढग पर तानाशाही देश बन जाएगा। लेकिन अमेरिकी लोगो की एक सर्वथा नगण्य सख्या ही ऐसी थी जो ऐसे क्रान्तिकारी वामपक्षी या दक्षिण पक्षी सपने मन मे सजो रही थी।

यद्यपि अमेरिकी लोग बहुत निराश और भयभीत हो गए थे तो भी अधिकाश लोगो की दिलचस्पी समूची आर्थिक और सामाजिक प्रणाली के आमूलचूल पुनर्गठन के बजाय ऐसे तात्कालिक कदम उठाने मे थी जिनसे मन्दी के कुछ विशिष्ट प्रभाव दूर किये जा सके। उदाहरण के लिए किसानो ने यह माँग की कि कृषि-जिन्सो की कीमतो को स्थिर रखने के लिए कदम उठाये जाएँ और उन्होने फसल गिरवी रख कर जो मियादी कर्जे लिये है, उनकी मियाद बढा दी जाय। श्रमिको ने माँग की कि ऐसे नये सरकारी निर्माण कार्य खोले जाएँ जिनसे उन्हे रोजगार मिले और बेरोजगारी बीमा किया जाय एव बेरोजगारी की दशा में उन्हे राहत दी जाय। जिन लोगो ने अपने मकान बनाने के लिए मकानों पर बन्धक-ऋण लिये थे उन्होने अपने मकानो को बचाने के लिए गारण्टियाँ चाही और जिन लोगो ने अपना पैसा बचाकर बैको मे जमा

कराया था, उन्होने संघीय सरकार से, जमा-खाते का बीमा करने और शेयर-बाज़ार पर नजर रखने की माँग की।

यह सच है कि सरकारे आर्थिक मन्दी के स्वरूप को पूरी तरह समझ नही सकी और उसके लिए उन्होने पुराने घिसे-पिटे उपाय ही अपनाये और अपने पहले के पूर्वग्रह ही कायम रखे जिसका परिणाम यह हुआ कि सन् 1930 से प्रारम्भ दशक के अन्त तक बडे पैमाने पर देश मे बेरोजगारी बनी रही। लेकिन मन्दी के प्रभावो का पूर्णत. अन्त होने मे देरी जरूर लग गई तो भी 'नई नीति' के वर्षो मे कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक सुधारो के आन्दोलन, जो गृह-युद्ध के बाद के वर्षों मे बराबर अधूरे चलते आ रहे थे, कामयाब और पूर्ण हो गए।

सन् 1930 के दशक की मन्दी का प्रभाव इतना ज़बर्दस्त था कि लोगो ने ठोस सुधारो की आवश्यकता को बहुत उत्कट रूप मे अनुभव किया और इन सुधारो का विरोध बहुत कमजोर हो गया। नतीजा यह हुआ कि पहले जिन सुधारो को असम्भव समझा जाता था, वे बडी द्रुत गति से सम्पन्न हो गए। इसके अलावा यदि सन् 1940 और सन् 1950 के दशको मे काफी बडी आर्थिक उन्नति न हुई होती तो ये सुधार आन्दोलन सफल न हो पाते। एकदम मन्दी की स्थिति से पुन आर्थिक अभिवृद्धि के युग के आगमन का परिणाम यह हुआ कि लोगो के वेतनो और आमदनियो मे बहुत बड़ी वृद्धि हुई। यदि आर्थिक अभिवृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय मे वृद्धि न होती तो वेतनो और आमदनियो मे भी इतनी वृद्धि कभी न हो पाती। आमदनियो की वृद्धि का एक परिणाम यह हुआ कि सीमित राष्ट्रीय आय के वितरण के प्रश्न को लेकर जो बहुत-से कटु विवाद उठ सकते थे, उनसे संयुक्त राज्य बच गया।

इस प्रकार अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था एक द्रुत विकास की प्रक्रिया मे से गुजरती रही है—और यह विकास कभी-कभी तो इतना द्रुत हुआ है कि उस समय जो समस्याएँ बहुत तात्कालिक और विकट प्रतीत होती थी, वे एकदम स्थिति बदल जाने से निरर्थक हो गई और उनका स्थान बाद के जमाने की नई समस्याओ ने ले लिया। आर्थिक क्षेत्र की कुछ नीतियाँ

अस्थायी रही, क्योंकि वे मन्दी युद्ध या इसी तरह के स्वल्पकालिक दौरो मे अपनाई गई थी, लेकिन कुछ नीतियो का अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर स्थायी असर पडा।

और परिवर्तन की यह प्रक्रिया अभी समाप्त नही हुई है। आर्थिक और सामाजिक क्षितिजो पर नई समस्याएँ उभर रही है और उनका सामना करने के लिए नई नीतियाँ अपनानी पडेंगी। हम यह दावा नहीं करते कि हमे अपनी मौजूदा और भविष्य मे दिखाई पडने वाली तमाम कठिनाइयो पर विजय पाने के उपायो की जानकारी है। आज पुरानी धारणाएँ और पुराने समाधान नई समस्याओ मे ठीक नही अटते और उनके लिए नये दृष्टिकोणो की आवश्यकता है और यही आज के जमाने की चुनौती है।

इन समस्याओ के समाधान के लिए एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने मन मे भविष्य के वाछनीय सामाजिक और आर्थिक जीवन की एक मूर्ति अकित करे। सिर्फ यह कह देना कि हर चीज का प्राचुर्य ही हमारा लक्ष्य है, काफी नही है। इसके विपरीत यह कहना अधिक स्पष्ट और सार्थक होगा कि हमारा लक्ष्य सभी लोगो की आमदनियो को जीवन-यापन के लिए अनिवार्य न्यूनतम स्तर से काफी ऊँचा उठाना है। इसी तरह यदि हम यह कहे कि हर आदमी को विश्राम के लिए पर्याप्त समय देना और उसे देश के साँस्कृतिक जीवन मे रचनात्मक ढग से भाग लेने के योग्य बनाने के लिए अच्छी व्यापक शिक्षा देना हमारा लक्ष्य है तो वह लक्ष्य हमारी पहुँच के बाहर नही होगा।

ये ऐसी आकाक्षाएँ है, जो सर्वत्र पाई जाती है। लेकिन इनके अलावा एक और लक्ष्य भी है जो ससार के अन्य भागो की अपेक्षा सयुक्त राज्य मे अधिक बार और अधिक बलपूर्वक प्रकट किया गया है। वह लक्ष्य यह है कि हर अमेरिकी के पास इतनी सम्पत्ति हो कि वह आर्थिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अनुभव करे। अमेरिकी इतिहास के प्रारम्भ से ही इस लक्ष्य को लोगो ने सामने रखा है। इस लक्ष्य की अभिव्यक्ति का एक बडा साधन सन् 1862 का होमस्टैड ऐक्ट (वासभूमि अधिनियम)

था, जिसके मूल में यह विचार निहित था कि जो भी अमेरिकी चाहे वह इतनी सम्पत्ति अवश्य प्राप्त कर सके जो उसके परिवार की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। अमेरिका में व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामित्व के द्वारा आर्थिक सुरक्षा का आदर्श इतना बद्धमूल होने का ही यह परिणाम था कि यहाँ सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के कानून बनाने का आन्दोलन यूरोप से बहुत पीछे शुरू हुआ। आज बहुत-से अमेरिकियों का यह विश्वास है कि सामाजिक सुरक्षा के सरकारी कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हैं और उन्हें इतना बढ़ाया जाना चाहिए कि व्यक्ति आपातकालीन परिस्थितियों का सामना कर सके और साथ ही उसकी जीवन-निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएँ हमेशा पूरी हो सकें। लेकिन साथ ही वे इसे भी एक अत्यधिक वांछनीय लक्ष्य बनाये रखना चाहते हैं कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास अपनी निज की सम्पत्ति हो।

आगामी अध्यायों में हम तात्कालिक महत्त्व की समस्याओं और सुदूर-भविष्य की समस्याओं, दोनों पर विचार करेंगे। हमारी तात्कालिक महत्त्व की समस्याएँ ये हैं : आर्थिक वृद्धि की गति को काफी बढ़ाना, जहाँ तक सम्भव हो पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना और कीमतों को काफी हद तक स्थिर रख सकना; एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकना; शिक्षा, अनुसन्धान और प्रशिक्षण की प्रणालियों में सुधार कर उन्हें आधुनिक उद्योग विद्या और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के अनुकूल ढालना, पूंजी, साधन और ज्ञान को एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित करना; और समाज की निरन्तर बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक साधन-सम्पदाओं का संरक्षण करना और शहरी और [illegible] भाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके नये-नये साधन विकसित करना।

अपने-अपने मोर्चों पर अपनी समस्याएँ नज़र नही आती या उनमे उनका समाधान करने की क्षमता नही है। इनमे से हरेक वर्ग को अपने आत्म-हित के लिए आर्थिक परिवर्त्तनो की मांग करने का अधिकार है और इसलिए अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के सामाजिक दृष्टि से उचित और अनुचित उपयोग मे भेद करने की भारी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है। अमेरिकी जनता की ओजस्विता, अमेरिका की राजनीतिक और सामाजिक सस्थाओ का लचकीलापन और देश का अतीत काल का विकास—ये सभी चीजें यह विश्वास पैदा करती हैं कि आर्थिक गति-विधि और आचरण के स्तर को जनता के सामान्य कल्याण के लिए ऊँचा उठाकर इन समस्याओ के प्रभावकारी और स्वीकरणीय हल निकाले जा सकेंगे।

9

आर्थिक उन्नति में सन्तुलन

उत्पादकता की भाति आर्थिक उन्नति और स्थिरता भी किसी 'प्राकृतिक' नियम से स्वतः उत्पन्न नही होती। उत्पादकता में वृद्धि के लिए ज्ञान, श्रम, प्रबन्ध, पूंजी, प्राकृतिक साधन-सम्पदा और समुचित सरकारी नीतियों के सम्मिश्रणों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उत्पादकता वृद्धि उत्पादित माल की बिक्री के लिए निरन्तर वृद्धि पर भी निर्भर करती है। अगर बहुत तेज आर्थिक उतार-चढाव आये, कीमतों में निरन्तर वृद्धि होती रहे या व्यवसाय के ढाँचे मे अपरिवर्त्तनीयता आ जाय तो उत्पादित माल की बिक्री के लिए बाजारो का विस्तार खतरे में पड़ सकता है। इसलिए, यद्यपि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे विस्तार और उन्नति की बहुत सम्भावनाएँ निहित हैं, तो भी इन तीन सम्भावित खतरो को दृष्टि मे रखते हुए यह पहले से ही निश्चित नही माना जा सकता कि अर्थ-व्यवस्था मे वृद्धि होगी ही और उसमें स्थिरता भी आयेगी ही। यह बात भी हम निश्चित रूप मे नही मान सकते कि हमारी विस्तीर्यमान अर्थ-व्यवस्था से हमे स्वतः ही वे वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध हो जाएँगी, जो हमारे अत्यन्त आवश्यक राष्ट्रीय उद्देश्यों और सामान्य कल्याण को समुन्नत करेंगी।

सम्भावित उत्पादन वृद्धि और उसका उपयोग

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे राष्ट्र के उत्पादक साधनो के उपयोग के सम्बन्ध मे तीन तरह से निश्चय किये जाते है। उपभोक्ता यह फ़ैसला करते है कि वे किस किस्म की वस्तुओं के लिए पैसा खर्च करना चाहेगे। दूसरे व्यवसायी लोग यह निश्चय करते हैं कि भावी उत्पादन और सेवाओ से लिए संयन्त्र, मशीनरी तथा अन्य पूंजीगत सामग्री में वे कैसा

और कितना धन निवेश करेंगे। और तीसरे संघीय, राज्यीय और स्थानीय शासन अपनी विधि-निर्माण और बजट की प्रक्रियाओ से सार्वजनिक सेवाओ के परिमाण और स्वरूप का निर्णय करते हैं।

ये तीनो व्यवस्थाएँ परस्पर सम्बद्ध हैं, क्योंकि एक तो समस्त उत्पादन, चाहे वह उपभोग के लिए हो, या व्यावसायिक निवेश के लिए, या सरकारी सेवाओ के लिए, किया राष्ट्र की श्रमिक शक्ति द्वारा ही जाता है, और दूसरे, किसी एक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किये गए उत्पादक साधनो और प्राकृतिक सम्पदा से दूसरी वस्तुएँ तैयार नही हो सकती, उदाहरण के लिए उपभोग्य सामग्री तैयार करने वाले साधन निवेश अथवा सरकारी सेवाओ के लिए काम नही आ सकते। सरकार स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थ-व्यवस्था मे भी अपने सरकारी व्यय कार्यक्रमो, ऋण के उपायो और अन्य नीतियो से राष्ट्र के उत्पादक साधनो के उपयोग पर प्रभाव डाल सकती है। केवल सत्तावादी (तानाशाही) देशो मे ही नही, लोकतन्त्रीय देशो मे भी सरकार के पास ऐसे अधिकार और साधन होते है, जिनसे वह इस बात के लिए अर्थ-व्यवस्था को बाधित कर सकती है कि सरकार की वैदेशिक नीति या आन्तरिक आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यो के लिए जिन वस्तुओ का उत्पादन सर्वप्रथम आवश्यक है, उन्हे वह प्राथमिकता दे। बुनियादी तौर पर ये निश्चय व्यक्तिगत रूप मे लोगो द्वारा किये जाते है। उपभोक्ता और व्यवसाय प्रबन्धक अपने आर्थिक व्यवहार द्वारा, और नागरिक अपने राजनीतिक चुनाव द्वारा, व्यक्तिगत तौर पर ये निर्णय करते है। सन् 1960 मे उपभोक्ताओ, व्यवसाय प्रबन्धको और सरकार, तीनो के द्वारा किये गए इन निश्चयो के फलस्वरूप सयुक्त राज्य मे 5 खरब 4 अरब 40 करोड डालर के सामान और सेवाओ का उत्पादन हुआ। यहाँ उन थोडे-से महत्त्वपूर्ण प्रयोजनो का अध्ययन करना दिलचस्प होगा जिनके लिए अमेरिकी जनता ने अपनी साधन-सम्पदा का बँटवारा किया।

राष्ट्र का लगभग एक-तिहाई खर्च खाना, कपडा और आश्रय की प्राप्ति के लिए किया गया; और दस प्रतिशत मकानो की सजावट, ब्याज

की अदायगी और व्यक्तिगत सेवाओ (हज्जामो की दूकानो, कानूनी सेवाओ और बीमा आदि) पर व्यय हुआ। उपभोक्ताओ ने मनोरजन, सिगरेट, शराव और जेवर आदि विलासिता की वस्तुओ पर जो खर्च किया वह शिक्षा और डाक्टरी चिकित्सा (जिसमे सरकारी और गैर-सरकारी दोनो क्षेत्रो मे शिक्षा सस्थाओ और अस्पतालो के निर्माण और संचालन का व्यय शामिल है) पर हुए कुल सम्मिलित व्यय से कुछ ही कम है। पहले लगायी गई रोको के फलस्वरूप, शिक्षा, मूल अनुसन्धान, डाक्टरी चिकित्सा एव स्वास्थ्य सम्वन्धी देख-भाल और प्राकृतिक साधनो का विकास और सरक्षण आदि महत्त्वपूर्ण मदो पर उतना व्यय नही किया गया, जितना किया जाना चाहिए था और उसमे गम्भीर कमियाँ रह गईं। इन गम्भीर कमियो पर आजकल जो चर्चा चल रही है, उस के फलस्वरूप यह सम्भव है कि भविष्य मे उन्हे पहले से अधिक महत्त्व और प्राथमिकता दी जाय। इससे अनेक सरकारी और गैरसरकारी प्रयोजनो के लिए निर्धारित की जाने वाली राशियो मे परिवर्तन हो सकते है।

आर्थिक वृद्धि और उपलब्ध धन के विभिन्न मदो मे वटवारे के दीर्घकालीन रुझानो को दृष्टि मे रखते हुए अगले दशक की सम्भावनाओ की कल्पना करना सम्भव है। यह सम्भव है कि 1970 मे सयुक्त राज्य की कुल राष्ट्रीय आय, 1960 मे प्रचलित मूल्यो के हिसाब से, 8 खरव डालर हो जाय, जव कि 1960 मे वह 5 खरव डालर के लगभग थी। परिशिष्ट तालिका 24 मे अगले दशक की सम्भावित आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इस तालिका से यह सकेत मिलता है कि सन् 1970 तक सन् 1960 की अपेक्षा 3 खरव डालर की वस्तुएँ और सेवाएँ अधिक उपलब्ध होने लगेगी।

तालिका 12

मुख्य-मुख्य प्रयोजनों के लिए राष्ट्र का व्यय, 1960

	अरब डालरों में	कुल का प्रतिशत
1 उपभोक्ताओं की मूल जरूरतें (खाना, कपडा, मकान)......	161.4	32 0
2. उपभोक्ताओं की अन्य जरूरते (घरेलू वस्तुएँ और व्यक्तिगत व्यवसाय आदि)......	54.5	10 8
3. परिवहन (खरीदे और स्वय चलाए गए वाहन)......	40 7	8.1
4. उपभोक्ताओं की विलासिता और अर्ध-विलासिता की चीजें......	41 8	8.3
5 शिक्षा (सरकारी और निजी)..................	23 2	4.6
6 अनुसन्धान और विकास....................	13 0	2 6
7. डाक्टरी चिकित्सा और देखभाल...............	27 6	5 5
8. निजी धार्मिक और परोपकार के कार्य	4 7	0 9
9. निजी पूँजी-निवेश (अनुसन्धान और विकास पर किये गए खर्च शामिल नही)	72 4	14.3
10. राष्ट्रीय सुरक्षा (अनुसन्धान और विकास के व्यय शामिल नही)......	40 4	8.0
11 अन्य सरकारी काम	23 4	4 6
12 विदेशों मे कुल निवेश...	1 5	0 3
कुल राष्ट्रीय आय[1]	504 4	100 0

1 विस्तृत जानकारी के लिए देखिये परिशिष्ट तालिका 21।

चार्ट 12

कुल राष्ट्रीय उत्पादन, 1960-1970 (संभावित)

(1960 के मूल्यों के हिसाब से)
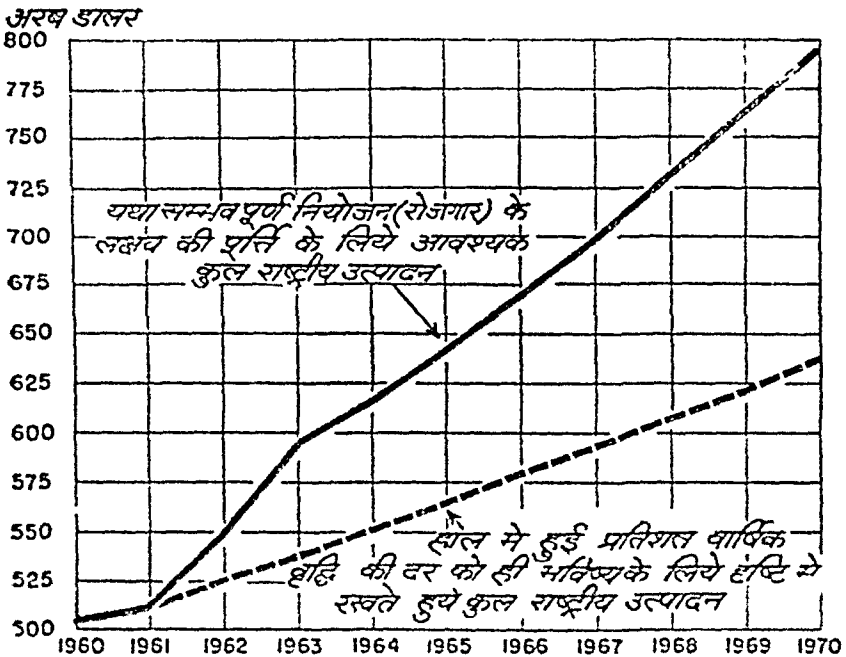
'यथासम्भव पूर्ण नियोजन' का अर्थ इतना नियोजन है कि उसमें 4 प्रतिशत से अधिक श्रमिक बेकार न हों।

उसी के हिसाब से काम के घंटो मे कम या अधिक कमी होगी। देश की श्रमिक-शक्ति मे वृद्धि, उत्पादकता मे वृद्धि और काम के घटो मे कमी के तर्क सगत अनुमानो को दृष्टि मे रखकर हमने यह हिसाब लगाया है कि सन् 1960 के बाद प्रतिवर्ष सयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्थाओ मे 4½ प्रतिशत की वृद्धि होगी और, इस प्रकार देश की आय

सन् 1970 तक सन् 1960 के मूल्यो के अनुसार 8 खरब डालर हो जाएगी, जब कि सन् 1960 मे वह 5 खरब डालर है। लेकिन यदि राष्ट्र की आय (या उत्पादन) पहले की तरह कुल 2½ प्रतिशत वार्षिक ही बढे तो सन् 1970 मे वह कुल 6 खरब 40 अरब डालर तक ही पहुँच पायेगी अर्थात् 1960 से प्रारम्भ सारे दशक मे कुल 1 खरब 40 अरब डालर की ही वृद्धि होगी। इसका अर्थ यह होगा कि वह समय आने के लिए और भी लम्बी अवधि की जरूरत होगी, जबकि हमारी महत्त्वपूर्ण जरूरते उपलब्ध साधनो से पूरी हो सके।

चार्ट 13

कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि मे कारक तत्व 1960-1970
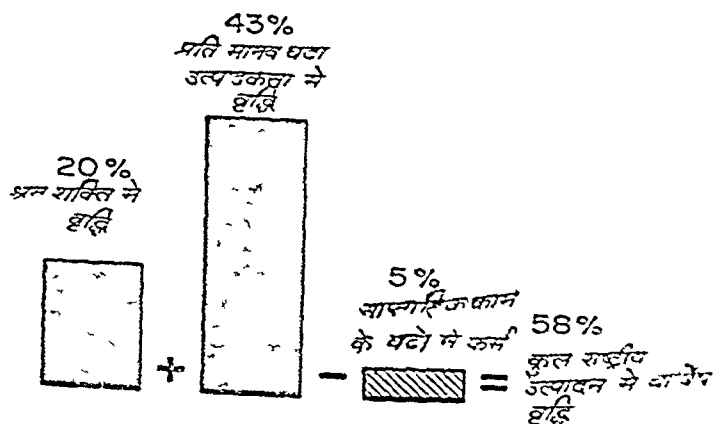
लेकिन 4½ प्रतिशत वार्षिक उत्पादन वृद्धि सम्भव तभी होगी जबकि लोगो मे अतिरिक्त उत्पादन की माँग हो। अगर यह वृद्धि हो जाय तो

सघीय, राज्यीय और स्थानीय शासन करो के रूप में 80 से 90 अरब डालर तक अतिरिक्त आय करो के रूप मे खीच लेगे। इसका अर्थ यह है कि या तो सरकार को अपने व्यय के कार्यक्रमो को काफी बढाना पडेगा या करो मे कमी करनी पड़ेगी ताकि लोगो को निजी व्यय के लिए अधिक धन उपलब्ध हो और वे उससे उपभोग्य वस्तुएँ खरीद सके या उसे बचाकर पूंजी-निर्माण मे लगा सके। अधिक सम्भावना यह है कि सरकार ये दोनो उपाय ही थोडे-थोडे अपनायेगी। वास्तव मे अपने व्यय-कार्यक्रमो मे वृद्धि और करो मे कमी से प्राइवेट व्यय को प्रोत्साहन देकर सरकार इन दोनो साधनो से वृद्धि की भावी गति को, बल्कि उत्पादन मे हुई वृद्धि के बटवारे को भी प्रभावित करती है। यह बडे महत्त्व की बात है कि लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाओ, विद्वत्तापूर्ण पुस्तको और काग्रेस (ससद्) की बहसो के जरिये इस बारे मे एक सार्वजनिक वाद-विवाद चल पडा है कि देश के सम्भावित साधनो के पूर्ण उपयोग के लिए क्या किया जाय और किन कामो को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाय।

तब यह सवाल उठता है कि सन् 1970 मे 3 खरब डालर का जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उसका उपयोग किन-किन कामो मे किया जा सकता है।

उस समय तक देश की जनसख्या मे 3 करोड 30 लाख की वृद्धि हो जाएगी। यदि हम मान ले कि उस समय भी रहन-रहन का स्तर यही रहेगा तब 65 अरब डालर की अतिरिक्त आय इस अतिरिक्त आबादी के उपभोग व्यय मे चली जाएगी। कुल उत्पादन मे इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए श्रम-शक्ति और कारखानो के सयन्त्रो और मशीनो आदि मे वृद्धि की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार सन् 1970 तक 1960 के स्तर की अपेक्षा प्रतिवर्ष सयन्त्रो, उपकरणो, रिहायशी आवास गृहो, विदेशी निवेश और शिक्षा एव अन्य- गैर-सरकारी सेवाओ के लिए 30 से 35 अरब डालर तक की अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। इसलिए अतिरिक्त आबादी और सयन्त्रो और उत्पादन क्षमता मे अतिरिक्त वृद्धि की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए 95 से 100 अरब

डालर अतिरिक्त राशि की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार यह राशि निकाल देने पर भी वस्तुओं और सेवाओं के सरकारी और गैर सरकारी उपयोग के लिए 2 खरब डालर की राशि बच जाएगी।

इस 2 खरब डालर के अतिरिक्त उत्पादन के कुछ वैकल्पिक उपयोग भी सम्भव हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यय की जाने वाली राशि के स्तर को बढ़ाने का ही सवाल है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस सम्भावित उत्पादन वृद्धि के कारण रहन-सहन के स्तर और पूंजी-निवेश के वांछनीय स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यय को बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन यदि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी हो गई और शस्त्रास्त्रों पर व्यय में कमी की जा सकी तो और भी बहुत-से आवश्यक कामों के लिए धन की ज़रूरतें ज्यादा पूरी की जा सकेंगी।[1]

राष्ट्रीय आयोजन संघ (नेशनल प्लैनिंग एसोसिएशन) की राष्ट्रीय आर्थिक प्रायोजन माला को दृष्टि में रखकर अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्राकृतिक साधन संरक्षण (खासकर जलोपलब्धि और उसका उपयोग), स्थलीय और हवाई यातायात और इसी तरह के अन्य कई उपयोगों के लिए अतिरिक्त और अधिक विस्तृत कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सन् 1960 के मूल्यों के हिसाब से करीब 69 अरब डालर के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी।[2] यह व्यय करना अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की क्षमता से बाहर नहीं है और यदि सन् 1970 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी खर्चों में कुछ कमी की जा सकी तो वह अनिवार्य भी हो जाएगा। इस प्रकार के खर्च अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के भावी विकास और अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। इन्हीं क्षेत्रों में शासन खासकर राज्यीय और स्थानीय शासन, प्रभाव डाल सकता है।

---

1. परिशिष्ट तालिका 25 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के खर्चों में कमी की जा सके तो किन दूसरे कामों पर कितना-कितना व्यय बढ़ाया जा सकेगा।

2 परिशिष्ट तालिका 26 भी देखिये।

इसमे सन्देह नही कि यदि अगले दशक मे राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी खर्चों मे कमी की जा सके तो रहन-सहन के स्तर को तेज गति से ऊँचा उठाया जा सकेगा । यदि सन् 1970 तक 2 खरब डालर वार्षिक की यह अतिरिक्त अवशिष्ट आय पूरी की पूरी सयुक्त राज्य के श्रमिको और अन्य वेतन भोगियो का रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने के लिए मिल जाय तो उससे प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मे $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी । लेकिन यह सब हिसाब लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि उपभोक्ताओ और सरकार की बढती हुई माँगो को पूरा करने के लिए पूंजीगत सामग्री और उद्योग-व्यवसाय मे नये निवेश के लिए भी धन की आवश्यकता होगी । इसके अलावा सन् 1970 तक विदेशो में सयुक्त राज्य के निवेश मे जो वृद्धि होगी उसका भी ध्यान रखना होगा ।

इस बात की काफी सम्भावनाएँ है कि उत्पादन मे सम्भावित यह वृद्धि किसी एक प्रयोजन के लिए नही, बल्कि इन सभी प्रयोजनो के सम्मिश्रण के लिए प्रयुक्त की जाएगी । इसका उपयोग लोगो की मजदूरियो और वेतनो मे वृद्धि और गरीबी के अवशेषो के खातमे के द्वारा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए किया जाएगा । ऐसा प्रतीत होता है कि इस अतिरिक्त उत्पादन की आय मे से स्वास्थ्य-सेवाएँ, शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुसन्धान, प्राकृतिक साधनो के विकास और संरक्षण, परिवहन, उत्पादक सयन्त्र और उपकरण और विदेशी निवेश आदि की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था करने के बाद लोगो के रहन-सहन के स्तर मे $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति व्यक्ति की वृद्धि सम्भवत. असगत नही होगी । लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय बढाना पड गया, तब लोगो के रहन-सहन के स्तर और सरकार की सुरक्षा से भिन्न सेवाओं मे सुधार स्वभावत अधिक धीरे-धीरे होगा ।

और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओ के सुधार आदि मे लगाया जाय। कुछ लोग दूसरी ओर, यह कहते है कि वैज्ञानिक और उद्योग-विद्या-सम्बन्धी अनुसन्धानो को, जिनमे अन्तरिक्ष की खोज का एक विशाल कार्यक्रम भी शामिल है, सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तीसरे वर्ग का कहना है कि अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का उपयोग मुख्यत उत्पादकता को बढाने और उन लोगो के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए जिनकी आमदनी मुश्किल से अपने आपको जीवित रखने लायक ही है, किया जाना चाहिए।

हम इन सब विचारो के विवाद मे यहाँ नही पडना चाहते। महत्त्व की बात यह है कि आज आर्थिक विकास और अतिरिक्त उत्पादन से राष्ट्रीय आय मे होने वाली वृद्धि के समुचित बटवारे के सम्बन्ध मे दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। यह अहसास बहुत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही यह भी समझ लिया जाना चाहिए कि इस सम्बन्ध मे आवश्यक नीतियो के निर्धारण और उनके कार्यान्वय की अभी शुरूआत ही है।

इन सब बातो पर विचार करने से यह भी मालूम होता है कि इस अतिरिक्त उत्पादन के लिए बहुत-से आवश्यक, बल्कि तत्काल आवश्यक, उपयोग है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति ऐसी नही है कि उसे अपने अतिरिक्त उत्पादनो के उपयोग के लिए कोई मौका ही नज़र न आता हो। कुछ लोगो का कहना है कि सयुक्त राज्य की समृद्धि इस बात पर निर्भर है कि शस्त्रास्त्रो पर होने वाला व्यय न केवल जारी रखा जाय बल्कि उसे बढाया भी जाय। लेकिन वास्तविकता यह है कि शस्त्रास्त्रो के उत्पादन पर बहुत ज्यादा राशि खर्च होने से अन्य वाँछनीय उद्देश्यो की पूर्त्ति मे बाधा पडती है।

किसी एक किस्म के खर्च मे परिवर्त्तन से, उदाहरण के लिए सैनिक व्यय मे एकाएक वृद्धि या कमी से, कुछ कठिनाई तो हो सकती है, लेकिन वह स्थायी नही होगी। इस प्रकार की कठिनाई पर बजट और

वित्त सम्बन्धी उचित नीतियो से विजय पायी जा सकती है। आर्थिक विस्तार की आवश्यकता सिर्फ इसीलिए नही है कि बढ़ती हुई श्रमिको की फौज को रोजगार पर लगाये रखना एक वाछनीय उद्देश्य था। वह इसलिए भी आवश्यक है कि वस्तुओ और खाद्य का अतिरिक्त उत्पादन अन्य महत्त्वपूर्ण और तात्कालिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए जरूरी है।

आर्थिक उतार-चढ़ाव

कुछ दशक पूर्व यह विचार, कि एक स्वतन्त्र व्यवसाय प्रणाली में गम्भीर और देर तक चलने वाले उतार-चढावो को रोका जा सकता है, वैसा ही अवास्तविक प्रतीत होता था जैसा कि यह विचार कि भूकम्पो को रोकना सम्भव है। बहुत समय तक अर्थशास्त्रियो का यह विचार रहा कि विकासोन्मुख और स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था की जो न्यूनतम कीमत चुकानी अनिवार्य है वह है आर्थिक सुरक्षा। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था मे इस अरक्षा के विरुद्ध सिर्फ इतनी ही आशा की जा सकती है कि जो लोग समय-समय पर आने वाले इन जबर्दस्त उतार-चढावो के शिकार होगे, उन्हे बेरोजगारी के समय सहायता देकर या बेरोज़गारी बीमा करके कुछ सरक्षण दिया जा सकता है।

अर्थशास्त्र के नियमो के अनुसार, उत्पादन आय को पैदा करता है और फिर उस आय के द्वारा उन वस्तुओ की माँग पैदा करता है जो उस उत्पादन के द्वारा उत्पादित हुई होती हैं। इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि उत्पादन तभी बढाया जाएगा, जब कि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच ऐसा सम्बन्ध हो जिससे व्यवसाय का प्रबन्धक अतिरिक्त बिक्री से अतिरिक्त मुनाफे की आशा कर सके। यदि आर्थिक गति-विधि मे सकुचन आ जाय तो कच्चे माल की कीमते, मजदूरियाँ और ब्याज-दर, तीनो मे गिरावट आयेगी। इससे उपभोक्ताओ को गिरी हुई नीची कीमतो पर वस्तुएँ खरीदने का और उत्पादको को कम मजदूरी पर अधिक मज़दूर रखने और अपने उद्योग मे अधिक निवेश

करने का प्रलोभन होगा। इसका परिणाम यह होगा कि सकुचन का यह रुझान एकदम उल्टा हो जाएगा।

वास्तव मे ये प्रक्रियाएँ आम तौर पर अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो के अनुसार नही होती। होता यह है कि जब मजदूरी की दरो मे कमी आती है तो, इससे पूर्व कि उससे उत्पादक लोग अधिक मजदूर रखे या उपभोक्ता अधिक माल खरीदे, आम तौर पर उसके फलस्वरूप मजदूरो की सख्या कम हो जाती है और उनकी क्रयशक्ति कम हो जाने से वस्तुओ की विक्री भी घट जाती है। इस प्रकार मजदूरी मे कटौती बाजार मे खरीद-विक्री को वढाने के वजाय उसे घटा देती है और इस प्रकार अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के वजाय क्षति पहुँचाती है।

कुछ मन्दी की स्थितियाँ ऐसी भी आयी, जब कि व्यवसायियो ने न तो कीमते कम की और न उत्पादन वढाया, क्योकि उन्हे यह भरोसा नही था कि मूल्यो मे कमी ग्राहकों को अधिक खरीद के लिए प्रेरित कर सकेगी। इसी तरह व्याज-दर मे कमी से प्रेरित होकर व्यवसायियो ने अपने निवेश मे वृद्धि भी नही की, क्योकि उन्हे यह विश्वास नही था कि इस निवेश-वृद्धि से होने वाले अतिरिक्त उत्पादन की विक्री हो सकेगी। सन् 1930 से प्रारम्भ दशक के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि उद्योग-व्यवसाय का विस्तार तभी किया जाता है जब कि विक्रय-मूल्य और लागत का सम्बन्ध उत्पादक के लिए लाभ-जनक हो, किन्तु इस विस्तार के लिए उसे प्रेरणा तब मिलती है जब कि उसे यह लगता है कि उसके उत्पादित माल की विक्री के लिए अधिक बडा बाजार उपलब्ध हो सकेगा। मन्दी के वर्षो मे उद्योगो का विस्तार न होने का कारण यह था कि उत्पादको को यह आशा नही थी कि अपने उत्पादन के लिए उन्हे अधिक विस्तृत बाजार मिल सकेगा।

व्यवसायी-वर्ग की प्रतिक्रिया कभी तो ऐसी होती है कि थोडे-बहुत अस्थायी धक्के के बावजूद वह यह आशा करता है कि बाजार

का काफी विस्तार होगा और कभी इसके विपरीत उसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि व्यावसायिक क्षेत्र मे आर्थिक गतिरोध आ जाएगा। अशत. यह एक मनोवैज्ञानिक रवैया होता है जो विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टियो पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता कभी-कभी अपने उपभोग के स्तर को गिरने से रोकते ही नही है, वल्कि बढा भी देते है, चाहे उन्हे उपभोग्य वस्तुओ की खरीद के लिए बहुत अधिक कर्जदार ही क्यो न हो जाना पडे। ऐसा तब होता है जब उन्हे लगता है कि उनकी नौकरी बिलकुल सुरक्षित है और उनकी आमदनी बढती जाएगी। दूसरी ओर कभी-कभी यही उपभोक्ता यह महसूस करते है कि उनकी नौकरी सुरक्षित नही है, इसलिए वे कोई नया ऋण लेने मे हिचकिचाते है। अमेरिका मे आर्थिक विकास के लिए जो कदम उठाये जाते है उनका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि अमेरिकी लोगो को अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की भावी समृद्धि का पूरा भरोसा है, हालाकि यही एकमात्र कारण नही है। यदि अमेरिका का दीर्घकालिक आर्थिक भविष्य अनुकूल नजर न आता तो व्यवसायी वर्ग नये सयन्त्रो और नई मशीनो पर अरबो डालर खर्च न करता और न ही लोग अपने मकान वनाने और उपभोग्य वस्तुएँ खरीदने के लिए अपनी सम्पत्तियाँ बन्धक रखते।

व्यवसाय के विस्तार के लिए व्यवसायियो, श्रमिको और उपभोक्ताओ को यह विश्वास होना बहुत जरूरी और महत्त्वपूर्ण है कि यदि कोई गम्भीर उतार-चढाव आये भी तो उनका सामना किया जा सकेगा, भले ही उसके लिए सरकार को कोई कार्यवाही करनी पडे। अन्य देशों की भाँति सयुक्त राज्य मे भी लोग यह मानते है कि आर्थिक अभिवृद्धि के अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने और गम्भीर उतार-चढ़ावो को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। यह मान्यता 1946 के रोज़गार अधिनियम मे निहित है, जिसका दोनो वड़े राजनीतिक दलो ने समर्थन किया था। इस अधिनियम ने सिर्फ सरकार पर नई जिम्मेदारी ही नही डाली, बल्कि उसे पूरा करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाने और

नियम बनने के लिए आवश्यक तन्त्र भी स्थापित कर दिया है। रोज़-गार अधिनियम बनाने के वाद का अब तक का इतिहास बहुत उत्साह-वर्धक है। यह ठीक है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद जो असाधारण आर्थिक प्रगति हुई है और हाल के वर्षो मे मूल्यो मे जो अपेक्षाकृत स्थिरता रही है उसका मुख्य कारण सिर्फ यही कानून नहीं है, तो भी इस कानून के अन्तर्गत अपनाई गई सरकारी नीतियो ने इसमे सहायता अवश्य दी है।

अमेरिका के आर्थिक विकास के दौरान मे दोनो प्रकार के दौर आये है—ऐसे भी जब कि आर्थिक विस्तार और अभिवृद्धि मे योग देने वाली ताकते शक्तिशाली रही और ऐसे भी जब कि वे कमज़ोर रही। सन् 1930 के दशक मे ये ताकते कमजोर थी, इसलिए सरकारी नीतियो के लिए आर्थिक विस्तार की प्रक्रियाओ को उत्तेजित करना कठिन था। इसके विपरीत 1945 से 1955 तक आर्थिक विस्तार की ताकते शक्तिशाली थी और वाजार के विस्तार की आशाएँ भी अधिक थी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद आर्थिक विस्तार की प्रवृत्तियो को वढाने मे कुछ अस्थायी कारणो के अलावा चार वडे और महत्त्वपूर्ण अभिवर्धक कारणो ने भी योग दिया। इस अवधि मे उद्योगविद्या (टैकनोलॉजी) की उन्नति हुई। आवादी और परिवारो मे असाधारण वृद्धि हुई। लोग वडी सख्या मे शहरो से हटकर उपनगरो मे वसने लगे, जिससे नये मकानो, नये वाजारो, सार्वजनिक उपयोग के स्थानो और अन्य सम्वद्ध सार्वजनिक निर्माण कार्यों की आवश्यकता वढी। किस्तो पर या वन्धक रखकर टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओ और मकानो की खरीद के लिए ऋण देने की सुविधाओ मे वृद्धि हुई। इन चार वडे कारणो के अतिरिक्त 1945 से 1947-48 तक की युद्धोत्तर नि शस्त्रीकरण की स्वल्प अवधि के वाद राष्ट्रीय प्रतिरक्षा पर खर्च वढाने और प्रतिरक्षा सम्वन्धी सस्थाओ के विस्तार से भी आर्थिक विस्तार को वहुत प्रोत्साहन मिला। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी जरूरी है कि निजी उद्योग-व्यवसाय का

विस्तार सिर्फ इन्ही वर्षो मे नही हुआ जब कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के खर्च सरकार ने वढा दिये, वल्कि द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद और 1950 से प्रारम्भ दशक के मध्य मे कोरियाई लडाई के वाद सैनिक व्यय में कमी के वर्षो मे भी उसका विस्तार हुआ।

जव तक आर्थिक विस्तार मे योग देने वाले प्रवल कारण मौजूद है तव तक छोटे-मोटे उतार-चढावो का मुकावला ऋण और वित्त सम्वन्धी समुचित नीतियाँ अपना कर किया जा सकता है। युद्धोत्तर काल के अनुभव ने अनुकूल परिस्थितियो मे इन नीतियो की प्रभाव-कारिता सिद्ध कर दी है।

लेकिन दीर्घकालिक विस्तार की ये परिस्थितियाँ क्या हमेशा अनु-कूल रहेगी ? आर्थिक उतार-चढाव के वारे मे विचार करते हुए अमेरिकी लोग आम तौर पर यह मानकर चलते है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे आर्थिक विस्तार के अनुकूल परिस्थितियाँ हमेशा विद्यमान हैं, इसलिए सरकार को अपनी नीति सिर्फ कभी-कभी आने वाले छोटे-मोटे स्वल्प-कालिक उतार-चढावो का मुकावला करने के लिए ही निर्धारित करनी चाहिए। वास्तव मे, सन् 1950 के दशक के मध्य से अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि की गति सन्तोपजनक नही रही है।

इस तथ्य की दो व्याख्याएँ की जाती हे। पहली यह कि आर्थिक शिथिलताओ (रिसैशन) का, खासकर 1958-59 मे, मुकावला करने के लिए जो नीतियाँ अपनाई गई, वे अपर्याप्त थी। इसलिए इस शिथिलता से जो उद्धार हुआ वह देर तक नहीं टिका और सन् 1960-61 मे फिर शिथिलता का एक झल्ला आया। यद्यपि ये दोनो शिथिलताएँ अधिक गम्भीर नही थी, फिर भी उनके एक के वाद एक शीघ्रता से आने के फलस्वरूप आर्थिक अभिवृद्धि की गति मे कमी तो आई ही। लेकिन यह विचार प्रकट करने वालो का कहना है कि इन शिथिलताओ से यह सिद्ध नहीं होता कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे अन्तर्निहित विस्तार की ताकते कमजोर पड गई है, इन से सिर्फ इतना ही साबित होता है कि सरकार को उतार-चढाव के इन दौरो का मुकावला करने के लिए अधिक प्रभाव-कारी नीतियाँ अपनानी चाहिएँ।

दूसरी व्याख्या यह की जाती है कि उतार-चढाव के चक्रो का मुकाबला करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियाँ स्वल्पकालिक उतार-चढावो का मुकाबला करने के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन वे आर्थिक वृद्धि के लिए दृढता से किये जाने वाले दीर्घकालिक प्रयत्नो का स्थान नही ले सकती। नई-नई औद्योगिक विधियो के विकास से, खास कर स्वचालित यन्त्रो के निर्माण से, प्रति व्यक्ति उत्पादन मे तीव्र गति से वृद्धि हुई है, लेकिन उत्पादकता की यह वृद्धि सारे समाज के लिए हितकर तभी हो सकती है जब कि रोजगार के अवसरो और माँग मे भी उसी अनुपात से वृद्धि हो। इसलिए हम आगामी दशको मे नई-नई औद्योगिक विधियो के जिस द्रुत विकास की आशा कर रहे हैं, उससे आर्थिक अभिवृद्धि तो तीव्र गति से अवश्य हो सकेगी, लेकिन साथ ही उसका यह तकाजा भी है कि सरकार की नीतियाँ भी आर्थिक विस्तार को बढाने और कायम रखने वाली हो।

यदि ये नीतियाँ सफल हो जाएँ तो आर्थिक शिथिलताओ का मुकाबला करने और आर्थिक उद्गार को थामे रखने के लिए उठाये जाने वाले स्वल्पकालिक कदमो से लाभ की गुजायश अधिक होगी। यह निश्चय करने के लिए, कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की अधिक गम्भीर और मुख्य समस्या दीर्घकालिक आर्थिक विकास की है या स्वल्पकालिक उतार-चढावो का मुकाबला करने की, इससे अधिक कुछ नही कहा जा सकता। हमारे अपने खयाल मे सबसे सुरक्षित मान्यता यह होगी कि सरकार को दोनो ही बातो का खयाल रखना चाहिए, उसकी नीतियाँ दीर्घकालिक आर्थिक अभिवृद्धि को समुन्नत करने के साथ-साथ व्यापार मे आने वाले स्वल्पकालिक शिथिलता के दौरो का मुकाबला करने वाली भी होनी चाहिए।

दीर्घकालिक अभिवृद्धि की चाहे कोई भी नीतियाँ अपनाई जाएँ, बीच-बीच मे व्यावसायिक उतार-चढाव आते ही रहेगे। इसके बावजूद यह भरोसा करने के कारण है कि, यदि बहुत विपरीत परिस्थितियाँ पैदा ९ तो भी सघीय सरकार व्यवसायी वर्ग और श्रमिक वर्ग के सह-

योग से उन्हे इतना नही बिगडने देगी कि सन् 1930 के दशक की-सी भयकर मन्दी फिर आ जाय। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे पिछले पच्चीस वर्षो मे मन्दी के झटको को सहन करने वाली कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ कायम हो गई है, जो किसी भी मन्दी की भयकरता को कम कर देगी।

पहले यह स्थिति थी कि हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रो मे यदि मन्दी का रुझान आता था तो वह सारी ही अर्थ-व्यवस्था मे मन्दी ला देता था। जहाँ एक बार व्यवसाय मे खतरे या चिन्ता की जरा-सी स्थिति पैदा हुई कि बैंको मे रुपया जमा कराने वालो मे तहलका मच जाता और वे अपनी रकमो के डूबने के भय से अपना पैसा निकालने के लिए बैंको पर टूट पडते। बैंक इन लोगो का रुपया वापस करने के लिए व्यवसायियो को दिये हुए अपने ऋण वापस माँगते और इस तरह कुछ व्यवसायो के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा हो जाती। इस प्रकार थोडे-से लोगो की दिक्कत व्यापक बनकर बहुत-सी फर्मो और उद्योगों के लिए दिक्कत का कारण बन जाती। आज स्थिति बदल गई है। सघीय सरकार ने बैंको मे जमा खातो के बीमे की योजना बनाकर लोगो की जमा रकमो के डूबने का भय दूर कर दिया है। इसी तरह की योजनाएँ गृह ऋण बैंको और पारस्परिक बचत बैंकों आदि के लिए भी बनाई गई है।

पहले मन्दिया उस हालत मे भी फैलती थी, जब कि एक उद्योग मे बेकार हुए व्यक्ति अपनी खरीद मे कमी कर देते और उससे अन्य उद्योगो के तैयार माल की बिक्री कम हो जाती। लेकिन आज उस स्थिति का पूरा नही तो आंशिक इलाज अवश्य हो गया है क्योंकि सरकार ने बेरोजगारी बीमा योजना बनाकर बेरोजगारी की हालत मे भी लोगो के लिए एक न्यूनतम आय की व्यवस्था कर दी है ताकि वे अपने लिए घर मे [illegible] जीवन की अनिवार्य वस्तुएँ तो खरीद ही सकते है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कानूनो की योजना मे भी फायदा होगा, क्योंकि इससे एक तो वृद्धावस्था पर लोगो की आय का जरिया बना [illegible]

से निवृत्त हो जाना चाहते है उन्हे कुछ-न-कुछ रकम मिलती रहेगी।

पहले आर्थिक उतार-चढावों को अधिक उग्र बनाने वाला एक कारण और भी था। व्यवसाय प्रबन्धक अपने विस्तार कार्यक्रमो मे तब तक के लिए कटौती कर देते थे और पूंजी-गत व्ययो को तब तक स्थगित रखते थे, जब तक कि उन्हे यह यकीन न हो जाय कि बाजार मे उनके माल की माँग फिर बढने लगी है। व्यवसाय प्रबन्धको के इस रवैये मे अब बहुत परिवर्तन हो गया है जैसा कि उनके दीर्घकालिक निवेश कार्यक्रमो से पता चलता है। इन लोगो ने अब बिक्री मे आने वाले स्वल्पकालिक उतार से घबराकर अपने विस्तार कार्यक्रमो मे कटौती करना बन्द कर दिया है। हालाकि व्यवसायियो के रुख मे यह परिवर्तन स्पष्ट नज़र आने लगा है तो भी व्यावसायिक निवेश मे स्वल्पकालिक उतार-चढावो का पूर्णत अन्त अभी नही हुआ।

कर-प्रणाली अब भी पहले की भाँति आर्थिक क्षेत्र मे स्वत. स्थिरता लाने का काम करती रहती है। यदि मुनाफो और आमदनियो मे कमी आती है तो कर भी कम हो जाते है और इस प्रकार कुल आय कम हो जाने पर भी स्वायत्त आय उतनी कम नही होती। करो मे कमी हो जाने से सरकार के बजट मे घाटे की स्थिति पैदा जाएगी और उसके कुछ अश की पूर्ति वह बाजार से ऋण लेकर करेगी।

मन्दी के आघातो को सहन करने की इन पहले से बनी-बनाई व्यवस्थाओ से काफी आशावादिता पैदा हुई है और वह सही भी है। लेकिन यह सम्भव है कि एक गम्भीर और देर तक चलने वाली मन्दी को रोकने के लिए ये व्यवस्थाएँ अकेली पर्याप्त न हो। यह आशा करना दुराशा-मात्र होगा कि आर्थिक ढाँचे मे परिवर्तन हो जाने से और मन्दी के आघात को कम करने वाली कुछ ऐसी नई व्यवस्थाएँ हो जाने से जो 1929-33 मे नही थी, अब मन्दी कभी आ ही नही सकती। हमारी स्थिति की तुलना एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति से की जा सकती है जो एक खिडकी मे से फिसलकर नीचे गिरता है, लेकिन एक आगे की ओर बढ़ी हुई सिल उसे आधे रास्ते मे ही रोक लेती है। अगर वह

एक ही मज़िल नीचे गिरा होगा तो उसे अधिक चोट नही लगेगी। लेकिन अगर वह बीसवी मजिल से गिरा हो और दसवी मजिल पर सिल से अटक कर रुका हो तो यह उम्मीद करना कि आधे रास्ते मे ही रुक जाने के कारण उसे अधिक चोट नही लगेगी, अपने आपको झूठी सान्त्वना देना होगा।

दूसरे शब्दो मे स्थिरीकरण की नीति को केवल उन्ही व्यवस्थाओ पर भरोसा नही करना चाहिए जो आघात की कठोरता को कम करने के लिए पहले-से स्वत बनी हुई है। सरकार को आर्थिक गति-विधि मे नीचे की ओर किसी भी गम्भीर झुकाव को एक पूर्ण मन्दी मे परिणत होने से रोकने के लिए कार्रवाई करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए। सरकार के पास मन्दी का मुकाबला करने के साधन हमेशा रहते ही है।

और सरकार को सिर्फ मन्दी के खतरे के प्रति ही सजग नही रहना चाहिए, क्योकि स्थिरीकरण की जो बनी-बनाई व्यवस्थाएँ आर्थिक शिथिलता के आघात को कम करती है, वही इस शिथिलता से ऊपर उभरने की प्रवृत्ति को भी मन्द कर सकती है। आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि जब एक बार आर्थिक शिथिलता को रोक दिया जाय, तो वह सट्टे-फाटके से कृत्रिम तेजी को भी न आने दे और जरूरत पडे तो इस शिथिलता से ऊपर उभरने की प्रवृत्ति को सहारा भी दे।

अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक सुलभ उपाय है मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीति। इस नीति मे सबसे बडी आसानी यह है कि उसे झटपट, और आम तौर पर नया कानून पास किये बिना, अमल मे लाया जा सकता है और परिवर्त्तित परिस्थितियो के अनुसार ढाला जा सकता है। आर्थिक अभिवृद्धि को सहारा देने के लिए एक उपयुक्त मुद्रा-नीति अत्यन्त आवश्यक है। वह उचित से अधिक माग को रोकने मे भी प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है। अन्य परिस्थितियो मे उसकी प्रभाविता सीमित होती है। मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीति को सफल बनाने के लिए तह जरूरी है कि कर, ऋण-व्यवस्था और व्यय सम्बन्धी नीतियो मे भी उसके अनुसार ही परिवर्त्तन कर दिये जाएँ।

यह सही है कि आर्थिक शिथिलता के समय लोगो की कर सम्बन्वी देनदारियाँ स्वत ही कम हो जाएँगी, लेकिन सरकार भी लोगो की क्रय-शक्ति वढाने के लिए करो की दर मे कमी कर सकती है। वास्तव मे सन् 1930 के दशक और आज के ज़माने मे एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है और वह यह कि आज सघीय सरकार के कर वहुत ऊँचे हैं और वहुत व्यापक क्षेत्र मे वटे हुए है। इसलिए आज लोगो की क्रय-शक्ति मे कमी को रोकने के लिए करो की दर मे कमी का उपाय सन् 1930 के दशक की मन्दी के दिनो की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। साथ ही करो मे कमी व्यवसायियो को अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन के साधन के रूप मे भी इस्तेमाल की जा सकती है। यदि लोगो को यह भरोसा होगा कि उनके उत्पादित माल की बिक्री के लिए फिर से बाज़ार मिल जाएगा और दीर्घकालिक आर्थिक अभिवृद्धि सभव होगी तो ये प्रोत्साहन कारगर सिद्ध होगे। सन् 1930 के दशक की मन्दी के समय यह भरोसा लोगो को नहीं था।

ऋण-व्यवस्था भी राज्यवित्तीय नीति का एक शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकती है। तेजी (व्यापार उत्कर्ष) के दिनो मे सरकार जनता से ऋण लेने के लिए अपने बॉड जारी कर सकती है ताकि निजी व्यवसायो द्वारा धन की खीच का मुकाबला कर सके और उसे सीमित भी कर सके। और व्यापार मे गिरावट के दिनो मे करो से कम धन प्राप्त होने के कारण अपने खर्चो को चलाने के लिए सरकार सघीय रिजर्व बैंक की विस्तारक मुद्रा नीति से सहायता प्राप्त देश की बैंकिग प्रणाली से वित्त व्यवस्था कर सकती है।

सरकार के व्यय कार्यक्रम भी मन्दी को रोकने वाले साधन हैं। जब गैरसरकारी उद्योग और व्यवसाय खूब बढ रहे हो, तब कुछ ऐसे सरकारी निर्माण कार्यों को धीमा या स्थगित किया जा सकता है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण न हो। लेकिन जब झुकाव मन्दी की ओर हो या सचमुच मन्दी आ गई हो तब सरकारी निर्माण कार्यक्रमो की गति तेज़ की जा सकती है। इस नीति को सर्वाधिक प्रभावकारी बनाने के लिए इसका

निर्माण सघीय स्तर पर होना चाहिए और उसमे राज्यीय और स्थानीय शासनो से भी घनिष्ट सहयोग रखा जाना चाहिए।

यदि निकट भविष्य मे काफी बडे पैमाने पर नि शस्त्रीकरण सम्भव हो जाय तो एक बडे पैमाने पर स्वल्पकालीन हेरफेर करना पडेगा। सघीय सरकार के खर्च मे इस नि शस्त्रीकरण से जो बचत होगी उसका कुछ लाभ करो मे काफी कमी करके उपभोक्ताओ को दिया जा सकता है। साथ ही सघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो के जिन सैनिकेतर कार्यक्रमो की गति हाल के वर्षो मे धन की कमी से मन्द रही है, उन्हे भी इस बचत से तेज किया जा सकता है। इन कार्यक्रमो मे शिक्षा और स्वास्थ्य, प्राकृतिक साधनो का विकास और सरक्षण, शहरी इलाको का पुनर्निर्माण और स्थलीय और हवाई परिवहन के साधनो का निर्माण शामिल है। बडे पैमाने पर नि शस्त्रीकरण से सयुक्त राज्य के कुछ उद्योगो और क्षेत्रो मे, जिनका सम्बन्ध इस समय सामरिक उत्पादन से हैं, काफी हेरफेर करना होगा। लेकिन इस हेरफेर से जो आर्थिक नुक्सान होगा उसके डर से नि.शस्त्रीकरण को टालने की आवश्यकता नही है, क्योकि यदि पहले से ही योजनापूर्वक इस हेरफेर की तैयारी कर ली जाय, तो यह भय नही रहेगा। सयुक्त राज्य की आर्थिक समृद्धि केवल सामरिक आवश्यकता के उत्पादनो पर ही निर्भर नही है।

नि शस्त्रीकरण के फलस्वरूप जब देश के भीतर आर्थिक विस्तार शिथिल हो जाय तो अन्य देशो को, खासकर उन देशो को, जो अभी औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक स्थिति मे हैं, पूंजी का निर्यात बढाया जा सकता है। इससे उन अल्प विकसित देशो की सयुक्त राज्य से माल खरीदने की क्षमता बढेगी और वहाँ के निर्यातकारी उद्योगो मे उत्पादन को बढावा मिलेगा। सन् 1930 के दशक की मन्दी के समय अनेक देशो ने, जिनमे सयुक्त राज्य भी था, अपने आन्तरिक बाजारो की रक्षा के लिए आयात पर प्रतिबन्ध का तरीका अपनाकर और अपने निर्यात को बढाने के लिए दूसरो की तुलना मे अपनी मुद्राओ का अवमूल्यन (डिवैल्युएशन) करके, अनुदान (सब्सिडी) देकर और इसी प्रकार के

अन्य साधन अपनाकर बेरोज़गारी का 'निर्यात' किया था। इसके परिणाम सभी देशो के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए। इस प्रकार की व्यापार-नीतियो से हर देश ने स्वय हेरफेर करने के बजाय उसे दूसरो पर मढने की कोशिश की, लेकिन आमतौर पर वह उसी के लिए घातक सिद्ध हुई। जल्दी ही सबने यह महसूस कर लिया कि कोई भी देश इस विश्वव्यापी आम आर्थिक मन्दी से अपने आपको प्रभावकारी ढग से अलग नही कर सकता। ऐसी दशा मे यदि उद्योग-सम्पन्न देश अपनी बेकार क्षमताओ के कुछ भाग का उपयोग अल्पविकसित देशो के साथ इस ढग से करे कि दोनो को ही उससे लाभ हो, तो वह अधिक रचनात्मक होगा।

दीर्घकालिक आर्थिक अभिवृद्धि, व्यावसायिक उतार-चढाव, मन्दी और बेरोज़गारी की समस्याएँ अभी तक हल नही की जा सकी। एक स्वतन्त्र व्यवसाय वाली अर्थ-व्यवस्था मे, जहाँ हर व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से यह निर्णय करता है कि वह कहाँ काम करे, क्या उत्पादन करे, क्या खरीदे-खाये, वहाँ बीच-बीच मे आर्थिक उतार-चढाव आयेंगे ही और उनकी वजह से आर्थिक हेरफेर भी करने ही होगे। लेकिन यह जरूरी नही है कि ये हेरफेर मन्दियो और बडे पैमाने पर बेरोज़गारी मे परिणत हो जाएँ। अमेरिकी जनता यह स्वीकार करती है कि गम्भीर आर्थिक उतार-चढावो का मुकाबला करने और समुचित आर्थिक अभिवृद्धि को सहारा देने के लिए सरकार द्वारा कुछ नीतियो का अपनाया जाना व्यवसाय और श्रम की स्वतन्त्रता के प्रतिकूल नही है। अनेक वर्ष पूर्व लोग मन्दियाँ आने पर अपने आपको असहाय अनुभव करते थे और प्रकृति पर छोड देते थे, लेकिन अब उन्होने अपना यह रवैया बिलकुल छोड दिया है और प्रकृति का दृढता से मुकाबला करते है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे गम्भीर और लम्बी मन्दियाँ अनिवार्य नही हैं। लेकिन यदि गलत नीतियाँ अपनायी जाएँ तो वे जरूर आ सकती है। इसलिए हमारे सामने यह चुनौती है कि हम समुचित नीतियाँ विकसित करे और अपनाये।

मूल्य वृद्धि की समस्या

मन्दियो से बचना सन्तुलित आर्थिक अभिवृद्धि को कायम रखने के बृहत्तर कार्य का एक पहलू मात्र है। इसी का दूसरा पहलू मुद्रा-स्फीति है और वह केवल अविच्छिन्न आर्थिक विकास के लिए ही नही, बल्कि एक बडी जन-सख्या के कल्याण के लिए भी घातक है। सन् 1946 के रोजगार अधिनियम पर काग्रेस (ससद्) मे हुई बहस मे यह दलील दी गई थी कि पूर्ण रोजगार के ध्येय की पूर्त्ति के लिए अपनायी जाने वाली नीतियाँ लागत मूल्यो और विक्रय मूल्यो मे बार-बार वृद्धि करती रह सकती है।

लेकिन यह बात आमतौर पर स्वीकार की गई कि उत्पादकता वृद्धि के अनुपात मे मजदूरियो मे वृद्धि करना न केवल मूल्यो के स्थिरीकरण की नीति के प्रतिकूल नही होगा, बल्कि वह लोगो की क्रय-शक्ति और उपभोग मे आवश्यक वृद्धि करने के लिए वाछनीय भी होगा। लेकिन कुछ व्यक्तियो ने यह भय प्रकट किया कि यदि सभी लोग रोजगार पर लगे होगे तो श्रमिक उत्पादकता वृद्धि के अनुपात मे जितनी मजदूरी बढाना उचित होगा उससे भी अधिक वृद्धि और अन्य लाभो की माग करेगे। और यदि ऐसा हुआ तो व्यवसायो के प्रबन्धक यह सोचकर मजदूरियो मे वृद्धि कर देगे कि बाजार की परिस्थितियाँ अनुकुल होने पर कीमते बढाकर मजदूरी के खर्च मे हुई इस वृद्धि की पूर्त्ति की जा सकेगी और सम्भव होगा तो उससे भी अधिक कीमते वसूल की जा सकेगी। कुछ लोगो ने यह भय प्रकट किया कि बाज़ार की अनुकूल परिस्थितियाँ देखकर व्यवसायी लोग कीमते बढायेगे और तब श्रमिक लोग महगाई के नाम पर अपनी मजदूरियाँ बढवाने की माँग करेंगे और बढवा भी लेगे।

इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि सब लोगो को पूरा रोज़गार देने की नीति पर अमल किया जाएगा तो मूल्यो मे कुछ न-कुछ वृद्धि निरन्तर होती ही रहेगी। इन अर्थशास्त्रियो के एक

वर्ग का कहना था कि कीमतो मे थोडी-थोडी वृद्धि निरन्तर होती रहना उतना बुरा नही जितना कि स्थायी रूप से बेरोज़गारी का बना रहना या बीच-बीच मे बेरोज़गारी के दौर आते रहना। दूसरे वर्ग का कहना था कि मूल्य-स्तर मे निरन्तर वृद्धि होती रहने पर व्यावसायिक ढाचे मे कुछ असन्तुलन आना जरूरी है। इसलिए आर्थिक अभिवृद्धि को निरन्तर जारी रखने के लिए कुछ-न-कुछ बेरोजगारी को स्थायी रूप से कायम रखना या बीच-बीच मे पैदा करते रहना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्र को निरन्तर मुद्रा-स्फीति के दुष्प्रभाव सहन करने पडेंगे।

इस अधिनियम के फलस्वरूप पिछले डेढ दशक मे रोजगार का स्तर अमेरिका मे ऊँचा रहा है, किन्तु फिर भी इस अवधि मे इस सवाल का फैसला नही हो सका। हम अभी तक कोई ऐसा सुनिश्चित तरीका नही निकाल सके जिससे रोज़गार के स्तर को ऊँचा रखते हुए मूल्यो मे निरन्तर वृद्धि को रोका जा सके। आज कीमते सन् 1940 से पहले की अपेक्षा दुगुनी है, लेकिन यह वृद्धि मुख्यत द्वितीय विश्व युद्ध का और कोरियाई युद्ध के बाद पुन शास्त्रास्त्र वृद्धि का परिणाम है। सन् 1951 के बसन्त मे जो कीमते थी उनकी अपेक्षा सन् 1961 के बसन्त मे 15 प्रतिशत ऊँची कीमते है, लेकिन इस अवधि मे रक्षा व्यय के स्तर को देखते हुए यह वृद्धि कुछ अधिक नही है। परन्तु 1961 तक उपभोग्य सामग्रियो के मूल्यो मे निरन्तर वृद्धि होती रही है, ऐसे समय भी जबकि सरकार का रक्षा व्यय नही बढा। इसका अर्थ यह है कि मूल्यो के स्थिरीकरण की समस्या अभी तक हल नही हुई। अगर कृषि-जन्य वस्तुओ की कीमतो मे कुछ गिरावट न आयी होती तो मूल्यो का सूचक अक और भी ऊँचा होता।

सरकार की राजवित्तीय और ऋण-सम्बन्धी नीतियो ने मूल्य-वृद्धि को सीमित करने मे कुछ सहायता दी है। यदि ये नीतियाँ न अपनाई गई होती तो मूल्य और भी बढ गए होते। सरकार के बजटो मे कुछ अधिशेष यानी उसके खर्च से आय का आधिक्य होता रहा है। सन् 1947 के बाद के 14 वर्षों मे से सात मे सरकार का तथाकथित नकद

बजट अधिशेष (सरप्लस) का बजट रहा है। इस अवधि मे सरकार के बजटो मे आय कुल मिलाकर व्यय से लगभग चार अरब डालर अधिक रही। हाल के वर्षों मे सरकार करो मे कमी करने की माँग अक्सर ठुकराती रही है, क्योकि उसे भय था कि कही इससे मुद्रा-स्फीति (इनफ्लेशन) न हो जाय, हालाकि वह यह भी जानती थी कि कर घटाने से लोगो की चीजो की माँग बढेगी और उससे आर्थिक अभिवृद्धि का स्तर ऊँचा होगा। सरकार की ऋण-नीति ने भी मूल्यो मे वृद्धि को रोकने मे कुछ योग दिया है। खास तौर से ऋण देने पर कुछ रोक लगाकर सरकार ने प्राइवेट रिहायशी मकानो के निर्माण की गति को धीमा किया।

हाल के वर्षों मे इस बात को लेकर खूब बहस चलती रही है कि क्या ऋण-प्रतिबन्ध नीति प्रभावकारी और उचित होगी। ऋणो पर प्रतिबन्ध लगाने और उन्हे सीमित करने की नीति ने अनेक व्यवसायो पर बुरा असर डाला है और जो व्यवसाय बाहरी ऋण पर जितना अधिक निर्भर करता है उस पर उतना ही अधिक असर पड़ा है। लेकिन यह तर्क इस विषय मे निर्णायक नही है क्योकि यदि ऋणो पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय तो स्फीतिजन्य मूल्य वृद्धि ही उसका एक मात्र अनिवार्य विकल्प होगी। मूल्य-वृद्धि की सभी परिस्थितियो मे राजवित्तीय (फिस्कल) और ऋण-प्रतिबन्ध सम्बन्धी नीतियाँ अपनाने के विरोध मे एक दलील और दी जाती है जो अधिक गम्भीर है। वह दलील यह है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती है, जिनमे इन नीतियो को अपनाने से मूल्य तो कुछ स्थिर हो जाएँगे, लेकिन साथ ही उससे काफी बेरोजगारी भी पैदा होगी। ऐसी दशा मे इलाज बीमारी से भी खराब होगा।

राजवित्तीय और ऋण-प्रतिबन्ध सम्बन्धी उपाय लागत मूल्यो (उत्पादन व्ययो) और वस्तुओ के विक्रय-मूल्यो मे वृद्धि को रोकने के बजाय माँग मे वृद्धि को रोकने मे अधिक कारगर सिद्ध होते है। लागत और कीमतो मे वृद्धि तो व्यवसायो और श्रमिक यूनियनो की शक्ति पर निर्भर है। इसलिए अमेरिकी शासन के भीतर और बाहर, दोनो जगह यह सुझाव दिया गया है कि सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ भी निर्धारित करे

जो मुद्रास्फीति की सम्भावनाओ को रोकने में राजवित्तीय और ऋण-प्रतिबन्ध सम्बन्धी नीतियो की पूरक हो सकें। मूल्य-वृद्धि का मुकाबला करने के लिए जो पूरक उपाय सुझाये गए हैं उनमें से कुछ ये है . एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अधिक प्रभावकारी नीतियाँ अपनायी जाएँ , आयात-नीतियाँ लचकीली रखी जाएं , और मूल्य एव मजदूरी सम्बन्धी राष्ट्रीय नीतियो के बारे मे प्रबन्धको और श्रमिको के बीच एक समझौता हो। ये समस्याएँ हैं जिनका पर्याप्त आर्थिक अभिवृद्धि और समुचित मूल्य-स्थिरता के उद्देश्यो की पूर्त्ति के लिए सामना करना ज़रूरी है।

गतिशीलता और जड़ता

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे उत्पादकता की वृद्धि के लिए जो शर्त्तें आवश्यक है उनमे से एक शर्त्त यह भी है कि गतिशीलता का स्तर ऊँचा बना रहे। कुशल प्रबन्धक, श्रमिक और पूंजी तीनो ही ऐसी गतिशील स्थिति मे रहे कि जब जहाँ उनकी आवश्यकता हो या उनके लिए अनुकूल अवसर हो तभी वहाँ पहुँच सके। यह सम्भावना, कि इस गतिशीलता का स्थान कभी जडता ले सकती है, एक ऐसी समस्या है जो अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की भावी अभिवृद्धि को खतरे मे डाल सकती है। आर्थिक गतिशीलता अनेक प्रकार की हो सकती है—उदाहरण के लिए अमेरिकी लोग देश के एक भौगोलिक इलाके से दूसरे इलाके मे, एक कारखाने से दूसरे कारखाने मे और एक धन्धे से दूसरे धन्धे मे आसानी से जा सकते है , साहसी व्यवसायी लोग अपने जमे-जमाये और सुरक्षित व्यवसायो से छुट्टी पाकर नये-नये व्यवसाय प्रारम्भ कर सकते है , और पूंजी भी एक व्यवसाय से और एक स्थान से दूसरे व्यवसाय और स्थान मे जा सकती है।

भौगोलिक गतिशीलता, जो अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे पिछले सत्तर वर्ष से चली आ रही है, हमेशा वरदान ही सिद्ध नही होती। न तो औद्योगिक समृद्धि वाले नगर और न ही औद्योगिक समृद्धि से रहित

नगर अच्छे सामाजिक जीवन के लिए अनुकूल है। जो श्रमिक और उनके परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का सिलसिला अक्सर लगाये रखते है, वे न तो अपना निजका घर बना सकते हैं और न समाज के राजनीतिक, सास्कृतिक और सामाजिक जीवन मे भाग ले सकते है। लेकिन आज क्योकि प्राय हर कर्मचारो के पास अपनी मोटर गाडी है, इसलिए वह अपना निवासस्थान वदले विना अपना काम का स्थान वदल सकता है। यदि किसी इलाके मे एक उद्योग की हालत खराव हो जाय तो भी यह जरूरी नही है कि वहाँ के सामुदायिक जीवन पर उसका असर वुरा ही पडे, वशर्त्ते कि उस इलाके मे कोई नया उद्योग विकसित हो जाय और वह उपलव्ध जन-शक्ति को खपा ले। यही आम तौर पर होता भी है। लेकिन इसके मुकावले मे कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो हमेशा निरन्तर मन्दी के शिकार रहते है, उदाहरण के लिए कोयला खानो और इमारती लकडी वाले ऐसे क्षेत्र जहाँ से कोयले और लकडी का प्राय सम्पूर्ण दोहन कर लिया गया है। इसमे से कुछ मे नये उद्योगो का विकास वहुत अपर्याप्त हुआ है और वेकार मजदूरो के दूसरी जगह जाने की गति भी वहुत मन्द रही है, जिससे सारे राष्ट्र मे समृद्धि होने पर भी वहाँ वेरोजगारी काफी अधिक रही है। इस कठिन समस्या को निवटाने के लिए एक नये सघीय क्षेत्र पुर्नविकास प्रशासन की स्थापना के साथ कुछ विशेष नीतियाँ प्रारम्भ की गई है।

एक ही इलाके मे श्रमिको के एक कारखाने से दूसरे कारखाने में जा सकने के अवसर वाछनीय अवश्य है किन्तु इस गतिशीलता की पूरी छूट भी उनके पूर्ण प्रतिवन्ध के समान ही अवाछनीय होगी। फर्म और उसके श्रमिको दोनो का लाभ अन्तत इसी मे है कि श्रमिक एक ही जगह टिके रहे और उनके लिए कारखाना वदलने की जरूरत कम से कम हो। श्रमिको को वरिष्ठता (सीनियॉरिटी)का अधिकार प्राप्त है, उनको वार्षिक वेतनो की गारण्टी होती है, नौकरी से अलग करने पर उन्हे मुआवजा देना पडता है और दूसरे कई लाभ भी उन्हे देने अनिवार्य होते हैं। इस-लिए आम तौर पर फर्मे यह पसन्द करती हैं कि यदि उनकी व्यावसायिक

गति विधि मे अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए शिथिलता का दौर आ भी जाय तो भी वे अपने कर्मचारियो को बर्खास्त करने के बजाय काम पर लगाये रखे। लेकिन कारखानो मे वेतनभोगी श्रमिको की सख्या मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिको की अपेक्षा तीव्र गति से बढ रही है, इससे स्वभावत श्रमिको का एक स्थान या एक कारखाने से दूसरे स्थान या कारखाने मे जाना भी कम होता जा रहा है।

लेकिन यदि प्रबन्धक और श्रमिक एक ही फर्म से इतने चिपके रहें और दूसरे ऐसे धन्धो की खोज ही न करें, जिनमे उनकी दक्षता और कौशल का अधिक अच्छा उपयोग हो सकता हो, तो उत्पादकता कम हो जाती है। कुछ प्राइवेट फर्मो के पेन्शन सम्बन्धी नियम ऐसे है कि यदि उनके प्रबन्धक या कर्मचारी उनके यहाँ से काम छोडकर कही अन्यत्र चले जाएँ तो वे पेन्शन के अधिकार से वचित हो जाते हैं। इस प्रकार के नियमो का यही नतीजा होता है कि प्रबन्धक और कर्मचारी किसी दूसरी जगह नही जा पाते और उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। इस खतरे को महसूस कर उसे दूर करने के उपाय सोचे गए हैं। कुछ प्राइवेट पेन्शन योजनाओ मे, उदाहरण के लिए कालेजो के अध्यापको की सेवा निवृत्ति की योजना मे, यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति एक जगह से काम छोडकर दूसरी जगह चला जाए तो भी उसका पेन्शन का अधिकार बना रहता है। इसी तरह सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभो से भी व्यक्ति अपना काम बदलने पर वचित नही होता। किन्तु फिर भी इस समय ऐसी अनेक प्राइवेट पेन्शन योजनाएँ है जो लोगो को एक नौकरी से दूसरी नौकरी मे जाने से अनुचित रूप से रोकती हैं।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे एक और किस्म की गतिशीलता भी है और वह यह कि बहुत-से लोग बाजार की बदलती हुई जरूरतो के मुताबिक एक किस्म के धन्धे को छोडकर दूसरी किस्म के धन्धे मे जाने को तैयार रहते हैं। कुछ अन्य देशो की अपेक्षा अमेरिका मे लोगो मे यह प्रवृत्ति अधिक है कि वे अपने आपको किसी एक किस्म के धन्धे से

जीवन भर बाधकर नहीं रखते। प्रशिक्षित इजीनियर व्यवसाय अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए, टैकनीशियन विश्वविद्यालयो मे अध्यापक बनने के लिए और कुशल श्रमिक सुपरवाइज़र बनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अब क्योकि बहुत-से कार्यो के लिए खास किस्मों की ट्रेनिंग ज़रूरी हो गई है, इसलिए भविष्य मे यह सम्भव है कि लोग अपने उन कामो को बदलने के लिए तैयार न हो जिनकी विशेष ट्रेनिंग वे पहले ले चुके है। उद्योग विद्या (टैकनोलॉजी) की उन्नति के युग का यह अनिवार्य परिणाम है।

स्वचालित यन्त्रो के अधिकाधिक अपनाये जाने से ये प्रवृत्तियाँ और भी बढेगी। इस बात के प्रमाण अभी से मिलने लग गए है कि आधुनिक उद्योग विद्या के फलस्वरूप नई उत्पादन-विधियाँ निकल आने से कुछ किस्म के काम करने वाले लोगो मे तो बेकारी बढ गई है और कुछ किस्म के काम करने वाले लोग दुर्लभ हो गए है। स्वचालित यन्त्रो के उपयोग के प्रारम्भिक दौर मे तो यह सम्भव था कि इन मशीनो के उपयोग मे जो लोग बेकार हो, वे इन नई मशीनो के निर्माण और रख-रखाव के लिए अधिक आदमियो की माँग के कारण खप जाएँ। लेकिन आगे चलकर यह सम्भव है कि नई तकनीकी विधियो के कारण मजदूरो मे बेरोजगारी बढ जाय और जब तक नये उद्योग और नई सेवाएँ काफी विकसित न हो जाएँ और ये मजदूर उनमे काम न करने लगे अथवा काम के घण्टो मे कमी न कर दी जाय तब तक वह उग्र रूप धारण किये रहे।

यही कारण है कि यदि श्रमिको के एक काम या उद्योग से हटकर दूसरे मे लगने की गतिशीलता को बनाये रखना है तो उद्योग विद्या की उन्नति के युग मे शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रबन्धो का बहुत महत्त्व होगा। कुछ व्यावसायिक कम्पनियो और यूनियनो ने श्रमिको को उन उद्योगो मे पुनः प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम आरम्भ भी कर दिये है जिनमे स्वचालित यन्त्रो का उपयोग महत्त्वपूर्ण है। संघीय सरकार भी उन श्रमिको के, जिनका रोजगार स्वचालित यन्त्रों या अन्य कारणो से

पुराना पड गया है, पुन प्रशिक्षण के कार्यक्रमो में सहायता देती है। इसके अलावा वहुत-से श्रमिक काम के घण्टो में कमी का लाभ उठाकर विशेष प्रशिक्षणो के पाठ्यक्रमो में भाग लेते हैं ताकि उद्योग विद्या में हो रही प्रगति के लिए अपने आप को तैयार कर सकें या अपना धन्धा वदल सकें। भूतपूर्व सैनिको को मुफ्त शिक्षा की जो सुविधाएँ दी गई हैं उसके फलस्वरूप एक पूरी पीढी के लोग अपनी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति अनुकूल न होने पर भी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके है। इसके अतिरिक्त कालेजो के छात्रो और ग्रेजुएटो को भविष्य मे विभिन्न पेशो, तकनीकी क्षेत्रो या व्यवसायो मे काम के लिए अपने आपको तैयार करने के लिए वहुत-सी छात्रवृत्तियाँ, शिक्षा ऋण या अन्य प्रकार की सहायताएँ भी सरकार या प्राइवेट निधियो से दी जाती हैं।

अन्तिम वात यह कि सन्तुलित आर्थिक अभिवृद्धि के लिए पूंजी की गतिशीलता भी आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा है, पूंजी उपलव्व कराने वाली आधुनिक सस्थाएँ—शेयर वाजार, निवेश निधियाँ, पेन्शन निधियाँ, वीमा कम्पनियाँ, वैंक और अन्य वित्तीय सगठन निवेश-पूंजी के अनेक प्रकार के स्रोत हैं और उनसे पूंजी को सर्वाधिक लाभकारी कामो मे लगाने मे सहायता मिलती है। फिर भी पूंजी मे उतनी गतिशीलता नही है जितनी कि होनी चाहिए। पेन्शन निधियो और निवेश निधियो का धन स्वभावत सरकारी हुडियो और वाजार के सवसे अच्छे शेयरो मे लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उपलव्व पूंजी का सब प्रकार के उद्योगो मे समान वितरण नही हो पाता।

कम्पनियो के विकास और विस्तार के लिए पूंजी का सवसे महत्त्वपूर्ण स्रोत उनकी अपनी आन्तरिक निधियाँ यानी मूल्य ह्रास निधि और अवितरित लाभ निधियाँ है। ये निधियाँ कम्पनी के अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखी जाती है। लेकिन वहुत-सी बडी कम्पनियो ने, जिनके पास ये निधियाँ वहुत वडी मात्रा मे जमा हो गई है, दूसरी फर्में, जिन्हे पूंजी की आवश्यकता है, अपने मे मिला ली है और इस प्रकार उनमे अपनी ये निधियाँ लगाकर उन्होने पूंजी की गतिशीलता को वढाया है।

इसके अलावा विशेष वित्तीय सुविधाओ की स्थापना कर, विशेष वर्गों और क्षेत्रो को, जैसे कृषको, छोटे उद्योग चलाने वालो और अनुन्नत इलाको आदि को, अनुकूल शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था की गई है।

एक गतिशील अर्थ-व्यवस्था मे प्रबन्धको, श्रमिको और पूंजी मे कुछ गतिशीलता कायम रखना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यदि व्यवसाय सचालको को यह भरोसा रहे कि सरकार विदेशी और आन्तरिक प्रतिस्पर्धा से उन्हे सरक्षण देगी और इस प्रकार उन्हे हमेशा मुनाफा मिलता रहेगा, यदि मजदूरो को यह भरोसा हो जाए कि वे हमेशा उसी काम पर लगे रह सकेगे, और यदि पूंजी लगाने वालो को यह यकीन रहे कि उन्हे कभी नुकसान नही होगा तो आर्थिक अभिवृद्धि की जीवन-शक्ति नष्ट हो जायगी। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण सुरक्षा तो सिर्फ कब्र मे है। एक गतिशील अर्थ-व्यवस्था मे व्यक्ति को एक ओर कम काम करने पर कम और अधिक अच्छा काम करने पर अधिक पुरस्कार देने की व्यवस्था कर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और दूसरी ओर अनुचित कष्टो और खतरो से उसकी रक्षा भी की जानी चाहिए।

साराश

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था अगले दस-पन्द्रह वर्षो मे प्राचुर्य के युग मे प्रवेश करती है या नही, यह आर्थिक और आर्थिकेतर और सरकारी और गैर सरकारी, दोनो क्षेत्रो मे किये जाने वाले बहुत से निश्चयो और कार्रवाइयो पर निर्भर है। आर्थिक क्षेत्र मे इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि आर्थिक वृद्धि की गति को काफी ऊँचा रखा जाय और मन्दी, मुद्रा-स्फीति और आर्थिक ढाचे की गतिहीनता को रोका जाय। सन् 1930 के दशक की अपेक्षा आज इन भावात्मक और निषेधात्मक कामो को अधिक अच्छी तरह समझा जा रहा है और साथ ही आज उनके लिए आवश्यक नीतियो और कार्यक्रमो को अपनाने की योग्यता और इच्छा भी लोगो मे पहले से अधिक है। यदि युद्ध को टाला जा सके तो कोई कारण नही कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की ये उज्ज्वल और आशा-पूर्ण सम्भावनाएँ निकट भविष्य मे अधिकाधिक पूर्ण न हो सके।

10

रहन-सहन का स्तर और आय का विभाजन

प्राय सभी देशो मे रहन-सहन के खासे ऊँचे स्तर की जनता की प्रबल और बढती हुई आकाक्षा हमारे जमाने की इतनी महत्त्वपूर्ण घटना बन गई है कि उसे 'बढती हुई आशाओ की क्रान्ति' भी कहा जाता है। वर्त्तमान शताब्दी से पूर्व मानव समाज यह मानता था कि विधाता ने ही आम जनता के भाग्य मे अनिवार्य रूप से गरीबी लिख दी है और जीवन की सुख-सुविधाएँ सिर्फ एक छोटे-से उच्चवर्ग के लिए ही हैं। लेकिन आज ससार भर मे भी सभी जगह लोगो ने इस विचार को ठुकरा दिया है। इसके विपरीत उनका यह विश्वास है कि रहन-सहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का एक अच्छा स्तर सभी लोगो को उपलब्ध होना चाहिए और वह सम्भव भी है। अनेक देशो मे, खासकर सयुक्त राज्य मे, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफी प्रगति की गई है। फिर भी सभी जगह, यहाँ तक कि सयुक्त राज्य मे भी, गरीबी की समस्या अभी तक विद्यमान है।

अमेरिका मे बढती हुई आशाओ की क्रान्ति का उद्देश्य अन्य देशो की अपेक्षा अधिक महत्त्वाकाक्षापूर्ण है। आज, अमेरिकी श्रमिक और कृषक एक ऐसे जीवन-स्तर की आशा करते है, जो अधिक सम्पन्न वर्ग के लोगो के जीवन-स्तर से प्रकार मे ही नही, मात्रा मे भी अधिक भिन्न न हो—और उनमे से बहुतो ने काफी हद तक यह जीवन-स्तर प्राप्त भी कर लिया है। इस दृष्टि से अमेरिका द्रुत गति से एक 'मध्य वर्गीय' राष्ट्र बन रहा है। यद्यपि कुछ वर्ग-भेद अभी तक मौजूद है, तो भी न तो वह पहले जैसा स्पष्ट और अपरिवर्त्तनीय है और न ही अपमानकारक

और न अन्य बहुत-से देशो मे अभी तक विद्यमान वर्ग भेद जैसा।

सयुक्त राज्य मे वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए हर आदमी को निम्नतम स्तर पर लाने का तरीका नही अपनाया गया, बल्कि यह कोशिश की गई है कि हर आदमी को ही ऊँचा उठाया जाय। अल्प-आय वर्गो की आय अनुपात के लिहाज से दूसरो से अधिक बढी है और दूसरी ओर बहुत अधिक ऊँची आय और समृद्धि की बढती को कम किया गया है। इसका अर्थ यह नही समझा जाना चाहिए कि यहाँ 'हर व्यक्ति की समान आय' के सामाजिक सिद्धान्त को अपनाया जा रहा है। यह सिद्धान्त अमेरिका के लोगो को कभी भी बहुत आकृष्ट नही कर सका। इसके विपरीत अमेरिकी लोगो ने यह यत्न किया है कि सब लोगो को समान अवसर मिले—खास तौर से शिक्षा और उत्पादक एव जीवन की आवश्यकता पूर्ति करने वाले धन्धे के अवसर।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की जो अभिवृद्धि हुई है उसके फलस्वरूप यहाँ जीवन का स्तर काफी ऊँचा हुआ है। और यदि अमेरिका अपनी निरन्तर सन्तुलित आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को भविष्य मे भी साकार कर सका तो सन् 1970 तक संयुक्त राज्य मे औसत अमेरिकी परिवार का रहन-सहन का स्तर इस समय के स्तर से कम-से-कम एक तिहाई और ऊँचा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम हो गया और शस्त्रीकरण का बोझ कुछ सीमित हो गया तो सम्भव है कि अमेरिका उससे भी जल्दी गरीबी का पूर्ण अन्त कर सके। किन्तु सयुक्त राज्य मे अवशिष्ट गरीबी को खत्म करने के लिए आवश्यक वृद्धि के साथ-साथ सरकार की नीतियों मे भी उचित परिवर्तन होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय आय के न्यायपूर्ण और समान विभाजन मे और भी सुधार हो। इसके लिए ये नीतियाँ अपनानी होगी—सघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो की कर-प्रणालियों मे परिवर्त्तन, गरजमन्द लोगो को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण; स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता कार्यक्रमो मे सुधार,

हमारे महानगर क्षेत्रो, शिक्षा-प्रणालियो और अन्य सामाजिक सस्थाओं मे परिवर्तन कर उन्हे आने वाले प्राचुर्य के युग के अनुकूल बनाना।

गरीबी के अवशेष

यद्यपि ऐसा कोई सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर अभी निर्धारित नही हुआ जिससे यह कहा जा सके कि कितनी आय पर्याप्त है और कितनी अपर्याप्त, तो भी सयुक्त राज्य मे आज भी ऐसे लोगो की सख्या बहुत बडी है जिनकी आय उससे कम है जितनी कि अमेरिकी लोग सन्तोष-जनक रहन-सहन के लिए आवश्यक समझते हैं। यद्यपि न्यूनतम स्तर से कम आय वाले वर्ग के स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयत्न किये गए हैं तो भी अमेरिका के शहरी और देहाती दोनो क्षेत्रो मे, अन्तर्राष्ट्रीय जीवन-स्तर की तुलना मे नही, अमेरिकी जीवन-स्तर की तुलना मे, अभी तक गरीबी मौजूद है। सन् 1959 मे लगभग 48 लाख, यानी 12 प्रतिशत, गैर-कृषक परिवारो की कुल आमदनी 3,000 डालर से कम थी। इसके अलावा 12 लाख, यानी 27 प्रतिशत, कृषक-परिवारो की कुल आमदनी 2,000 डालर से कम थी। और लगभग 40 लाख व्यक्तियो की भी, जिनका किसी परिवार से सम्बन्ध नही था, और जिनकी सख्या इस वर्ग मे आने वाले लोगो की सख्या का 38 प्रतिशत थी, आमदनी 2,000 डालर से कम थी।

लेकिन सयुक्त राज्य मे गरीबी की यह अवशिष्ट समस्या अतीत की गरीबी की समस्या से भिन्न है। पिछले दशक तक हाथ का श्रम करने वाले अधिकतर मजदूरो की आमदनी न्यूनतम वांछनीय जीवन-स्तर की दृष्टि से अपर्याप्त थी। परन्तु आज मजदूरी कमाने वाले लोगो की आमदनी न्यूनतम जीवन-स्तर से ऊँची है और जिस परिवार मे एक से अधिक व्यक्ति कमाने वाले है, उनकी गिनती तो मध्यम-आय वर्ग मे भी ऊँची स्थिति मे की जाती है। अवशिष्ट गरीबी तो खास-खास परिस्थितियो मे पाई जाती है— उदाहरण के लिए छोटी जोतो वाले फार्मों मे, हमेशा मन्दी का शिकार रहने वाले इलाको मे, कुछ खास आयु-वर्गों मे और ऐसे परिवारो मे

जिनके मुखिया कुछ कारणो से पूरे समय या समुचित मजदूरी पर काम नही कर सकते।

यदि 3,000 डालर वार्षिक से कम आमदनी वाले गैर-कृषक परिवारो का बारीकी से अध्ययन किया जाय तो अतीत काल की गरीबी का अन्तर स्पष्ट हो जाएगा। इनमे से आधे से अधिक परिवारो के मुखिया बीमारी, शारीरिक असमर्थता, बुढापा या रोजगार पाने की अयोग्यता या अनिच्छा के कारण बेकार थे। इनमे से लगभग 35 प्रतिशत परिवारो के मुखियाओ की आयु 65 वर्ष या इससे अधिक थी। कुछ परिवारो की मुखिया विधवाएँ या तलाकशुदा अथवा परित्यक्त पत्नियाँ थी, जिन्हे बच्चो का पालन करना था, लेकिन जिनके पास इतना समय, प्रशिक्षण और योग्यता नही थी कि वे पूरे समय का रोजगार या पूरी मजदूरी पर काम पा सके। बहुत-से अल्प-आय वर्ग के शहरी परिवार ऐसे थे जो सयुक्त राज्य के आर्थिक दृष्टि से कम विकसित हिस्सो से (खासकर पुएर्तोरिको से) आये थे और जिनके पास सामान्य शहरी धन्धो की योग्यता और कौशल की कमी थी। इसलिए आज शहरी इलाको मे पाई जाने वाली गरीबी का मुख्य कारण विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत अयोग्यताओ या असमर्थताओ के कारण उपर्युक्त काम पाने की कठिनाई है।

गरीबी के इन अवशिष्ट स्थलो का उन्मूलन करने के लिए केवल देश की आम आर्थिक अभिवृद्धि पर ही भरोसा नही किया जा सकता। हमारी कर-प्रणाली और आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमो से—विशेषत: जीविकोपार्जन की योग्यता को बढाने और भेदभाव को खत्म करने वाले कार्यक्रमो से—एव हमारे सख्यात्मक ढाँचो मे जीवन की परिवर्त्तमान पद्धतियो के अनुसार हेर-फेर से इस गरीबी के उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाये जा सकते है।

कर-प्रणाली

सयुक्त राज्य की आधुनिक आय-कर प्रणाली की एक आधारभूत विशेषता यह है कि पहले जहाँ आय-कर बहुत कम प्रतिशत लोगों पर

लगता था वहाँ अब वह अधिकतर आय-भोगियो पर लगता है। सन् 1939 मे मोटे तौर पर 7 प्रतिशत श्रमिको ने सघीय आय-कर के फार्म भरे थे किन्तु सन् 1959 मे आय-कर के फार्म भरने वाले श्रमिको का अनुपात 65 प्रतिशत से अधिक हो गया, क्योकि एक तो लोगो की आमदनियाँ बढ गई और दूसरे युद्ध-काल मे आय-कर के लिए आय की छूट की सीमा कम कर दी गई थी। वास्तव मे आय-कर देने लायक आमदनी वाले लोगो की सख्या इनमे भी अधिक है, क्योकि बहुत-से पति-पत्नी आय-कर के सयुक्त फार्म भरते है।

व्यक्तिगत सघीय आय-कर का सबसे निचला खण्ड 20 प्रतिशत कर का है, जब कि सबसे ऊँचे खण्ड मे व्यक्तिगत आय का 90 प्रतिशत सरकार आय-कर के रूप मे ले लेती है। किन्तु आय-कर की यह सबसे ऊँची दर बहुत कम लोगो पर लगती है, इसलिए अमेरिका मे औसत कर-भार कम है। इसके अलावा आय के काफी अश को आय-कर से मुक्त कर दिया जाता है और साथ ही कुछ किस्म की आय पर कर लगाया जाता है (जैसे कि पूंजी-लाभ पर), जिससे कुल आय पर कर का अनुपात कुछ कम हो जाता है। फिर भी यह अनुमान लगाया गया है कि जिन लोगो की वार्षिक आय 4,000 डालर से 5,000 डालर तक है, वे वास्तव मे सघीय सरकार को 8 प्रतिशत कर देते है, जब कि एक लाख डालर या इससे अधिक आय वाले लोग औसत 40 से 50 प्रतिशत तक आय-कर देते है। इसके अलावा कुछ राज्यो और नगरो ने भी आय-कर लगा रखे है, हालाकि उनके कर सघीय सरकार के करो की तुलना मे कम प्रगतिशील है।

अगर सभी प्रत्यक्षकरो को, चाहे वे सघीय हो या राज्यीय या नगरीय जोडा जाय तो 2,000 डालर से कम आय वाले व्यक्तियो और परिवारो पर 25 प्रतिशत, 6,000 डालर से 8,000 डालर तक की आय वालो पर 24 प्रतिशत, और 15,000 डालर से अधिक आय वालो पर 35 प्रतिशत कर-भार पडता है। सर्वोच्च आय वर्ग मे 50 प्रतिशत से भी

काफी अधिक आय उपर्युक्त सभी प्रकार के सरकारीआय-करों मे निकल जाती है। निम्नतम आय-वर्ग के परिवारो द्वारा अदा किये जाने वाले कर मुख्यत. उत्पादन-कर या स्थानीय शासनो द्वारा लगाये गए स्थावर सम्पदा-कर होते है जो उपभोग्य वस्तुओ के मूल्यो और मकान-भाड़ों में ही शामिल कर दिये जाते है। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि निम्नतम आय-वर्ग मे आने वाले परिवारो को ही उन सरकारी सहायता एव व्यय कार्यक्रमो का सबसे अधिक लाभ मिलता है जो खास तौर से गरीबी और असुरक्षा का सामना करने के लिए बनाये जाते है।

जैसा कि हमने देखा है, सन् 1920 के दशक के बाद सयुक्त राज्य के सबसे सम्पन्न 5 प्रतिशत लोगो की आमदनी मे वृद्धि औसत आमदनी मे हुई वृद्धि से कम है। इन लोगो की आमदनी का अधिकतर भाग व्यवसाय से हुए कुल मुनाफो से प्राप्त होता है। ये मुनाफे भी लगभग उतने ही बढे हैं जितनी कि मजदूरो को दी जाने वाली मजदूरी में वृद्धि हुई है। लेकिन निगम-कर (कार्पोरेशन टैक्स), व्यक्तिगत आय-कर और सम्पदा-कर आदि मिलकर इतने अधिक हो जाते है कि इन व्यावसायिक मुनाफो मे से इन्हे निकाल देने के बाद सम्पन्नतम वर्ग के अमेरिकी लोगो की आय और दौलत में वृद्धि बहुत सीमित रह जाती है।

सघीय सरकार की कर-प्रणाली मे अप्रत्यक्ष करो (उत्पादन-कर और बिक्री-कर) का भाग अन्य देशों की कर-प्रणालियो की तुलना में बहुत कम होता है। किन्तु सयुक्त राज्य मे राज्यीय और स्थानीय शासनो की कर-प्रणालियो मे अनुपात की दृष्टि से अप्रत्यक्ष करो का महत्त्व बहुत अधिक होता है। इसलिए सयुक्त राज्य की समूची कर-प्रणाली को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए संघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो के बीच वित्तीय सम्बन्धों मे परिवर्त्तन करना अत्यावश्यक होगा।

अमेरिकी कर-प्रणाली का विश्लेषण करने वाले कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यहाँ उच्च आय-वर्गों मे व्यावसायिक मुनाफे और व्यक्तिगत आय पर इतनी अधिक ऊँची दर से कर लगाये जाते हैं कि उनसे व्यवसायों

के प्रवन्ध की लाभकारी व्यवस्था और निवेश तथा कार्य के लिए प्रोत्साहन पर बुरा असर पडता है। दूसरी ओर इस के उत्तर में यह कहा जाता है कि पिछले एक दशक मे अपेक्षाकृत काफी ऊँचे कर होने पर भी व्यवसायो मे निवेश का स्तर ऊँचा ही बना रहा है और काम करने, धन बचाने और उसे व्यवसायो मे निवेश करने के प्रोत्साहन मे किसी तरह की कमी दृष्टिगोचर नही हुई। इतना होने पर भी व्यावसायिक मुनाफो और ऊँची आमदनियो पर कर की दरें अब इतनी ऊँची हो गई हैं कि यदि उनमे और वृद्धि की गई तो उससे राष्ट्रीय आय के समुचित और न्यायपूर्ण विभाजन मे सहायता उतनी नही मिलेगी जितना कि व्यवसाय-प्रवन्ध और पूंजी-निवेश को धक्का पहुँचेगा।

किन्तु सम्पन्न लोगो पर कर लगाने के तरीको मे सुधार के लिए अभी काफी गुजाइश है। उच्चतम आय-वर्ग पर आय-कर की दर इतनी ऊँची है कि सरकार को मजबूरन कुछ विशेष छूटें देनी पडी हैं जिनसे 'आय-कर प्रणाली मे कटाव' आ गया है। इसलिए अब यह कोशिश की जा रही है कि आय-कर के उच्चतम खण्डो मे कमी कर दी जाय, किन्तु साथ ही दूसरी ओर इस ऊँची दर के कारण अब तक जो विशेष छूटे दी जाती थी, उन्हे भी खतम कर दिया जाय, कर से बचने के रास्ते बन्द कर दिये जाएँ और सम्पदा-कर को अधिक प्रभावकारी बना दिया जाय। इसका परिणाम यह होगा कि ये सम्पन्न वर्ग कर तो लगभग उतना ही देते रहेगे, जितना अब देते है, किन्तु उसका ढग अधिक वाछनीय और युक्तियुक्त हो जाएगा।

कुल राष्ट्रीय आय का सबसे बडा भाग क्योकि अल्प और मध्यम आय-वर्गों के लोगो के हिस्से आता है, इसलिए यह कहना सम्भवत. अनुपयुक्त नही होगा कि सरकार के विशाल व्यय-कार्यक्रम केवल सम्पन्नतम व्यक्तियो पर लगाये गए करो की आय से ही नही चलाये जा सकते। इसे इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि जो लोग अपनी वार्षिक आय 20,000 डालर या इससे अधिक बताते हैं उनकी कुल आमदनी बिना कर काटे 30 अरब डालर के लगभग होती है, जब कि सघीय,

आर्थिक और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम

आर्थिक अभिवृद्धि से और मध्यम आय-वर्ग और उच्च आय-वर्ग पर लगाये जाने वाले भारी करो से वित्तीय साधनो मे जो वृद्धि होती है उस का मुख्य लाभ अल्प आय वाले बहुसख्यक वर्ग को ही प्राप्त होता है। वास्तव मे, आय के पुनर्वितरण की नीतियाँ उच्च आय वर्ग की आमदनियो को घटाने की दृष्टि से उतनी निर्धारित नही की जाती, जितनी कि निम्न आय वर्गो की आमदनियो को बढाने की दृष्टि से की जाती है।

हाल का आर्थिक विकास और सरकार के विशेष कार्यक्रम, दोनो ने ही अल्प-आय वर्ग के लोगो की अपनी वास्तविक आमदनी को विभिन्न तरीको से बढाने की योग्यता मे सुधार किया है। उदाहरण के लिए अमेरिका की विस्तीर्यमाण अर्थ-व्यवस्था मे स्त्रियो के लिए पूर्ण-कालिक और अंश-कालिक रोजगार के अवसर बढ रहे हैं और स्त्रियो और पुरुषो की मजदूरियो का अन्तर कम हो रहा है। स्त्रियाँ इन अवसरो का लाभ उठा रही हैं। कुल अमेरिकी श्रम शक्ति मे चौदह वर्ष या इससे ऊपर की आयु की मजदूर लडकियो की सख्या 1940 मे 26 प्रतिशत थी, किन्तु 1960 मे वह 36 प्रतिशत हो गई। काम के समय मजदूर स्त्रियो के बच्चो की देख-भाल की व्यवस्था कर दी जाती है और बहुत-से परिवार घरो मे अनेक काम, जो पहले स्त्रियो को हाथो से करने पडते थे, अब मशीनो से करने लगे है, इसलिए स्त्रियाँ मजदूरी करने के लिए पहले से अधिक अच्छी स्थिति मे हो गई है।

इसी प्रकार सघीय और राज्यीय सरकारो ने बीमारी, बुढापा, परिवार के पालक की मृत्यु, शारीरिक असमर्थता, बेरोजगारी या अन्य कारणो से आर्थिक सकट मे पडे लोगों की सहायता के लिए कुछ आपातकालिक और स्थायी कार्यक्रम बनाकर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर ले रखी है। फिर भी अमेरिका मे कुछ अन्य औद्योगिक राष्ट्रो की अपेक्षा राष्ट्र की आय का कम प्रतिशत भाग सामाजिक सुरक्षा पर खर्च किया जाता है (देखिये परिशिष्ट तालिका 22)।

केवल बेरोजगारी बीमा और सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत

आने वालों की सख्या ही नही बढ रही, बल्कि स्वास्थ्य और अस्पताल सेवा की व्यावसायिक बीमा योजनाओं और व्यावसायिक फर्मों, ट्रेड यूनियनों एव परोपकारी सगठनो द्वारा तेज़ी से बढाये जा रहे पेन्शन और जन-कल्याण कार्यक्रमो के अन्तर्गत आने वालों की सख्या में भी द्रुत गति से वृद्धि हो रही है।

तालिका 13

सरकारी और गैर-सरकारी बीमा और पेन्शन कार्यक्रम (1940-1960)
लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या लाख में

	1939-40	1949-50	1959-60
सरकारी			
बुढ़ापा और मृत्यु बीमा	354	464	750[1]
बेरोज़गारी बीमा	251	348	470[1]
राज्य कर्मचारी पेन्शन (संघीय, राज्यीय और स्थानीय शासन)	20	44	41
रेलवे पेन्शन	12	14	9
गैर सरकारी			
पेन्शन योजनाएँ	37	86	202
सामूहिक जीवन	अज्ञात	194	421
अस्पताली चिकित्सा	123	766	1279
शल्य क्रिया व्यवस्था	54	542	1169
नियमित चिकित्सा	30	216	826
बड़े इलाज की व्यवस्था	अज्ञात	1	219
आमदनी का जरिया न रहने पर सहायता	अज्ञात	378	432

यद्यपि इन सरकारी और गैर-सरकारी बीमा और पेन्शन कार्यक्रमों में भारी वृद्धि हो रही है, तो भी चालू लाभ योजनाओं से सभी व्यक्तियों

१. इसमें वे सभी लोग शामिल है जो वर्ष भर में किसी भी समय इन योजनाओं के अन्तर्गत आनेवाले रोज़गार में लगे हों।

को जीवन के सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक सकटो से उतना सरक्षण नही मिलता जिनना कि मिलना चाहिए। किन्तु यह आशा की जा सकती है कि मज़दूरियो, व्यावसायिक निवेशो और सरकारी सेवाओ मे वृद्धि के साथ सन्तुलन रखते हुए इन सरकारी और गैर-सरकारी कार्य-क्रमो मे भी कुछ विस्तार हो सकता है। उत्पादकता मे जैसे-जैसे वृद्धि होगी, वैसे-वैसे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर अनुचित वोझ डाले विना इन कार्यक्रमो से अधिकाधिक लोगो को अधिकाविक लाभ पहुँचाया जा सकेगा।

तालिका 14

चिकित्सा और निजी स्वास्थ्य बीमा

वर्ष	कुल व्यय (अरव डालरो मे)	प्रति व्यक्ति व्यय (डालरो मे)	कुल राष्ट्रीय आय का प्रतिशत अश
1948	7 ι5	52 68	2 3
1949	7 91	53·02	2·4
1950	8 65	57 50	2·4
1951	9·35	60 59	2 4
1952	10·10	65 84	2 5
1953	10 99	68 91	2 6
1954	11·84	74·45	2·8
1955	12 84	79 09	2 9
1956	14 29	86 42	3 1
1957	15 49	91 99	3 3
1958	16 76	97 77	3 6
1959	18 32	104 93	3·7

जहाँ गरीबी के निरन्तर बने रहने की वजह कोई ऐसे आर्थिक कारण हो, जो व्यक्ति के बस से बाहर हो, वहाँ सरकार उन आर्थिक

परिस्थितियों का इलाज करने के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम अपनाती है। उदाहरण के लिए सरकार ऐसे कृषको को, जो मुश्किल से अपना निर्वाह कर पाते है, सहायता देने के लिए अतिरिक्त कृषि-भूमि, बढिया बीज और उर्वरक, यान्त्रिक औजार और तकनीकी परामर्श आदि देने के कार्यक्रम अपनाती है या उन्हे दूसरा अश-कालिक या पूर्ण-कालिक काम प्राप्त करने मे सहायता देती है। कभी-कभी ऐसे इलाको मे रहने वाले परिवारो के कारण भी, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए है, विशेष समस्याएँ पैदा हो जाती है। यही नही, कुछ स्थानो पर कारखानो के स्थान मे परिवर्तन हो जाने या उपभोक्ताओ की रुचियाँ बदलने और नई वस्तुओ या उत्पादन-विधियो के आविष्कार से प्रतिस्पर्धा बढाने आदि के कारणो से भी श्रमिक आर्थिक सकट मे पड जाते है और उससे कुछ विशिष्ट समस्याएँ पैदा हो जाती है। अतीत मे आर्थिक शिथिलता या मन्दी वाले इलाके केवल स्थानीय समस्या समझे जाते थे। सरकार उनकी सिर्फ इतनी ही सहायता कर सकती थी कि जिन श्रमिको पर इस मन्दी का असर पडा हो उन्हे बेरोजगारी बीमा या आम सहायता कार्यक्रमो के अन्तर्गत ले। इनमे से कुछ इलाको मे व्यवसायियो ने स्वेच्छिक और सहकारी आधार पर अपने आर्थिक साधनो को एकत्र कर अपने मौजूदा बेकार कारखानो को नये कामो मे लगाना प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु अधिकतर मामलो मे ये समस्याएँ केवल स्थानीय प्रयत्नो से ही हल नहीं हो सकती। इसलिए हाल के वर्षों मे काग्रेस ने सघीय सरकार को यह अधिकार दे दिया है कि वह मन्दी के शिकार क्षेत्रो को नये उद्योगो को आकृष्ट करने और रोजगार के नये अवसर पैदा करने के लिए सहायता दे।

इसके अतिरिक्त सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी भी हैं जो अमेरिकी जनता की एक बड़ी सख्या को अपनी उपार्जन और उपभोग की क्षमता बढाने मे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देती हैं। उदाहरण के लिए सरकार सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, मनोरंजन, सस्ते मकानो का निर्माण, भूतपूर्व सैनिको की

सहायता आदि के रूप मे अनेक मुफ्त या सस्ती सेवाएँ और सुविधाएँ देती है। जाति, लिंग, धर्म या जन्म-स्थान आदि के कारण किये जाने वाले भेद-भावो को समाप्त करने वाले कानून भी लोगो की कमाई और जीवन-स्तर को बढाने मे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देते है।

गैर-सरकारी सस्थाओ के परोपकारी कार्य

सघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमो के अतिरिक्त गैर-सरकारी तौर पर भी बहुत-से ऐसे कार्यक्रम चलते है जिनका प्रयोजन लोगो के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना और जीवन के प्रकार को सुधारना है। इन कार्यक्रमो पर सन् 1956 मे 7 5 अरब डालर व्यय किये गए थे और उसके बाद से उनमे निरन्तर वृद्धि हो रही है। अनेक व्यक्ति, व्यावसायिक कम्पनियाँ, निजी समाजसेवी प्रतिष्ठान और धर्मार्थ-ट्रस्ट धर्म, समाज-कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान और कला आदि के क्षेत्रो मे बिना किसी लाभ-प्राप्ति की आकाक्षा के काम करने वाली निजी सस्थाओ को बहुत बडी मात्रा मे दान या सहायता देते है।

गैर-सरकारी तौर पर किये जा रहे परोपकार और समाज सेवा के कामो की विशालता और विविधता अमरीकी प्रणाली की एक विशिष्टता है। दान देना सिर्फ धनी लोगो का ही काम नही है, आम तौर पर सभी अमेरिकी परिवार जन-कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी कार्यों मे कुछ-न-कुछ योगदान अवश्य करते है। करीब 1950 के बाद से यह बात विशेष रूप से देखने मे आ रही है कि व्यावसायिक कम्पनियो ने स्थानीय समाजसेवी सस्थाओ और अस्पतालो को ही नही, राष्ट्रव्यापी स्तर पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य सगठनो, शिक्षा सस्थाओ, छात्रवृत्ति-कार्यक्रमो, सग्रहालयो और सास्कृतिक गति-विधियो और प्राकृतिक एव सामाजिक विज्ञानो की अनुसन्धान सस्थाओ को हमेशा बहुत बडी राशियाँ दान मे दी है।

बहुत-सी ऐसी सस्थाएँ या प्रवृत्तियाँ, जो अन्य देशो मे सरकार या

चर्च की वित्तीय सहायता पर निर्भर रहती हैं, सयुक्त राज्य मे पूर्णत: या अशत व्यक्तियो या व्यावसायिक फर्मो के स्वेच्छिक दान से ही चल जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरकार कर की छूट देकर स्वेच्छिक दान की इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी देती है। जो लोग स्वीकृत और विश्व सनीय परोपकारी सस्थाओ को दान देते है, उन्हे अपनी कुल कर-योग्य आय के 20 प्रतिशत तक भाग पर सघीय आय-कर से छूट मिल जाती है। (इसके अतिरिक्त धार्मिक और कुछ शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियो

तालिका 15

संयुक्त राज्य मे प्राइवेट दान का विवरण (1956)

	लाख डालरो मे	कुल का प्रतिशत
दान के स्रोत		
व्यक्तियो द्वारा दान	51,720	69
व्यावसायिक कम्पनियो द्वारा दान	5,100	7
धर्मार्थ ट्रस्ट	2,370	3
निजी प्रतिष्ठान	6 000	8
पूंजी से उपलब्ध आय (प्रतिष्ठानो को छोडकर)	10,000	13
कुल	75,190	100
दान प्राप्त करने वाले या दान के प्रयोजन		
धार्मिक संस्थाएँ	37,600	50
आम जन-कल्याण संस्थाएँ	17.300	23
शिक्षा	9,770	13
स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाएँ	6,760	9
प्रतिष्ठानों में नये [illegible]	2,260	3
विविध प्रयोजन	1.500	2
कुल	75,190	100

के लिए दान देने पर 10 प्रतिशत आय और भी कर से मुक्त कर दी जाती है) । व्यावसायिक कम्पनियाँ अपनी कुल आय का 5 प्रतिशत दान मे दे सकती है और उस राशि को काटने के वाद ही उन पर सघीय कम्पनी-कर लगता है ।

व्यक्तियो और कम्पनियो को दान की राशियो पर आय-कर मे जो छूट दी जाती है उसे इस आधार पर उचित वताया जाता है कि इनसे एक तो इस प्रकार के कार्यों का निर्णय करने और उन पर अमल करने मे लोग विना किसी सरकारी दवाव के स्वेच्छ या अपने विवेक से काम लेते हैं और दूसरे स्थानीय लोगो और इलाको मे आत्म-निर्भरता की भावना आती है । इससे काम की स्वतन्त्रता और विविधता वढती है और साथ ही इस वात की सम्भावनाओ मे भी वृद्धि होती है कि विज्ञान, शिक्षा और जन-कल्याण सम्वन्धी नये विचारो और नई कल्पनाओ को जनता से सहारा मिलेगा । इस प्रकार प्राइवेट तौर पर किये जाने वाले परोपकार और जन-कल्याण के कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रमो के पूरक वन जाते हैं और सयुक्त राज्य मे जीवन के स्तर और जीवन के प्रकार को ऊँचा उठाने मे महत्त्वपूर्ण योग देते है ।

जीवन पद्धति मे परिवर्त्तन

पिछले वीस वर्ष से ऊपर के अर्से मे जीवन-स्तर मे जो अभूतपूर्व विकास हुआ है और साथ ही उद्योगो और जन-सख्या मे भी जो द्रुत वृद्धि हुई है, उन्होने मिल कर अमेरिकी लोगो की जीवन-पद्धति मे वहुत वडे परिवर्त्तन किये है । इन परिवर्त्तनो मे से एक यह है कि लोगो के रहने और काम के स्थानो मे तवदीली हो गई है, जो किसी भी तरह कम महत्त्वपूर्ण नही है । कारखाने और घर अव शहरो से हटकर देहातो मे जाने लगे है । सडको मे सुधार होने और हर चार अमेरिकी परिवारो मे से तीन के पास अपनी निजकी मोटरे होने से अव लोगो के लिए अपने काम के स्थानो के नजदीक रहना जरूरी नही है । इसका परिणाम यह हुआ है कि उपनगरो और नजदीकी देहातो मे रिहायशी वस्तियाँ ढेर की

ढेर खडी हो गई है और शहरो मे या तो वृद्धि हुई ही नही और हुई भी तो बहुत मामूली। उदाहरण के लिए न्यूयार्क की आवादी वढने के वजाय उलटे घट गई है। सन् 1960 मे उसकी जन-सख्या 1950 की अपेक्षा 1,80,000 कम थी, क्योकि वहुत-से परिवार शहर छोड़कर उप-नगरो मे चले गए थे।

निवास और काम के ढाचे मे इस परिवर्तन ने जीवन के आराम और काम की परिस्थितियो मे वहुत सुधार किया है। लेकिन इसने वहुत-सी कठिनाइयाँ भी पैदा की है, खास कर वडे शहरो और राजधानी क्षेत्रो के लिए। इसका एक कारण यह है कि आज अमेरिका मे प्राइवेट मोटरो की सख्या मे भारी वृद्धि हो जाने के कारण, नये-नये चौडे राजमार्गो के निर्माण के कार्यक्रमो के वावजूद, सडको पर वहुत भीड होने लगी है और वस-सेवा आदि सामूहिक परिवहन सुविधाओ के आधुनिकीकरण की उपेक्षा हो रही है।

शहरो मे नागरिक सेवाओ के खर्चे वढ रहे है और उनसे सुविधाओ मे भी वृद्धि हो रही है, फिर भी शहर उसके अनुपात मे अपने साधनो का तेज गति से विकास नही कर पा रहे। अमेरिकी नगरो के सामने अपने कार्यों का पुनर्निर्धारण करने, अपनी पुरानी और अपर्याप्त सडको, गलियो, भवनो और सेवाओ का पुनर्निर्माण और अपनी म्युनिसिपल सस्थाओ और वित्त-व्यवस्था मे सुधार की गम्भीर समस्याएँ पहले से ही विद्यमान है और आगामी वर्षो मे वे और भी गम्भीर हो जाएँगी। इनमे से अन्तिम समस्या खासतौर से महत्त्वपूर्ण है और उसके हल के लिए नागरिक प्रशासन और नागरिक वित्त की नई व्यवस्थाएँ करनी पडेगी और उनकी लपेट मे पुराने नगर और नए विस्तीर्यमाण उपनगर, दोनो आ जाएँगे।

नगर प्रशासन और स्थानीय राजनीतिक गुट नई उठ रही समस्याओं का पहले से ही अनुमान करने और उनके समाधान के लिए प्रभावकारी उपाय अपनाने मे बहुत शिथिल रहे है। शासन की ओर से पर्याप्त पहल न होने के कारण कुछ इलाकों में कुछ प्राईवेट वर्गों ने इन समस्याओं

के स्वरूप और आकार का अध्ययन करना और उनके व्यावहारिक हल ढूढना प्रारभ कर दिया है। नगर-पुर्नविकास के ये वढते हुए आन्दोलन आम तौर पर व्यवसाय-सचालको, ट्रेड यूनियन नेताओ और खास-खास पेशो मे लगे लोगो के सयुक्त सहकारी प्रयास का परिणाम हैं। ये स्कूलो और अन्य सस्थाओ की, जिनके स्वरूप और कार्यो के आकार मे वहुत परिवर्त्तन हो गया है, समस्याओ के समाधान का प्रयत्न करते हैं।

अमेरिकी लोगो की जीवन-विधि मे दूसरा महत्त्वपूर्ण आधुनिक परिवर्त्तन अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता मे हुए भारी सुधार और स्वचालित यन्त्रो के अधिकाधिक उपयोग का परिणाम हे। अमेरिकी लोगो को अव अपने काम पर उतना समय खर्च नही करना पडता, जितना पहले करना पडता था, और इसमे तनिक भी सन्देह नही कि जैसे-जैसे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था और उन्नत होती जाएगी उन्हे और भी अधिक अवकाश मिलने लगेगा।

अमेरिका मे काम के घटे घटाकर इस समय औसत 40 घटे प्रति सप्ताह कर दिये गए है और वहुत-से काम ऐसे है जिनमे अब शारीरिक श्रम वहुत नही करना पडता और अव वे पहले की भाति वोझ नही मालूम होते। इसके परिणामस्वरूप इस समय मोटे तौर पर अमेरिकी लोगो के दिन का विभाजन इस प्रकार है उनका तिहाई दिन काम मे, तिहाई दिन खाली अवकाश मे और तिहाई दिन सोने मे व्यतीत होता है। जिन उद्योगो मे काम का समय प्रति सप्ताह 40 घटे से भी कम हैं, उनके वहुत-से श्रमिक खाली समय मे दूसरी जगह अशकालिक काम करके अपनी आमदनी वढाने का प्रयत्न करते है। किन्तु जैसे-जैसे वास्तविक मजदूरी वढती जाएगी, वैसे-वैसे इस तरह अतिरिक्त समय मे काम करने की पद्धति कम होती जाएगी। वास्तव मे श्रमिको की उत्पादकता इतनी वढ जाएगी कि दो जगह काम करना अवाछनीय हो जाएगा। इस तरह अमेरिकी लोगो का सोने के समय से अतिरिक्त खाली अवकाश का समय वढकर लगभग 40 प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा श्रमिको को हर वर्ष मिलने वाली छुट्टियाँ वढा दी जाएँगी, कम काम के दिनो मे

खाली बैठकर मजदूरी पाते रहने के दिनो मे भी वृद्धि हो जाएगी और यही नही, शायद सप्ताह मे काम के दिन, जो इस समय आमतौर पर पाँच होते है, घटाकर चार कर दिये जाएँ। यदि यह सब सम्भव हुआ तो अमेरिकी श्रमिको का खाली अवकाश का समय और भी बढ जाएगा।

समूचे मानवीय इतिहास मे यह बात देखने में आयी है कि मानव समाज के एक अल्पसख्यक और सौभाग्यशाली वर्ग के पास ही इतनी दौलत और इतना खाली वक्त होता है कि वह उसे अपनी इच्छानुसार रचनात्मक काम में लगा सके। मानव सभ्यता ने जो बड़े-बड़े उन्नति और प्रगति के काम किये है उनमे से बहुतो का श्रेय उन लोगो को है जिन्हे 'खाली निठल्ले रहने वाले' कहा जाता है। इन लोगों ने ही अपने अवकाश के दिनो मे कला, विज्ञान और विज्ञानेतर मानवीय विद्याओं मे अपनी प्रतिभा का विकास किया। अमेरिका में भी, पश्चिमी जगत् के अन्य देशो की भाति अधिकतर लोगो का दैनिक जीवन मुख्यत. काम करने और भौतिक अभावो की पूर्त्ति के लिए संघर्ष करने मे व्यतीत होता रहा है। उन्हे जो खाली समय मिलता था उसे वे 'मनोरंजन' में व्यतीत अवश्य करते थे, किन्तु यह समझ कर कि यह मनोरंजन बाद मे किये जाने वाले काम के वास्ते मनुष्य को तैयार करने के लिए जरूरी है। इस प्रकार दैनिक जीवन का समूचा आयोजन मूलत. काम और जीवन-संघर्ष के लिए होता था। लेकिन अब इतिहास मे यह पहला मौका आया है जबकि समूची जनता के लिए आराम और अवकाश भी एक सम्भावना बन गया है, बल्कि सम्भावना ही नही, एक समस्या बन गया है।

कुछ लोगो को इस बात मे सन्देह है कि पश्चिमी सभ्यता सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से ऐसी स्थिति में पहुँच गई है जहाँ काम के घंटों मे काफी कमी करके अवकाश के घंटो मे वृद्धि की जा सकेगी इन लोगों का कहना है कि काम के दिनों में मनुष्य के क्रिया-कलाप का निर्धारण मुख्यतः उनके सामने उपस्थित काम से होता है। और खाली अवकाश के दिनों में भी उसके क्रिया-कलाप कुछ हद तक उसके परिवार और समुदाय की आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों पर निर्भर होते हैं। किन्तु

काम के समय आदमी को अपने क्रिया-कलाप के लिए चुनाव की उतनी स्वतन्त्रता नही होती, जितनी अवकाश के समय होती है। और निर्णय करने की हर स्वतन्त्रता मे यह सम्भावना रहती है कि कही उसका दुरुपयोग न किया जाय।

अतीत मे जब कभी काम के घटो को घटाने की कोशिश की गई, किसी-न-किसी ने यह चिन्ता अवश्य प्रकट की कि लोगो को अधिक अवकाश मिलने का अर्थ यह है कि वे मदिरालयो, नाचघरो या जूआखानो मे अथवा पारिवारिक झगडो मे अधिक समय व्यतीत करने लगेंगे। किन्तु वास्तव मे ये चिन्ताएँ निराधार सिद्ध हुई है। इसका एक आशिक कारण यह है कि बहुत-से श्रमिको ने खाली समय मे दूसरे अशकालिक काम ले लिये। लेकिन इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि काम के दिनो या घटो मे कमी उस समय हुई है जिस समय श्रमिको की आमदनियाँ बढ रही थी और उनके रहन-सहन का ढग बदल रहा था। उदाहरण के लिए आमदनियाँ बढने से लोग भाडे के मकानो के बजाय अपने निजके मकान बनाकर रहने लगे और उससे उन्होने अपने खाली समय का उपयोग बागबानी या घर की सजावट और सुधार आदि अधिक आनन्ददायक और रचनात्मक कामो मे करना पसन्द किया।

अमेरिका मे युद्धोत्तर काल के प्रारम्भिक वर्षो मे 'अपना काम आप करो' की जो लहर चली वह सिर्फ उपभोग्य वस्तुओ की कमी का, या उसके बाद सेवाओ के महगी हो जाने का परिणाम नही थी, बल्कि वह बडी सख्या मे लोगो के अपने मकान बना लेने और उनके अवकाश के समय मे वृद्धि का अनिवार्य परिणाम थी। थोरस्टाइन वैब्लन ने जिसे 'मानव की कर्म-कौशल वृत्ति' अर्थात् अपने हाथो के रचनात्मक कार्य से आत्माभिव्यक्ति की आकाक्षा कहा है, उसकी बड़े पैमाने पर तृप्ति का भी यह एक प्रयत्न था। इसके अलावा खाली अवकाश के समय के और बहुत-से शौकों और दस्तकारी के क्रिया-कलापो और खेल-कूद एव घर से बाहर मनोरंजन की प्रवृत्तियो मे भी भारी

वृद्धि हुई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण विशाल राष्ट्रीय और राज्यीय मनोरजन उद्यानो मे मिल सकता है, जहाँ आनन्द-विहार के लिए कैम्प लगाने वालो, मछली पकडकर दिल बहलाने वालो और प्रकृति-प्रेमियो की भारी भीड रहती है। इन क्रिया-कलापो मे वृद्धि के कारण ही मनोरजन और खेल के सामानो की बिक्री बहुत बढ गई है।

कुछ अमेरिकी लोग इस बात से चिन्तित है, और उनकी यह चिन्ता अकारण भी नही है, कि खाली समय के अधिक बौद्धिक उपयोगो का भविष्य बहुत अच्छा नही है। उनका खयाल है कि सगीत का रसास्वादन और उसकी रचना, नाटक, पुस्तको का अध्ययन और प्रणयन, और अन्य कलाओ, मानवीय विद्याओ एव विज्ञानो का समुचित विकास नही हो सकेगा। उनकी राय मे सिनेमा आदि सामूहिक मनोरजन के साधनो और रेडियो, टेलीविजन आदि सचार साधनो के दर्शको और श्रोताओ की सख्या मे जिस तेजी से वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए सास्कृतिक मनोरजनो का रूप अधिकाधिक व्यावसायिक होता जाएगा और वे इस दृष्टि से दिये जाएँगे कि निम्नतम रुचि और प्रतिभा वाले लोगो का मनोरजन कर सके और इस प्रकार उनका स्तर गिर जाएगा। सिनेमा फिल्मो, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमो, सस्ती लोकप्रिय पत्रिकाओ और समाचारपत्रो मे उन्हे इस सास्कृतिक अधोगति के आसार अभी से नजर भी आने लगे है। वे यह चेतावनी भी देते है कि सामूहिक और विशाल पैमाने पर विज्ञापन के कुछ तरीके भी ऐसे है जिनसे लोगो की रुचियो मे यह पतन आ सकता है।

लेकिन इस बात के उत्साहवर्धक लक्ष्य भी सारे देश मे दिखाई दे रहे है कि अधिकाधिक अमेरिकी लोग सास्कृतिक विकास के अवसरो का लाभ उठा रहे है। उदाहरण के लिए रेडियो और टेलीविजन के जरिये सगीत, नृत्य और नाटक ऐसे लोगो तक भी पहुँच गए है जिन्होने 'शास्त्रीय' सगीत नृत्य और नाटको का कभी रसास्वादन नही किया था, बल्कि हमेशा उनका मजाक उडाया था। साहित्य, कला, इतिहास, विज्ञान और सार्वजनिक मामलो से सम्बद्ध कार्यक्रम भी आम तौर पर

अधिकाधिक अमेरिकी लोगो की रुचियो को परिष्कृत और प्रभावित कर रहे है। देश-भर मे शहरो और कस्बो मे प्राइवेट लोगो द्वारा चलाये जा रहे वाद्य-वृन्दो और सगीत-मण्डलियो की सख्या अधिकाधिक बढ रही है और उन्हे अधिकाधिक लोकप्रियता भी प्राप्त हो रही है। इससे लोगो मे सगीत का शौक बढने से वाद्य यन्त्रो और अच्छे सगीत के रिकार्डो की बिक्री मे वृद्धि हो रही है। अधिकाधिक शहरो मे पेशेवर नाटक मडलियाँ और रगमच और शौकिया कलाकारो के नाटक दल बढ रहे है। अमेरिकी लोगो की बहुत बडी सख्या चित्रकारी और मूर्ति-कला की शौकीन है और साप्ताहिक अवकाश और अन्य छुट्टी के दिनो मे सग्रहालय और चित्र-वीथिएँ दर्शको से भरी रहती है। उत्कृष्ट उपन्यासो और विद्वत्तापूर्ण पुस्तको के सस्ते सस्करणो की भारी बिक्री, जो अब भी निरन्तर बढ रही है, पिछले दशक की एक बडी सास्कृतिक घटना है। जो भी व्यक्ति सयुक्त राज्य मे लोक-सस्कृति की वास्तव मे जाँच-पडताल करने की चेष्टा करेगा, वह यह देखेगा कि यह सस्कृति बहुत प्राणवान् और विविधतापूर्ण है, भले ही वह उच्चतम कोटि की न हो।

तो भी अमेरिकी लोगो के सामने अगले कुछ दशको की जो बृहत्तम चुनौतियाँ विद्यमान है, उन मे से एक शिक्षा की प्रणाली मे सुधार करने की भी है, जिससे न सिर्फ अच्छे वैज्ञानिक, टैकनीशियन और कुशल श्रमिक तैयार हो, बल्कि प्राचुर्य और बाहुल्य का जो नया जमाना आ रहा है, उसमे सास्कृतिक विकास और मनोरजन के रचनात्मक क्रिया-कलापो के निरन्तर बढते हुए अवसरो मे भाग लेने की व्यक्ति की क्षमताओ मे भी वृद्धि हो सके।

साराश

आम जीवन-स्तर मे सुधार और अल्प-आय वर्ग के परिवारो के स्तर को ऊँचा उठाने की आवश्यकता सयुक्त राज्य मे केवल सामाजिक उद्देश्य के रूप मे ही स्वीकार नही की गई है, बल्कि वह आर्थिक आवश्यकता भी है। कारण, अमेरिकी उद्योगो का अस्तित्व बड़े पैमाने पर वस्तुओ

की बिक्री पर निर्भर है। केवल उच्च आय-वर्ग के लोगो का उपभोग का स्तर ऊँचा होना, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से कितना ही वाछनीय हो, अमेरिका के उद्योगो के बढते हुए उत्पादन की बिक्री की आवश्यकता पूरी करने के लिए काफी नही है।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि उत्पादकता-वृद्धि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जन-कल्याण की अभिवृद्धि उसके मुकाबले मे गौण वस्तु है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये दोनो एक-दूसरे का विकल्प नही है, बल्कि पूरक है। एक स्वस्थ लोकतन्त्र मे उत्पादकता को बढाने के लिए श्रमिको के कल्याण और सुख-सुविधाओं मे वृद्धि करना आवश्यक है, और उससे उत्पादकता बढ जाने पर सभी की सुख-समृद्धि बढती है। गडबडी तब पैदा होती है, जबकि दोनो को पूरक न मानकर एक के मुकाबले मे दूसरे पर अधिक बल दिया जाता है। यही कारण है कि व्यवसायियो, ट्रेड यूनियनो, कृषको और सरकारी अधिकारियो का सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायित्वपूर्ण और परस्पर सहकारी रवैया उत्पादकता और जन-कल्याण दोनो मे वृद्धि के बीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम रखने के लिए अत्यावश्यक है। यदि ऐसा नही होगा तो आर्थिक अभिवृद्धि मन्द हो जायेगी और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए निरन्तर की जा रही माँग को एक नियत और स्थिर राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण से ही पूरी करने का प्रयत्न किया जाएगा, जो अधिकतर निष्फल ही रहेगा। उसका अन्तिम परिणाम सामाजिक तनाव मे वृद्धि और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की और अधिक क्षति होगी।

सयुक्त राज्य ने उत्पादकता और रहन-सहन का स्तर, दोनों मे काफी वृद्धि के लक्ष्य एक साथ प्राप्त किये है। यदि उचित सन्तुलन कायम रखा गया और आर्थिक अभिवृद्धि जारी रही तो यह भरोसा किया जा सकता है कि अगले दस वर्षों मे, और शायद इससे भी कम समय में, कम आय के कारण होने वाली गरीबी अमेरिकी समाज के लिए कोई बड़ी समस्या नही रह जाएगी।

11

संयुक्त राज्य के उद्योगों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण

बडी और छोटी कम्पनियाँ और उनके प्रबन्धक अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे उत्पादकता की वृद्धि मे जो महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उसकी चर्चा हमने प्रथम भाग मे की थी। किन्तु हमने इस प्रश्न को बिना उत्तर दिये ही छोड दिया था कि क्या बडी कम्पनियो को नई औद्योगिक विधियो और प्रबन्ध विधियो से होने वाले लाभो की खातिर अमेरिका के लोकतन्त्र और स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा के आदर्शों का बलिदान कर दिया गया है। यह प्रश्न नया नही है। अमेरिकी इतिहास के दौरान मे अनेक बार यह प्रश्न पूछा जाता रहा है और विभिन्न प्रकार के कानूनो मे उसका उत्तर खोजने की चेष्टा की जाती रही है।

आज कुछ अमेरिकी लोगो का खयाल है कि लोकतन्त्र की रक्षा के लिए राजनीतिक और आर्थिक फैसले करने का काम विकेन्द्रित रहना जरूरी है और इस विकेन्द्रीकरण के साथ आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण का किसी भी तरह मेल नही बैठता। हैमिल्टन के सत्ता और सम्पत्ति पर राष्ट्र के स्वामित्व के सिद्धान्त और जैफर्सन के व्यक्ति की स्वतन्त्रता और आत्म-उत्तरदायित्व के सिद्धान्त मे प्रत्यक्षत जो विरोध नजर आता है उसे आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण का प्रश्न जितने स्पष्ट रूप मे प्रस्तुत करता है उतने स्पष्ट रूप मे कोई दूसरा प्रश्न प्रस्तुत नही करता। किन्तु हमारा विश्वास है कि इन दोनो सिद्धान्तो मे, जो अशत परस्पर-विरोधी है एक व्यावहारिक समन्वय अब होने लगा है।

केन्द्रीकरण की मात्रा

बडी कम्पनियाँ अमेरिकी उद्योग क्षेत्र पर वास्तव मे किस हद तक

छायी हुई है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आर्थिक केन्द्रीकरण को नापने के अनेक तरीके निकाले गए है।

बडी कम्पनियो के अपेक्षाकृत प्राधान्य और महत्त्व को नापने के लिए अमेरिका की सौ सब से बडी निर्माता कम्पनियों के बारे मे आँकड़े सचित किये गए है। सन् 1947 मे देश की 100 सबसे बडी निर्माता कम्पनियो का उत्पादन समूचे निर्माण-उद्योग के कुल उत्पादन का 23 प्रतिशत था। सन् 1954 मे वही बढ़कर 30 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया।[1]

इसका दूसरा पैमाना 'केन्द्रीकरण के अनुपात' को चित्रित करता है। यदि किसी विशिष्ट उद्योग की चार सबसे बड़ी कम्पनियाँ उस उद्योग के कुल पोत-लदान (शिपमेट) का 50 प्रतिशत या इससे अधिक पोत-लदान करती हो तो यह कहा जाता है कि उस उद्योग मे केन्द्रीकरण का अनुपात बहुत ऊँचा है। मध्यम दर्जे के केन्द्रीकरण वाले उद्योग वे माने जाते है जिनमे यह अनुपात 20 से 50 प्रतिशत तक होता है और कम केन्द्रीकरण वाले उद्योगो मे उनकी गिनती की जाती है जिनमे यह अनुपात 20 प्रतिशत से कम होता है।[2] उदाहरण के लिए मोटर गाडी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमे केन्द्रीकरण बहुत अधिक है, क्योकि इस उद्योग की चार सबसे बडी कम्पनियाँ सयुक्त राज्य मे कुल मोटर गाडियो के (जिनमे कार, बस, लारी, ट्रक और उनके पुर्जे भी शामिल है) पोत-लदान का 75 प्रतिशत पोत-लदान करती है। सन् 1947 और 1954 के बीच अधिक केन्द्रीकरण वाले उद्योगों का पोत-लदान का भाग कुल पोत-लदान के 25 7 प्रतिशत से बढकर 26.9 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि यद्यपि बिलकुल मामूली है तो भी वृद्धि तो है ही।

यद्यपि बडी कम्पनियों के महत्त्व और अधिक केन्द्रीकरण वाले

---

1. सन् 1947 और 1954 के लिए कुल उत्पादन के आंकडे और सन् 1960 के लिए कुल बिक्री के आंकडे लिये गए है।

2 देखिये परिशिष्ट तालिका 27।

उद्योगो के अनुपात मे हाल के वर्षो मे कुछ वृद्धि हुई है तो भी अधिक केन्द्रीकरण वाले उद्योगो की सख्या मे कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इस विरोधाभास का कारण यह है कि आम तौर पर उन्ही उद्योगो का तीव्र गति से विकास हुआ है जिनमे वडी कम्पनियो का प्राधान्य और केन्द्रीकरण का अनुपात ऊँचा था और जिन उद्योगो मे वडी कम्पनियाँ अधिक नही थी और केन्द्रीकरण का अनुपात भी ऊँचा नहीं था, उनका विकास उतनी तीव्र गति से नही हुआ।

इस प्रकार इस प्रश्न का निर्णय, कि क्या हाल के वर्षो मे केन्द्रीकरण मे थोडी वहुत वृद्धि हुई है या वह स्थिर रहा है, अशत इस वात पर निर्भर है कि इसके लिए पैमाना कौन-सा अपनाया जाता है। जो भी हो, यह निश्चित है कि यह वृद्धि वहुत अधिक नहीं हुई।

अमेरिकी उद्योगो मे वडी कम्पनियो का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व होने पर भी, अधिकतर श्रमिक आज भी अधिक केन्द्रीकरण वाले उद्योगो मे काम करते है। सन् 1954 मे कम केन्द्रीकरण वाले उद्योगो मे 63 लाख कर्मचारी काम करते थे। यह सख्या मोटे तौर पर निर्माण-उद्योगो के कुल कर्मचारियो की सख्या का 40 प्रतिशत थी। इसी प्रकार मध्यम केन्द्रीकरण वाले उद्योगो मे 57 लाख कर्मचारी थे, जो कि निर्माण-उद्योगो की कुल कर्मचारी सख्या का 36 प्रतिशत थे। अधिक केन्द्रीकरण वाले उद्योगो मे कर्मचारियो की सख्या और निर्माण-उद्योगो की कुल सख्या के मुकावले मे उसका अनुपात दोनो क्रमश 39 लाख और 24 प्रतिशत थे। इस प्रकार यह जाहिर है कि निर्माण उद्योगो के तीन-चौथाई कर्मचारी कम या मध्यम केन्द्रीकरण वाले उद्योगो मे काम करते है। कपडा, सिले-सिलाये वस्त्र, लकडी, लकडी का सामान और छपाई आदि उद्योगो मे कोई खास केन्द्रीकरण नही है। कुछ सेवा-उद्योगो मे भी छोटी इकाइयो का ही वाहुल्य है। उदाहरण के लिए, इस देश के मुख्य राष्ट्रीय मार्गों के साथ-साथ 41,000 मोटल (ऐसे होटल, जहाँ पर्यटक अपनी मोटरो के साथ ठहर सकते है)

स्थापित है। पाँच लाख से अधिक सस्थान, यानी कुल सेवा-सस्थानो के आधे से अधिक, ऐसे व्यक्तियो द्वारा चलाये जाते है, जो स्वय मालिक भी है और कर्मचारी भी। इस तरह अमेरिका मे, ऐसे लोगो के लिए, जो अपने मालिक खुद बनना चाहते है, बहुत अवसर है।

ये आँकडे इस अतिरजनापूर्ण धारणा का खण्डन करते है कि अमेरिकी उद्योगो पर कुछ बडी कम्पनियाँ छाई हुई है। फिर भी इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता कि अधिकतर गतिशील उद्योगो मे बडी कम्पनियो का बहुत महत्त्व है और इन थोडी-सी बडी कम्पनियो की आपसी प्रतिस्पर्धा बहुसख्यक छोटी कम्पनियो की आपसी प्रतिस्पर्धा से भिन्न किस्म की है। यह स्थिति वास्तव मे चिन्ता जनक है।

केन्द्रीकरण के सम्बन्ध में चिन्ता के कारण

निजी उद्योग की आधारभूत विचारधारा यह है कि एक बन्धनहीन और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ-व्यवस्था मे किसी भी उद्योग मे कोई खास कम्पनी इस उद्योग के अन्य कारखानो पर छायेगी नही। यदि किसी कम्पनी मे मुनाफे की गुजाइश इतनी अधिक है कि उसका और विस्तार किया जा सकता है तो इस बात की सम्भावना है कि उस क्षेत्र मे उसके कुछ प्रतिस्पर्धी खडे हो जाएँ। इसके अलावा हर कम्पनी का विस्तार एक निश्चित सीमा तक ही हो सकता है। उससे अधिक विस्तार होने पर उसकी कार्यकुशलता कम हो जाएगी और उत्पादन-व्यय बढ जायगा। इस प्रकार यह समझा जाता है कि स्वतन्त्र और प्रतिस्पर्धा-युक्त अर्थ-व्यवस्था विकेन्द्रित आर्थिक सत्ता वाली प्रणाली है।

कुछ यूरोपीय देशो मे कम्पनियो की आपसी प्रतिस्पर्धा की उग्रता को कम करने के लिए कुछ विशिष्ट उद्योगो की उत्पादक कम्पनियो ने कीमते न गिरने देने के लिए आपस मे सघ (कार्टल) बनाकर समझौते कर लिये हैं। किन्तु सयुक्त राज्य मे कम्पनी-गुटो के निर्माण को रोकने वाले कानून बनाकर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को सीमित करने

वाली इस प्रवृत्ति को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ उन्हीं उद्योगो मे इस प्रकार आपसी समझौतो से बने हुए कम्पनी-गुट है, जिनमे इसके लिए विशेष रूप मे कानून द्वारा अनुमति दी गई है। कम्पनी-गुटो के समझौते अमेरिकी लोगो की साहस, उद्यम और गतिशीलता की भावना के भी प्रतिकूल हैं। वे यह नही चाहते कि उनके विस्तार और प्रसार के ससर्ग मे किसी भी प्रकार की बाधा आये, चाहे वह स्वय ही खडी की गई हो। उनकी यह प्रतिक्रिया सन् 1930 के दशक मे मन्दी के प्रभाव से उबरने के लिए किये गए प्रारम्भिक प्रयत्नो के समय स्पष्ट दीख पडी थी। उस समय कुछ उद्योगो मे इन कम्पनी-सघो (कार्टलो) जैसी 'साकेतिक कूट प्राधिकारो' (कोड अथारिटीज) व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था, किन्तु उसका बहुत विरोध किया गया। इसीलिए जब उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के उत्पादक कम्पनियो के सघ निर्माण के प्रयत्न को अवैध ठहरा दिया तो आम तौर पर व्यावसायिक वर्ग के भीतर और बाहर इसका स्वागत किया गया।

लेकिन अमेरिका मे उत्पादक कम्पनियो के सघ न होने का अर्थ यह नही है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। इसके विपरीत कुछ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उद्योगो मे थोडी-सी बडी कम्पनियो का ही बाजार पर प्रभुत्व है और इन उद्योगो मे नये आने वाले उद्यमी उत्पादको को इन पुरानी और जमी हुई विशाल कम्पनियो को चुनौती देने मे भारी कठिनाई का सामना करना पडता है।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि ये विशाल कम्पनियाँ प्रतिस्पर्धा के सघर्ष मे सफल है और उत्पादकता को बढाने मे इतना महत्त्वपूर्ण योग देती है तो उनको लेकर चिन्ता करने की क्या बात है। इस प्रश्न के उत्तर मे इन कम्पनियो से चिन्ता के पाँच मुख्य कारण बताये है

1. यद्यपि यह सही है कि जब तक किसी उद्योग मे परस्पर प्रति-

स्पर्धा करने वाली बहुत-सी कम्पनियाँ विद्यमान है, तब तक वास्तविक अर्थो मे उस उद्योग मे 'एकाधिकार' जैसी चीज़ नही है, तथापि थोडी-सी कम्पनियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बहुतो की आपसी प्रतिस्पर्धा से भिन्न चीज है। ऐसे उद्योगो मे, जिनमे प्रमुख फर्मे थोडी-सी है, उत्पादित वस्तुओ के जो मूल्य चलते है, और जिन्हे 'सुव्यवस्थित' मूल्य कहा जाता है, वे सैकडो प्रतिस्पर्धियो की प्रतिस्पर्धा से बाजार मे स्वत. बनने वाले मूल्यो से भिन्न होते है। इसलिए स्वभावत. ऐसे उद्योगो मे इस बात की सभावना रहती है कि वे मूल्यो को साधारणत. औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप बनने वाले स्तर से ऊँचे स्तर पर रखा सके और मौका पडने पर उन्हे उससे और भी ऊंचा उठाया जा सके।

2. किसी उद्योग मे कुछ सौ वडी कम्पनियों का पूँजी-निवेश उस उद्योग के कुल निजी निवेश का एक बहुत भाग होता है। इस निवेश को भी 'सुव्यवस्थित' निवेश कहा जा सकता है। यह निवेश बडी कम्पनियो के प्रबन्धको की भावी व्यवसाय सम्बन्धी आशाओ के अनुरूप किया जाता है और इसीलिए आर्थिक गति-विधि के वास्तविक स्तर को निर्धारित करने मे उसका बहुत हाथ रहता है।

3 यदि कम्पनियाँ बहुत बडी हो तो हजारो प्रबन्ध अधिकारी, इजिनीयर, वैज्ञानिक और अन्य कर्मचारी तथा हजारो तथाकथित 'स्वतन्त्र' विक्रेता और लाखो या करोडो उपभोक्ता एक ही कम्पनी पर आश्रित हो जाते है। इससे कर्मचारियो के लिए अपने रोजगार के वास्ते फर्म का चुनाव करने, व्यापारी के लिए बिक्री के वास्ते वस्तुओ को चुनने और उपभोक्ता के लिए खरीद के वास्ते वस्तुओ को पसन्द करने की गुजायश बहुत कम रह जाती है।

4. यह सम्भव है कि बडी फर्में छोटी फर्मो के, चाहे वे उत्पादन मे अधिक कुशल ही क्यो न हो, बाजार मे उतरने में बाधा पैदा कर सके। बड़ी फर्में अपनी आर्थिक सम्पन्नता का अनेक प्रकार से उपयोग कर सकती है। वे अपने माल के विज्ञापन पर इतनी विशाल रकमे खर्च कर सकती है कि वे छोटी फर्मो की पहुँच से बाहर हो। वे कुछ समय तक 'मूल्य

सम्बन्धी युद्ध' भी चला कर छोटी फर्मों को बाजार से निकालने की कोशिश कर सकती है। वे विक्रेताओ के साथ इस आशय के समझौते कर सकती हैं कि वे सिर्फ उन्ही का माल बेचे। इसी तरह के दूसरे कार्य भी वे कर सकती है जो छोटी फर्मों की क्षमता से बाहर हो। इसके अलावा बडी फर्मे पेटेण्टो के मामले मे भी आपस मे समझौता कर लेती है, जिससे वे आपस मे तो एक दूसरे के पेटेण्ट का उपयोग कर लेती हैं, परन्तु नई फर्मों को उसका उपयोग नही करने देतीं। लेकिन कम्पनी-गुटो के निर्माण के विरुद्ध बनाये गए कानूनो मे आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग की इन सम्भावनाओ को कुछ हद तक सीमित अवश्य कर दिया गया है, परन्तु उसका पूर्णत अन्त नही हुआ।

5 आर्थिक सत्ता के कुछ थोडे-से लोगो मे केन्द्रित होने का परिणाम यह भी हो सकता है कि वे लोग अनुचित रूप से राजनीतिक दबाव डाले।

विशालता और एकाधिकार

आर्थिक सत्ता के भी, अन्य सत्ताओ की भाति उपयोग और दुरुपयोग, दोनो सम्भव है। स्वभावत सर्वोत्तम नीति यह होगी कि आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को तो रोका जाय, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाय कि अर्थ-व्यवस्था बडी कम्पनियो की उपयोगिता, कार्य-कुशलता और ऊँची उत्पादकता के लाभो से वचित न हो। लेकिन आम तौर पर आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश करते समय विशाल फर्मों की समस्याओ और एकाधिकार की समस्याओ, दोनो को एक समझ लिया जाता है। यह ठीक है कि इन दोनो की समस्याओ मे परस्पर सम्बन्ध है, तो भी वे एक नही है। आम परम्परागत विचारधारा मे यह समझा जाता है कि यदि बहुत-से उत्पादक एक ही बाजार मे अपना माल बेचे और हर एक-दूसरे से सस्ता माल बेचने के लिए कीमत इतनी कम कर दे कि वह सारा उत्पादन, जिससे लाभ होने की सम्भावना हो, बाजार मे खप जाय तो किसी फर्म का एकाधिकार नही रहता। हमने ऊपर

बताया है कि अनेक उद्योगो मे, और खुदरा व्यापार मे भी, इस तरह की जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा न केवल हाल के दशको मे कायम रही है, बल्कि और भी बढी है। लेकिन कुछ उद्योगो मे प्रतिस्पर्धा का रूप बदला है। उनमे मूल्यो की प्रतिस्पर्धा ने वस्तुओ की किस्म, डिज़ाइन और उधार की शर्तो की प्रतिस्पर्धा का रूप धारण किया है।

इसके अलावा एक और किस्म की प्रतिस्पर्धा भी धीरे-धीरे बढ रही है। उदाहरण के लिए रेल परिवहन को सडक परिवहन और विमान परिवहन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड रहा है और रेल परिवहन उद्योग मे आर्थिक केन्द्रीकरण बहुत अधिक मात्रा मे होने पर भी यह प्रतिस्पर्धा काफी जबर्दस्त है। इसी तरह बिजली के पारेषण (ट्रान्समिशन) के लिए तार और अन्य सामग्रिया सप्लाई करने मे ताबा और एल्युमीनियम उद्योगो मे प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना इस्पात उद्योग को एल्युमीनियम और अन्य हल्की धातुओ के उद्योगो से करना पड रहा है और एक-न-एक दिन उसे इसी का सामना विकिरण द्वारा मजबूत बनाये गए प्लास्टिक के उद्योग से भी करना पडेगा। इसी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला तेल और गैस उद्योगो को भी परमाणु शक्ति से करना पडेगा। छोटे खुदरा दुकानदारो, भण्डार-शृङ्खलाओ, सहकारी दुकानो और डाक से आर्डर लेकर माल सप्लाई करने वाली बडी दुकानो मे भी इसी तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही है। इस तरह की प्रतिस्पर्धा नई तकनीकी विधियो का आविष्कार कर या प्रबन्ध सम्बन्धी नई तकनीको को अपनाकर बहुत प्रभावकारी ढग से चलाई जा सकती है।

महत्त्व लम्बे अर्से के बाद ही नजर आता है। यह सही है कि कोई-कोई समय ऐसा भी हो सकता है जबकि कुछ उद्योग, जैसे कि इस्पात या रासायनिक सामान के उद्योग, काफी व्यापक शृङ्खला मे वस्तुओ की कीमतो को निर्धारित करने मे बडा असर डाल सकते हो। खासकर, ऐसे उद्योगो मे, जिनके उत्पादनो की माँग अधिक घटती-बढती नही है, यह सम्भव है कि कुछ कम्पनियाँ अपने मुनाफे बढा सके या कम से कम उनमे कमी न होने देने के लिए अपनी कीमते उस स्तर से ऊँची रखे, जो विशुद्ध प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से आवश्यक है। किन्तु इन उद्योगो मे कीमते अन्तत इतने ऊँचे स्तर पर नही रखी जाएँगी, कि उपभोक्ता लोग ऐसी दूसरी वस्तुओ की खोज करने लगे जिनसे उनकी जगह काम चल सके। इन उद्योगो मे उत्पादनो की कीमते न तो इतनी गिरने दी जाती है कि उनसे उन पर आने वाली लागत ही न निकल सके और न उन्हे इतना ऊँचा जाने दिया जाता हे कि लोग उनकी जगह काम दे सकने वाली दूसरी चीजे निकालने के लिए प्रयत्न करे। लेकिन इन दोनो सीमाओ के मध्य मे रहने पर भी मूल्यो का निर्धारण बाजार की प्रतिस्पर्धा मे नही होता, बल्कि इन उद्योगो के सचालक ही ये मूल्य निर्धारित करते है। अर्थशास्त्री लोग इन्ही मूल्यो को 'सचालको द्वारा निर्धारित मूल्य' कहते है।

आर्थिक दृष्टि से निर्धारित मूल्य-सीमाओ के भीतर वास्तविक मूल्य निर्धारित करते समय समझदार और उत्तरदायित्व का ज्ञान रखने वाले व्यवसायियो को और भी अनेक बातो का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जनमत, कम्पनी गुटो के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की सम्भावना, सामूहिक सौदेबाजी और बाजार की दीर्घकालिक सम्भावनाओ आदि पर मूल्य नीति का प्रभाव। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस अर्थ-व्यवस्था मे बडी कम्पनियो का बहुत महत्त्व है, उसकी आर्थिक नीति सम्बन्धी समस्याएँ उस अर्थ-व्यवस्था की समस्याओ से बिलकुल भिन्न होगी, जिसका मुख्य लक्ष्य प्राइवेट उद्योगो के एकाधिकारो को खत्म करना और प्रतिस्पर्धा को बनाये रखना होता है। इस भेद पर और आर्थिक नीति

के लिए उसके महत्त्व पर विचार करने से पूर्व संयुक्त राज्य के कम्पनी-गुट विरोधी (ऐंटी-ट्रस्ट) कानून के क्रमिक विकास पर एक नजर डालना उपयोगी होगी ।

कम्पनी-गुट विरोधी क़ानून

सन् 1787 मे जैफर्सन ने अमेरिकी लोगो से अनुरोध किया था कि वे अपने सविधान मे एक एकाधिकार-विरोधी व्यवस्था का समावेश कर ले । कम्पनी-गुट विरोधी सघीय कानून बनने से काफी पहले ही अनेक राज्यों ने कम्पनियो के गुटो और एकाधिकार की प्रवृत्ति के विरुद्ध कानून बना डाले थे । लेकिन ये कानून मुख्यत आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण के विरुद्ध जनता के भय को अभिव्यक्त ही करते थे, एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकते नही थे । सन् 1890 में काग्रेस (ससद्) द्वारा कम्पनी-गुट विरोधी शेरमान कानून पास किये जाने के बाद ही पहले पहल सघीय सरकार ने एकाधिकार की प्रवृत्तियो को रोकने के लिए आवश्यक अधिकार अपने हाथ में लेने प्रारम्भ किये । बाद मे सन् 1914 मे क्लेटन के कम्पनी-गुट-विरोधी कानून और सन् 1950 के विलय-विरोधी कानून से सरकार के इन अधिकारों को परिवर्त्तित परिस्थतियों और समस्याओं के अनुकूल बनाया गया ।

सन् 1890 और 1914 के कम्पनी-गुट विरोधी कानूनो का प्रयोजन मुख्यत व्यापार-निरोधक कार्रवाइयों को, अर्थात् बडी कम्पनियो की उन व्यक्तिगत या सामूहिक कार्रवाइयो को रोकना था, जिनसे वे किसी उद्योग मे प्रतिस्पर्धा को बहुत कम कर सकती थी, किसी खास उत्पादन के लिए बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकती थी या लागत न बढ़ने पर भी अपने उत्पादन का मूल्य बढ़ा सकती थी । प्रारम्भ मे अदालतो ने सन् 1890 के कानून को दृढता से लागू नही किया । लेकिन उन्नीसवी शताब्दी की समाप्ति पर उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के फलस्वरूप इस कानून का अधिक कठोरता से पालन कराया जाने लगा और सन् 1914 के क़ानून से उसका और भी विस्तार हुआ । उसके

बाद से कम्पनी-गुट-विरोधी कानूनो का और भी दृढता से पालन कराया जाने लगा, खासकर ऐसे मामलो मे जहाँ कोई उत्पादक कम्पनी अपने प्रतिस्पर्धियो को खत्म करने या अन्य तरीको से बाजार पर हावी होने की कोशिश करती। कभी-कभी तो सरकार ने किसी उत्पादक कम्पनी के खिलाफ एकाधिकार की कार्रवाइयो और मूल्यो को मनमाने स्तर पर रखने के प्रयत्नो के सुबूत मिलने से पहले ही कार्रवाई कर दी।

कुछ हद तक कम्पनी-गुट-विरोधी कानून की व्याख्या इस प्रकार की जाने लगी, मानो वे केवल व्यापारिक प्रवृत्तियो का निरोध करने वाली मौजूदा कार्रवाइयो को रोकने के लिए ही नही, बल्कि उनकी सम्भावनाओ को रोकने के लिए भी बनाये गए हो। यह सम्भावना तब समझी जाती थी जब कि कोई कम्पनी दूसरी कम्पनियो का अपने साथ विलय करके अपने आकार को अपने उद्योग या बाजार की तुलना मे अधिक बडा बना लेती थी। कम्पनी-गुट-विरोधी कानून का प्रयोजन इस प्रकार के विलयो को रोकना भी है, इस बात की पुष्टि सन् 1950 के विलय-विरोधी कानून से हो जाती है। इस कानून ने कम्पनियो के इस तरह के विलय को रोकने की कार्रवाई को और भी सुदृढ बनाया। यह कानून द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कम्पनियो के विलय की घटनाएँ बडे पैमाने पर होने के कारण बनाया गया। हाल के वर्षो के इन व्यावसायिक विलयो ने नई समस्याएँ खडी कर दी है और कम्पनी-गुट-विरोधी नीति के उद्देश्यो और इस नीति पर अमल के बारे मे कुछ पुराने विवाद खडे कर दिये है।

कुछ उद्योग ऐसे है, जिन्हे आर्थिक या सुरक्षा सम्बन्धी कारणो से प्राइवेट उत्पादको की अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा के लिए नही छोडा जा सकता। ये उद्योग है सार्वजनिक उपयोग के उद्योग, जैसे रेल, सडक और जल परिवहन, बिजली और गैस, टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो और टेलीविजन। यद्यपि अन्य अनेक देशो मे इन सब या अधिकाश उद्योगो पर सरकार का एकाधिकार है तो भी सयुक्त राज्य मे इनमे से अधिकाश उद्योग प्राइवेट लोगो के हाथो मे है, परन्तु सरकार उन पर नजर रखती

है। इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे कुछ म्युनिसिपैलिटियो द्वारा सचालित नागरिक परिवहन सर्विसे, सघीय सरकार द्वारा संचालित डाक-सेवा और सरकार द्वारा चलाये जा रहे बिजली के उत्पादन और वितरण के कुछ कारखाने, जो आमतौर पर सरकार की बहुद्देश्यक नदी-परियोजनाओं के अंग है।

प्राइवेट व्यक्तियो द्वारा चलाये जाने वाले जनोपयोगी सेवा-उद्योगो के सघीय और राज्यीय सरकारो द्वारा नियमन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को कम करना है क्योकि वह इन उद्योगो के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसका दूसरा उद्देश्य उपभोक्ताओ को पर्याप्त मात्रा मे ये सेवाएँ उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा इन उद्योगों को अपने स्वामित्व और नियन्त्रण मे लिये जाने के बजाय इन्हे प्राइवेट व्यवसायियो के हाथो मे रखते हुए इन पर अपनी नजर रखने के लाभ और हानियाँ दोनो है। एक ओर बहुत-से अमेरिकी यह समझते है कि बडे-बडे सरकारी उद्योगों से बचना एक लाभ है। दूसरी ओर सरकार के ऊपरी निरीक्षण और नियमन की आवश्यकता मे एक नुक्सान भी है और वह यह कि अनेक प्राइवेट हित अक्सर नियामक सरकारी सगठनो के निर्णयो को प्रभावित करने का प्रयत्न करते है। लेकिन नियमन के समर्थको का कहना है कि कुछ मामलो मे नियामक संगठन परिवहन, सचार और बिजली आदि के क्षेत्रो मे न केवल एक ही काम के एक से अधिक कम्पनियो द्वारा किये जाने और इस प्रकार श्रम और धन के अपव्यय को रोकते है, बल्कि पहले से जमी हुई कम्पनियो को हानिकर प्रतिस्पर्धा से भी बचाते है। जो भी हो, नियामक सरकारी सगठनो के कामो मे यदि इस किस्म की कुछ त्रुटियाँ हो तो उनकी कांग्रेस मे और जनता मे आलोचना हो सकती है और इस आलोचना के फलस्वरूप उनमे सुधार भी सभव है। जनोपयोगी सेवा उद्योगो के सचालन की विभिन्न पद्धतियो के गुण-दोष चाहे कुछ भी हो, अधिकतर अमेरिकी लोगो का यह खयाल है कि इस प्रकार के जनोपयोगी सेवा उद्योगो के राष्ट्रीयकरण अथवा प्राइवेट कम्पनियो द्वारा अनियन्त्रित और मनमाने तौर पर सचालन के बजाय

अच्छा है कि ये उद्योग रहे प्राइवेट व्यवसायियो के हाथो मे, किन्तु इन पर सरकार का निरीक्षण और नियमन रहे।

बडी कम्पनियो का गठन और कार्य

इस समय सरकार के कम्पनी-गुट-विरोधी रुख और व्यावसायिक गति-विधि के सरकार द्वारा नियमन की अन्तर्निहित विचारधारा पर नये सिरे से पुनर्विचार किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि बडी कम्पनियो द्वारा चलाये जाने वाले व्यवसायो और व्यावसायिक प्रबन्ध के स्वरूप मे हाल मे महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन हुए है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे वडी कम्पनियाँ जो रचनात्मक भूमिका अदा करती है, उसके महत्त्व को अब अधिकाधिक स्वीकार किया जाने लगा है। यही कारण है कि अब यह माँग पहले की भाति उग्र नही रही कि कम्पनी-गुट-विरोधी कानूनो का उपयोग कम्पनियो के आकार को नियन्त्रित करने और उन्हे बहुत बडी कम्पनियो का रुख धारण न करने देने के लिए किया जाय। अमेरिकी जनता ने, यहाँ तक कि ट्रेड यूनियनो ने भी, यह स्वीकार कर लिया है कि बडी कम्पनियाँ इस देश मे रहेगी ही लेकिन इसका यह अर्थ नही है कि इससे कम्पनियो के बडे-बडे गुटो के निर्माण को रोकने वाला कानून कम महत्त्वपूर्ण हो जायेगा।

कम्पनियो के आकार के सम्बन्ध मे जनमत मे हाल मे जो भारी परिवर्त्तन हुआ है उसके अनेक कारण है। लोग अब यह महसूस करने लगे है कि बहुत-सी कम्पनियो मे जैसी उग्र प्रतिस्पर्धा होगी वैसी ही कम कम्पनियो मे भी हो सकती है। दूसरी बात यह कि लोग अब यह भी जान गए है कि अब प्रतिस्पर्धा एक ही उद्योग की अनेक कम्पनियो मे नही होती, बल्कि अलग-अलग उद्योगो मे भी होती है। साथ ही लोगो की यह आशका भी बहुत-कुछ कम हो गई है कि यदि एक ही या कुछ ही कम्पनियाँ बहुत बडी होगी तो वे अपने उत्पादन की मनमानी कीमतें रखकर उपभोक्ता का शोषण कर सकेगी। कारण, लोग अब यह अनुभव करते है कि यदि कम्पनी बडी होगी तो वह बडे पैमाने पर

अधिकाधिक लोगो के लिए उत्पादन करेगी और क्योंकि उसके कारखाने भी बडे होगे, इसलिए वे कम मुनाफा लेकर भी उत्पादन कर सकेंगे। अब लोगो मे यह आशका भी नही रही कि कम्पनियो के मालिक या प्रबन्धक अपने क्षेत्र मे एकाधिकार के फलस्वरूप भारी मुनाफे कमा कर विशाल व्यक्तिगत सम्पत्तियाँ बना लेंगे। इसके विपरीत यह देखा गया है कि बडी-बडी कम्पनियो के निर्माण के साथ ही साथ अमेरिका के सभी सामाजिक वर्गों के लोगो मे आय और सम्पत्ति का पहले से अधिक न्यायपूर्ण वितरण होने लगा है। यह धारणा कि उत्पादन के केन्द्रीकरण से सम्पत्ति भी कुछ थोडे-से लोगो के हाथो मे केन्द्रित हो जाएगी, इस तथ्य के कारण अब निर्मूल सिद्ध हो गई है कि कम्पनियो का, खासकर बडी कम्पनियो का, स्वामित्व कुछ थोडे-से लोगो के हाथो मे न होकर बहुत बडी सख्या मे विद्यमान शेयर होल्डरो (हिस्सेदारो) के हाथो मे होता है। इसके अलावा एक ओर बडी-बडी कम्पनियो का आपेक्षिक महत्त्व बढ रहा है और दूसरी ओर धनी लोगो की कुल व्यक्तिगत स्वायत्त आय का प्रतिशत अनुपात निरन्तर कम होता जा रहा है।

तौर पर बडी कम्पनियो मे छोटी कम्पनियो से भी अधिक है, क्योकि बडी कम्पनियो के पास इस के लिए वित्तीय साधन अधिक होते हैं और सामूहिक बीमा कराने मे उन्हे खर्च कम पडता है।

बडी कम्पनियो के सम्बन्ध मे हुए इस रुख-परिवर्तन के फलस्वरूप न्यायालयो के निर्णयो मे भी कम्पनी-गुट-विरोधी कानूनो की कुछ भिन्न व्याख्याएँ की गई और खयाल है कि इस सम्बन्ध मे शायद और भी परिवर्तन हो।

कम्पनी-गुट-विरोधी कार्रवाइयो की आवश्यकता है या नही, इसका फैसला दो कसौटियो के आधार पर किया जाता है—पहली यह कि कम्पनी का ढाँचा कैसा है और दूसरी यह कि वह काम किस ढग से करती है। ढाँचा विषयक कसौटी मे यह देखा जाता है कि कम्पनी कितनी बडी है, उसमे किन्ही अन्य कम्पनियो का विलय तो नही हुआ या अन्य कम्पनियो के साथ उसके कोई गठबन्धन तो नही है। कम्पनियो के ढाँचे और आकार की कसौटी के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई यह मानकर की जाती है कि जो कम्पनियाँ बहुत बडी हैं और जिनका बाजार मे बिकने वाले माल मे बहुत बडा हिस्सा है, वे सम्भवत बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। इस प्रकार केवल कम्पनियो के ढाँचे और आकार की कसौटी पर ही निर्भर करने से उन कम्पनियो के साथ व्यर्थ ही अन्याय होता है, जिन्होने अपने उत्पादन की किस्म अच्छी होने के कारण या अपने उत्तम सगठन की बदौलत अपनी आर्थिक सत्ता का निर्माण किया है। इस प्रवृत्ति का नतीजा यह हुआ है कि वास्तव मे ही एकाधिकार की चेष्टा करने वाली कम्पनियो के साथ-साथ ऐसी कम्पनियाँ भी कम्पनी गुट विरोधी कानून का शिकार हो जाती है जो ऐसी चेष्टा नही करती, किन्तु फिर भी बहुत बडी होती हैं।

इसके विपरीत अब हाल मे यह तर्क दिया जाने लगा है कि कोई भी कम्पनी तब तक सिर्फ इसीलिए बुरी नही हो सकती कि वह बहुत बडी है, जब तक कि वह अपनी आर्थिक सत्ता का दुरुपयोग न करे।

यह तर्क देने वाले कम्पनी के काम के ढग की कसौटी पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि कसौटी यह होनी चाहिए कि कम्पनी अपनी आर्थिक सत्ता का वास्तव मे रचनात्मक उपयोग कर रही है या हानिकारक उपयोग। हमे ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी के काम के ढग की कसौटी पर भविष्य मे और भी अधिक बल दिया जाएगा, हालाकि उससे न्यायिक निर्णय मे कुछ कठिनाइयाँ पैदा होती है। एक कठिनाई यह है कि अभी तक ऐसी कोई निश्चित कसौटी नही निकाली गई जिससे यह कहा जा सके कि आर्थिक सत्ता का उपयोग रचनात्मक ढग से किया जाता है या हानिकारक ढग से। जब ऐसी कसौटी निर्धारित कर ली जाएगी तब केवल ढांचे की कसोटी का, यानी इस धारणा का कि कम्पनी का बडा होना ही हानिकारक है, महत्त्व स्वय धीरे-धीरे कम हो जाएगा।

लेकिन कम्पनी के ढांचे की कसौटी के सम्बन्ध मे रुख मे जो थोडा परिवर्तन हुआ है, उसका अर्थ यह नही है कि न्यायलय इस कसौटी को अब महत्त्वहीन समझने लग गये है। अभी हाल मे ही ड्यू पॉण्ट कम्पनी को न्यायालय ने आदेश दिया था कि वह अपने जनरल मोटर्स के शेयर बेच दे। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए ड्यू पॉण्ट पर यह आरोप नही लगाया कि उसने जनरल मोटर्स के शेयर खरीद कर उन पर अनुचित प्रभाव डाला है, परन्तु उसने यह आशका अवश्य प्रकट की कि वह ऐसा कर सकती है। इस प्रकार उसने यह निर्णय करते हुए कम्पनी के काम के वास्तविक ढंग को नही, बल्कि उसके ढांचे की कसौटी पर ही मामले को परखा। फिर भी इस बात की काफी आशा है कि काम के ढग की कसौटी पर, अर्थात् आर्थिक सत्ता के वास्तविक दुरुपयोग पर, ही भविष्य मे अधिक बल दिया जाएगा। कम्पनियो के काम के ढग के सम्बन्ध मे यह कसौटी, कि क्या काम सार्वजनिक हित मे है और क्या नही, अब धीरे-धीरे बन भी रही है।

कम्पनियां व्यवसाय मे इसीलिए आती है कि मुनाफा कमा सकें और मुनाफा कमाने का अर्थ यह है कि उनका माल अधिक अच्छे तरीके

से तैयार किया और वेचा जाता है। लेकिन केवल उत्पादन और विक्री का कौशल ही, एकमात्र ऐसी कसौटी नही है जिनसे कि कम्पनियो के मुनाफो और उनके काम के ढग के वारे मे निर्णय किया जाता है, या किया जाना चाहिए। कम्पनियो के प्रवन्धक अव यह वात अधिकाधिक महसूस करने लगे है कि मुनाफा कमाने के लिए कर्मचारियो और जनता, दोनो के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए। और अच्छे जन-सम्पर्क के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि कम्पनियाँ समूची अर्थ-व्यवस्था पर अपने कार्यकलाप के प्रभाव को देखे। इसमे सन्देह नही कि जिन सरकारी सगठनो के हाथ मे कम्पनी-गुट-विरोधी कानूनो को लागू करने का भार है, वे जहाँ-कही इन कानूनो का उल्लघन होते देखेंगे वही आवश्यक कार्रवाई करेंगे, किन्तु साथ ही कम्पनियो द्वारा आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह वात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि कम्पनियाँ जो कुछ करती हे, वह सवकी नजर मे रहे। उदाहरण के लिए यदि मूल्य-नीति की सरकार और काग्रेस द्वारा जाँच की जाती रहे तो वह अदालतो के जरिये कम्पनी-गुट-विरोधी कानून को लागू कराने की कार्रवाई की अपेक्षा अधिक कारगर हो सकती है। वास्तव मे कुछ अन्य देशो मे, जहाँ उद्योग सरकार के हाथो मे है, राष्ट्रीयीकृत उद्योगो पर उतनी कडी नजर नही रखी जाती, जितनी कि अमेरिका मे वडे प्राइवेट उद्योगो पर रखी जाती है।

सम्भवत आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकने मे सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण योग कम्पनियो की नये ढग की प्रवन्ध-व्यवस्था का हे, जिसकी हम ऊपर चर्चा कर चुके है। अव व्यावसायिक प्रवन्ध ऐसे लोगो के हाथ मे आ गया है जो उसे अपने जीवन मे आगे वढने के लिए एक लक्ष्य के रूप मे अपनाते है, और आधुनिक ढग की कम्पनियो को एक ऐसी वस्तु के रूप मे समझा जाता है जिसका एक अपना जीवन और अस्तित्व है, इसलिए पुराने जमाने के उद्योग-सचालको मे जनता की उपेक्षा करने की जो वृत्ति थी, वह अव नये प्रवन्धको मे नही पाई जाती। आज कम्पनियो और उनके प्रबन्धको पर इस बात के लिए बहुत दवाव पड रहा है कि

वे अपने व्यवसाय को समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से चलाये। लेकिन स्वय आधुनिक कम्पनियाँ भी एक सस्था के रूप मे ऐसे दबाव पैदा करती है जो इन रचनात्मक प्रवृत्तियो के प्रभाव को कुछ हद तक नष्ट कर देते है, जैसा कि हाल मे बिजली का सम्मान बनाने वाली कुछ बड़ी कम्पनियो की परस्पर मिलकर बोली लगाने की साजिश के समय देखने मे आया। इस साजिश के अनेक कारणो मे से एक यह था कि कम्पनियों के अधिकारियो पर, जो अपनी स्थिति बनाये रखने और भविष्य मे और ऊँचे पदो पर तरक्की के लिए चिन्तित थे, मालिको का ऊपर से यह दबाव पडा कि वे अपनी कम्पनियो के माल की बिक्री और मुनाफो को बढाएँ, या कम से कम उन्हे गिरने न दे, इसी मे उनकी सफलता है।

इसका अर्थ यह है कि यद्यपि बडी कम्पनियो द्वारा अपनी आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण प्रभाव काम कर रहे है तो भी एकाधिकार के दुरुपयोग के लिए अवसर और प्रेरणाएँ मौजूद अवश्य है। ये अवसर और प्रेरणाएँ बडी कम्पनियों को इसलिए मिलती है क्योकि वे अपने ऊपर किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा का अवाछनीय और परेशान करने वाला दबाव नही पडने देना चाहती, वे अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यो के लिए करना चाहती है, या उनमे मानवीय प्रकृति और समाज की और भी कमजोरियाँ होती है। यद्यपि सरकार यह स्वीकार करती है कि बडी कम्पनियो का रुख अब रचनात्मक है और अधिकतर कम्पनियो के प्रबन्धको का रवैया भी अधिकाधिक उत्तरदायित्त्वपूर्ण होता जा रहा है तो भी इस बात की जरूरत है कि सरकार कम्पनियो के काम के ढग पर नजर रखे और जहाँ भी उसे आर्थिक सत्ता का दुरुपयोग होता नजर आये वही हस्त-क्षेप करे।

आज शायद ही कोई अमेरिकी ऐसी कम्पनी-गुट-विरोधी नीति का समर्थक हो, जो बड़ी कम्पनियो को सिर्फ इसलिए टुकड़े-टुकडे कर दे कि उनसे आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावना है। इसके विलोम के तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि शायद ही कोई ऐसा अमेरिकी

नागरिक हो जो ऐसी कम्पनी-गुट विरोधी नीति को खत्म करने का समर्थक हो जिससे आर्थिक शक्ति के वास्तविक दुरुपयोग को टोका जा सकता है। अमेरिकी लोगो की एक बहुत बडी संख्या, जिसमे व्यवसाय जगत् के नेता भी है, इस तथ्य को स्वीकार करती है कि एक लोकतन्त्रीय देश मे सत्ता और अधिकार के साथ जवाबदेही भी होनी जरूरी है। आधुनिक युग की बडी कम्पनियो मे व्यक्तिगत तौर पर शेयर होल्डरो का सीधा नियन्त्रण अक्सर कमजोर और प्रभावहीन होता है। यह सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी कम्पनी के शेयरो मे पैसा नही लगायेगा जिसके बारे मे उसे यह यकीन न हो कि उसके प्रबन्धक कौशल और उत्तरदायित्व के साथ काम करते है जिससे उसके शेयरो की कीमत बढेगी और उसे मुनाफा भी सन्तोषजनक मिलेगा। लेकिन फिर भी, अगर सरकार की कम्पनी-गुट-विरोधी नीतियाँ न होती और कम्पनियो के काम की सार्वजनिक जाँच की व्यवस्था न होती तो यह सम्भव था कि प्रबन्धक लोग अपनी कम्पनियो की आर्थिक सत्ता का दुरुपयोग करते और उन्हे किसी के आगे जवाब भी न देना पडता। इस प्रकार इस व्यवस्था से कम्पनियाँ अपनी आर्थिक सत्ता के अच्छे या बुरे उपयोग के बारे मे अमेरिकी जनता के सम्मुख उत्तरदायी हो जाती है।

लघु उद्योग नीतियाँ

कम्पनी-गुट-विरोधी नीति तत्वत एक निषेधात्मक (नेगेटिव) नीति है जिसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है। इसके विपरीत लघु और मध्यम उद्योगो की समस्यायो का मुकाबला करने के लिए ठोस भावात्मक (पौजिटिव) उपाय और नीतियाँ होनी चाहिएँ। लेकिन ये नीतियाँ और उपाय मुख्यत स्वय व्यवसायी लोगो की ही जिम्मेदारी है। सरकारी कार्यक्रम तो उन फर्मो को, जिन्हे प्रतिस्पर्धा के कारण कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है, आवश्यक पहल करने और कदम उठाने के लिए केवल सहायता ही दे सकते है और वह उचित भी है।

छोटे और मध्यम व्यवसायो के जीवित रहने की समस्या अनेक कारणो से पैदा होती है। ये कारण अलग-अलग या परस्पर मिलकर एक फर्म की अपने उद्योग मे प्रतिस्पर्धा मे टिकने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते है। इनमे से कुछ कारण बडी फर्मो को अधिक लाभ-पूर्ण स्थिति का परिणाम होते है। लेकिन अनेक छोटी फर्मों की कठिनाइयो के ऐसे कारण भी होते है, जिनका बडी कम्पनियो की प्रतिस्पर्धा की शक्ति से कोई सम्बन्ध नही होता। इनमे से सबसे अधिक बडा और प्रभावशाली कारण सम्भवत यह है कि बहुत-सी फर्में, बल्कि उनके कर्मचारी भी, नई औद्योगिक विधियो को अपनाने के लिए तैयार नही होते, जिसमे उनके उत्पादन और उत्पादन-विधियाँ दोनो, बडी कम्पनियो की प्रतिस्पर्धा के बिना भी, पुराने हो जाते है। विदेशो से आयातित माल की प्रतिस्पर्धा उतना बड़ा कारण नही है, क्योकि विदेशो मे मजदूरी की दर सस्ती होने और उसके फलस्वरूप विदेशी उत्पादनो की लागत कम होने के कारण उनकी प्रतिस्पर्धा मे न टिक सकने की जिस असमर्थता की अक्सर दुहाई दी जाती है, उसका वास्तविक कारण यह होता है कि ये असमर्थ अमेरिकी फर्में अपनी उत्पादकता के स्तर को ऊँचा उठाने, अपने पुराने ढग के उत्पादनो की किस्म सुधारने या अपने बिक्री और वितरण के दकियानूसी तरीको मे परिवर्तन करने के लिए तैयार नही होती।

इसलिए यह जाहिर है कि जहाँ तक इन फर्मों के पुरानी लीक से न हटने के कारण उनकी प्रतिस्पर्धा की स्थिति के बिगडने का ताल्लुक है, सरकार उनकी इस समस्या के हल मे कोई सहायता नही दे सकती। ऐसे मामलो मे सरकार उन्हे ऋण, अनुपूर्त्तियाँ, सरक्षणात्मक तट-कर या अन्य रूपो मे जो सहायता देती है, उससे केवल रोग के बाहरी लक्षण का ही इलाज होता है, रोग के मूल कारण का नही और उसका नतीजा यह होता है कि जिन कठिनाइयों को दूर करने की नीयत से यह सहायता दी जाती है, वे हमेशा के लिए जड जमाकर बैठ जाती है। ऐसे मामलो मे केवल इन फर्मो को नये तरीक़े अपनाने की सलाह देकर ही वास्तव में

सहायता पहुँचायी जा सकती है। इसके मुकाबले मे बहुत-सी दूसरी छोटी फर्मे ऐसी भी है जो आवश्यक परिवर्त्तन करने के लिए तैयार हैं, पर उनके पास उनके लिए पर्याप्त आर्थिक साधन नही हैं और न वे काम करने के लिए पूर्णत स्वतन्त्र ही है। ऐसी फर्मों को सरकार वित्तीय और तकनीकी विधियो के प्रशिक्षण की सहायता दे सकती है ताकि वे जो कदम उठाना चाहती हैं उसे प्रभावकारी बनाने के लिए जिन वस्तुओं की कमी है, उनकी पूर्ति हो सके।

सरकार की नीतियाँ आम तौर पर भी छोटी फर्मो को कुछ ऐसी कठिनाइयो पर विजय पाने मे सहायता दे सकती हैं जो बडी फर्मो की प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हे झेलनी पडती हैं। इन फर्मो की सबसे बडी कठिनाई वित्तीय है। इसलिए ऐसी फर्मों को, जिनके कुछ उन्नति कर सकने की सम्भावनाएँ है, अनुकूल शर्तो पर ऋण देने के लिए कुछ कार्य-क्रम बनाये गए है। इन कार्यक्रमो के परिणाम बहुत प्रोत्साहनजनक सिद्ध हुए है। किन्तु यह नही कहा जा सकता कि छोटी फर्मों को वित्तीय सहा-यता देने की मौजूदा विधियाँ सर्वोत्तम है। हो सकता है कि कृषि-फार्मों को वित्तीय सहायता देने के लिए अर्ध-सरकारी सगठनो की जो शृखला स्थापित की गई है, वैसी ही शृखला छोटी फर्मों को सहायता देने के लिए भी आवश्यक हो। ऐसी वित्तीय सस्थाएँ स्थापित करने के लिए सन् 1958 मे एक कानून पास किया गया था, और उसके अन्तर्गत बहुत-सी ऐसी सस्थाएँ काम भी कर रही है।

जहाँ तक कि कुछ अन्य कठिनाइयो का ताल्लुक है, छोटी फर्मे उन पर विजय पाने के लिए स्वय ही अपने तौर-तरीको मे कुछ हेरफेर कर रही है। उदाहरण के लिए छोटी फर्मे बडी फर्मो की भाति बडे पैमाने पर अनुसन्धान और विकास के कार्य करने हाथ मे नही ले सकती। इसलिए ऐसी परामर्शदात्री फर्मे स्थापित की जा रही है जो छोटी फर्मों को तक-नीकी विधियो को विकसित करने के मामले मे सलाह-मशविरा देती है। इसी तरह कुछ राज्य सरकारो ने और व्यवसायियो के कुछ स्वैच्छिक सगठनो ने भी छोटी फर्मों की तकनीकी सहायता के लिए कार्यक्रम

बनाये है ।

छोटी फर्मो ने अपने आकार के छोटेपन के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयो पर विजय पाने के लिए एक और तरीका भी अपनाया है और वह यह है कि एक से अधिक छोटी फर्मे परस्पर मिल जाती है। लेकिन छोटी फर्मो का यह पारस्परिक विलय पिछले दस वर्षो मे हुए बडी फर्मो के विलयो से भिन्न किस्म का है । इस विलय मे अलग-अलग फर्मो की पृथक् सत्ता पूर्णत नष्ट नही होती, बल्कि वे अपनी काम की स्वतन्त्रता को काफी हद तक बनाये रखती है। इन विलयो के परिणाम-स्वरूप बनी अनेक बडी फर्मो को अधिक अनुकूल और वाजिब शर्तों पर अधिक पूंजी जुटाने मे सफलता मिली है । इससे उनके सयुक्त व्यवसाय को और भी अनेक प्रकार से नया बल प्राप्त हुआ है ।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कई अहम क्षेत्रो मे छोटी फर्मो ने बडी और विशाल फर्मो से भी अपने आपको अधिक सफल सिद्ध किया है । अतीत मे छोटी फर्में अपने लिए बेहतर अवसरो की खोज करके अपने अस्तित्व को कायम रख सकी है। भविष्य मे भी छोटी और मध्यम कम्पनियाॅ मुख्यत अपनी व्यक्तिगत निपुणता और जागरूकता के बल पर ही जीवित रह सकेगी । सरकारी सहायता उनके इन गुणो का स्थान नही ले सकती । वह केवल इन गुणो को सहारा ही दे सकती है ।

सारांश

यह स्पष्ट है कि अमेरिका एक ओर तो उन नीतियो मे परिवर्तन कर रहा है जिनका उद्देश्य आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकना था और दूसरी ओर वह छोटे उद्योगो को सहायता देने के लिए नये उपाय भी अपना रहा है । इस प्रकार वह धीरे-धीरे एक तरफ निरन्तर आर्थिक विकास और दूसरी तरफ स्वतन्त्रता और किसी कार्य के लिए उपक्रम करने की प्रवृत्ति की रक्षा, दोनो मे समन्वय कर रहा है । इस प्रक्रिया मे 'एकाधिकारवादी पूंजीवाद' की पुरानी धारणाएँ तीव्र गति से समाप्त हो रही है, क्योकि पिछले बीस वर्षों मे बड़ी कम्पनियो के स्वरूप और

प्रभाव मे और छोटी कम्पनियो की प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे बहुत दूरगामी परिवर्तन हो गए है। लेकिन इस परिस्थिति के फलस्वरूप जो नये रुख और नई नीतियाँ अपनायी जा एँगी, उनके बारे मे अभी से कोई विस्तृत पेशीनगोई नही की जा सकती। लेकिन यह जरूरी है कि व्यावसायिक व्यवहार के उन तरीको का और अधिक स्पष्टीकरण किया जाय, जो शेयरहोल्डरो, कर्मचारियो और उपभोक्ताओ की आवश्यकताओ को पूरा करने के साथ साथ उपलब्ध साधनो के अधिक प्रभावकारी उपयोग और आर्थिक उन्नति और स्थिरता मे भी योग दे सकें। व्यावसायिक व्यवहार के ऐसे नियमो को अधिक अच्छे और पूर्ण रूप मे विकसित और निर्धारित करना आर्थिक शक्ति को आर्थिक अभिवृद्धि के साधन के रूप मे इस्तेमाल करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण शर्त है।

12

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान

संयुक्त राज्य का अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत् की परिस्थितियों और रुझानो पर ससार के सभी देशो से अधिक प्रभाव है। वह कच्चे माल और तैयार वस्तुओ का ससार का सबसे बडा निर्यातक और आयातक है। अनेक देशो के लिए वह सबसे बडा बाजार और सामान की उपलब्धि का सबसे बड़ा स्रोत है। कुछ देशो का तो आधे से अधिक निर्यात अमेरिका को होता है और वही उनको अधिकतर माल सप्लाई करता है। किसी भी अन्य देश की अपेक्षा अमेरिका के व्यवसायी ही विदेशो मे अपनी पूंजी सबसे अधिक लगाते है। इसी तरह अन्य देशो के लोग भी अपने देश के बाद दूसरे नम्बर पर अमेरिका मे ही अपनी सबसे अधिक पूंजी लगाते है। अमेरिकी सरकार ही अन्य देशो को सीधी या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ के जरिये सबसे अधिक सहायता देती है, ताकि वे आर्थिक और सामाजिक उन्नति कर सके या कम्युनिस्ट आक्रमण और आन्तरिक षड्यन्त्र से रक्षा के लिए अपनी सैनिक शक्ति मजबूत कर सके। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्य देशो के मुद्रा कोषो मे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्रा अमेरिकी डालर ही है।

किन्तु अमेरिका के दृष्टिकोण से शेष ससार के साथ उसका वैसा सम्बन्ध नही है, जैसा उसका अमेरिका के साथ है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था शेष ससार की अर्थ-व्यवस्था पर उतनी निर्भर नहीं रही, जितनी कि शेष ससार की अर्थ-व्यवस्था उसकी अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर रही है। उदाहरण के लिए, यद्यपि सन् 1960 मे अमेरिका का निर्यात और आयात विश्व के कुल निर्यात और आयात का क्रमश. $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत और $13\frac{1}{2}$ प्रतिशत था तो भी सयुक्त राज्य की कुल राष्ट्रीय आय का वह क्रमश:

6 प्रतिशत और 5 प्रतिशत ही था। इसी तरह सन् 1960 मे अमेरिका ने अन्य देशो मे दीर्घकालिक निवेश के लिए 4 अरब डालर से अधिक राशि, जो ससार के सभी देशो के विदेशी पूंजी-निवेश के आधे से अधिक थी, लगायी थी। लेकिन उस वर्ष अमेरिकी लोगो ने अपने देश मे जितनी कुल प्राइवेट पूंजी लगायी थी, उसकी तुलना मे वह कुल 5½ प्रतिशत ही थी।

सयुक्त राज्य और शेष संसार की आर्थिक दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भरता मे जो असमानता है वह उन्नीसवी शताब्दी मे और उसके बाद काफी हद तक प्रथम विश्व युद्ध तक ब्रिटेन और शेष ससार की पारस्परिक आर्थिक निर्भरता की असमानता से बिलकुल उलटी है। उस ज़माने मे ब्रिटेन विश्व के आर्थिक जगत् का नेता था। ब्रिटेन मे सामान और सेवाओ का जितना उत्पादन और उपभोग होता था, उसमे उसके विदेशी व्यापार का हिस्सा अधिक होता था और ब्रिटेन जो बचत या पूंजी निर्माण करता उसमे भी विदेशी निवेश ही महत्वपूर्ण भाग अदा करता था। विश्व का करीब-करीब सारा व्यापार ही ब्रिटेन की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग के आधार पर होता था और उन्नीसवी शताब्दी का स्वर्ण-मान मुख्यत बैंक ऑफ इग्लैण्ड, लन्दन के द्रव्य बाजार और ससार भर मे फैले ब्रिटिश बैंको, बीमा कम्पनियो और जहाजरानी की फर्मों के जरिये से स्वत. चलता रहता था। इस प्रकार एक तरह से यह कहा जा सकता है कि उन्नीसवी शताब्दी की स्वतन्त्र-व्यापार वाली विश्व की अखण्ड आर्थिक प्रणाली इतनी निर्बाध और बेरोकटोक गति से इसलिए चलती थी कि ब्रिटेन आर्थिक दृष्टि से शेष ससार पर जितना अधिक निर्भर करता था, उतना शेष ससार उसपर निर्भर नही था।

यद्यपि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली द्वितीय विश्वयुद्ध के तत्काल बाद के वर्षो की अपेक्षा काफी अच्छी है, क्योकि हाल के वर्षों मे उसमे सुधार हुआ है तो भी बहुत-सी गम्भीर समस्याएँ अभी तक मौजूद हैं। इन समस्याओ के समाधान के लिए आवश्यक नेतृत्व और साधन उपलब्ध कराने की सबसे बडी जिम्मेदारी सयुक्त राज्य पर है,

क्योंकि गैर-कम्युनिस्ट संसार मे वही सबसे बड़ा, सबसे सम्पन्न और सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र है। मोटे तौर पर इस समय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के सम्मुख तीन बड़ी कठिनाइयाँ हैं :

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार उतना नही हो रहा जितना होना चाहिए और न उसके लाभ उतने मिल रहे है जितने मिलने चाहिएँ क्योकि (1) तटकर और अन्य बाधाओ के कारण सामान और सेवाएँ एक देश से दूसरे देश मे निर्बाध रूप मे नही जा पाती; (2) कच्चे माल के विश्व व्यापार मे वृद्धि धीमी गति से हो रही है और उसमे स्थिरता नही है, और (3) मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था पर्याप्त नही है।
- एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अल्पविकसित देशो को न तो अपने निर्यात व्यापार से और न ही प्राइवट विदेशी निवेश से उतना धन प्राप्त हो रहा है जितना उन्हे अपनी बढती हुई आबादी और लोगो की उपभोग की बढती हुई आशाओ के अनुरूप अपनी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए जरूरी है।
- सोवियत संघ और साम्यवादी चीन की साम्राज्य विस्तार की महत्त्वाकांक्षाओ के कारण अनेक विकसित और विकासोन्मुख देशों की अर्थ-व्यवस्था पर भारी बोझ पड रहा है, क्योकि उन्हे साम्यवादी देशो के बाह्य आक्रमण और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के आन्तरिक षड्यन्त्रो से अपनी रक्षा के लिए बहुत खर्च करना पडता है।

लेकिन अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था और शेष अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के परस्पर सम्बन्धो मे जो असमानता है उसकी वजह से संयुक्त राज्य इन महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ के हल के लिए कुछ सीमा तक ही नेतृत्व और साधन प्रदान कर सकता है या उसके लिए तैयार हो सकता है। इस अध्याय मे हम अमेरिकी दृष्टिकोण से इन समस्याओ को प्रस्तुत करेंगे और यह बतायेंगे कि संयुक्त राज्य ने अपने अन्य साथी और मित्र देशो के साथ मिलकर इनके हल के लिए क्या मुख्य नीतियाँ

और कार्यक्रम अपनाये। यहाँ हम स्वभावत अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयो के आर्थिक पहलू पर ही जोर दे रहे है तो भी यह वात नहीं भुलाई जानी चाहिए कि इन कठिनाइयो का समूचे मानव-समाज के भविष्य के लिए गम्भीर राजनीतिक और सामरिक महत्त्व भी है।

सयुक्त राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप

सयुक्त राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के पारस्परिक सम्वन्धो की असमानता का मूल कारण अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का विशिष्ट स्वरूप हे, जिसकी चर्चा हम पिछले अध्यायो मे कर चुके हैं। यह कहना अनुपयुक्त नही होगा कि सयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था राष्ट्रीय नही, वल्कि महाद्वीपीय अर्थ-व्यवस्था है। उसके प्राकृतिक साधनो का विस्तार और विविधता, उसकी आवादी की विपुलता, वहुविधता और उत्पादकता, उसके उपभोग का ऊँचा स्तर और वित्तीय साधनो की प्रचुरता, और उसमे सामान, धन और जन-शक्ति के आन्तरिक आवागमन की अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता—इन सबको देखने से यह कहा जा सकता है कि सयुक्त राज्य अपने आप मे एक महाद्वीप हे। इस दृष्टि से केवल सोवियत सघ ही उसकी कुछ वरावरी कर सकता है, लेकिन वह भी बहुत अधिक नही। यहाँ तक कि यूरोपीय साझा वाजार भी, चाहे उसमे ब्रिटेन और कुछ अन्य छोटे नजदीकी देश भी मिल जाएँ, उतनी मात्रा मे आत्मनिर्भरता और आन्तरिक क्रय-शक्ति प्राप्त नही कर सका जितनी कि अमेरिका ने प्राप्त कर ली है, हालाकि यह सम्भव है कि कुछ समय बाद वह अपनी जनता को वे लाभ अधिकाधिक मात्रा मे प्रदान कर सके जो सयुक्त राज्य ने अपनी अर्थ-व्यवस्था की विशालता, समृद्धि और गतिशीलता से प्राप्त किये है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के महाद्वीपीय अर्थ-व्यवस्था होने का एक परिणाम यह है कि सयुक्तराज्य कच्चे, आधे-तैयार और तैयार सभी प्रकार के माल का सवसे बडा आयातक भी है और सबसे बडा निर्यातक है, और उसकी यह स्थिति सारे ससार मे अनूठी है। वैसे आम तौर

पर औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशो के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप यह होता है कि वे भारी मात्रा मे निर्यात तैयार माल का करते है और आयात कच्चे माल का। दूसरी ओर अल्पविकसित देशो के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप इससे उलटा होता है—उनका अधिकतर निर्यात कच्चे माल का और आयात तैयार माल का होता है।

बीसवी शताब्दी से पूर्व अमेरिका मुख्यत कृषि-जिन्से और औद्योगिक कच्चा माल निर्यात करता था और कारखानो मे निर्मित वस्तुएँ आयात करता था। लेकिन जब अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन बढकर उसके कृषि जिन्सो और कच्चे माल के उत्पादन से काफी आगे निकल गया तब भी वह कृषि-जिन्सो का और काफी हद तक औद्योगिक कच्चे माल का भी बडा निर्यातक बना रहा। सयुक्त राज्य मे कृषि की उत्पादन क्षमता बहुत ऊँची होने के कारण यहाँ कृषि-जिन्सो की उपज देश की अपनी जरूरतो से ज्यादा होती है, इसलिए अमेरिका अनाज, माँस, अन्य खाद्य-पदार्थ, पशुओ का चारा, रूई और तम्बाकू आदि अपनी फालतू वस्तुएँ ससार के अन्य देशो को सप्लाई करता है। यह ठीक है कि अमेरिकी उद्योग स्वय कुछ आयातित धातुओ और खनिज पदार्थो पर काफी हद तक निर्भर हैं तो भी अमेरिका कुछ औद्योगिक कच्चा माल और ईधन काफी बडी मात्रा मे अन्य देशो को निर्यात करता है। जब भी ऐसा मौका आया कि डालर क्षेत्र से बाहर के देश विश्व की इन कच्ची और आधी-तैयार वस्तुओ की बढती हुई माँग को पूरा करने मे असफल रहे तभी सयुक्त राज्य ने इन वस्तुओ का निर्यात काफी तेज गति से और काफी अधिक मात्रा मे बढा दिया। लेकिन साथ ही साथ निर्यात और तैयार वस्तुओ का निर्यात इन वस्तुओ के निर्यात से भी अधिक रहा है और वह अब भी बढ रहा है।

विश्व-व्यापार मे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की यह दोनो प्रकार की भूमिका ससार के विभिन्न भागो को भेजे जाने वाले और उनसे मगाये जाने वाले उसके माल का अध्ययन करके भली भाँति समझी जा सकती है। कम विकसित देशो की तुलना मे सयुक्त राज्य एक उन्नत औद्योगिक

देश है, और उनसे मुख्यत कच्चा औद्योगिक माल आयात करता है और उसके बदले मे उन्हे मुख्यत कारखानो मे तैयार माल भेजता है।

चार्ट 14
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति, 1959
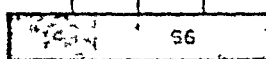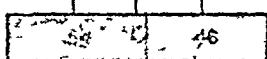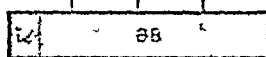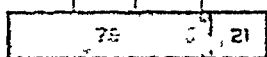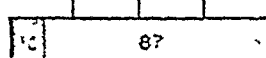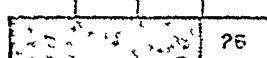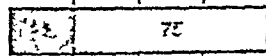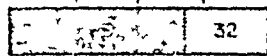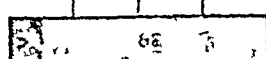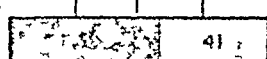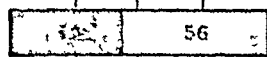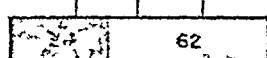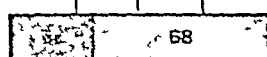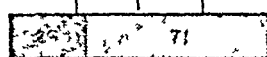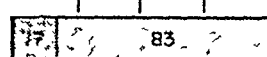
a. इसमें अनेक अर्ध-निर्मित वस्तुएँ भी शामिल है।

लेकिन औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध देशो के साथ उसके व्यापार का स्वरूप इससे उलटा है, हालाकि यो, सब मिलाकर देखा जाय तो, ये देश उसके कारखानो मे निर्मित माल के सबसे बड़े आयातक है।

परन्तु यदि कुल समुच्चय की दृष्टि से देखा जाय तो आयात और निर्यात अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के लिए अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण है। उष्ण कटिबन्ध की कुछ चीजो, जैसे कॉफी, कोको, प्राकृतिक रबड, सख्त रेशा, केला, सख्त लकडी की कुछ किस्मो और कुछ तिलहनो का सयुक्त राज्य मे उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नही होगा। इसी तरह अलोह धातुएँ और खनिज—जैसे मैंगनीज, क्रोम, निकल, ताँबा, बॉक्साइट, टीन और हीरे—सयुक्त राज्य मे पैदा नही होते या उचित मूल्य पर उनका यहाँ उत्पादन नही किया जा सकता। इसलिए इन वस्तुओ को इस्तेमाल करने वाले अमेरिकी उद्योग इनके आयात पर निर्भर करते है। दूसरी ओर कुछ अमेरिकी उद्योग ऐसे भी है जो बहुत कुछ निर्यात-बाजार पर निर्भर हैं, जैसे सिनेमा फ़िल्मे, कुछ किस्मो की औद्योगिक और कृषि मशीनरी और कुछ अन्य जिन्से।

यद्यपि पिछले दस वर्षों मे अमेरिका के कुल निर्यात का 60 प्रतिशत भाग कारखानो मे तैयार माल का था, तो भी तैयार माल के निर्यात की गति मे वृद्धि सबसे धीमी थी। दस वर्षों मे उसमे केवल 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अमेरिका से निर्यात की जाने वाली वस्तुओ मे सबसे अन्तिम स्थान आधे-तैयार कच्चे माल का और आधे-तैयार निर्मित माल का है, परन्तु इन्ही के निर्यात मे इन दस वर्षो मे सबसे अधिक, यानी 150 प्रतिशत, वृद्धि हुई। कच्चे माल का स्थान मात्रा और वृद्धि की गति दोनो के लिहाज से इन दोनो के बीच में है। इसके निर्यात मे 1950 के दशक मे 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। विदेशी व्यापार के खाते मे दूसरी तरफ कच्चे माल और आधी-तैयार निर्मित वस्तुओ के आयात मे इस दशक मे लगभग उसी गति से वृद्धि हुई जिस गति से सयुक्त राज्य की कुल राष्ट्रीय आय मे, लेकिन कारखानो मे तैयार निर्मित माल के आयात मे लगभग 150 प्रतिशत वृद्धि हो गई।

व्यापार की समस्याएँ और नीतियाँ

शेष ससार के साथ सयुक्त राज्य के व्यापार का जो ढाँचा है उसमे कुछ समस्याएँ स्वभावत अन्तर्निहित हैं और हाल के वर्षों मे वे बहुत महत्त्वपूर्ण हो गई है। किन्तु अमेरिका के विदेशी व्यापार का एक बडा भाग ऐसा भी है, जिसके सामने विदेश मे व्यापार करने मे आम तौर पर होने वाले सामान्य व्यावसायिक खतरो के अलावा कोई बडे खतरे नही है, इसलिए अमेरिकी आयात और निर्यात के सम्मुख उपस्थित कठिनाइयो का उल्लेख करते हुए हमारा अभिप्राय उनका अतिरजनापूर्ण वर्णन करना नही है। मात्रा की दृष्टि से देखे तो अमेरिकी विदेशी-व्यापार का समस्याग्रस्त अश उसके कुल विदेशी व्यापार का बहुत छोटा अश है। फिर भी तीन कारणो से वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। पहला यह कि समस्या और कठिनाई से ग्रस्त इस व्यापार का सम्बन्ध, खासकर आयात के मामले मे, ऐसे व्यावसायिक हितो से है, जो खूब सगठित हैं, हल्ला-गुल्ला कर सकते हैं और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली हैं। दूसरा यह कि अमेरिका के आयात और निर्यात के तुलनात्मक स्तरो मे एक छोटा-सा परिवर्तन भी सयुक्त राज्य के अदायगी सन्तुलन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकता है। तीसरा कारण यह है कि बहुत-से देशो के लिए सयुक्त राज्य के साथ व्यापार इतना महत्त्वपूर्ण है कि वे अमेरिका को उसके उन कामो से जाँचते है, जो वह अपनी आयात और निर्यात की-समस्याओ को हल करने के लिए करता है। अन्य देशो का यह रुख सयुक्त राज्य की परराष्ट्र नीति की प्रभावकारिता के लिए बहुत महत्त्व-पूर्ण है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध मे पुराना सिद्धान्त यह है कि जो राष्ट्र जिन वस्तुओ और सेवाओ के उत्पादन मे अन्य देशो की अपेक्षा अधिक सुविधा और लाभ की स्थिति मे है, यदि वह उनका उत्पादन कर सके और उन्हे विदेशो मे बिना किसी बाधा के बेच सके तो उससे विश्व व्यापार प्रणाली के सभी सदस्य देशो को लाभ होता है। इस सिद्धान्त की मान्यता यह है कि यदि आयात और निर्यात पर तट-कर

आदि की बाधाएँ अपेक्षाकृत मामूली होंगी, तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभो की इस विश्व व्यापार प्रणाली मे भाग लेने वाले देशों मे देर-सवेर समुचित वितरण हो जायेगा, बशर्ते कि हर देश की

चार्ट 15

कुछ चुने हुए देशों के साथ संयुक्त राज्य का विदेशी व्यापार, 1959
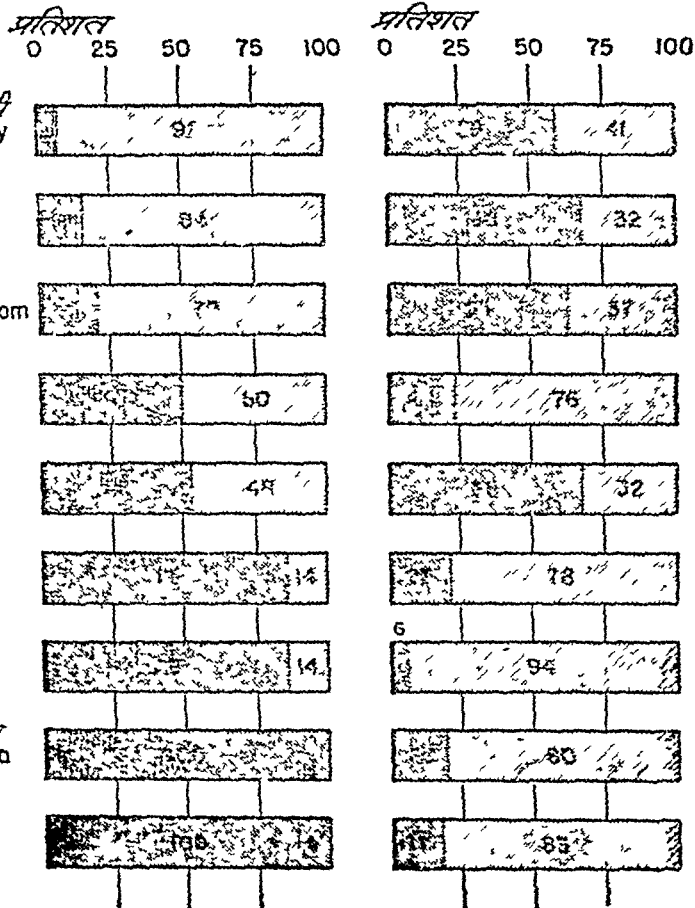
1. इसमें बहुत-सी अर्द्ध निर्मित वस्तुएँ भी शामिल है ।

विशिष्टता उन वस्तुओ का उत्पादन हो, जिनका वह दूसरो से सस्ता और अच्छा उत्पादन या निर्माण कर सकता है।

किन्तु फिर भी, उन्नीसवी शताब्दी के थोडे-से समय को छोडकर, शेष सारे समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के अधिकतर सदस्य देश अपनी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्थाओ के ढाँचे या परिस्थितियो मे अनवरत परिवर्तन करने के लिए, जो कभी-कभी बहुत उग्र होते है, अनिच्छुक रहे हैं, हालाकि ये परिवर्तन इस सिद्धान्त के अनुसार अनिवार्य होते हैं कि जो देश किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए दूसरे देशो से अधिक लाभजनक स्थिति मे है, वही उसका उत्पादन करे और उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे बेरोकटोक बेच सके। यहाँ तक कि उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे भी सयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रास आदि नये औद्योगिक राष्ट्रो ने अपने 'शिशु उद्योगो' को ब्रिटेन के पहले से जमे हुए और उन्नत उद्योगो की प्रतिस्पर्धा से सरक्षण देना ज़रूरी समझा। दूसरी ओर जब इन नये औद्योगिक राष्ट्रो ने, कुछ तो तटकर आदि सरक्षणो के द्वारा और कुछ अन्य उपायो से, अपने आपको औद्योगिक क्षेत्र मे मज़बूत बना लिया तब उल्टा ब्रिटेन ही स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त को छोडने के लिए मजबूर हो गया ताकि वह सयुक्त राज्य, जर्मनी और जापान के नये और अधिक कुशल उद्योगो की प्रतिस्पर्धा से अपने कुछ पुराने ढर्रे के उद्योगो को बचा सके।

दोनो विश्व-युद्धो के बीच की अवधि मे, खासकर सन् 1930 के दशक की भारी मन्दी के बाद, प्राय सभी प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रो ने अपने गिरते हुए आन्तरिक बाजारो को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए अपने आयात सम्बन्धी प्रतिबन्ध बढा दिये। इस प्रकार अपेक्षाकृत अधिक लाभजनक स्थिति वाली वस्तुओ और सेवाओ के उत्पादन और निर्बाध व्यापार के पुराने सिद्धान्त को मानते हुए भी प्राय सभी देशो ने अपने औद्योगीकरण को बढाने के लिए, या अपने पुराने और अकुशल उद्योगो को अन्य देशो के नये और कुशल उद्योगो की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए अथवा मन्दी के दिनो मे अपने आन्तरिक उत्पादन को आयात के

दुष्प्रभावों से रक्षा करने के लिए आयात पर पाबन्दियाँ लगा दी ।

सयुक्त राज्य ने अपने समूचे इतिहास मे हमेशा इनमे से किसी एक या एकाधिक उद्देश्यो के लिए आयात पर प्रतिबन्ध लगाये रखा है। सन् 1860 के वाद, सिर्फ दो मौको को छोडकर, हमेशा ही सयुक्त राज्य अपने तटकर की दरो मे समय-समय पर वृद्धि करता रहा है और सन् 1930 के स्मूट-हॉले टैरिफ ऐक्ट के समय तो ये दरे अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई । लेकिन उसके बाद सन् 1934 से यह रुझान उल्टा हो गया । राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट द्वारा प्रारम्भ किये गए पारस्परिक व्यापार समझौता कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका ने अन्य देशों के साथ समझौते करके अपने अनेक तटकरो को या तो विलकुल खत्म कर दिया या उनमे काफी कमी कर दी और इन समझौतो के फलस्वरूप अन्य देशो ने भी अमेरिका की खास खास चीजो पर अपने आयात-कर कम कर दिये । काग्रेस समय-समय पर पारस्परिक व्यापार समझौता अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार देती रही है कि वे अन्य देशो से अमेरिकी माल पर तटकर सम्बन्धी रियायते प्राप्त करें और उसके बदले मे उन्हे भी रियायते दे ।

किन्तु 1940 के दशक के बाद राष्ट्रपति को दिये गए इस अधिकार की प्रभावकारिता कुछ कम हो गई, क्योंकि उपर्युक्त कानून मे दो सशोधन कर दिये गए, जिनसे ऐसे अमेरिकी निर्माता, जो यह महसूस करते हो कि उन्हे विदेशी प्रतिस्पर्धा से नुक्सान हो रहा है या हो सकता है, तटकर मे प्रस्तावित कमी को रोक सकते है या पहले कम किये गए तटकरो को फिर बढवा सकते है । इसके अलावा काग्रेस ने वस्त्र, सीसा, जस्त, चीनी आदि कुछ वस्तुओ के आयात के लिए कोटे भी वाँधे, क्योकि यह महसूस किया गया कि तटकर बढाने से भी इन वस्तुओ मे विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकावला नही किया जा सका, या राष्ट्रीय रक्षा अथवा अन्य कारणो से ऐसा करना आवश्यक है ।

बहुत-से अमेरिकी उद्योगो मे, खासकर वडे पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगो मे—जैसे कि टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओ के उद्योग—अमेरिकी

निर्माताओ को यह डर नही है कि अमेरिका के आन्तरिक बाजार मे विदेशी निर्माता उनका मुकाबला कर सकेंगे। और ये उद्योग विदेशी बाजारो मे भी अपना माल अधिक बेच सकते है, बशर्ते कि अन्य देश माल मगाने के मामले मे डालर क्षेत्र से भेदभाव न बरते। लेकिन दूसरी ओर कुछ उद्योग ऐसे भी हैं, जिनमे अमेरिका के आन्तरिक बाजार मे विदेशी निर्माताओ की तरफ से काफी जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा है। इनमें बहुत-से उद्योग वे हैं जिनमे श्रम की बहुत जरूरत पडती है, या जो अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं या ऐसे खास और जटिल किस्म के उपकरण तैयार करते है जो बडे पैमाने पर तैयार नही किये जा सकते। उदाहरण के लिए अनेक प्रकार के कपडे, घडियाँ, चीनी मिट्टी का सामान, कुछ रासायनिक पदार्थ और कुछ खास किस्मो के बिजली के या दूसरे भारी सामान, जिनके लिए इजीनियरी और श्रम दोनो की बहुत अधिक आवश्यकता पडती है, इनमे शामिल किये जा सकते है। इन और इनके जैसी अन्य वस्तुओ के अमेरिकी निर्माताओ ने तटकर मे वृद्धि, कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध, सरकारी खरीद मे तरजीह आदि उपायो से देश के आन्तरिक बाजार विदेशी निर्माताओ की वास्तविक या सम्भावित प्रतिस्पर्धा से सरक्षण या तो प्राप्त कर लिया या उसके लिए उद्योग कर रहे हैं।

अमेरिकी आयात प्रतिबन्धो मे भविष्य मे कमी होगी या नहीं, यह अभी अनेक कारणो से अनिश्चित है। अन्य बडे औद्योगिक राष्ट्रो की तुलना मे अमेरिका मे इस समय ये प्रतिबन्ध कम हैं। अमेरिकी तटकरो मे जो भी कमियाँ आसानी से या बिना किसी विवाद के की जा सकती थी, वे सभी पारस्परिक व्यापार समझौता कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जिन मामलो मे तटकर की दरे कम नही की गई, उनमे भी तटकरो का प्रभाव प्राय खत्म हो गया है क्योंकि या तो उन वस्तुओ के मूल्यो मे दीर्घकाल के लिए कमी कर दी गई है या लोगो की रुचियाँ बदल जाने से उनका आयात ही नगण्य रह गया है। इसलिए यदि आयात-करो में भविष्य मे और कमियाँ की गई तो उनसे अमेरिका

के आन्तरिक बाजार मे विदेशी प्रतिस्पर्धा के बढने की ही अधिक सम्भावना है। संयुक्त राज्य मे इस प्रतिस्पर्धा मे वृद्धि को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से स्वीकार तभी किया जाएगा जब कि (क) इस प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होने वाले उद्योगो के मालिक और मजदूर, दोनो स्वेच्छा से या सरकारी सहायता से आवश्यक हेरफेर और परिवर्तन करने को तैयार हो और उसके लिए समर्थ भी हो; और (ख) विदेशी बाजारो मे अमेरिकी निर्यात को बढाने के लिए भी उतने ही अवसर मिले और सयुक्त राज्य के निर्यातक उसका लाभ उठाने के लिए तैयार और समर्थ हो।

अमेरिकी उत्पादक अपने देश के आन्तरिक बाजार मे विदेशी प्रतिस्पर्धा बढने पर आवश्यक परिवर्तन अनेक प्रकार से कर सकते है। अनेक उद्योगो मे यह सम्भव है कि उत्पादकता मे वृद्धि अथवा उत्पादित माल की किस्म मे सुधार कर लिया जाय, जिससे कि तटकर मे कमी कर देने पर भी वे मूल्य या किस्म के लिहाज से विदेशी माल का मुकाबला कर सके। लेकिन अतीत मे यह देखा गया है कि कुछ अमेरिकी उद्योग या कारखाने विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होने पर इन परिवर्तनो के लिए तैयार नजर नही आये। और कुछ उद्योग ऐसे है जिनमे उत्पादकता बढाने के लिए अधिक अनुसधान, पूंजी या प्रबन्ध-कौशल अथवा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसके बिना ये उद्योग इस दिशा मे प्रगति नही कर सकते।

कुछ उद्योग ऐसे भी है जिनमे विदेशी उत्पादक उत्पादन के लिए इतनी अधिक लाभजनक स्थिति मे है, कि अमेरिकी उत्पादको का उत्पादकता मे यथासम्भव वृद्धि करने पर भी उनकी प्रतिस्पर्धा मे टिकना सम्भव नही है। यह वात उन देशो के आयात के बारे मे खास तौर मे सही है जिनमे मजदूरी की दर और कच्चे माल का मूल्य बहुत कम है। ऐसी वस्तुओ के मामलो मे यदि अपेक्षाकृत लाभजनक स्थिति के सिद्धान्त को पूरे तौर पर लागू करना हो तो यह जरूरी होगा कि अमेरिका अपनी पूंजी और अपने श्रमिको को और किस्मो के उत्पादन मे लगाये और इन

वस्तुओ की अपनी माँग को पूरा करने के लिए पूर्णत आयात पर ही निर्भर रहे। और पिछले तीस वर्षो मे काफी अधिक किस्मो की वस्तुओ के बारे मे यह दु खद परिवर्त्तन करना भी पडा है। यह बात सहज मे समझ मे आने वाली है कि इन वस्तुओ के उत्पादन मे लगे हुए उत्पादको और श्रमिको ने स्वभावत अपने देर से चले आ रहे कामो को बन्द या कम करने का प्रतिरोध किया। जिन इलाको मे आयात की प्रतिस्पर्धा से भिन्न अन्य उद्योगो मे भी शिथिलता या ह्रास आ रहा था, वहाँ यह प्रतिरोध और भी उग्र हुआ। इसलिए इन ह्रासोन्मुख, अवरुद्ध उद्योगो और शिथिलता तथा मन्दी के शिकार इलाको मे ही तटकरो मे प्रस्तावित कमी को रुकवाने या पहले हुई कमियो को रद्द करवाने के लिए सबसे अधिक आन्दोलन हुए और वे सफल भी हुए। यही नही, इन उद्योगो और इलाको ने नये कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगवाने और सरकारी खरीद मे तरजीह या अन्य प्रकार के सरक्षण औरसहायताएँ प्राप्त करने मे भी सफलता प्राप्त की।

हाल के वर्षो मे उद्योगो, कम्पनियो, श्रमिको और मन्दी के शिकार इलाको को आयात की प्रतिस्पर्धा के कारण दोनो प्रकार के परिवर्त्तन करने के लिए सहायता देने के अनेक प्रस्ताव किये गए। जहाँ व्यावहारिक और सम्भव प्रतीत हुआ उन्हे अपनी उत्पादकता को बढाने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया और साथ ही जहाँ उचित हुआ, उन्हे अपनी पूंजी और श्रमिको को दूसरी किस्मो के उत्पादनो या दूसरे इलाको मे लगाने के लिए भी प्रोत्साहन और मदद देने के सुझाव दिये गए। लेकिन इस प्रकार के परिवर्त्तन करने के लिए सहायता देने के अनेक प्रस्ताव पिछले दस वर्षो मे काग्रेस मे पेश किये जाने पर भी उनमे से पास कोई नही हुआ। फिर भी विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित कुछ उद्योगो और इलाको ने इस तरह के परिवर्त्तन के लिए सघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो द्वारा मन्दी-ग्रस्त इलाको की सहायतार्थ प्रारम्भ किये गए कार्यक्रमो के अन्तर्गत, जिनका अध्याय 9 मे उल्लेख किया जा चुका है, सहायता प्राप्त की। अमेरिकी आयात प्रतिबन्धो मे भविष्य मे

कोई और कमी की जाती है या नही, राजनीतिक दृष्टि से इसकी सम्भावना इस बात पर बहुत कुछ निर्भर है कि क्या आयात की प्रतिस्पर्धा के बढने से प्रभावित होने वाले उद्योगो, उत्पादको और इलाको को उपर्युक्त परिवर्त्तन करने के लिए सहायता देने के प्रभावकारी कार्यक्रम अपनाये जाते है। यह बात इसलिए भी है, कि जितना भी सरक्षण इन उद्योगो के ऊपर से हटाया जा सकता था, करीब-करीब वह सब पहले ही हटाया जा चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे अमेरिकी निर्यात के लिए अवसर और गुजाइश को बढाना भी एक कठिन कार्य हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के एकदम बाद के पुर्ननिर्माण और पुनरुद्धार के वर्षो मे यूरोप और जापान को अमेरिका से किये जाने वाले निर्यात के कम होने का यह कारण उतना नहीं था कि वहाँ इस निर्यात की कीमत अच्छी वसूल नही हो सकेगी या वहाँ अमेरिकी माल पर तटकर अधिक है, जितना कि यह कारण था कि इन देशो के पास अपनी जनता का पेट भरने या अपनी युद्धध्वस्त अर्थ-व्यवस्था के पुर्ननिर्माण के लिए अमेरिका से खाद्य, ईंधन और पूंजीगत सामग्री मगाने के लिए मूल्य की अदायगी के साधन पर्याप्त नही है। इसी तरह लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के अल्प-विकसित देश भी नि सन्देह अमेरिका से कही अधिक माल आयात करते यदि उनके पास उसका मूल्य चुकाने के लिए पर्याप्त डालर होते। लेकिन यूरोप के पुनरुद्धार का कार्यक्रम 1950 के दशक के मध्य मे समाप्त हो जाने और 1957 मे हुए स्वेज सकट के भी खत्म हो जाने के बाद विश्व के बाजार मे अमेरिकी निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे काफी परिवर्त्तन होता रहा है।

यूरोप के उद्योग न केवल द्वितीय विश्वयुद्ध के दुष्प्रभावो से मुक्त हो गए है, बल्कि उन्होने उत्पादकता, उत्पादन और साहसिक उद्यम के नये ऊँचे स्तर प्राप्त कर लिये है। इसका एक कारण यह है कि मार्शल योजना के अन्तर्गत अमेरिका ने जो रुख अपनाये और जो ढग अपनाये उनसे यूरोप के देशो ने अनेक सबक लिये। इसका दूसरा कारण यूरो-

पीय साझा बाजार का निर्माण और प्रगति है। इस बाज़ार के निर्माण से सदस्य देशो मे आर्थिक उन्नति के अवसर बढे और उनमे निर्माताओ का परस्पर प्रतिस्पर्धा का उत्साह भी बढा। इसका तीसरा कारण यह था कि यूरोपीय देशो की सरकारो ने अपने निर्यात को बढाने के लिए विशेष प्रयत्न किये और कार्यक्रम बनाये और साथ ही 1949 के मुद्रा-सुधारो के परिणामस्वरूप अमेरिकी डालर के साथ अपनी मुद्राओ की विनिमय दर घटा दी।

आज यह स्थिति है कि यूरोपीय देशो के, खासकर यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशो के, निर्माता यूरोप के भीतर भी और बाहर भी अपने उत्पादनो के लिए नये-नये बाजार खोजने मे जोरो से लगे है। यूरोप और जापान के निर्माता और निर्यातक मूल्य, उत्पादन की किस्म, ग्राहको की जरूरतो और रुचियो की सन्तुष्टि, मशीनो की मरम्मत और फालतू पुर्जो की सप्लाई, ऋण की व्यवस्था, जहाजी परिवहन और बीमे का खर्च और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य पहलुओ की दृष्टि से न केवल अमेरिकी निर्माताओ और निर्यातको का सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहे है, बल्कि पिछले कुछ वर्षो मे उन्होने उन्हे प्रतिस्पर्धा मे पछाड भी दिया है।

यूरोपीय देशो और जापान मे फिर से निर्यात की क्षमता पैदा हो जाना एक स्वागतयोग्य घटना है। ये देश अपने आर्थिक स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए विदेशी व्यापार पर सयुक्त राज्य की अपेक्षा कही अधिक निर्भर है। यदि इन देशो को अपनी जनता के रहन-सहन को सन्तोषजनक बनाना हो, ससार के अल्पविकसित भागो की सहायता के काम मे हिस्सा बटाना हो और कम्युनिस्टो के आक्रमण और आन्तरिक षडयन्त्र से अपनी रक्षा करनी हो तो उनकी अर्थ-व्यवस्थाओ को निरन्तर उन्नत करते रहना और उनके विदेशी व्यापार को बढाना जरूरी है। इसलिए इन देशो की आर्थिक उन्नति स्वय अमेरिका के भी हित मे है और उनकी प्रतिस्पर्धा की शक्ति अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को सीधा लाभ भी पहुँचा सकती है, क्योकि उससे अमेरिकी उत्पादन कर्ताओ को भी

कता यूरोप और जापान के श्रम-प्रधान उद्योगो की अपेक्षा कई गुना अधिक थी और इसलिए मज़दूरी की सस्ती दर के कारण कम लागत आने के इन देशो के लाभ को बराबर करके भी अमेरिकी उद्योगो का माल उनसे सस्ता पडता था। यह ठीक है कि पिछले दस वर्षो मे यूरोप मे मजदूरी की दरो मे वृद्धि हो रही है और जापान मे यह वृद्धि उससे भी अधिक हे, लेकिन साथ ही यह भी सही है कि ये देश नये सयन्त्र और मशीने लगाने और अधिक अच्छे कुशल प्रबन्ध-विधियो और अधिक अच्छे वितरण के तरीको को अपनाने पर उससे भी अधिक खर्च कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अमेरिका और इन देशो के उद्योगो की उत्पादकता का अन्तर आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है और कुछ मामलो मे वह पूर्णत समाप्त हो गया है। यदि यूरोपीय देश उद्योगो मे नई पूंजी के निवेश को इसी तरह बढाते रहे, जैसा कि सम्भव प्रतीत होता है, तो अमेरिका और यूरोप की मजदूरी की दरो का अन्तर, हालाकि वह अब कम हो रहा है, अमेरिकी उद्योगो के लिए और भी अधिक गम्भीर समस्या पैदा करेगा और उनके लिए निर्यात बाजार मे अपनी निर्मित वस्तुओ की कीमते नीची रखना मुश्किल हो जाएगा।

इस असगति का दूसरा कारण यह है कि कुछ अमेरिकी कम्पनियो का रुख अपने निर्यात व्यापार के प्रति बहुत उत्साहपूर्ण नही है। अमेरिका की अधिकतर निर्माता कम्पनियो का निर्यात उनकी कुल बिक्री का बहुत ही थोडा हिस्सा होता है। इसलिए वे अपने उत्पादन को देश के भीतर बेचने वाले विभाग को अधिकाधिक कार्यकुशल बनाने की ओर जितना ध्यान देती है, उतना अपने निर्यात-व्यापार विभाग की ओर नही देती। ये कम्पनियाँ अपने आन्तरिक बिक्री विभाग के उच्च अधिकारियो को बिक्री बढाने के लिए जितनी स्वतन्त्रता देती है उतनी अपने निर्यात विभाग के उच्च अधिकारियो को निर्यात बढाने के लिए नही देती। इसके अलावा अमेरिकी लोग अपने देश की आर्थिक और सास्कृतिक परिस्थितियो से जितने

परिचित हैं उतने अन्य देशो की परिस्थितियो से परिचित नही हैं, इसलिए वे यह जानते है कि अमेरिकी खरीदार क्या खरीदना चाहता है, लेकिन अन्य देशो का खरीदार क्या खरीदना चाहता है, इस की उन्हे पूरी जानकारी नही है।

वहुत-सी अमेरिकी कम्पनियो मे यह भी प्रवृत्ति देखी गई है कि वे माल का अन्य देशो मे निर्यात करने के वजाय उसका उत्पादन ही अन्य देशो मे करती है। इसके दो कारण है, एक यह कि इससे निर्यात वाजार मे उन्हे प्रतिस्पर्घा कम करनी पडती है और दूसरा यह कि उन्हे यूरोप और जापान मे अपनी पूंजी का निवेश करने के लिए नये और अधिक आकर्षक अवसर उपलब्ध है। कुछ मामलो मे तो अमेरिकी कम्पनियो ने यूरोप मे अपने ही कारखाने खडे कर लिये हैं और कुछ मामलो मे यूरोप मे पहले से ही मौजूद कम्पनियो के साथ उन्होने साझेदारी कर ली है या उनके साथ लाइसेस सम्बन्वी समझौते कर लिये है। इससे इन कम्पनियो को दो लाभ होते है। एक तो वे यूरोपीय साझा वाजार और उससे सम्बद्ध देशो की तटकर सम्बन्धी दीवारो के भीतर ही व्यापार कर सकती हैं और अमेरिका से माल निर्यात करने पर तटकर की ऊँची दीवार को पार करने की जो कठिनाई होती है, वह उन्हे नही उठानी पडती, और दूसरे, वे यूरोप मे मजदूरी की सस्ती दर के कारण कम खर्च मे माल तैयार करके वहाँ से आसानी से ससार के अन्य भागो को निर्यात कर सकते है। इसके अतिरिक्त वहुत-सी अमेरिकी कम्पनियां उन अल्प विकसित देशो मे भी, जिन्हे पहले वे अपना माल अमेरिका से निर्यात करती थी, अव अपनी निर्माण शाखाएँ या अधीनस्थ सहायक कम्पनियां खोलने लग गई है। ये अमेरिकी कम्पनियां अपने देश से मशीनरी आदि के पुर्जे और हिस्से या अर्ध-निर्मित वस्तुएँ भेजती है और इन निर्माणशालाओ या अधीनस्थ सहायक कम्पनियो मे उन्हें जोड़कर पूरी मशीनें तैयार की जाती हैं या निर्मित वस्तु को अन्तिम रूप से जोडकर या सुधारकर तैयार किया जाता है और फिर ये सब चीजें उन देशो में वेची जाती है। यही कारण है कि

पिछले दस वर्षों मे पुर्जों, हिस्सो और अर्द्धनिर्मित वस्तुओ का निर्यात काफी बढा है।

और अन्त मे यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि बहुत-से देश अमेरिका मे निर्मित माल के साथ भेदभाव बरतते है। कुछ मामलो मे अमेरिकी माल के आयात को रोकने के लिए तटकर की ऊँची दीवारें खडी कर दी जाती है और कुछ मे अमेरिकी माल के आयात के लिए कोटे बाँध दिये जाते हे या विदेशी मुद्रा सम्बन्धी पाबन्दियाँ लगा दी जाती हैं। हाल के वर्षों मे यूरोपीय देशो और जापान की आर्थिक स्थिति सुधरने और मुद्राओ की परिवर्त्तनीयता (एक मुद्रा का दूसरी मे परिवर्त्तन) मे काफी सुधार होने के कारण और कुछ हद तक व्यापार-समझौता कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए आपसी समझौते से तटकरो मे कमी की वजह से अमरीकी माल के साथ यह भेदभाव काफी कम हो गया है। किन्तु अब भी पर्याप्त भेदभाव मौजूद है। अल्पविकसित देशो मे यह भेदभाव विदेशी मुद्रा की कमी के कारण और उनके नव-स्थापित शिशु उद्योगो को सरक्षण देने के लिए किया जाता है। पश्चिमी यूरोप के देशो मे यह भेदभाव दो कारणो से हो रहा है। एक तो उन देशो के उद्योगो को सरक्षण देने के लिए और दूसरे इसलिए कि साझा बाजार के सदस्य देशो के पारस्परिक व्यापार पर आन्तरिक सीमा शुल्क कम हो रहे है और बाहरी देशों से उनके आयात पर सीमा-शुल्क बढाया जा रहा है।

इन तथा कुछ अन्य कारणो का सम्मिलित परिणाम यह हुआ है कि हाल के वर्षों मे अमेरिका से पूर्ण-निर्मित माल के निर्यात मे वृद्धि की गति धीमी रही है। इनमे से कुछ कारण तो जीवन के ऐसे तथ्य है जिनके सम्बन्ध मे कुछ नही किया जा सकता और वे वांछनीय भी हैं। और दूसरे कारण ऐसे है जिन्हे, यदि अमेरिकी व्यावसायिक फर्में चाहे और उनमे उसके लिए पर्याप्त शक्ति हो तो, वे निवारण कर सकती हैं। यदि अमेरिकी फर्में अपने आन्तरिक बाजार मे प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकती हैं तो इसमें सन्देह का कोई कारण नही कि उनमे से बहुत-सी

फर्मे विदेशो मे बढ रही प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए भी देर-सवेर आवश्यक कदम उठा सकेगी। अमेरिकी फर्मो मे नि.सन्देह इतनी योग्यता है कि वे अपने निर्यात विभागो के कर्मचारियो और उनकी कार्यपद्धति मे सुधार कर सके और अपने निर्यात को बढाने के लिए अधिक समझदारी और सूझ-बूझ से काम ले सके। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उन्नति की गति को बढाने के लिए उसकी औद्योगिक उत्पादकता को बढाना भी जरूरी होगा। सयुक्त राज्य मे उद्योगो के प्रबन्धक और श्रमिक दोनो ही अगर अपनी जिम्मेदारी को कुछ थोडा-सा और महसूस करे तो वे अपनी लागत को इतनी कम कर सकते है कि विश्व के बाजार मे अपने प्रतिस्पर्धियो का मुकाबला कर सके।

इसके अतिरिक्त अमेरिकी सरकार ने भी हाल मे अमेरिका के निर्मित माल के निर्यात को बढाने के लिए अपनी नीतियो और कार्य-क्रमो को सुधारना प्रारम्भ कर दिया है। अब तक सरकार निर्यात को बढाने के लिए सबसे बडी सीधी सहायता यह देती थी कि वह अन्य देशो को दी जाने वाली अनुदान या ऋण की सहायता के साथ उससे अमेरिकी वस्तुओ और सेवाओ की एक निश्चित मात्रा की खरीद की शर्त लगा देती थी। पर अभी कुछ समय से काग्रेस वाणिज्य विभाग के लिए निर्यात को प्रोत्साहन देने, विदेशी बाजारो मे अमेरिकी माल का प्रचार करने और अन्य तरीको से अमेरिकी निर्यातको को मदद देने के लिए काफी राशियाँ स्वीकार कर रही है। कुछ ऐसे प्रस्तावो पर भी विचार किया जा रहा है जिनसे अमेरिकी निर्यातक सरकार की मदद से विदेशी खरी-दारो को उधार माल बेच सकेंगे और सरकार उस उधार की वसूली की गारण्टी करेगी। इस तरह अब सयुक्त राज्य की सरकार भी अपने निर्यातको को इस प्रकार की सहायताएँ देने लगी है जो यूरोपीय देशो और जापान की सरकारे अपने निर्यातको को वर्षो से देती आ रही हैं।

यद्यपि अमेरिका के कारखानो में निर्मित माल के निर्यात को

प्रोत्साहन देने की समस्या अपेक्षाकृत नई है, परन्तु सयुक्त राज्य के कृषि-उत्पादनो की समस्या सरकार और प्राइवेट उत्पादको को काफी समय से परेशान करती रही है। सयुक्त राज्य मे अनाज, गल्ला, पशुओ का चारा, कपास, तम्बाकू, ताजा फल और अन्य कृषि उत्पादन इतनी अधिक मात्रा मे पैदा होते है कि देश के ऊँचे जीवन-स्तर को देखते हुए भी वे उसकी अपनी आन्तरिक माँग से काफी अधिक है। लेकिन दिक्कत यह है कि अन्य देश इन फालतू उत्पादनो को खरीदने के लिए या तो तैयार नही है, या उनमे इसके लिए सामर्थ्य नही है। पश्चिमी यूरोप मे कृषि को काफी समय से अत्यधिक सरक्षण दिया जाता रहा है और यूरोपीय देश बाहर से कृषि-जिन्से सिर्फ उतनी ही मगाते है जितनी कि उनकी कमी को पूरी करने के लिए जरूरी है। इसमे से कुछ मात्रा वे अन्य देशो से व्यापारिक तरजीह के समझौतो के अन्तर्गत लेते है और फिर भी अगर कुछ कमी रह जाय तो उसकी पूर्ति के लिए वे अमेरिका से कृषि-जिन्से खरीदते है। ससार के अल्प विकसित भाग मे, खासकर दक्षिणी एशिया और लैटिन अमेरिका मे, अन्न की उपज वहाँ की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए काफी नही है। इसलिए उन्हे अनाज आयात करने की बहुत जरूरत पडती है ताकि अपनी जनता के अन्न के उपभोग के स्तर को शरीर-धारण के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से ऊँचा उठा सके। कही-कही तो अन्न की उपज जीवन-यात्रा चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से भी नीचे रहती है, इसलिए वहाँ अन्न के उपभोग को न्यूनतम स्तर तक पहुँचाने के लिए भी अन्न का आयात आवश्यक हो जाता है। लेकिन इस आवश्यकता के बावजूद ये देश खाद्य पदार्थो का आयात नही कर पाते, क्योकि एक तो उनके पास उसके लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नही होती और दूसरे गरीबी के कारण उनकी जनता की क्रय-शक्ति भी इतनी नही होती कि वह अन्न खरीद सके।

इसलिए सयुक्त राज्य सरकार बहुत-से अल्प विकसित देशो को गुद के रूप मे उन्ही की स्थनीय मुद्रा मे क़ीमत लेकर अपनी फालतू

कृषि-जिन्से देती रही है ताकि वे अपनी खाद्यान्न की कमी पूरी कर सके। हाल मे इस कार्यक्रम को 'शान्ति के लिए अन्न कार्यक्रम' के नाम से पुनर्गठित किया गया है और इस कार्यक्रम ने बहुत-से देशो को अपने आहार के स्तर को ऊँचा उठाने मे सहायता दी है। लेकिन इन देशो को बहुत बडी मात्रा मे अमेरिकी कृषि-जिन्से भेजने से अन्य देशो को व्यापारिक आधार पर किये जाने वाले कृषि-जिन्सो के निर्यात मे कभी-कभी रुकावट पडती रही है और इन देशो मे अमेरिका के पास वहाँ की स्थानीय मुद्रा इतनी बडी मात्रा मे जमा हो गई है कि उसका समुचित उपयोग एक गम्भीर समस्या बन गया है और यह भी आशका हो गई है कि कही इसका प्रभाव मुद्रा-स्फीति को पैदा करने वाला न हो। लेकिन मौजूदा शताब्दी के शेष वर्षों मे ससार की आबादी मे भारी वृद्धि का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसे देखते हुए अमेरिकी कृषि की असाधारण उत्पादकता मानव समाज के लिए एक बहुत बडा वरदान सिद्ध हो सकती है। सिर्फ इस समस्या का हल करना आवश्यक है कि इन फालतू अमेरिकी कृषि उत्पादनो का वितरण कैसे किया जाय, यानी जिन लोगो को इन जिन्सो के आयात की बहुत अधिक आवश्यकता है, उनमे उसे खरीदने के लिए ज़रूरी क्रय-शक्ति कैसे पैदा की जाय। 'शान्ति के लिए अन्न' कार्यक्रम इसी दिशा मे एक कदम है, लेकिन आने वाले वर्षो मे इस दिशा मे इससे भी अधिक प्रगति करनी पड़ेगी।

सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि आगामी दशक मे अमेरिका शेष ससार मे अपना निर्यात किस हद तक बढा सकता है, यह कुछ हद तक प्राइवेट व्यवसायियो के क्रिया-कलाप पर और कुछ हद तक उन कार्यक्रमो और नीतियो पर, जिन्हे सयुक्त राज्य की सरकार अमल मे लाना चाहेगी या ला सकेगी, निर्भर है। यदि अमेरिकी माल का, खासकर कारखानो मे निर्मित माल का, निर्यात विश्व के बाजारो की वृद्धि के अनुकूल उचित मात्रा मे बढाना है तो अमेरिकी सरकार को अन्य देशो की सरकारो को यह समझाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना होगा कि उन्हे डालरो से खरीदे जाने वाले माल के साथ अवशिष्ट

भेदभाव भी खत्म कर देना चाहिए यदि यह सम्भव न हो तो उसे कम अवश्य कर देना चाहिए। देश के भीतर भी, और अन्य देशो के साथ मिलकर भी, ऐसे नये उपाय करने की आवश्यकता है जिनसे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे होने वाली नई वृद्धि के लाभो में अमेरिका भी समुचित हिस्सा बटा सके और इस व्यापार वृद्धि के प्रतिकूल प्रभावो को कम किया जा सके।

प्राइवेट विदेशी निवेश

सन् 1914 से पूर्व ब्रिटिश लोग विदेशों मे अपनी पूंजी का जितने बड़े पैमाने पर निवेश करते थे, उतने बडे पैमाने पर विदेशो मे निवेश करने की न तो सयुक्त राज्य के प्राइवेट निवेशको को कभी आवश्यकता अनुभव हुई और न उनका उस ओर कभी झुकाव ही हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था एक ऐसे स्तर पर पहुँच चुकी थी कि उसका अपना खाद्य और कच्चे माल का आन्तरिक उत्पादन उसकी आवश्यकता पूरी नही कर सकता था। इसलिए ब्रिटिश व्यवसायियो को अपने उद्योगो की और फिर अन्य देशों के उद्योगो की भी ज़रूरतें पूरी करने के लिए विदेशो मे इन वस्तुओ की उपलब्धि का विकास करने के लिए पूंजी का निवेश करना पडा। इस विदेशी पूंजी-निवेश से लोगो को देश के भीतर पूंजी-निवेश से होने वाले मुनाफे से भी कही अधिक मुनाफा कमाने का अवसर नज़र आया। इसका नतीजा यह हुआ कि लन्दन के द्रव्य बाज़ार के रास्ते से न केवल अंग्रेज निवेशको का, बल्कि अन्य यूरोपीय देशो के धनी लोगो का, पैसा भी विदेशो मे निवेश के लिए जाने लगा। उन्नीसवी शताब्दी मे ससार मे अपेक्षाकृत अधिक शान्ति थी और ब्रिटेन की विश्वव्यापी नौ सेना इस शान्ति की रक्षा के लिए सर्वत्र विद्यमान थी; इसलिए विदेशो मे धन का निवेश करना देश के भीतर निवेश करने से अधिक खतरनाक नही समझा जाता था।

आज अमेरिकी निवेशको को अपने देश के भीतर ही काफी लाभदायक कामो मे अपना धन लगाने के अवसर उपलब्ध है और अमेरिकी अर्थ-

व्यवस्था की ज़रूरतें पूरी करने के लिए विदेशों में कच्चे माल के रूप में काम आने वाली जिन सामग्रियों के स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है, वे अपेक्षाकृत कम हैं। इनमे कुछ खनिज पदार्थ, कुछ धातुएँ और कुछ कृषि-उत्पादन शामिल हैं। इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि देश के भीतर लगाई गई पूँजी विदेशों मे लगाई गई पूँजी की अपेक्षा अधिकृत सुरक्षित रहती है। युद्ध, क्रान्ति और उग्र राष्ट्रवाद के खतरे और सामान और धन के एक देश से दूसरे देश में जाने पर लगी मौजूदा पाबन्दियाँ प्राइवेट निवेशकों को अपना धन दूसरे देशो में लगाने के लिए निरुत्साहित करती हैं। यद्यपि आज भी अमेरिका का प्राइवेट विदेशी पूँजी-निवेश किसी भी अन्य देश के विदेशी पूँजी-निवेश से बडा है तो भी ऐसे देशों की, जो अपने आर्थिक विकास के लिए हाथ-पाँव मार रहे और भारी संघर्ष कर रहे हैं, विदेशी पूँजी की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिहाज से वह बहुत कम है।

अमेरिका के विदेशी निवेश का सबसे अधिक भाग कनाडा और लैटिन अमेरिका में लगा हुआ है, खासकर उनके पैट्रोलियम और निर्माण उद्योगो मे। एक ही जगह यह केन्द्रीकरण इस बात को स्पष्ट सूचित करता है कि इस समय अमेरिकी निवेशको को विदेशी निवेश के लिए व्यापक प्रोत्साहन नही मिल रहा और पश्चिमी गोलार्द्ध में धन का निवेश करना अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। अन्यत्र भी अमेरिकी निवेशकों का पूँजी-निवेश मुख्यत मध्यपूर्व के तेल उद्योग में और पश्चिमी यूरोप के निर्माण में ही केन्द्रित है। साँझा बाजार की प्रगति के बाद तो पश्चिमी यूरोप के निर्माण उद्योगो मे अमेरिकी पूँजी का निवेश और भी अधिक देखने में आया है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य सरकार ने अनेक उपायों से अमेरिकी निवेशकों को विदेशों में पूँजी-निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। उसने इसके लिए लोगों को कर सम्बन्धी विशेष लाभ दिये, उन्हें उनकी पूँजी और लाभ को डालर में परिवर्तन करने की गारंटी की और विदेशों में पूँजी लगाने की संभावनाओं और लाभों के बारे में जान-

कारी दी। इसके अलावा सरकार ने अन्य देशों के साथ निवेश-सन्धियाँ भी कीं, जिनके अन्तर्गत हर देश एक-दूसरे को यह वचन देता है कि वह दूसरे के निवेशक के साथ समान बर्ताव करेगा, उसकी कमाई पर दोहरा कर नही लगायेगा और सम्पत्ति की जब्ती या राष्ट्रीयकरण की दशा मे पर्याप्त मुआवजा देगा। किन्तु फिर भी इन सन्धियो की संख्या बहुत थोडी है।

तालिका 16

विदेशो मे सीधी लगी कुल अमेरिकी पूंजी—1960 तक

उद्योग	कनाडा	लैटिन अमेरिका	पश्चिमी यूरोप	अन्य	कुल	उद्योग की दृष्टि से प्रतिशत
		(अरब डालरो मे)				
पैट्रोलियम	2 7	3 3	1 7	3·3	10·9	33
खनन और प्रद्रावण उद्योग	1 3	1 3	[1]	3	3 0	9
निर्माण उद्योग	4·8	1·6	3 8	1 0	11 2	34
व्यापार	6	·8	7	3	2 4	8
सार्वजनिक उपयोग की सेवाएँ	6	1 2	[1]	7	2·5	8
विविध	1·1	1 1	·3	·2	2 7	8
कुल	11·2	9 2	6 6	5 7	32 7	100
क्षेत्र की दृष्टि से प्रतिशत	34	28	20	18	100	

अन्य देश युद्ध के बाद के प्रारम्भिक काल की अपेक्षा अब प्राइवेट विदेशी निवेशको के लिए अपने यहाँ अधिक अनुकूल वातावरण पैदा कर रहे है। यह बात बहुत-से ऐसे नव-स्वतन्त्र देशो के बारे मे खास तौर से

1. 5 करोड़ डालर से कम।

सही है जो औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत प्राप्त किये गए दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवो और कट्टर राष्ट्रवादी और समाजवादी रुझान के कारण शुरू मे प्राइवेट विदेशी निवेशको को शका की दृष्टि से देखते थे। इस मैत्रीपूर्ण रुख का एक कारण यह है कि उन्हे अपने विकास के लिए पूँजी की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए उन्हे न आन्तरिक स्रोतो से, न अन्य सरकारो से और न ही अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो से उसकी पर्याप्त उपलब्धि हो रही है। दूसरा कारण यह है कि बहुत-से अल्प-विकसित देश यह अनुभव करने लगे है कि उत्तरदायित्वपूर्ण अमेरिकी लोगो द्वारा किया गया पूँजी-निवेश न केवल आवश्यक पूँजी और तकनीकी एव प्रबन्ध विपयक ज्ञान की प्राप्ति का कुशल और अच्छा साधन है, बल्कि उसके कार्यों से जनता के एक बडे भाग के आर्थिक और सामाजिक कल्याण मे भी वृद्धि हो सकती है। हाल के वर्षों मे अमेरिकी कम्पनियों ने अन्य देशो मे स्थानीय उद्योगो के विकास को प्रोत्साहित करने, स्थानीय व्यक्तियो को तकनीकी और प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण देने और उन्हे उच्च पदो पर नियुक्त करने और अपने कर्मचारियो और उनके परिवारो के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने मे जो योग दिया है, उसने अनेक देशो मे लोगो के मन से यह भय दूर करने मे महत्त्वपूर्ण सहायता दी है कि अमेरिकी लोग उनका 'शोषण' करेगे या वे उन पर फिर 'साम्राज्यवाद' को लादना चाहते है।

यद्यपि अन्य देशो का रुख अमेरिकी पूँजी को स्वीकार करने के लिए पहले से अधिक अनुकूल है और अमेरिकी सरकार भी अपने प्राइवेट निवेशको को विदेशो मे पूँजी लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, तो भी विदेशो मे निवेशित प्राइवेट पूँजी वह भूमिका अदा नही करेगी, जो उसने उन्नीसवी शताब्दी मे की थी। न केवल प्राइवेट पूँजी का अन्य देशो को निर्यात बहुत कम पैमाने पर हो रहा है, बल्कि प्राइवेट पूँजी आम तौर पर कुछ ऐसे कामो मे भी नही लग रही जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है। उन्नीसवी शताव्दी मे प्राइवेट विदेशी पूँजी बुनियादी परिवहन सुविधाओ, सार्वजनिक उपयोग की सेवाओ एव

स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओ मे लगती थी, परन्तु आज कुछ देशो के मामलो मे इस बात की बहुत कम सभावना है कि विदेशी पूंजी इन कामो मे लगे। लेकिन कृषि, खनिज उद्योगो, निर्माण-उद्योगो और वितरण व्यवसायो मे प्राइवेट विदेशी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इन सुविधाओ और सेवाओ का पर्याप्त मात्रा मे विकसित होना ज़रूरी है।

बीसवी शताब्दी के मध्य मे अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के प्रवाह को जो काम पूरे करने है, प्राइवेट अमेरिकी विदेशी निवेश, उनका एक अश ही पूरा कर सकता है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी के एक देश से दूसरे देश मे प्रवाह को कैसे पर्याप्त उन्नत किया जाय, यह समस्या, सयुक्त राज्य और पूंजी का आयात करने वाले देश, दोनो के लिए अगले दशक की महत्त्वपूर्ण समस्याओ मे मे एक होगी।

वैदेशिक सहायता कार्यक्रम और नीतियाँ

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सयुक्त राज्य की सरकार ने अन्य देशो को लगभग 80 अरब डालर की सहायता दी है ताकि वे अपनी युद्ध-ध्वस्त अर्थ-व्यवस्थाओ का पुनर्निर्माण करने, अपनी राष्ट्रीय रक्षा-व्यवस्थाओ को सुधारने और अपनी आर्थिक वृद्धि की गति को तेज करने के लिए जरूरी वस्तुएँ और सेवाएं खरीद सके। सरकारी ऋण और अनुदान इसलिए जरूरी थे, क्योकि वस्तुओ का सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और पूंजी का सामान्य प्रवाह अनेक देशो को उपर्युक्त उद्देश्यो की पूर्ति मे पर्याप्त साधन उपलब्ध नही करा सकता था। इसके अलावा, अमेरिकी सरकार ने सयुक्त राष्ट्र सघ की विविध सस्थाओ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एव विकास बैंक और अमेरिकी राज्यो का सघ आदि अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ को भी अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए 5 अरब डालर की राशि दी।

अमेरिकी लोग अपने साथी और मित्र देशो को इतनी बडी मात्रा आर्थिक सहायता देने के लिए अनेक कारणो से इच्छुक और उद्यत

रहे है। सबसे अधिक स्पष्ट कारण यह है कि अमेरिका जिन देशो को अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण समझता है उनकी अर्थ-व्यवस्थाओ को अस्त-व्यस्त होने से बचाना चाहता है और यह भी चाहता है कि कम्युनिस्ट उन्हे आक्रमण करके जीत न सकें या आन्तरिक षडयन्त्र से उनमे कम्युनिज्म स्थापित न करा सके। इस स्वार्थ भावना के साथ यह मानवीय भावना भी मिली रहती है कि ससार मे कही भी प्राकृतिक या मनुष्य-कृत विपत्तियो मे ग्रस्त लोगो की सहायता की जाय और अमेरिका की सम्पत्ति और दक्षता मे अल्पविकसित देशो को भी साझेदार बनाया जाय।

जिन यूरोपीय देशो को युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों से काफी बडी अमेरिकी सहायता मिली, उन्होने 1950 के दशक के शुरू मे ही काफी हद तक अपने आपको आर्थिक दृष्टि से खडा कर लिया और आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता भी प्राप्त कर ली। लेकिन पश्चिमी यूरोप मे उन्नीसवी शताब्दी की यह धारणा अब समाप्त हो गई है या धीरे धीरे समाप्त हो रही है कि किसी भी राष्ट्र के सफल अस्तित्व के लिए औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रो मे प्रमुखता, सैनिक प्रभुत्व, औपनिवेशिक शासन और श्रमिक वर्गों का राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर रहना आवश्यक है। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से ये देश एक नई बुनियाद पर अपने राजनीतिक और आर्थिक जीवन का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। यूरोप मे अनेक देश परस्पर मिलकर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अपने सघ बना रहे है और अपनी प्रभुसत्ताओ मे दूसरे देशो को भी हिस्सा दे रहे है और जो देश इन नई व्यवस्थाओ मे शामिल हो रहे है उनकी सुरक्षा, उत्पादनता और जन-जीवन के स्तर मे वृद्धि हो रही है। यूरोप के इस सघ को और भी बडा और व्यापक बनाने मे सफलता मिलेगी या नही, यह अभी से नही कहा जा सकता। किन्तु इसके परिणाम का प्रभाव बडा दूरगामी होगा, लोकतन्त्रीय समाजो के भविष्य के लिए निर्णायक होगा। यही कारण है कि संयुक्त राज्य ने इस एकीकरण के कार्य मे दिल-चस्पी ली है और इसे अनेक तरीको से प्रोत्साहन भी दिया है।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक गैर-कम्युनिस्ट देशो का पश्चिमी यूरोपीय देशो से भी कही अधिक काया-पलट हो रहा है। पश्चिम के व्यापार और विचारो के सस्पर्श से ये देश अपने सदियो पुराने सामाजिक और आर्थिक ढाँचे से बाहर निकल आये हैं और अपनी पुरानी जीवन-पद्धति मे फिर से लौट जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इनमे से कुछ देशो ने अभी हाल मे ही स्वाधीनता प्राप्त की है, फिर भी ये सभी देश अपनी आर्थिक अभिवृद्धि की गति तेज करना चाहते है ताकि अपनी जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठा सकें। लेकिन अधिक-तर अल्प-विकसित देशो से तब तक न तो उत्पादकता को बढाया जा सकता है और न ही जीवन-स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है, जब तक कि उनकी मौजूदा आर्थिक प्रणाली और उनके परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यो और सामाजिक सस्थाओ मे दूरगामी परिवर्तन न किये जाएँ। किन्तु इस प्रकार के विकासात्मक परिवर्तन न तो आसान है और न जल्दी किये जा सकते है।

इसके अतिरिक्त, इनमे से कई देशो के लिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया दो महत्त्वपूर्ण कारणो से बहुत पेचीदा हो गई है। पहला यह कि सोवियत सघ और कम्युनिस्ट चीन हर सम्भव उपाय से उन पर अपने प्रभुत्व का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे है। दूसरा यह कि पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान और आर्थिक टैकनोलॉजी के फलस्वरूप इन देशो की जनसख्या मे बहुत तेज रफतार से वृद्धि हो रही है। अभिप्राय यह है कि इन देशो की प्राकृतिक और अन्य साधन-सम्पदाओ के विकास और उपयोग मे इतनी तीव्रता से वृद्धि की जानी चाहिए कि कम्युनिस्ट इन देशो को आक्रमण या आन्तरिक षडयन्त्रो से जीत न सके और साथ ही उत्पादन उनकी आबादी की वृद्धि से आगे निकल जाय।

इस प्रक्रिया मे लगे गैर-कम्युनिस्ट देशो की आबादी ससार की कुल आबादी के आधे के लगभग है और उनके पास पृथ्वी की अछूती प्राकृतिक सम्पदाओ का, जिनका दोहन अभी तक नही किया गया, सबसे बडा भडार है। इतने बडे पैमाने पर होने वाले परिवर्तनो का परिणाम सिर्फ

इन देशों की जनता के लिए ही नही, सयुक्त राज्य के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण होगा। अमेरिका की इस प्रक्रिया मे सिर्फ इसीलिए दिलचस्पी नही है कि भविष्य मे वह इनसे कच्चे माल के आयात की आवश्यकता पूरी कर सकेगा। इन देशो के भविष्य मे उसकी दिलचस्पी का और भी अधिक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि आज इन देशो और औद्योगिक दृष्टि से काफी उन्नत और अग्रणी देशो की उत्पादकता और रहन-सहन के स्तर मे जो भारी अन्तर है, वह इस प्रक्रिया से कम हो जाएगा और अमेरिका इसे बहुत आवश्यक समझता है। यदि दुनिया के कुछ थोडे-से देश धन-धान्य और सम्पदा से भरपूर हो और बहु-सख्यक देश गरीबी और भारी जनसख्या की समस्याओ के साथ जूझ रहे हो और उनके बीच की यह खाई बराबर अधिकाधिक चौडी होती जाय तो ऐसी दुनिया मे कोई भी नई राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था स्थापित नही की जा सकती।

इसीलिए यूरोपीय राष्ट्रो और अल्पविकसित देशो मे जो कायाकल्प चल रहे है, उनमे सयुक्त राज्य की गहरी दिलचस्पी है। आशा है कि ये कायापलट पश्चिमी समाज के, खासकर सयुक्त राज्य के लोकतन्त्र के अस्तित्व और प्रगति के लिए खतरा सिद्ध नही होगे। इसका अर्थ यह नही है कि अन्य देश अमेरिकी समाज के विशिष्ट मूल्यो और संस्थाओ को अपना लेगे। अमेरिकी लोगो के लिए दूसरो को यह आदेश देना कि वे किस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक प्रणालियाँ अपनाये, न तो व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव है और न नैतिक दृष्टि से उचित ही। बल्कि आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि इन नये उभरते समाजो के रुख और उनकी नव-विकसित सस्थाएँ इस प्रकार की हो कि अमेरिकी समाज से सर्वथा भिन्न होते हुए भी अमेरिकी लोगो का उनके साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व सम्भव हो और वे परस्पर व्यापार कर एक-दूसरे को लाभ पहुँचा सके और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के हल के लिए आपस मे सहयोग कर सके।

ससार-भर के देशो मे इस समय जो नये रुख और नई संस्थाएँ

विकसित हो रही है वे उनकी जनता द्वारा अपनी राजनीतिक और आर्थिक सामर्थ्य और सांस्कृतिक सम्भावनाओ की सीमाओ के भीतर रहते हुए स्वयं निर्धारित की जानी चाहिएँ। इन बातो को दृष्टि मे रख कर यदि तोला जाय तो परिमाण की दृष्टि से अमेरिका की वैदेशिक आर्थिक गति-विधि का महत्त्व बहुत सीमित है। फिर भी दो दृष्टियो से उसकी बहुत अधिक अहमियत भी है।

पहली यह कि अमेरिका की वैदेशिक आर्थिक गति-विधि इन देशो के वित्तीय और तकनीकी साधनो को बढाती है, जो मात्रा मे स्वल्प होने पर भी उनके आर्थिक विकास कार्यक्रमो की सफलता या असफलता पर निर्णायक प्रभाव डाल सकते है। दूसरी यह कि ये वैदेशिक आर्थिक गति-विधियाँ अमेरिका मे तथा अन्य देशो मे अमेरिकी और अन्य लोगो के लिए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करती है जिनमे वे परस्पर मिलकर रचनात्मक ढग से वास्तविक जीवन की परिस्थितियो मे रह सकते है और यह बात दोनो के लिए बहुत अर्थयुक्त और महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न जातियो और ऐतिहासिक पृष्ठभूमियो वाले लोगो का दैनन्दिन और व्यावहारिक जीवन मे अनवरत रूप से साथ रहना एक ऐसा सर्वोत्तम और सम्भवत एकमात्र उपाय है जिससे पारस्परिक विश्वास और एक-दूसरे को समझने के और एक-दूसरे के ज्ञान को अपनाने के मौके मिलते है और सांस्कृतिक बाधाओ की परवाह किये बिना एक-दूसरे की तकनीको को स्वेच्छा से सीखने के अवसर उपलब्ध होते है। इस तरीके से, अमेरिकी लोग शासन और अर्थ-व्यवस्था दोनो मे कार्यरत लोकतन्त्र की एक मिसाल पेश कर सकते है।

इन देशो का आर्थिक विकास और सामाजिक कायाकल्प आसानी से नही किया जा सकता और न शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है। इसलिए यह सम्भव है कि इस प्रक्रिया मे अमेरिका काफी समय तक दिलचस्पी और हिस्सा लेता रहे। जरूरत इस बात की है कि सयुक्त राज्य की वैदेशिक आर्थिक गति-विधि को अमेरिका की परराष्ट्र नीति का एक अविच्छिन्न और अविभाज्य अग समझा जाय और यह माना

जाय कि उसका उद्देश्य केवल तात्कालिक खतरों को रोकना ही नही, बल्कि कुछ दीर्घकालिक ठोस लक्ष्यो का प्राप्त करना है।

विकास की समस्याओ और भावी सम्भावनाओ को अधिक अच्छी तरह हृदयंगम किये जाने के कारण ही सन् 1961 मे सयुक्त राज्य के वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। उसके लक्ष्यो, उपायो और प्रशासन मे परिवर्तन किये गए। अमेरिका यह स्वीकार करता है कि आर्थिक अभिवृद्धि और सामाजिक परिवर्तन, दोनो विकास की समूची प्रक्रिया के अनिवार्य हिस्से है, इसलिए उसके वैदेशिक सहायता कार्यक्रम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशो को कृषि-सुधार करने, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को ऊँचा उठाने, शहरो और देहातो मे अच्छी आवास-व्यवस्था करने, कर-प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील बनाने, मजदूरो और मालिको के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने और अन्य सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यो को प्राप्त करने मे सहायता प्रदान करते हैं। सहायता प्राप्त करने वाले देशो के लिए अब दोनों दृष्टियो से कार्यक्रम बनाये जाते है—एक ओर उनके दीर्घकालिक उद्देश्य निर्धारित किये जाते है और दूसरी ओर स्वल्पकालिक कार्यक्रमो को अच्छी तरह चलाने के लिए धन का समुचित विभाजन किया जाता है। मार्शल-योजना की भाँति अब भी कार्यक्रम निर्माण की यह पद्धति पुनः एक बुनियादी पद्धति के रूप मे अपना ली गई है। वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विभिन्न कार्यो को विभिन्न संगठनो के द्वारा चलाने की नीति को हाल मे बदल देने के कारण एक नई अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (एजेन्सी फॉर इटरनेशनल डेवलपमेट) स्थापित की गई है जिसमे इन सब विभिन्न सगठनो के कार्यों का समावेश कर दिया गया है। अब यह एजेन्सी ही परराष्ट्र विभाग की देखरेख मे वैदेशिक विकास सहायता का सारा काम करती है। काग्रेस ने इस नये सगठन को यह अधिकार दे दिया है कि वह इन देशो के विकास कार्यक्रमो के लक्ष्यो की पूर्ति को आसान बनाने के लिए दीर्घ-कालिक सहायता के वायदे कर सकता है।

यदि कांग्रेस इस कार्यक्रम के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त

राशि मजूर करने को तैयार हो और अमेरिकी जनता भी इस कार्यक्रम को समग्र रूप से अपना समर्थन प्रदान करती रहे तो ये परिवर्तन आगामी वर्षों मे अमेरिकी वैदेशिक सहायता के कार्य-कलापो को काफी हद तक प्रभावकारी बना देंगे। लेकिन यह कार्य बहुत विशाल है और अमेरिका इसमे जो योग दे रहा है वही अकेला इसे सफल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पश्चिमी यूरोप के देश, जापान और अन्य राष्ट्र भी आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यो को पूरा करने के लिए कुछ इलाको मे काफी बडे पैमाने पर सहायता दे रहे है। विकसित देशो के इन प्रयत्नो को काफी बढाना और समन्वित करना होगा, तभी अगले दस वर्षों मे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशो को दी गई कुल सहायता वास्तव मे कुछ प्रभावकारी रूप धारण कर सकेगी।

सयुक्त राज्य का अदायगी सन्तुलन और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की सभी वैदेशिक गति-विधियो—व्यापार, पूंजी-निवेश और सहायता—के लिए अमेरिका और अन्य देशो के बीच मुद्रा का अनेक प्रकार का आदान-प्रदान होता है। मुद्रा के इस सारे आदान-प्रदान को सक्षेप मे अदायगी सन्तुलन के ब्यौरे मे दिखाया गया है। इसमे शेष ससार के साथ अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध एक नजर मे देखा जा सकता है। वह इस सम्बन्ध मे आने वाले उतार-चढावो को देखने के लिए एक थर्मामीटर का भी काम दे सकता है। इससे यह पता चल सकता है कि कैसे समय-समय पर अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था और शेष ससार की अर्थ-व्यवस्था के बीच अदायगी के प्रवाह मे कभी तो बहुत-बडा नफा हुआ और कभी घाटा।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आम तौर पर अमेरिका के व्यापारिक वस्तुओ और सेवाओ के वैदेशिक व्यापार मे सन्तुलन अमेरिका के पक्ष मे ही रहा, अर्थात् उसने अन्य देशो को ये वस्तुएँ और सेवाएँ दी अधिक और उनसे ली कम। इसी तरह सन् 1940 मे अमेरिका द्वारा अन्य देशो

मे प्राइवेट पूंजी का निवेश पुन प्रारम्भ किये जाने के बाद से आम तौर पर अमेरिकी निवेश के लिए विदेशो मे सरकारी पूंजी अधिक गई पर उस पर होने वाली आय अमेरिका मे कम आयी।[1] यही स्थिति विदेशो मे गई प्राइवेट अमेरिकी पूंजी के बारे मे भी है। हालाकि उसकी मात्रा कम है पर अब वह धीरे-धीरे बढ रही है (देखिए परिशिष्ट तालिका 17 और 18)। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने अपने सभी प्रकार के सरकारी वैदेशिक सहायता कार्यक्रमो और अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो के कार्यों मे समय-समय पर दिये गए आर्थिक योगदान की शक्ल मे काफी बडी रकमो की विदेशो को अदायगी की।

1940 के दशक मे संयुक्त राज्य का अदायगी सन्तुलन उसके अपने पक्ष मे था, क्योकि अन्य देशो का अमेरिकी माल का आयात अमेरिका को किये गए उनके निर्यात के मूल्य से और अमेरिकी सहायता के रूप मे प्राप्त रकमों से अधिक था। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक देशो को अमेरिका के साथ अपना लेन-देन का हिसाब निपटाने के लिए अपने स्वर्ण और डालर के सुरक्षित कोष की सहायता लेनी पडी, जिससे उनका बहुत-सा सोना संयुक्त राज्य के स्वर्ण कोष मे आ गया। सन् 1949 मे संयुक्त राज्य का स्वर्ण कोष बढकर 24 अरब डालर का हो गया। मार्शल-योजना के दिनो मे और सन् 1950 मे अल्प विकसित देशो को अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता प्रारम्भ की जाने पर अमेरिका के भुगतान सन्तुलन मे कुछ मामूली-सा घाटा नजर आया अर्थात् अमेरिका की देनदारी उसकी लेनदारी से बढ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत-से यूरोपीय देश अमेरिका से सोना और डालर वसूल कर अपना स्वर्ण एव

तालिका 17

संयुक्त राज्य का अदायगी सन्तुलन, 1956-1960 (लाख डालरों में)

	कैलेंडर वर्ष				
	1956	1957	1958	1959[1]	1960
क. अमेरिकी सरकार के लेनदेन					
1. सैनिक कार्यक्रम	—26560	—26540	—29730	—26530	—25180
2. आर्थिक सहायता कार्यक्रम	—5350	—8660	—8950	—7060	—8470
3. ब्याज और मूल की वसूली	+6730	+8640	+8510	+13590	+9510
4. अमेरिकी सरकार के अन्य लेन देन	—5260	—5520	—4770	—7890	—7070
	—30420	—32080	—34940	—27890	—31210
ख. प्राइवेट अमेरिकी लेनदेन					
1. व्यापार	+22420	+36130	+9260	—14040	+20050

वसूली	+6730	+8640	+8510	-- . >	-- -
4. अमेरिकी सरकार के अन्य लेन देन	—5260	—5520	—4770	—7890	—7070
	—30420	—32080	—34940	—27890	—31210
ग. प्राइवेट अमेरिकी लेनदेन 1. व्यापार	+22420	+36130	+9260	—14040	+20050
2. प्राइवेट पूंजी और आय	—5730	—4990	—2290	+4010	—6100
3. अन्य सब प्राइवेट अमेरिकी लेन देन	—7680	—5570	—10840	—13650	—15320
	+9010	+25670	—3870	—23680	—1370
ग. अमेरिकी सरकार की सिक्योरिटियो को छोड़कर अन्य रूपों मे अमेरिका में लगी विदेशी पूंजी	+5300	+3610	+240	+5480	+3270
घ भूल-चूक	+6430	+7480	+3800	+7830	+9050
ङ. कुल घाटा (+अधिशेष)	—9680	+4680	—34770	—38260	—38360

1. इसमें 1959 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में अमेरिका द्वारा दी गई 13750 लाख डालर की राशि शामिल नहीं है.।

से काफी मात्रा मे सोना बाहर जाने लगा है ।

तालिका 17 मे सन् 1956 से 1960 तक के वर्षों मे अमेरिका के अदायगी सन्तुलन की स्थिति सक्षेप मे दिखायी गई है । (इन पाँच वर्षों की अदायगियो का विस्तृत ब्योरा परिशिष्ट तालिका 19 मे देखा जा सकता है) ।

ये दोनो तालिकाएँ इस ढग से बनाई गई है कि उनमे व्यापार और सामान्य प्राइवेट आर्थिक गति-विधि के फलस्वरूप होने वाली अदायगियो को सयुक्त राज्य सरकार के आर्थिक क्रियाकलापो और कार्यक्रमो के फलस्वरूप की जाने वाली अदायगियो से अलग करके दिखाया गया है । इस तरीके से यह हिसाब आसानी से लगाया जा सकता है कि हाल के वर्षो मे विभिन्न किस्मो के सरकारी और गैर-सरकारी लेन-देन मे अमेरिका को कितना बडा घाटा रहा है । यह कथन, कि अमेरिका के अदायगी सन्तुलन मे घाटा पूर्णत या मुख्यत वैदेशिक सहायता कार्यक्रमो का परिणाम है, विवाद का विषय है, क्योकि वैदेशिक सहायता से अन्य देशो मे अमेरिकी धन जाता है, बल्कि उससे अमेरिका के व्यापारिक निर्यात मे भी वृद्धि होती है । इसके अतिरिक्त सन् 1960 मे आर्थिक सहायता कार्यक्रमो के अन्तर्गत घाटा, जैसा कि तालिका 17 मे दिखाया गया है, अदायगी सन्तुलन के कुल घाटे के एक चौथाई से भी कम है ।

हाल के वर्षो मे अमेरिका से सोने की जो निकासी हुई है, उसके बावजूद, सयुक्त राज्य के सुरक्षित मुद्रा कोष इतने बडे हैं कि 1950 के दशक के प्रारम्भ मे अमेरिका के अदायगी सन्तुलन मे जो छोटा-सा घाटा हम देखते हैं, वैसे घाटे चिन्ता का कारण नही है । लेकिन 1958 से 1960 तक लगातार जो भारी घाटा दिखायी देता है, वैसा घाटा अवश्य चिन्ता का कारण है और केवल सयुक्त राज्य के लिए ही नही, उसके साथी और मित्र देशो के लिए भी, खास तौर से इसलिए कि बुनियादी कठिनाइयो के प्रभाव अक्सर अस्थायी सट्टेबाजी की गति-विधियो से बढ़ जाते है ।

केवल अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के देश की आन्तरिक स्थिति के पहलू

से देखा जाय तो लगातार इतनी बडी मात्रा मे घाटा होना इस बात का सकेत है कि आन्तरिक आर्थिक परिस्थितियो और वैदेशिक आर्थिक परिस्थितियो के बीच सन्तुलन और समन्वय बिगड गया है। इस प्रकार का असन्तुलन आम तौर पर इसलिए होता है कि देश का लागत और मूल्यो का आन्तरिक स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से मेल नही खाता। इन दोनो स्तरो मे मेल के अभाव का कारण या तो स्वल्पकालिक व्यापारिक उतार-चढाव का चक्र होता है या व्यावसायिक ढाचे मे होने वाले दीर्घकालिक परिवर्त्तन या दोनो। इनमे से जो भी कारण हो, उसको दृष्टि मे रखकर समय-समय पर आने वाले इन व्यापारिक चक्रो को रोकने की कार्रवाई करके, या उत्पादकता मे वृद्धि कर और अर्थ-व्यवस्था के ढाँचे मे परिवर्त्तन कर, या राष्ट्रीय मुद्रा की विनिमय-दर मे परिवर्त्तन कर या इसी प्रकार के अन्य कदम उठाकर तालमेल के इस अभाव का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए कब, ठीक कौन-सा कदम उठाया जाय, इसका चुनाव इस बात को दृष्टि मे रखकर किया जा सकता है कि कब कौन-सी बात आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सम्भव और व्यवहार्य है।

लेकिन कोई भी देश, खासकर अमेरिका, अदायगी सन्तुलन मे लगातार घाटा बना रहने पर केवल आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से ही चिन्तित नही होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली और उसमे सयुक्त राज्य के डालर की विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए सयुक्त राज्य इस प्रकार के असन्तुलन को रोकने के लिए जो भी कार्रवाई करेगा उसकी एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अवश्य होगी। यही कारण है कि सयुक्त राज्य एक सीमा तक ही ये कार्रवाइयाँ कर सकता है और वह भी कुछ खास किस्म की ही। इसमे जो समस्याएँ उलझी हुई हैं उनको समझने के लिए वर्त्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की मुख्य-मुख्य विशेषताओ पर सक्षेप मे विचार करना जरूरी है।

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धो के मध्यमवर्त्ती काल से अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था मे जो मुद्रा-प्रणाली रही है उसे स्वर्ण या विनिमय प्रणाली अथवा मुख्य मुद्राओ वाली प्रणाली (की करैन्सी सिस्टम) कहा जा सकता

है। इसका अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमे सब देश अपनी अदायगी सन्तुलन के आखिरी बचत या घाटे के लेन-देन का निबटारा या तो सोना ले-दे कर या ऐसी मुद्राएँ ले-देकर करते हैं जिनकी सारे ससार मे माँग होती है और जिन पर सरकारो और व्यापारियो दोनो को भरोसा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सयुक्त राज्य का डालर, और कुछ हद तक पौंड स्टर्लिंग मुख्य मुद्राएँ रही है। दूसरे देश एक-दूसरे के साथ या सयुक्त राज्य और ब्रिटेन के साथ अपने अन्तर्राष्ट्रीय हिसाब-किताब को निबटाने के लिए इन मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं और अपने सुरक्षित मुद्रा-कोषो का कुछ भाग अपने केन्द्रीय बैंको मे या न्यूयार्क और लन्दन के बैंको मे इन मुद्राओ की शक्ल मे जमा रखते हैं। इसी प्रकार संसार-भर के प्राइवेट बैंकर और व्यापारी फर्में भी, खास कर वे जो अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन करते हैं, या तो इन मुद्राओ की अपनी अवशिष्ट और अप्रयुक्त रकमो को बैंको मे जमा कर देते हैं या न्यूयार्क और लन्दन मे छोटी मियाद की सरकारी हुण्डियो मे लगा देते है।

मुख्य मुद्राओ वाली यह प्रणाली उन्नीसवी शताब्दी की स्वर्ण-मान प्रणाली का परिणाम है। स्वर्ण-मान प्रणाली उन्नीसवी शताब्दी के बाद भी काफी समय तक जारी रही, हालाकि वह कुछ कमजोर पड गई थी। लेकिन सन् 1931 मे जब ब्रिटेन ने पौंड स्टर्लिंग की सोने मे स्वत परिवर्तनीयता का परित्याग कर दिया तो वह प्रणाली खत्म हो गई। स्वर्ण-मान प्रणाली के अन्तर्गत सभी अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी सन्तुलनो का निबटारा, सिद्धान्तत, सोने मे किया जाता था और किसी भी देश के सुरक्षित मुद्रा कोष मे उसके सुरक्षित सोने की मात्रा ही गिनी जाती थी। लेकिन व्यवहार मे सब अदायगी सन्तुलनो का निबटारा मुद्राओ मे, विशेषत. पौड स्टर्लिंग मे किया जाता था, क्योंकि वह इच्छानुसार और निर्बाध रूप से सोने मे परिवर्तित किया जा सकता था।

दोनो विश्व युद्धो के मध्यवर्ती काल मे स्वर्ण-मान प्रणाली मे सशोधन दो कारणो से किया गया। पहला यह कि विश्व के व्यापार मे इतनी अधिक वृद्धि हो गई थी कि स्वर्ण-मान प्रणाली उसकी

आवश्यकताओ को पूरा नही कर सकती थी। अभिप्राय यह कि दोनों युद्धो के मध्यवर्ती काल मे विश्व का व्यापार तो बहुत अधिक बढ गया किन्तु सोने की उपलब्धि इतनी नही हुई कि उससे अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी सन्तुलन को निबटाया जा सके।

इसका दूसरा कारण और भी अधिक बुनियादी था। स्वर्ण-मान जब तक जारी रहा, तब तक सब देशो को अपने अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी सन्तुलन के निबटारे के लिए सोना देना पडता था। इसका असर यह होता था कि उनपर स्वत एक लगाम लगी रहती थी जिससे उन्हे अपनी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्थाओ को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल रखना पडता था ताकि अन्य देशो के साथ उनके लेन-देन मे असन्तुलन न हो। वे अपनी आन्तरिक आर्थिक नीतियाँ मनमाने तौर पर निर्धारित नही कर सकते थे। जिस देश के अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी सन्तुलन मे बहुत घाटा रहता था, उसे उसकी पूर्ति के लिए सोना देना पडता था। इससे उस की मुद्रा की पुश्त पर सोना कम हो जाता और फलस्वरूप वह पर्याप्त मुद्रा जारी नही कर सकता था। मुद्रा के अभाव मे व्याज-दरे बढ जाती, आन्तरिक व्यापार कम हो जाता और कीमतो और रोजगार मे भी कमी आ जाती। लेकिन आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से ये सब बाते चाहे जितनी अप्रिय हो, उनसे वैदेशिक अदायगी का असन्तुलन अवश्य ठीक हो जाता, क्योकि अन्य देशो की मुद्रा (व्याज की दर अधिक होने के कारण) उसमे खिच आती, (कीमते कम होने से) निर्यात बढ़ जाता और (आन्तरिक माँग कम हो जाने से) आयात घट जाता।

यह ठीक है कि उन्नीसवी शताब्दी मे जो स्वर्ण-मान प्रणाली प्रचलित थी उससे विदेशी व्यापार और लेन-देन के असन्तुलन का स्वतः इलाज हो जाता था किन्तु उसके लिए सम्बद्ध देश को कीमत बहुत भारी चुकानी पडती थी। उसकी आन्तरिक आर्थिक गति-विधि कम हो जाती थी और उससे बेरोजगारी बढ जाती थी। इसलिए बीसवी शताब्दी के शुरू के दशको मे ससार के अनेक बड़े लोकतन्त्रीय राष्ट्रों ने इस प्रणाली को राजनीतिक दृष्टि से अस्वीकार कर दिया। एक देश के बाद दूसरे

देश मे एक ओर पूर्ण वयस्क मताधिकार प्रणाली प्रचलित हो रही थी और दूसरी ओर साथ ही यह विचार भी दृढता से जडें जमाता जा रहा था कि जनता की आर्थिक सुरक्षा और सामान्य कल्याण का स्तर काफी ऊँचा उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा सन् 1914 के वाद दो विश्व युद्धो और उनके मध्यवर्ती काल मे आई भारी मन्दी ने सब देशो की सरकारो पर इस वात की जिम्मेदारी वढा दी कि वे अपने वित्तीय साधनो को सगठित करे और खास-खास राष्ट्रीय प्रयोजनो के लिए उनका वंटवारा करे। इस प्रकार राष्ट्रीय सरकारो के लिए धीरे-धीरे यह असम्भव हो गया कि वे अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ताकतो के प्रभाव और स्वर्ण-मान के कठोर नियन्त्रण की कैद मे रखते हुए अपने देश के रोजगार के स्तर, राष्ट्रीय आय के वितरण और रहन-सहन के स्तर को एक सीमा के भीतर ही बनाये रखे। इसलिए सबसे पहला वडा परिवर्तन इस मान्यता को अपना कर किया गया कि केवल सोना-चाँदी आदि कोई ठोस वस्तु ही किसी देश की मुद्रा का आधार नही होनी चाहिए। परिणाम यह हुआ कि एक के वाद एक अधिकाधिक देश अपनी मुद्रा को प्रात्यधिक आधार (फिड्यूशियरी वेसिस) पर प्रचलित करने लगे। इसका अभिप्राय यह कि मुद्रा जारी करने के लिए सोना या चाँदी को उसकी पुश्त पर रखना जरूरी न मान कर सरकारे अन्य रूपो मे अपनी साख (प्रत्यय) के आधार पर मुद्रा का प्रचलन करने लग गई। इससे वे मुद्रा और उधार के परिमाण, व्याज की दर और सरकार के व्यय के स्तर पर अधिक नियन्त्रण करने की स्थिति मे आ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि आन्तरिक कठिनाइयो को दूर करने के लिए स्वर्ण-मान प्रणाली के कठोर प्रतिबन्धो के बजाय सामाजिक दृष्टि से अधिक स्वीकरणीय तरीके अपनाना सम्भव हो गया।

दोनो विश्व युद्धों के मध्यवर्ती काल मे मुख्य मुद्राओ के द्वारा विनिमय की जो प्रणाली अपनाई गई वह वास्तव मे आन्तरिक क्षेत्र मे अपनाई गई प्रत्यय मुद्रा प्रणाली (फिड्यूशियरी मॉनीटरी मैकेनिज्म) का ही अन्तर्राष्ट्रीय रूप थी। इससे अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी सन्तुलनो के

निवटारे के लिए सोने का सहारा लेने के वजाय, जिसकी उपलब्धि पर्याप्त नही थी, डालर और पौड स्टर्लिंग के द्वारा उनका निवटारा करने की अधिक सरल और सुविधाजनक व्यवस्था मिल गई, राष्ट्रो के सुरक्षित मुद्रा कोषो मे केवल सोना रखने के वजाय डालर और पौड स्टर्लिंग जमा करने की आसानी हो गई और राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय हिसाब-किताव के असन्तुलन को दूर करने के लिए अधिक लचकीली विधियाँ उपलब्ध हो गई। लेकिन उन दो देशो (ब्रिटेन और संयुक्त राज्य) के लिए कुछ समस्याएँ भी उठ खडी हुई, जिनकी मुद्राओ का सहारा इसके लिए लिया जाने लगा।

ऐसे मौके वहुत कम रह गए जव कि इन दोनो मुख्य मुद्राओ की उपलब्धि और मांग मे उचित सन्तुलन रहता हो। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल वाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि प्राय. सभी देशो की डालर की मांग बेहद वढ गई और यह मांग इतनी वढी कि ये देश न अपने वैदेशिक व्यापार से हुई कमाई से, न अपने निजके सुरक्षित मुद्रा कोष से और न सरकारी या गैर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो से ऋण लेकर उसकी पूर्ति कर सकते थे। ऐसी स्थिति मे सयुक्त राज्य सरकार के वैदेशिक सहायता अनुदानो और ऋणो ने इन देशो की, खासकर पश्चिमी यूरोप के देशो की, डालर की इस कमी को दूर करने और उनके आयात के स्तर को बनाये रखने मे काफी सहायता दी।

लन्दन के सोने के बाजार मे उसका भाव 35 डालर प्रति औंस के अधिकृत भाव से (जिस पर सयुक्त राज्य का कोष विभाग अन्य देशो की सरकारो के माँग करने पर चाहे जितने डालरो के बदले मे सोना दे देता है) ऊँचा चला जाता है। उदाहरण के लिए अक्तूबर, 1960 मे जब सयुक्त राज्य के अदायगी सन्तुलन मे बहुत बडा घाटा हो गया तो डालर का मन्दी का सट्टा होने लगा और व्यापारियो और बैंको को अपने पास जमा डालरो की भारी मात्रा की सुरक्षा के बारे मे आशकाएँ होने लगी जिससे उनमे डालरो को सोने मे बदलवाने की खलबली मच गई और बाजार मे सोने का भाव 40 डालर प्रति औंस तक पहुँच गया। इस खलबली के कारण यूरोप के अनेक केन्द्रीय बैंक सयुक्त राज्य के कोष विभाग से अपने डालरो को सोने मे बदलवा कर अपने डालर कोष कम करने लगे। इससे सयुक्त राज्य से बहुत-सा सोना बाहर चला गया।

पौंड स्टर्लिंग को, जो दूसरे दर्जे की मुख्य मुद्रा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी कठिनाइयो का अनेक बार सामना करना पडा, क्योंकि ब्रिटेन के अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी सन्तुलन मे बार-बार घाटा आता रहा। ऐसे मौको पर अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो, अन्य देशो की सरकारो और उनके केन्द्रीय बैंको को बैंक ऑफ इग्लैण्ड को सकटकालीन सहायता देनी पडी ताकि वह स्टर्लिंग को अन्य मुद्राओ मे परिणत करने के लिए की जाने वाली माँगो को पूरा कर सके।

इस प्रकार युद्धोत्तर काल का अनुभव यह रहा है कि ये मुख्य मुद्राएँ कभी तो बेहद कम हो गई और कभी बहुत ज्यादा, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के निर्विघ्न चलने मे काफी बाधा आई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, जिसकी सर्वप्रथम कल्पना 1944 मे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन मे की गई थी, इस मुख्य-मुद्रा प्रणाली की खामियो को दूर करने का साधन मानी जाती है। इस निधि के अन्य कामो मे से एक काम यह है कि वह उन देशो को डालर दे, जिनके पास अपनी अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियो को पूरा करने के लिए उसकी पर्याप्त मात्रा नही है। वह कुछ खास परिस्थितियो मे सोना भी उन देशो को दे सकती

है। यदि ब्रिटेन और सयुक्त राज्य पर स्टर्लिग और डालर को सोने या अन्य मुद्राओ मे परिवर्त्तित करने की माँग का इतना अधिक दबाव पडे कि वे कठिनाई मे पड जाएँ तो यह निधि उनकी भी सहायता कर सकती है। लेकिन 1959-60 मे सयुक्त राज्य से बहुत बडी मात्रा मे और काफी अधिक समय तक सोना बाहर जाने पर भी सयुक्त राज्य सरकार ने उससे कोई सहायता नही माँगी। इसके मुकाबले मे ब्रिटेन ने युद्धोत्तर काल के स्टर्लिग पर बार-बार सकट आने पर निधि से काफी सहायता ली। निधि इन कार्यों को पूरी तरह से निभा सके, इसके लिए हाल के वर्षो मे अनेक बार उसके मुद्रा कोष मे वृद्धि करनी पडी। अभी हाल मे 1961 मे भी उस निधि के मुद्रा कोष को बढ़ाने की जरूरत पडी, जब कि डालर और स्टर्लिग पर सटोरियो का दबाव पडने के कारण मुख्य मुद्राओ वाले देशो की सहायता के लिए पूरक ऋणो की व्यवस्था की गई।

यद्यपि अधिकतर राष्ट्रो की सरकारे और उनके केन्द्रीय और प्राइवेट बैंक मौजूदा मुख्य-मुद्रा प्रणाली को पसन्द करते है तो भी पिछले कुछ वर्षो मे इस प्रणाली की दो प्रकार की आलोचनाएँ की जाती रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक व्यवसायियो के अधिक अनुदार वर्ग का कहना है कि इस प्रणाली के परिणामस्वरूप राष्ट्रो को अपने वैदेशिक अदायगी सन्तुलन को ठीक करने के लिए अपनी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियो मे परिवर्त्तन की वहुत अधिक छूट मिल जाती है। दरअसल, यह वर्ग चाहता है कि स्वर्णमान प्रणाली फिर से लागू कर दी जाय ताकि उससे सब देश स्वत नियन्त्रण मे रहे और जब भी किसी देश को काफी समय तक और काफी बडे अदायगी असन्तुलन का सामना करना पडे तो वह मजबूरन अपनी अर्थ-व्यवस्था को सकुचित कर दे।

मुख्य-मुद्रा प्रणाली की आलोचना करने वाले दूसरे वर्ग का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से पूरक सहायता मिलने पर भी अदायगी के लिए नकदी की समस्याएँ अन्तत अनिवार्य हैं। इस वर्ग का कथन है कि सोने का उत्पादन विश्व के व्यापार की तुलना मे मन्द गति से

बढा है और आगे भी मन्द गति से ही बढेगा। इसलिए मुख्य मुद्राओं को और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा दी जाने वाली पूरक सहायता को अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी सन्तुलन मे अधिकाधिक हिस्सा लेना पड़ेगा और इन दोनो मे से कोई भी वह सहायता पर्याप्त रूप मे नही दे सकता, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जरूरतो को पूरा कर सके। इसके अलावा इन आलोचको को यह भय भी है कि इन मुद्राओ पर शायद बहुत गम्भीर सकट आये और उन पर से लोगों का विश्वास उठने की और भी अधिक गम्भीर घटनाएँ घटे। उस दशा मे इन दोनो देशो के सुरक्षित मुद्रा कोपो पर इतना दवाव पड सकता है कि वह सभाले न सभले।

इसके साथ ही यह सम्भावना भी है कि यदि इन दोनो देशो के सामने डालर और स्टर्लिंग पर लोगो का विश्वास बनाये रखने की सभावना बहुत गम्भीर रूप धारण करके आये तो उनके लिए अपनी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्थाओ को सुधारने के बहुत कम उपाय रह जाएँ और उन्ही थोडे-से उपायो मे से कुछ को उन्हे चुनना पडे और उसका परिणाम उनके लिए अच्छा न हो। ब्रिटेन के बारे मे यह बात सही सिद्ध भी हो चुकी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी आर्थिक अभिवृद्धि की मन्द गति का कारण कुछ अश तक यह था कि उसे समय-समय पर आन्तरिक पूँजी-निवेश को सीमित करना पडा और उपभोक्ताओ की माँग पर भी अकुश लगाना पडा ताकि स्टर्लिंग मे लोगो का विश्वास बनाये रखने के लिए वह अपने निर्यात को बढा और आयात को घटा सके। दोनो विश्व युद्धो के मध्यवर्ती काल मे भी ब्रिटिश लोग स्टर्लिंग को एक मुख्य मुद्रा बनाये रखने के लिए काफी बडी बेरोजगारी और जीवन-स्तर की अभिवृद्धि के अभाव के रूप मे उसकी कीमत चुकाने को तैयार थे। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वे इसके लिए राजी नही हुए और उन्होने अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की, कोशिश की जिसका नतीजा यह हुआ कि बीच-बीच मे स्टर्लिंग मुद्रा कमजोर होती रही। जहाँ तक अमेरिकी लोगो का

सम्बन्ध है, अगर उन्हे डालर को एक मुख्य मुद्रा बनाये रखने के लिए अपनी अर्थ-व्यवस्था और अपने जीवन-स्तर की अभिवृद्धि को रोकना पडे तो वे उसके लिए ब्रिटिश लोगो से भी कम राजी होंगे। लेकिन अगर उसका अर्थ देश के भीतर मुद्रा-सकोच और वेरोजगारी मे वृद्धि हो तो वे उसके लिए और भी कम राजी होगे, क्योकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे डालर की साख को बचाने के लिए इन उपायो से भी अधिक महत्त्वपूर्ण और सामाजिक दृष्टि से स्वीकरणीय उपाय मौजूद है (उदाहरण के लिए, उत्पादकता मे और निर्यात उद्योगो की कार्यकुशलता मे वृद्धि)।

इसलिए मुख्य-मुद्रा-प्रणाली के बजाय किसी अन्य ऐसी प्रणाली को अपनाने के लिए, जिसमे ये खतरे और नुक्सान कम हो या बिलकुल न हो, अनेक सुझाव दिये गए है। इनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राबर्ट ट्रिफिन का यह सुझाव है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षित मुद्रा प्रणाली स्थापित की जाये। मोटे तौर पर श्री ट्रिफिन का सुझाव यह है कि एक नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जारी की जाय और अन्तर्राष्ट्रीय अदायगियो के साधन के रूप मे डालर और स्टर्लिंग की जगह उसका उपयोग किया जाय और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी के लिए सब राष्ट्र डालर या स्वर्ण के सुरक्षित कोष बनाने के बजाय इस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के सुरक्षित कोष बनाये। यह नई मुद्रा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, और सम्भव हो तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इण्टरनेशनल मॉनीटरी फण्ड) द्वारा सचालित की जाय। यह सम्भव है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के परिचालन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक मे परिणत कर दिया जाय, और उसे यह अधिकार दे दिया जाय कि जब जैसी आवश्यकता हो, वह इस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की सप्लाई बढा या घटा सके। दूसरी सम्भावना यह व्यक्त की जाती है कि जो भी नई व्यवस्था हो वहाँ सब देशो पर स्वत कुछ ऐसा दबाव डाल सके कि उन्हे एक उचित सीमा तक अपनी वैदेशिक अदायगियों को सन्तुलित रखना होगा और मुद्रा-स्फीति के सम्भावित प्रभावो को

सीमित करना होगा। यह स्वत पडने वाला दवाव कुछ वैसा ही होगा, जैसा कि स्वर्णमान से पडता था।

यूरोपीय साझा वाजार के देश एक यूरोपीय सुरक्षित मुद्रा कोष प्रणाली स्थापित करने का विचार कर भी रहे थे। उनका उद्देश्य इस प्रणाली को अन्तत इस यूरोपीय वाज़ार की एक सर्वमान्य मुद्रा वनाना था। यदि ऐसी प्रणाली स्थापित हो जाय और ब्रिटेन भी उसका सदस्य वन जाय तो मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की अनेक खामियाँ इससे दूर हो जाएँगी। साथ ही इससे सयुक्त राज्य को भी इस यूरोपीय प्रणाली मे शामिल होने और इस प्रकार उसे अटलाटिक के उस पार तक विस्तृत करने को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि यह यूरोपीय मुद्रा प्रणाली और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि दोनो का विलय हो जाय और यूरोप की इस नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को ट्रिफिन के प्रस्ताव के अनुसार मारे विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप मे मान्यता मिल जाय।

मौजूदा मुख्य-मुद्रा प्रणाली की कठिनाइयो को चाहे किसी भी उपाय से दूर किया जाय, उसका परिणाम यह होगा कि सयुक्त राज्य की अदायगी सन्तुलन की स्थिति पर दवाव कम हो जायेगा। लेकिन इससे सयुक्त राज्य अपनी विदेशी अदायगियो को उचित रूप से सन्तुलित रखने की जिम्मेदारी से पूर्णत' मुक्त नही होगा, हालाकि इस सन्तुलन को कायम रखने की कार्यवाहियो के लिए उसे अधिक समय लगेगा और साथ ही उसके लिए सम्भावित कार्यवाहियो मे से चुनाव की गुजायश भी अधिक रहेगी। उदाहरण के लिए, यह मुमकिन है कि वह अपनी मुद्रा को सीमित करने या आयात मे कमी करने के उपायो को आजमाने के वजाय उत्पादकता और निर्यात को बढाने के उपायो का सहारा ले, जिनमे अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। उपयुक्त परिस्थितियो मे वह डालर की विनिमय दर मे परिवर्त्तन करने के प्रश्न पर भी विचार कर सकती है। हालाकि फिलहाल उसकी कोई सम्भावना नही है, क्योकि अन्य देशो के पास काफी डालर जमा हो गए है और सयुक्त

राज्य पर यह नैतिक ज़िम्मेदारी है, और व्यावहारिक दृष्टि से भी यह सही है, कि वह अन्य देशो की सरकारो या लोगो के पास जमा इन डालरो के मूल्य को कायम रखे। सयुक्त राज्य की सरकार के लिए हर हालत मे ऐसी नीतियो या कार्यक्रमो को अपनाना जरूरी होगा जिनसे लोकतन्त्रीय मूल्यो की रक्षा करते हुए वह अपने निर्यात को इतने ऊँचे स्तर पर रख सके कि विश्व की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के कारण अपनाये जाने वाले वैदेशिक कार्यक्रम सन्तुलित रहे।

संयुक्त राज्य की विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

सयुक्त राज्य के सामने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था मे आने वाली कठिनाइयो का जो विवरण हमने अभी प्रस्तुत किया है, वह यह सूचित करता है कि विश्व की ऐसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था क़ायम करने के लिए, जो सभी स्वतन्त्र देशो की रक्षा और प्रगति के अनुकुल हो बहुत कुछ करना अभी बाकी हैं। इस कार्य मे अमेरिकी लोगो की एक विशेष जिम्मेदारी है, क्योकि उनके पास ताकत है, दौलत है और साथ ही काम करने की स्वतन्त्रता भी अधिक है। इस कार्य का आर्थिक पहलू यह है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण कर दिया जाय ताकि सयुक्त राज्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी-निवेश को ऊँचे स्तर पर रख सके। यह काम सन् 1914 से पहले के जमाने को पुन. लाने की कोशिश करके नही किया जा सकता। यह काम केवल ऐसे साधनो से ही किया जा सकता है जो वर्तमान वास्तविकताओ और भविष्य की आवश्यकताओ को स्वीकार करे और ससार-भर मे बदल रहे मूल्यो और आशाओ को काफी ध्यान मे रखे।

द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अमेरिका ने पृथक्ता, अर्थात् अपने आपको शेष संसार की उलझनो से अलग रखने, की जो नीति अपना रखी थी, उससे तुलना करके जब हम देखते है तो मालूम होता है कि उसने अपनी वैदेशिक नीति को बीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध की नई परिस्थितियो के

साथ बहुत तेज गति से और काफी दूर तक ढाल लिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इन परिवर्तनो से युग की आवश्यकताओ की पर्याप्त पूर्ति हो जाती है। अमेरिका के लोगो मे अब भी राष्ट्रीयता और प्रभु-सत्ता की पुरानी परम्परागत धारणाओ के नुक्ते-निगाह से सोचने की प्रवृत्ति है। यद्यपि वे यह स्वीकार करते है कि अन्य देशो का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, साझेदारी और पारस्परिक प्रभु-सत्ता के आशिक त्याग के नये दृष्टिकोणो से सोचना उनके अपने लिए सगत हो सकता है, लेकिन, जहाँ तक अमेरिकी लोगो की जिम्मेदारियो और आवश्यकताओ का ताल्लुक है, वे इन नई सृजनात्मक धारणाओ को उनके साथ पूर्णत जोडने के लिए तैयार नही है। अमेरिकी लोगो मे एक प्रवृत्ति यह भी है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयो के हल मे देरी होती है तो वे अधीर हो जाते है। वे आमतौर पर यह समझ ही नही पाते कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ को हल करना राष्ट्रीय समस्याओ के समाधान मे कही अधिक कठिन होता है, खासकर तब जब कि कोई देश केवल लोकतन्त्रीय उपायो और पद्धतियो को ही अपनाने के लिए कृत-सकल्प हो। इसके अलावा अमेरिकी लोग आम तौर पर यह समझने की गलती भी कर देते है कि सोवियत् रूस और चीन के कम्युनिस्टो की साम्राज्यवादी महत्त्वाकाक्षाएँ ही विश्व की आधुनिक समस्याओ का एकमात्र कारण है। यह ठीक है कि रूस और कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण और आन्तरिक षडयन्त्रो का खतरा बहुत बडा है और वह निरन्तर बढ भी रहा है, लेकिन अगर किसी चमत्कार से इस खतरे का किसी तरह अन्त हो जाय तो भी ससार मे कठिन और गहरी जडो वाली अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ बाकी रह जाएँगी, भले ही उनका हल करने के लिए उतनी त्वरित गति से प्रयत्न न किया जाय। वास्तव मे कम्युनिज्म का खतरा बहुत हद तक विश्व की आबादी, आशाओ और क्षमताओ मे हुए अधिक बुनियादी परिवर्तनो का परिणाम है, उनका कारण नही है। ये परिवर्तन और रुझान कम्युनिज्म के पनपने के लिए अवसर पैदा करते है और इन अवसरो के फलस्वरूप पनप कर कम्युनिज्म इन समस्याओ को और भी गम्भीर बना देता है।

अमेरिकी लोग मौजूदा आर्थिक प्रणाली के स्वरूप को, और इन खतरो के खिलाफ चौकसी और इन समस्याओ के हल के लिए आवश्यक कार्रवाइयो को, पहले से अधिक अच्छी तरह समझने लगे है। और जैसे-जैसे उनकी यह अनुभूति और समझ-बूझ बढती जायेगी, वैसे-वैसे आवश्यक नीतियो को अपनाने और उन्हे अधिक सक्षमता और जोश के साथ क्रियान्वित करने की उनकी इच्छा और योग्यता भी बढती जाएगी। किन्तु ये परिवर्तन चाहे कितने भी महत्त्वपूर्ण क्यो न हो, केवल उन्ही के आधार पर यह नही कहा जा सकता कि आगामी वर्षो मे अमेरिका की वैदेशिक नीतियाँ भविष्य की आवश्यकताओ को पूरा कर सकेगी। सयुक्त राज्य के लोगो को यह भी महसूस करना चाहिए कि अपने वैदेशिक व्यापार और पूँजी-निवेश से, अपनी वैदेशिक सहायता के विस्तार से और अपनी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिति मे सुधार से उन्हे भी अन्तत लाभ पहुँचेगा। यह लाभ जिस हद तक मौजूद है और जिस हद तक अमेरिकी लोग उसके महत्त्व को समझेगे, सम्भवत उसी हद तक वे अपनी अर्थ-व्यवस्था का अपने साथी और मित्र देशो की अर्थ-व्यवस्था के साथ एकीकरण करने का प्रयत्न करेगे।

वास्तव मे अमेरिका की वैदेशिक नीति के ठीक ढग से विकसित होने मे एक बडी कठिनाई यह रही है कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के ठीक ढग से चलने की उतनी चिन्ता नही की जितनी कि अमेरिकी समाज के कुछ मुख्य गुटो के तात्कालिक और प्रत्यक्ष स्वार्थो की पूर्त्ति की चिन्ता की। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस कठिनाई का एक कारण अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के साथ एकतरफा सम्बन्ध था। अमेरिका को अन्य देशो के साथ व्यापार करने या उनमे पूंजी लगा कर कमाई करने की उतनी जरूरत नही है, जितनी कि शेष ससार को अमेरिका के साथ व्यापार करने और उससे अपने यहाँ पूंजी लगवाने की है। कुछ हद तक इसका कारण सयुक्त राज्य और उसके साथी मित्र देशों के राजनीतिक और सामरिक सम्बन्ध भी है। प्रथम विश्व के बाद शेष संसार की शान्ति और तानाशाही देशो के आक्रमण

आन्तरिक षडयन्त्रो से उसकी रक्षा मुख्यत सयुक्त राज्य की आर्थिक और सैनिक शक्ति पर निर्भर रही है। लेकिन सयुक्त राज्य की अपनी शान्ति और सुरक्षा अपने साथी और मित्र देशो की आर्थिक और सैनिक शक्ति पर उतनी निर्भर नही रही।

सयुक्त राज्य की वैदेशिक नीतियो मे जिन परिवर्त्तनो की आवश्यकता है, वे अपने आप मे चाहे कितने ही कठिन हो, आगामी वर्षो मे जैसे-जैसे अमेरिकी लोगो को यह महसूस होता जाएगा कि उनकी अपनी सफलता के लिए वे आवश्यक हे, वैसे-वैसे उन्हे क्रियान्वित करना अधिकाधिक आसान होता जाएगा। आज भी सयुक्त राज्य राजनीतिक और आर्थिक दृष्टियो से शेष ससार पर पहले की अपेक्षा अधिक निर्भर है, और 1960 के दशक मे उसकी यह निर्भरता और भी बढती जाएगी। एक ओर अमेरिका के प्राकृतिक साधन-सम्पदा के स्रोत क्रमश क्षीण होते जा रहे है, अमेरिकी लोगो का रहन-सहन का स्तर ऊँचा होता जा रहा है, और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन क्षमता और उत्पादकता मे निरन्तर वृद्धि होती जा रही है, और दूसरी ओर यूरोपीय साझा बाज़ार और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय गुट अधिकाधिक तरक्की करते जा रहे है—इन दोनो बातो को देखते हुए अमेरिकी जनता विदेशी व्यापार और विदेशो मे पूँजी-निवेश के महत्त्व को अधिकाधिक महसूस करने लगेगी। कम्युनिस्ट देशो की शक्ति मे वृद्धि और एशिया और अफ्रीका के गैर-कम्युनिस्ट देशो की स्वतन्त्र रूप से काम करने की आज़ादी और क्षमता का परिणाम यह होगा कि सयुक्त राज्य पश्चिमी यूरोप और लैटिन अमेरिका के अपने साथी और मित्र देशो पर राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से अधिक निर्भर हो जाएगा। इन बुनियादी रुझानो के कारण सयुक्त राज्य की जनता और सरकार के लिए उन नीतियो और कार्यक्रमो को अपनाना, जो एक बेहतर राजनीतिक और आर्थिक विश्व प्रणाली के निर्माण मे अधिक प्रभावकारी ढग से योग दे सकते है, उतना कठिन नही रहेगा।

सयुक्त राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के इतने कठिन सभावित परिणामो का सामना इससे पहले कभी नही करना पडा जितने

कठिन परिणामो का सामना आज करना पड़ रहा है। उसने अपनी निज की समस्याओ के हल के लिए नही, बल्कि अधिकतर अपने साथी और मित्र देशों की समस्याओ के हल के लिए ही उनके साथ प्रभावकारी सहयोग किया है। लेकिन यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मे अमेरिका का अपना भी बहुत हित है। सयुक्त राज्य की व्यापारिक बाधाओ को कम करने, सयुक्त राज्य के निर्यात को बढाने और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-व्यवस्था को सुधारने मे जो कठिनाइयाँ है, उन्हे अमेरिका अकेला दूर नही कर सकता। जैसे-जैसे अमेरिका की जनता और काग्रेस इस बात को अधिक महसूस करने लगेगे वैसे-वैसे सयुक्त राज्य उन सस्थात्मक व्यवसायों मे, जिनका प्रयोजन अटलांटिक राष्ट्रो को अपनी सर्वसामान्य समस्याओ के हल और सर्वसामान्य बाह्य खतरो से रक्षा के लिए परस्पर घनिष्ठता से सगठित करना है, हिस्सा लेने के लिए अधिक तैयार और सक्षम होता जाएगा। इसी तरह संयुक्त राज्य उन अधिक व्यापक किन्तु अपेक्षाकृत शिथिल सगठनो मे भी शामिल हो सकता है, जो सभी विकसित और विकासोन्मुख देशो की सर्वसामान्य कठिनाइयो के हल के लिए बनाये जाएँगे। इन आशापूर्ण और रचनात्मक रुझानो से अन्तत. सयुक्त राज्य अपने उन उत्तरदायित्वो को, अधिक प्रेरणाप्रद और ओजस्वी ढग से पूरा कर सकेगा, जो एक नये और बेहतर ससार को बनाने के लिए जरूरी है—एक ऐसे संसार को, जिसमे सभी लोग एक दिन अधिक सुनिश्चित और सुरक्षित स्वतन्त्रता और अधिकाधिक सुख और क्षेम का उपभोग कर सकेगे।

13

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था : स्वरूप और भविष्य

हमने अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की अनेक पहलुओ से समीक्षा की है। हमने उसकी असाधारण सफलताओं की ओर संकेत किया है और साथ ही उसकी खामियो और अनसुलझी समस्याओ की भी चर्चा की है। शायद उसकी सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि सजग आलोचना ने, जो लोकतन्त्र मे खूब फलती-फूलती है, अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की खामियो और समस्याओ के अध्ययन और उनके रचनात्मक समाधानो और सुधार की अनवरत खोज को प्रोत्साहन दिया है।

अमेरिका की आज की आर्थिक और सामाजिक प्रणाली मे अनेक परिवर्तन हुए हैं। उसका आज का रूप 25 या 50 वर्ष पहले के रूप से बहुत भिन्न है। किन्तु उसका वर्तमान उन देशों की भाँति, जिनमे सामाजिक क्रान्तियाँ हुई, अतीत से बिलकुल विच्छिन्न नहीं हुआ। सयुक्त राज्य मे अतीत से विरासत मे मिली संस्थाओ को नये कामो के अनुकूल ढाल लिया गया है। यहाँ जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था उभर रही है उससे वे लोग चक्कर मे पड जाते है जो पूंजीवाद या समाजवाद जैसे पुराने परम्परागत नामो से उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था बन्धन-हीन पूंजीवाद अथवा समाजवाद के 'विशुद्ध' नियमो के अनुसार नही चलती। फिर भी वह इन दोनो मे से किसी भी व्यवस्था से अधिक प्रभावकारी रूप मे चल रही है।

इन अन्तिम पृष्ठो मे हम अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप को संक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत करने का यत्न करेंगे। एक तरह से यह एक असम्भव कार्य है, क्योंकि अमेरिकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है

कि यह कोई स्थिर और जड वस्तु नही है, बल्कि एक सजीव और चेतन वस्तु है, जो बहुत-सी, और कुछ अश तक परस्पर-विरोधी, प्रेरणाओं से प्रभावित होती रहती है। किन्तु अतीत मे उसकी जो प्रधान विशेषताएँ रही है, उन पर दृष्टिपात करके इस बात का कुछ अन्दाज लगाया जा सकता है कि भविष्य मे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के किस दिशा मे जाने की सम्भावना है।

अमेरिकी व्यक्तिवाद और शासन का कर्त्तव्य

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का सबसे बुनियादी तथ्य शायद यह है कि दूकानो और कारखानो, दफ्तरो और प्रयोगशालाओ, घरो और फार्मों मे काम करने वाले लोग यह महसूस करते है कि व्यक्तिगत तौर पर वे अमेरिकी प्रणाली के अविच्छिन्न अग है। न व्यवसाय प्रबन्धक, न कर्म-चारी और न ही सरकारी अधिकारी इस प्रणाली के एकमात्र प्रेरक या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अग समझे जाते है। हरेक का अपना-अपना अलग काम है और वह उसे पूरा करता है। उसके काम को दूसरा कोई पूरा नही कर सकता और न वह काम उस पर ऊपर की किसी अधिकारी सत्ता द्वारा उसपर थोपा जाता है। बल्कि वह स्वय उभरता और शक्ल अख्तियार करता है, उसकी आलोचना हो सकती है और उसमे परिवर्त्तन भी किया जा सकता है।

अमेरिकी लोग अपना काम-धन्धा करते हुए या अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हुए अपने और अपने परिवार के सुख के लिए प्रयत्न करते है। किन्तु उन्हे यह विश्वास है कि अपनी उन्नति के लिए उद्योग करते हुए वे अपने समाज के सर्वसामान्य हित और ध्येय को भी पूरा करते है। कभी-कभी हरेक का अपना हित अलग-अलग होने के कारण उनमे परस्पर-विरोध भी होता है, परन्तु वह 'वर्ग-सघर्ष' जैसी किसी चीज मे परिणत नही होता। इसके विपरीत ये विरोध या सघर्ष न्यूनाधिक प्रभावकारी ढंग से या तो आपसी वार्त्ता द्वारा, जैसा कि मजदूर सम्बन्धो मे होता है, प्रत्यक्ष रीति से निबट जाते है या राष्ट्र के

जीवन के द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से हल हो जाते हैं। यह इसलिए सम्भव है क्योकि अमेरिकी प्रणाली ऐसे गहरे बन्धनो पर आधारित है जिन्होंने परस्पर-विरोधी हितो और आकांक्षाओ को आपस मे बाँध रखा है। यद्यपि इन बन्धनो को बिलकुल स्पष्ट करना आसान नही है तो भी अमेरिकी लोकतन्त्र का सार यही है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की जिस विशिष्टता को समझना और हृदयगम करना सबसे कठिन है, वह यह है कि उसमे जहाँ एक ओर व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उपक्रम की रक्षा की जाती है, वहाँ सगठनात्मक प्रबन्ध भी ऊँचे दर्जे का है। ऊपर से देखने पर जिन उद्देश्यो और अभिवृत्तियो मे बुनियादी तौर पर विरोध नजर आता है, वही अमेरिकी जीवन-पद्धति मे परस्पर समन्वित हो जाती हैं। यद्यपि पिछले सौ वर्षों मे औद्योगिक विकास खूब हुआ है और बडे-बडे नगर बन गए है तब भी पुराने युग की साहसिकता और नये-नये क्षेत्रो की खोज के लिए आगे बढ़ने की वृत्ति कुछ-न-कुछ आज भी बाकी है। यह वृत्ति व्यक्ति मे स्वावलम्बन की भावना पैदा करती है और साथ ही आवश्यकता पडने पर सहकारी प्रयत्न मे शामिल होने के लिए भी उसे तैयार करती है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे आज भी इन दोनो वृत्तियो का रचनात्मक स्थान है। बडे से बडे कारखाने मे भी श्रमिक कर्मचारी केवल एक सख्या मात्र नही होता, मि० स्मिथ या मि० जोन्स के रूप मे और बहुत सम्भव है बिल या बॉब के आत्मीयतापूर्ण नामो के रूप मे उसकी एक पृथक् व्यक्तिगत सत्ता बनी रहती है। यह मात्र एक शिष्टाचार नही है। बल्कि यह व्यक्ति के प्रति एक स्थायी सम्मान या समादर को प्रकट करता है, और कुछ हद तक व्यक्ति का यह सम्मान ही अमेरिकी श्रमिको की उत्पादकता के ऊँचे स्तर का कारण है।

अब तक हमने जो कुछ विवेचन किया है, उसमे इस बात पर बल दिया है कि अमेरिकी प्रणाली मे कठिनाइयो और समस्याओ का समाधान किन्ही कट्टर सिद्धान्तो से नही बल्कि परीक्षण और गलतियो से प्राप्त अनुभव से सम्बद्ध तथ्यो और वास्तविक विकल्पो को दृष्टि मे रख

कर किया जाता है। इसका एक उदाहरण सरकारी और प्राइवेट उत्तरदायित्वो के बीच की विभाजिक रेखा का लचकीलापन है। जो विदेशी आगन्तुक अमेरिका के स्वतन्त्र व्यवसाय और उद्यम की सफलताओ को देखकर चकित रह जाते है, वे अक्सर इस बात पर भी बहुत आश्चर्य करते है कि यहाँ सरकार भी कृषि, आवास, सामाजिक सुरक्षा या आर्थिक व्यवस्था के विकास और स्थिरीकरण मे बहुत महत्त्वपूर्ण भाग अदा करती है। अमेरिकी लोगो मे इस बात को लेकर बहुत विवाद चलता रहता है कि सरकार का असली काम क्या है, किन्तु इस बुनियादी सिद्धान्त पर मतभेद आपको शायद ही नजर आयेगा कि एक स्वतन्त्र उद्यम प्रणाली मे व्यक्ति पर यथासम्भव अधिकतम भरोसा किया जाना चाहिए, परन्तु सामान्य जन-कल्याण की खातिर जब और जहाँ आवश्यक हो, सरकार को भी प्रभावकारी कार्रवाई करनी चाहिए।

कुछ देशो मे 'राज्य' को जनता से और राष्ट्रीय समाज की अन्य सस्थाओ से पृथक् और ऊँचा समझा जाता है। वह एक ऐसी ऊँची सत्ता माना जाता है, जिसके अपने अलग हित और उद्देश्य है जिन्हे और सब हितो और उद्देश्यो से पहले स्थान दिया जाता है। इन देशों मे सरकार इस सर्वोपरि राज्य का दृश्यमान पार्थिव रूप होती है और इसलिए वह राज्य की सत्ता और विशेषाधिकारों का उपभोग करती है और जनता उसकी आज्ञाओं का पालन करती है। परन्तु अमेरिकी जीवन ऐसी धारणाओ और मनोवृत्तियों से बिलकुल मुक्त है। अमेरिकी लोग केवल 'सरकार' की ही बात सोचते और करते हैं, वे 'राज्य' की बात नही सोचते या करते। और 'सरकार' को वे उस महिमा-मडित रूप में नहीं देखते, जिस रूप में कुछ देशो में 'राज्य' को देखा जाता है। यहाँ सरकार केवल समाज की एक सस्था मात्र है। इसके अलावा उसे आमतौर पर जनता का सेवक समझा जाता है। कानून और परम्परा ने उसकी सत्ता और विशेषाधिकार सीमित कर दिये हैं और उसकी नीतियाँ और क्रियाकलाप स्वयं सरकार के स्वतन्त्र समझे जाने वाले हितो से नही, बल्कि बहुत हद तक विभिन्न समूहों के परस्पर-प्रतिस्पर्धी हितों से

जीवन के द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से हल हो जाते हैं। यह इसलिए सम्भव है क्योकि अमेरिकी प्रणाली ऐसे गहरे बन्धनो पर आधारित है जिन्होंने परस्पर-विरोधी हितो और आकाक्षाओ को आपस मे बाँध रखा है। यद्यपि इन बन्धनो को बिलकुल स्पष्ट करना आसान नही है तो भी अमेरिकी लोकतन्त्र का सार यही है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की जिस विशिष्टता को समझना और हृदयगम करना सबसे कठिन है, वह यह है कि उसमे जहाँ एक ओर व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उपक्रम की रक्षा की जाती है, वहाँ सगठनात्मक प्रबन्ध भी ऊँचे दर्जे का है। ऊपर से देखने पर जिन उद्देश्यो और अभिवृत्तियो मे बुनियादी तौर पर विरोध नजर आता है, वही अमेरिकी जीवन-पद्धति मे परस्पर समन्वित हो जाती है। यद्यपि पिछले सौ वर्षों मे औद्योगिक विकास खूब हुआ है और बडे-बडे नगर बस गए है तब भी पुराने युग की साहसिकता और नये-नये क्षेत्रो की खोज के लिए आगे बढने की वृत्ति कुछ-न-कुछ आज भी बाकी है। यह वृत्ति व्यक्ति मे स्वावलम्बन की भावना पैदा करती है और साथ ही आवश्यकता पडने पर सहकारी प्रयत्न मे शामिल होने के लिए भी उसे तैयार करती है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे आज भी इन दोनो वृत्तियो का रचनात्मक स्थान है। बडे से बडे कारखाने मे भी श्रमिक कर्मचारी केवल एक सख्या मात्र नही होता, मि० स्मिथ या मि० जोन्स के रूप मे और बहुत सम्भव है बिल या बॉब के आत्मीयतापूर्ण नामो के रूप मे उसकी एक पृथक् व्यक्तिगत सत्ता बनी रहती है। यह मात्र एक शिष्टाचार नही है। बल्कि यह व्यक्ति के प्रति एक स्थायी सम्मान या समादर को प्रकट करता है, और कुछ हद तक व्यक्ति का यह सम्मान ही अमेरिकी श्रमिको की उत्पादकता के ऊँचे स्तर का कारण है।

अब तक हमने जो कुछ विवेचन किया है, उसमे इस बात पर बल दिया है कि अमेरिकी प्रणाली मे कठिनाइयो और समस्याओ का समाधान किन्ही कट्टर सिद्धान्तो से नही बल्कि परीक्षण और गलतियो से प्राप्त अनुभव से सम्बद्ध तथ्यो और वास्तविक विकल्पो को दृष्टि मे रख

कर किया जाता है। इसका एक उदाहरण सरकारी और प्राइवेट उत्तर-दायित्वों के बीच की विभाजिक रेखा का लचकीलापन है। जो विदेशी आगन्तुक अमेरिका के स्वतन्त्र व्यवसाय और उद्यम की सफलताओ को देखकर चकित रह जाते है, वे अक्सर इस बात पर भी बहुत आश्चर्य करते है कि यहाँ सरकार भी कृषि, आवास, सामाजिक सुरक्षा या आर्थिक व्यवस्था के विकास और स्थिरीकरण मे बहुत महत्त्वपूर्ण भाग अदा करती है। अमेरिकी लोगो मे इस बात को लेकर बहुत विवाद चलता रहता है कि सरकार का असली काम क्या है, किन्तु इस बुनियादी सिद्धान्त पर मतभेद आपको शायद ही नजर आयेगा कि एक स्वतन्त्र उद्यम प्रणाली मे व्यक्ति पर यथासम्भव अधिकतम भरोसा किया जाना चाहिए, परन्तु सामान्य जन-कल्याण की खातिर जब और जहाँ आवश्यक हो, सरकार को भी प्रभावकारी कार्रवाई करनी चाहिए।

कुछ देशो मे 'राज्य' को जनता से और राष्ट्रीय समाज की अन्य सस्थाओ से पृथक् और ऊँचा समझा जाता है। वह एक ऐसी ऊँची सत्ता माना जाता है, जिसके अपने अलग हित और उद्देश्य है जिन्हे और सब हितो और उद्देश्यो से पहले स्थान दिया जाता है। इन देशों मे सरकार इस सर्वोपरि राज्य का दृश्यमान पार्थिव रूप होती है और इसलिए वह राज्य की सत्ता और विशेषाधिकारों का उपभोग करती है और जनता उसकी आज्ञाओ का पालन करती है। परन्तु अमेरिकी जीवन ऐसी धारणाओ और मनोवृत्तियो से बिलकुल मुक्त है। अमेरिकी लोग केवल 'सरकार' की ही बात सोचते और करते है, वे 'राज्य' की बात नही सोचते या करते। और 'सरकार' को वे उस महिमा-मडित रूप मे नही देखते, जिस रूप मे कुछ देशो में 'राज्य' को देखा जाता है। यहाँ सरकार केवल समाज की एक सस्था मात्र है। इसके अलावा उसे आम-तौर पर जनता का सेवक समझा जाता है। कानून और परम्परा ने उसकी सत्ता और विशेषाधिकार सीमित कर दिये है और उसकी नीतियाँ और क्रियाकलाप स्वय सरकार के स्वतन्त्र समझे जाने वाले हितो से नही, बल्कि बहुत हद तक विभिन्न समूहों के परस्पर-प्रतिस्पर्धी हितो से

निर्धारित और निर्दिष्ट होते हैं।

सरकार देश की आर्थिक प्रक्रिया मे जो हिस्सा लेती है, उसे घटाने या वढाने के लिए आम तौर पर कानून की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि यह घटा-वढी विधायक और प्रशासक प्रक्रियाओ के आपसी नियन्त्रणो और सन्तुलनो का ही परिणाम नही होती, वल्कि वह वाद मे न्यायपालिका की परीक्षा की कसौटी पर भी खरी उतरनी चाहिए। इसके अलावा सभी नागरिको को सरकारी नीतियो और कार्य-क्रमों का समर्थन या विरोध करने का अधिकार है। इसलिए विशिष्ट हितो वाले अनेक समूहो ने अपने सदस्यो की ओर से विधायिका अथवा कार्यपालिका को प्रभावित करने के लिए अपने सगठन वना रखे हैं। ये सगठन कही अपनी आर्थिक शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसलिए काग्रेस ने इस प्रकार विधायको या प्रशासको को प्रभावित करने वाले सगठनो के क्रियाकलापो को नियन्त्रित करने के लिए भी कानून वनाये हैं। फिर भी ये तथा कुछ अन्य सावैधानिक और सगठनात्मक व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिनके द्वारा अमेरिकी लोकतन्त्र सरकार और प्राइवेट व्यक्तियो के निश्चयो को युक्ति-युक्त और सन्तोषजनक रूप मे सन्तुलित करता है।

सयुक्त राज्य की सघीय और राज्यीय सरकारो के सविधानो मे निरपवाद रूप से यह आधारभूत विश्वास निहित है कि आर्थिक क्रिया-कलाप व्यक्ति का अधिकार है और सरकार केवल एक सीमा तक ही उसे सार्वजनिक हित मे नियन्त्रित कर सकती है। यह सच है कि आर्थिक क्षेत्र मे सरकार के अधिकारो और कार्यो का पिछले वर्षो मे, खास कर बीसवी शताब्दी की अभूतपूर्व परिस्थितियो के फलस्वरूप, काफी विस्तार हुआ है, तथापि उसका कार्य अव भी गौण और सहायक कार्य मात्र है। आर्थिक क्षेत्र मे मुख्य भूमिका अव भी विकेन्द्रित प्राइवेट उद्यम के ही हाथ मे है। अमेरिकी लोगो मे इस स्थिति मे किसी तरह का बुनियादी परिवर्तन करने का भी कोई विचार नही है।

इसमे सन्देह नही कि अमेरिकी लोग, चाहे वे प्रवन्धक हो, या कृषक, या श्रमिक या उपभोक्ता, अपना निश्चय स्वय करना पसन्द करते

हैं। किन्तु वे यह भा स्वीकार करते है कि एक जटिल आधुनिक समाज कुछ नियमो के बिना नही चल सकता। उदाहरण के लिए, मोटर चलाने वाले लोग इस बात पर नाराजगी जाहिर करेंगे कि कोई उन्हे यह बताये कि वे कब और कहाँ मोटर चलाये, परन्तु इस थोडी-बहुत नाराजगी के बावजूद वे यातायात सम्बन्धी नियमो का पालन करते है, जिसके बिना यातायात मे बिलकुल ही अराजकता पैदा हो जायेगी। इस बात पर खासा विवाद हो सकता है कि यातायात को तीव्र गति से चलाने के लिए नियन्त्रक रोशनियाँ कम की जानी चाहिएँ या बढाई जानी चाहिएँ, लेकिन इस सिद्धान्त पर कोई विवाद या मतभेद नही होगा कि सरकार द्वारा यातायात के नियन्त्रण के लिए लगाई गई रोशनियाँ उपयोगी हैं और ड्राइवरो के स्वावलम्बन और आत्म-उत्तरदायित्व के साथ असगत नही है। लोगो के प्राइवेट क्रियाकलापो के बहुत-से अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओ पर सरकार के नियन्त्रण और निर्देशन के बारे मे भी यही बात है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में आयोजन का स्थान

सयुक्त राज्य के बारे मे गलतफहमी का एक कारण यह भी है कि यहाँ आयोजन के सम्बन्ध मे बहुत चर्चा होती है, हालाकि मजा यह है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को 'आयोजित अर्थ-व्यवस्था' से सर्वथा उल्टी व्यवस्था माना जाता है। आम तौर पर 'आयोजित अर्थ-व्यवस्था' का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था माना जाता है जिसमे उत्पादन, निवेश और उपभोग सम्बन्धी सभी बडे निश्चय किसी एक केन्द्रोय सत्ता द्वारा किये जाये। यह समझा जाता है कि एक केन्द्रीय सत्ता कुछ वर्षों की अवधि के लिए एक आर्थिक योजना बनाये और उत्पादन और वितरण के प्रबन्धक, जो राज्य के अधिकारी हो, उस योजना पर अमल करे। योजना का पूर्णत पालन न करने पर ये अधिकारी कठोर दड के भागी समझे जाते हैं। लेकिन वास्तव मे यह बात अमेरिकी प्रणाली से बिलकुल उल्टी है।

परन्तु अमेरिका मे एक सरकारी केन्द्रीय योजना नही है, इसका अर्थ यह नही कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे आयोजन के लिए कोई स्थान है ही नही। हमने इस तथ्य के महत्त्व पर काफी वल दिया है कि आज व्यवसायी लोग केवल स्वल्पकालिका उतार-चढावो को दृष्टि मे रखकर ही अपने निवेश सम्वन्धी निश्चय नही करते, वल्कि वे दीर्घकालिक संभावनाओ को नजर मे रखकर दूरदृष्टि से ये निश्चय करते है। व्यवसायी लोग एक नियत अवधि मे अधिकतम लाभ की प्राप्ति आदि अपने उद्देश्यो को तव तक पूरा नही कर सकते, जव तक कि वे अपने उत्पादनो की भावी विक्री आदि का पहले से ही अनुमान न लगायें। किसी एक वर्ग के उत्पादनो की विक्री की भावी सम्भावनाओ का अनुमान सारी अर्थ-व्यवस्था की भावी अभिवृद्धि के प्रसग मे ही लगाया जा सकता है। यही वात कृपको के निश्चयो के वारे मे भी लागू होती है। इसी तरह श्रमिक नेता अपना मजदूरी और वेतन सम्वन्धी सघर्प तव तक नही चला सकते और सरकार भी कृपि, जल और विद्युत् के विकास की सम्भावनाओ का अनुमान और सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरीकरण या राष्ट्रीय रक्षा कार्यक्रमो का निर्माण तव तक नही कर सकती जव तक कि हर क्षेत्र समूची अर्थ-व्यवस्था की सम्भावित अभिवृद्धि और आवश्यकताओ को नजर मे रखकर आयोजन न करे।

यह अवश्य सम्भव है कि व्यवसायियो, श्रमिक यूनियनो, कृपक सगठनो और सरकार की राय भावी आर्थिक अभिवृद्धि की गति, स्वचालित या अन्य तकनीकी विधियो के परिणाम और उपभोग की तुलना मे पूंजी-निर्माण की सही सम्भावनाओ आदि के वारे मे एक न हो। इन मतभेदो को लेकर वहस हो सकती है और कुछ हद तक देश मे विवाद भी छिड सकते हैं, जो लोकतन्त्र की जान है। लेकिन इस वात पर किसी का मतभेद नही है कि चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे श्रमिक वर्ग, या कृषि जीवी वर्ग या सरकार, सभी को अपने निश्चय भविप्य को दृष्टि मे रख कर योजनापूर्वक करने चाहिएँ। इस वारे मे भी दो राये नही है कि इन सभी वर्गो की योजनाएँ एक-दूसरे के साथ यथासम्भव

समन्वित होनी चाहिएँ और यह काम सरकार का है कि वह अपनी आर्थिक और वित्तीय नीतियो से आर्थिक अभिवृद्धि को सन्तुलित रखते हुए यह समन्वय करे।

योजनाबद्ध विकास सिर्फ केन्द्र-नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्थाओ की ही विशेषता नही है। वह उन अर्थ-व्यवस्थाओ को प्रभावकारी बनाने के लिए भी अनिवार्य है, जिनका आधार लोकतन्त्रीय सस्थाएँ है, जिनमे व्यवसाय और श्रम, दोनो स्वतन्त्र और बन्धनहीन है। लेकिन केन्द्र-नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था और स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था, दोनो के आयोजन के तरीके बिलकुल जुदा-जुदा है। केन्द्र-नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था योजना का एक निश्चित खाका तैयार कर लिया जाता है और उत्पादन अधिकारी उसमे दिये गए आदेशो से रचमात्र भी इधर-उधर नही हो सकते। दूसरी ओर लोकतन्त्रीय अर्थ-व्यवस्था मे आयोजन इस ढग से होता है कि हर कृषक, व्यवसायी, श्रमिक नेता या सरकारी अधिकारी सरकार द्वारा अथवा किसी प्रामाणिक प्राइवेट अनुसधान सगठन द्वारा निर्दिष्ट एक समग्र अर्थ-व्यवस्था के व्यापक ढाँचे के भीतर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और उनके लिए वह उत्तरदायी होता है। इसके अलावा इन प्राइवेट निश्चय-कर्त्ताओ का आयोजन जितना अच्छा होगा, केन्द्रीय आयोजन की आवश्यकता उतनी ही कम होगी।

यदि प्रशासन के भीतर और बाहर, दोनो जगह आर्थिक अभिवृद्धि की भावी सम्भावनाओ के बारे मे आम तौर पर मोटी योजनाएँ बना ली जाएँ तो विकेन्द्रित आयोजन मे बहुत सहायता मिल सकती है। ये मोटी आम योजनाएँ विभिन्न वर्गों के निश्चयकर्त्ताओ के लिए पथ-प्रदर्शन का काम दे सकती है। किन्तु वे अपने लिए कौन-सी योजना को चुने यह फैसला करना स्वय उन्ही का काम है। सरकारी और गैर-सरकारी विभिन्न वर्गों की योजनाओं मे समन्वय और एकीकरण इसीलिए हो पाता है क्योकि वे आर्थिक विकास की भावी सम्भाव-नाओ की एक ही व्यापक और आम योजना को लक्ष्य मे रखकर बनाई जाती है। इसका अर्थ यह नही है कि आर्थिक अभिवृद्धि की ठीक-ठीक

क्या गति होनी चाहिए, इसके बारे मे सब की राय एक ही हो। किन्तु कुछ समय से आहिस्ता-आहिस्ता मोटे तौर पर यह बात सभी लोग स्वीकार करने लगे है कि आर्थिक अभिवृद्धि के क्या स्तर होने चाहिएँ और उनके मुताबिक ही सब के उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाते हैं और सब लोग काम करते हैं।

स्वतन्त्र व्यवसाय वाली अर्थ-व्यवस्था मे आयोजन के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियो पर यहाँ हमे विस्तार से चर्चा नही करनी है। हम यहाँ सिर्फ इसी बात पर बल देना चाहते है कि यद्यपि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे केन्द्रित आयोजन नही होता तो भी इसमे आयोजन होता काफी मात्रा मे है और वह भी सरकारी और गैर-सरकारी दोनो प्रकार का। वास्तव मे अमेरिकी प्रणाली की स्वतन्त्रता और कुशलता के लिए यह आयोजन अनिवार्य है। राष्ट्रीय आयोजन एसोसियेशन (नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन) का एक मुख्य काम सरकारी सगठनो और विभिन्न गैर-सरकारी वर्गों और सगठनो द्वारा किये जाने वाले लोकतन्त्रीय आयोजन मे सहायता करना है।

सन् 1930 के दशक की मन्दी और सन् 1960 के दशक की अभिवृद्धि

सम्भव है, पाठक के मन मे एक प्रश्न घुमडता और उसे अशान्त करता हो। उसे यह यकीन हो सकता है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था आज बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन साथ ही उसके मन मे यह प्रश्न भी उठ सकता है कि तब अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था ने 1930 के दशक मे वैसी ही अभिवृद्धि क्यो नही दिखाई जैसी उसमे आज दीख रही है। उस दशक की मन्दी के दिनो मे कुछ अर्थशास्त्री यह व्याख्या करने का प्रयत्न करते थे कि अमेरिकी समाज की परिस्थितियो मे आर्थिक क्षेत्र मे जडता क्यो आनी स्वाभाविक थी। वही अर्थशास्त्री आज यह सिद्ध करने की चेष्टा करते है कि क्यो निरन्तर समृद्धि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की एक स्वाभाविक विशेषता बन गई है। ऐसी हालत मे इस

बात का क्या भरोसा है कि अमेरिका फिर से आर्थिक जड़ता और मन्दी के जमाने मे नही लौट जायेगा ?

यह नाजुक प्रश्न अवश्य उठाया जाना चाहिए। यह मानकर सन्तोष कर लेने से अधिक खतरनाक बात और कोई नही हो सकती कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था अब मन्दियो की सम्भावना से बिलकुल मुक्त हो गई है। यह जरूर सही है कि 1930 और 1960 के दशको मे कुछ निर्णायक अन्तर है। सन् 1930 के दशक मे सरकारी कार्रवाई बेतरतीब थी, जिसमे आर्थिक सुधारो और आर्थिक पुनरुद्धार के अनेक उपाय मिले-जुले थे और लोग, खासकर व्यवसायी लोग, उन्हे सन्देह की नजर से देखते थे। परन्तु आज अर्थ-व्यवस्था के भीतर ही कुछ ऐसे नियन्त्रण और ऐसी रोके है, जो उसके ढाँचे का अग बन गई है और जो सम्भावित मन्दियो के प्रभाव को कम करती है। शासन—कार्य-पालिका और विधायिका दोनो—आज इस ढग से सगठित हैं कि ज्योही आवश्यकता पडती है, वह तुरन्त कार्रवाई करता है। सब से अधिक महत्त्वपूर्ण एक तीसरा तत्व है और वह यह है कि मुख्य गैर-सरकारी वर्ग और आम जनता, दोनो ही सरकार द्वारा किये जाने वाले मन्दी-विरोधक कार्यो का समर्थन करने के लिए तैयार है और उनसे इसकी आशा की जाती है। यह स्वीकार कर लेने के बाद कि मन्दी आने पर अथवा आर्थिक अभिवृद्धि की गति के धीमी पड़ने पर आवश्यक निरोधक कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है, सभी लोग उन आवश्यक सरकारी कार्रवाइयो को बिना आपत्ति के स्वीकार कर लेगे, चाहे वे कुछ वर्गो को तात्कालिक या काल्पनिक हितो के विरुद्ध हो जाती प्रतीत होती हो। इन कारणो से आर्थिक भविष्य मे लोगो का विश्वास कही अधिक बढ गया है और उससे प्राइवेट व्यवसायी लोग आर्थिक विस्तार को जारी रखने या पुन प्रारम्भ करने के लिए पहले से अधिक अच्छे अवसर पा सकते है।

इस तरह, जहाँ 1930 के दशक मे आर्थिक मन्दी और जडता का भय बुरी तरह हावी हो गया था, वहाँ 1960 के दशक को लोग आर्थिक

प्राचुर्य के एक नये युग की देहरी समक्ष है। श्री रूजवेल्ट ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि राष्ट्र का तिहाई हिस्सा ऐसा है जिसके पास 'रहने को अच्छे मकान नहीं, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं और खाने को पर्याप्त पौष्टिक आहार नही।' उसी तिहाई भाग की इन आर्थिक अपर्याप्तताओ और अपूर्णताओ को दूर करने के लिए वर्तमान शताब्दि के मध्य तक सयुक्त राज्य ने काफी प्रगति कर ली है। आज गरीबी और आर्थिक अभाव की समस्याओ पर धीरे-धीरे विजय पाई जा रही है। जो लोग हारकर मैदान नही छोडते उन्हे कुछ समय भले ही लग जाय, परन्तु अन्तत. आर्थिक अभिवृद्धि और उसके उपायो मे सुधार से उनकी समस्या का हल जरूर निकल आयेगा। अगर युद्ध की सम्भावनाओ को किसी तरह रोका जा सके तो इस बात की काफी सम्भावना है कि सयुक्त राज्य अगले एक या दो दशको मे सभी के लिए प्रचुर भौतिक सम्पदा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

अगर यह मान ले कि अमेरिका अपनी भावी भावनाओ की चुनौती का सामना कर सकता है तो सन् 1970 तक औसत अमेरिकी परिवार के रहन-सहन का स्तर आज के स्तर से 30 प्रतिशत ऊँचा हो जाएगा और देश की उत्पादकता मे जो वृद्धि होगी उससे उत्पादन में 60 प्रतिशत वृद्धि की गुजायश रहेगी। तब अमेरिकी लोग अपने प्राकृतिक साधनों की रक्षा और विकास की आवश्यक सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध करने की और शिक्षा, स्वास्थ्य और बूढो की देखभाल की अपनी बढती हुई ज़िम्मेदारियो को पूरा कर सकेंगे।

लेकिन आर्थिक अभावो से उत्पन्न गरीबी और मानवीय कष्टो के उन्मूलन का अर्थ यह नही होगा कि अमेरिकी समाज की सब बडी समस्याएँ हल हो जायेगी। बल्कि वास्तविकता इसके विपरीत होगी। पूर्व अध्यायो मे हमने केवल अमेरिका की सफलताओ और उपलब्धियो का ही वर्णन नही किया है, बल्कि यह भी बताया है कि सन्तुलित आर्थिक विकास को कायम रखने, आर्थिक सत्ता के अत्यधिक

केन्द्रीकरण को रोकने और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की अन्य तात्कालिक किन्तु अधिक परिचित समस्याओ का समाधान करने के प्रयत्नो मे क्या कमियाँ है। इन लक्ष्यो के बारे मे अब अधिकाधिक मतैक्य होता जा रहा है और जैसे-तैसे आर्थिक व्यवहार के वाछनीय स्तरों मे सुधार होता जाएगा, वैसे-वैसे इन समस्याओ को निबटाने की विधियो और और तकनीको मे भी सुधार होता जायेगा। हमने हाल मे ही पैदा हुई समस्याओ की भी चर्चा की है, जो अभी-अभी स्पष्ट रूप में सामने आने लगी है और जिनका समाधान अधिकाधिक आवश्यक हो रहा है। आने वाले वर्षो मे इन समस्याओ पर अनेक कठिन निश्चय करने पडेगे और आवश्यक कदम उठाने होगे। उदाहरण के लिए आबादी मे हो रही वृद्धि, उद्योगो के विस्तार और सयुक्त राज्य मे गरीबी पर विजय पाने के लिए निरन्तर किये जा रहे प्रयत्नो के संभावित परिणामो को दृष्टि मे रखकर बडे नगरो और महानगर क्षेत्रो, शिक्षा प्रणाली और अन्य सामाजिक सस्थाओ को उनके अनुकूल ढालने की समस्याएँ ऐसी है जिन्हे हमे हल करना होगा, किन्तु इन समस्याओ को अभी तक पूरे तौर पर हृदयगम भी नही किया जा रहा। पश्चिमी राष्ट्रो को अधिक सगठित करने, अल्पविकसित देशो के आर्थिक और सामाजिक विकास को उन्नत करने एव कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद की चुनौती का मुकावला करने के लिए अधिक पर्याप्त साधन उपलब्ध करने और अधिक रचनात्मक अमेरिकी नेतृत्व प्रदान करने के लिए अभी बहुत कुछ काम बाकी है। लोगो को प्रशिक्षण देने और सभी प्रकार के वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसन्धान की सुविधाएँ प्रदान करने की बढ़ती हुई आवश्यकताओ को भी पूरा करना होगा। अन्तरिक्ष का अनुसन्धान मानव-जाति के लिए जिन भावी सम्भाव्यताओ का द्वार खोल रहा है, चाहे वे भलाई के लिए हों या बुराई के लिए, उनका भी यह तकाजा होगा कि अमेरिका उनके लिए अधिकाधिक साधनो और वैज्ञानिक दक्षता की व्यवस्था करे।

भावी जीवन-विधि

यद्यपि अमेरिका के सामने इस प्रकार की बहुत-सी गम्भीर समस्याएँ है तो भी उसके सामने कुछ अन्य जटिलतर और चकरा देने वाली समस्याएँ भी है, जो गरीबी के उन्मूलन की दिशा मे की जा रही प्रगति का परिणाम हैं। इन समस्याओ का सम्बन्ध भौतिक सामग्रियो के मात्रात्मक प्राचुर्य के युग मे जीवन के गुणात्मक स्वरूप के साथ है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन समस्याओ का सम्बन्ध केवल आर्थिक कठिनाइयो के साथ ही नही है, बल्कि प्रचुर भौतिक सामग्रियो से सम्पन्न समाज मे पैदा होने वाले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रश्नो से भी है। जीवन पद्धति किस ढग की हो, इसकी विविध समस्याओ मे से एक महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि व्यक्ति अपने अवकाश के खाली समय को किस ढग से बिताये और सब लोगो को एक निश्चित और बँधी-बँधायी पद्धति को अपनाने के लिए समाज पर आज जो दबाव पड रहे हैं उनका मुकाबला करते हुए व्यक्ति के सृजनात्मक व्यक्तित्व की रक्षा कैसे की जाय।

उत्पादकता मे हो रही निरन्तर वृद्धि और स्वचालित यन्त्रो के उपयोग के परिणामस्वरूप अमेरिकी लोग काम के घण्टो और शारीरिक श्रम मे कमी करके भी अधिकाधिक वस्तुओ और सेवाओ का उत्पादन कर सकेंगे। अभी हाल के वर्षो की स्थिति का अध्ययन करने पर इस बात के काफी प्रमाण मिल सकते है कि यदि अमेरिकी लोगो के पास धन और समय पर्याप्त हो तो वे अपने खाली समय मे ऐसे काम करना पसन्द करेंगे जो उन्हे रुचिकर होगे। अवकाश काल की इन प्रवृत्तियो की कुछ दिशाओ की हमने चर्चा की है, और इसमे तनिक भी सन्देह नही कि अनेक प्रकार की सास्कृतिक, मनोरजनकारी और हस्त-शिल्पिक प्रवृत्तियो मे बहुत अधिक और उत्साहवर्धक प्रगति हुई है। लेकिन भविष्य मे अमेरिकी लोगो को कुछ नई किस्म की रचनात्मक प्रवृत्तियो का विकास करना होगा ताकि उन्हे अपने खाली समय को व्यतीत करने के

लिए स्वेच्छा और आजादी से अपने मन-पसन्द क्रियाकलापो को चुनने का जो अधिकाधिक अवसर मिलेगा, उसका वे उपयोग कर सके। इसलिए आज अमेरिकी समाज के सामने, खासकर अमेरिकी शिक्षा-पद्धति के सामने यह चुनौती है कि वह अमेरिकी लोगो की रुचियो को नये ढग मे ढाले ताकि भविष्य मे उन्हे जो पहले से भी अधिक खाली समय मिलेगा उसे वे समाज को नुक्सान पहुँचाने वाली प्रवृत्तियो के बजाय अपने मन को सन्तुष्ट करने वाली और साथ ही समाज को लाभ पहुँचाने वाली प्रवृत्तियो मे लगा सके।

आज के जमाने मे एक ओर औद्योगिक देशो की अर्थ-व्यवस्थाएँ बहुत जटिल और परस्पर-निर्भर है और दूसरी ओर आबादियो मे वृद्धि, जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयत्न और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव उन पर और भी अधिक दबाव डाल रहे है। फलत. यह खतरा पैदा हो गया है कि कही ये मिलकर समाज को एक बँधी-बँधाई लीक पर चलने और सब व्यक्तियो को एक जैसा जीवन अपनाने के लिए मजबूर न करे। इसीलिए सरकारी सगठनो, व्यावसायिक कम्पनियो, ट्रेड यूनियनो को ही नही, विश्वविद्यालयो और अन्य प्राइवेट सस्थाओ को भी मजबूरन अपने आकार का विस्तार करना पडा है, अपने कार्यो को बढाना और अपनी कार्य-विधियो को युक्तियुक्त आधार पर स्थापित करना पड़ा है, ताकि वे बीसवी सदी के मध्यकाल की कठोर और परिवर्त्तमान परिस्थितियो का मुकाबला कर सके।

इस नये रुझान के परिणामस्वरूप आज एक नये किस्म के मानव का उदय हुआ है जिसे विलियम ह्वाइट ने 'संगठन मानव' का नाम दिया है। इस 'सगठन मानव' की सफलता अपने से ऊपर के अधिकारियो और अपने सहकर्मियो को इस बात का विश्वास दिखाने की उसकी योग्यता पर निर्भर है कि वह किन्ही नये और सर्वथा अपरम्परागत विचारो का प्रचार कर या अपने आचरण को पूर्णत. वैयक्तिक रूप देकर संगठन के निर्विघ्न कार्यसचालन मे बाधा नही डालेगा। इसके अलावा अमेरिकी लोगो की बहुत बड़ी सख्या आज उपनगरो मे रह रही

है और उसका जीवन-स्तर निम्नवर्गीय होने के बजाय मध्यवर्गीय है और साथ ही इन लोगो पर अपने स्थानीय समाज की जीवन-पद्धति का अनुसरण करने के लिए बहुत दबाव भी पड रहा है, जिससे वैयक्तिकता और सृजनात्मकता के लिए गुँजाइश और भी कम होती जा रही है। इसलिए भौतिक समृद्धि और प्राचुर्य का जो नया जमाना आ रहा है उसमे एक मुख्य काम ऐसी नई जीवन-विधियो का विकास करना होगा जिनसे लोग अपनी वैयक्तिकता का परित्याग किये बिना सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके और अपने व्यक्तिगत ध्येयो को भी प्राप्त कर सके।

किन्तु अमेरिकी समाज की कुछ ऐसी विशिष्टताएँ भी हैं जो समाज की बँधी लीक के अधिकाधिक परिपालन और सारे समाज को एकाकार बना डालने की प्रवृत्तियो को उदासीन करती रहती है। सयुक्त राज्य मे प्राय हर व्यक्ति का सम्बन्ध ऐसे अनेक समुदायो और सगठनो से रहता है जिनका आपस मे कोई सम्बन्ध नहीं होता। कारखाना, दफ्तर, ट्रेड यूनियन, गिरजाघर, राजनीतिक दल, सामाजिक क्लब और पडोस की सॉस्कृतिक एव खेल एसोसियेशने—इन सभी का अपने सदस्यो की वफादारी पर दावा होता है और सभी मे यह होड चलती है कि लोग उनमे अधिकाधिक भाग लें। एक तरह से देखा जाय तो इन सस्थाओ और सगठनो मे भाग लेना अपने आप मे एक बँधी परिपाटी का पालन करना है, क्योकि सामाजिक जीवन मे अधिकाधिक सक्रिय भाग लेने की वाँछनीयता की मौजूदा धारणा आज की एक बँधी परिपाटी ही है। किन्तु साथ ही व्यक्ति का किसी एक मन पसन्द धार्मिक सम्प्रदाय, राज-नीतिक दल, ट्रेड यूनियन या पेशा-वर्ग से सोद्देश्य सम्बन्ध रहने के कारण उसमे उसके प्रति आस्था और गहरी निष्ठा पैदा हो जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि वह कम मन पसन्द एव वाछनीय और अधिक सर्व-सामान्य एव व्यापक जीवन-पद्धति के पालन का प्रतिरोध करने लगता है। इस प्रकार की परस्पर-प्रतिस्पर्धी निष्ठाएँ और वफा-दारियाँ भी रुचियो और रुचियो मे विविधता पैदा करती है और इस

प्रकार अत्यधिक साम्य और एकरूपता लाने की प्रवृत्ति का प्रतिरोध करती है।

साम्य और एकरूपता की प्रवृत्तियो से अमेरिका को चिन्तित होने का कारण यह है कि उसकी आस्था परम्परा से ही व्यक्तिवाद के आदर्श के प्रति रही है। अमेरिकी समाज मे व्यक्तिगत सृजनात्मकता का भविष्य क्या होता है, यह इस बात पर निर्भर है कि लोग उसके विनाश के खतरो को कितनी उत्कटता से अनुभव करते है, अमेरिकी लोगो मे खुले मन से हर चीज पर विचार करने और प्रयोग करने की प्रवृत्ति कितनी है, व्यावसायिक कम्पनियो, ट्रेड यूनियनो और अन्य बडे सगठनो मे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना कितनी है, सरकार को किस हद तक जनता की मालिक के बजाय सेवक समझा जाता है और अन्य बहुत-सी सस्थाओ और मूल्यो का किस ढग से विकास होता है। जब तक अमेरिकी समाज की ये विशिष्टताएँ मौजूद है तब तक यह आशा है कि आने वाले दशको की अधिक कठिन परिस्थितियो मे भी लोग एक-न-एक दिन व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय के लिए नये और प्रभावकारी उपाय निकाल सकेंगे।

मार्क्सवादी सिद्धान्त और अमेरिकी प्रणाली

कम्युनिस्ट इस तथ्य से इन्कार नही करते कि अमेरिकी प्रणाली ने उद्योग-विद्या और प्रवन्ध कौशल के क्षेत्रो मे वहुत प्रगति की है और सफलता प्राप्त की है। वे स्पष्ट स्वीकार करते है कि इस सम्वन्ध मे वे अमेरिकी सफलताओ से सवक ले सकते है और लेना भी चाहते है। लेकिन उनका यह विश्वास है कि स्वतन्त्र व्यवसाय प्रणाली मे ये सफलताएँ जितनी तीव्र गति से प्राप्त होगी, उसका अन्तिम विनाश उतना ही नजदीक आता जायेगा। वे यह मानते है कि उद्योग-विद्या के क्षेत्र मे हुई प्रगति का उत्पादक उपयोग केवल कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं, फिर चाहे उस प्रगति का उद्‌गम कही भी हो।

मार्क्सवाद के अनुसार तथाकथित प्राकृतिक नियम ही पूंजीवाद को विनाश की ओर ले जा रहे है। कम्युनिस्टो का कहना है कि यह विनाश निम्न तर्कसगत प्रक्रिया के अनुसार होगा

1 उद्योग-विद्या (टैकनोलॉजी) के क्षेत्र मे प्रगति होने से वडी फर्मे छोटी फर्मो से अधिक अच्छी स्थिति मे और उन पर हावी हो जाएँगी।

2 इससे पूँजी कुछ थोडे-से लोगो के हाथो मे केन्द्रित हो जायेगी और उसके परिणामस्वरूप दौलत और आय भी थोडे-से हाथो मे केन्द्रित हो जायेगी। इससे मध्य वर्ग के लोग धीरे-धीरे प्रोलितेरियत वर्ग (शोपित निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग) मे आ जायेगे और इस प्रकार मुट्ठी भर धनी और वहुसख्यक गरीव लोगो के बीच मे एक चौडी खाई हो जाएगी।

3. इससे अनिवार्य रूप मे बेरोजगारी रहेगी और इस बेरोजगारी का लाभ उठाकर श्रमिको का शोषण किया जाएगा और उससे आम जनता की गरीबी और भी वढेगी।

4 इससे एक ओर उत्पादक शक्ति मे वृद्धि होगी और दूसरी ओर लोगो की क्रय-शक्ति कम होती जाएगी और परिणाम यह होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा हो जाएगा। इस खात्मे को रोकने के लिए कारखानो को शास्त्रास्त्रो के उत्पादन मे लगाया जा सकता है या अन्य साम्राज्यवादी दु साहस किये जा सकते है, पर इनसे पूंजीवाद का

अन्त रुक नही सकता, कुछ के लिए समय टल ही सकता है।

हमारा विश्वास है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के यथार्थ रूप का सर्वेक्षण और विश्लेषण करने से मार्क्सवादियो के इस तर्क का कदम-ब-कदम खडन हो जाता है। मार्क्सवादी सिद्धान्त उन्नीसवी शताब्दी के आर्थिक इतिहास की रोशनी मे गढा गया था और वह उस समय की घटनाओ की 'बन्धनहीन व्यवसाय' के सिद्धान्त के अनुसार की गई व्याख्या का उत्तर था। परन्तु आज की अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर यह मार्क्सवादी सिद्धान्त लागू नही होता। लेकिन कम्युनिस्ट लोग इस सिद्धान्त का परित्याग नही कर सकते क्योकि यह उनका बुनियादी सिद्धान्त है।

यह सही है कि टैकनोलॉजी के क्षेत्र मे की गई प्रगति से कुछ उद्योगो मे बडी फर्मों की स्थिति छोटी फर्मों के मुकाबले अच्छी हो गई है, लेकिन यह बात सब उद्योगो के बारे मे सही नही है। मार्क्सवादियो का यह कहना भी अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे सही सिद्ध नही हुआ कि पूँजी और उत्पादन क्षमता कुछ हाथो मे केन्द्रित होने से दौलत और आय भी कुछ ही हाथो मे केन्द्रित हो जाएँगी और उनके वितरण मे बहुत असमानता हो जाएगी। छोटी और मध्यम फर्मों ने अनेक क्षेत्रो मे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। मध्यम वर्ग के लोग प्रोलितेरियत वर्ग मे परिणत नही हुए। इसके विपरीत मार्क्सवादी जिन लोगो को 'मेहनतकश लोग' कहते है, उनकी स्थिति इतनी सुधार गई है कि वे निम्न वर्ग से ऊपर उठकर अधिकतर मध्यम वर्ग मे शामिल हो गए है। अमेरिका मे आज अधिक सख्या इस मध्यम वर्ग की ही है। अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था ने गरीबी को बढावी नही, बल्कि सयुक्त राज्य की समूची जनता को प्राचुर्य के युग की देहरी पर पहुँचा दिया है। उसने सम्पत्ति और आय को कुछ थोडे-से हाथो मे केन्द्रित करने के बजाय उन्नति और धनोपार्जन के अवसरो को अधिक व्यापक बनाया है और सभी लोगो को अधिक सन्तोष प्रदान किया है।

यह बात भी सही नही है कि उद्योगविद्या (टैकनोलॉजी) की प्रगति

से बेरोजगारी जरूर होगी ही। सैद्धान्तिक अन्तर्दृष्टि और पिछले दो दशकों के व्यावहारिक अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्वतन्त्र व्यवसाय वाला समाज चाहे तो बड़े पैमाने पर मन्दी और बेरोजगारी को रोक सकता है। सयुक्त राज्य की सरकार रोजगार को उच्चतम स्तर पर बनाये रखने की नीति से बंधी हुई है और दोनो बड़े राजनीतिक दलो, व्यवसायी, कृषक और श्रमिक वर्गों के नेताओ और आम जनता, सभी ने उसे स्वीकार किया है। इस नीति को क्रियान्वित करने के उपायो मे निरन्तर सुधार किया जाता है।

अपने देश मे मन्दी और बेरोजगारी की आशका से प्रेरित होकर अमेरिकी सरकार ने आक्रमण और साम्राज्यवाद की नीति भी नहीं अपनाई। इसके विपरीत, सयुक्त राज्य ने उपनिवेशवाद का अन्त करने के लिए एक रचनात्मक भूमिका अदा की है और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अल्पविकसित देशो के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुक्तहस्त होकर सहायता दी है।

बड़े पैमाने पर शस्त्रीकरण एक ऐसी आवश्यकता है जो ससार की परिस्थितियो ने लोकतन्त्रीय देशो पर जबर्दस्ती थोप दी है। वह फालतू उत्पादन क्षमता की निकासी का उपाय नही, बल्कि एक बोझ है। इस शस्त्रीकरण की मजबूरी के कारण बहुत-से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कामो को तब तक के लिए स्थगित करना पड़ा है जब तक कि शस्त्रास्त्रो मे कमी करना सम्भव नहीं होता और उत्पादक साधन इन रचनात्मक कामो के लिए मुक्त नहीं होते।

इस प्रकार अमेरिका का अनुभव यह बताता है कि मार्क्सवादी सिद्धान्त के तर्क वास्तव मे तर्क नही, तर्काभास हैं। अमेरिकी आर्थिक प्रणाली की व्यावहारिकता और नैतिकता पर हमारी गहरी आस्था है और उसका आधार यह अनुभव तो है ही साथ ही हमारा यह विश्वास भी है कि जैफर्सन का व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन का सिद्धान्त मानवीय आत्मा मे गहराई तक बद्धमूल है। हमे निश्चय है कि उत्पादन और प्रबन्ध को अधिक कुशल बनाने के लिए अमेरिकी प्रणाली मे किसी

भी सत्तावादी प्रणाली से अधिक गुंजाइश और क्षमता है। हम जानते है कि यह प्रणाली किसी भी तानाशाही प्रणाली से अधिक स्वतन्त्रता और आत्म-उत्तरदायित्व प्रदान करती है।

अमेरिकी आर्थिक प्रणाली का नाम क्या हो ?

तब हमे इस अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को क्या नाम देना चाहिए ? जो लोग परम्परागत आर्थिक विचारधाराओ के अनुसार इसे किसी वर्ग मे रखना या कोई पुराना नाम देना चाहते है, वे उसके स्वरूप को देख कर चक्कर मे पड़ जाते हैं।

अमेरिकी प्रणाली मे प्राइवेट व्यावसायिक क्रियाकलापो की मुनाफा कमाने की इच्छा आर्थिक अभिवृद्धि के प्रमुख प्रेरक कारणो मे से एक है इसलिए उस हद तक यह प्रणाली पूंजीवादी है। वास्तव मे यह स्वतन्त्र व्यवसायियो, स्वतन्त्र श्रमिको और स्वतन्त्र उपभोक्ताओ वाली आर्थिक प्रणाली है। लेकिन अगर पूंजीवाद का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमे व्यवसायी जो चाहे कर सकता है, जिसमे श्रमिको और उपभोक्ताओ का शोषण किया जाता है और पूंजीपति ही आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य लाभ उठाता है, तो उस अर्थ मे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पूंजीवादी नही है। यदि पूंजीवाद का अर्थ यह है कि सरकार केवल व्यवसायी के फायदे के लिए ही सब काम करे, तो उस अर्थ मे भी अमेरिकी प्रणाली पूंजी-वादी नही है। उन्नीसवी शताब्दी मे 'बन्धन हीन व्यवसाय' (लैसे फेयर) के सिद्धान्त का जो अभिप्राय था यदि वही पूंजीवाद का अर्थ है तो भी अमेरिकी प्रणाली को पूंजीवादी प्रणाली नही कहा जा सकता।

अमेरिकी प्रणाली समाजवादी प्रणाली भी नही है, अगर समाजवाद का अर्थ एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था हो, जिसमे सभी या अधिकाश कारखाने राज्य की सम्पत्ति हो और राज्य द्वारा चलाये जाते हो और राज्य ही यह निश्चय करता हो कि क्या उत्पादन किया जाये, कौन-से नये संयन्त्र लगाये जाएँ और क्या मजदूरियाँ और वेतन दिये जाये, आदि। यदि समाजवाद का अर्थ ऐसी व्यवस्था है जिसमे राज्य ही सामाजिक और

आर्थिक जीवन का नियामक हो तो भी अमेरिकी प्रणाली समाजवादी नही है। लेकिन यदि समाजवाद का अर्थ एक ऐसी प्रणाली हो, जो लोकतत्रीय पद्धति से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव-कल्याण और आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्यो और पैमानो को निर्धारित और प्राप्त करती है, तो सयुक्त राज्य को निम्सन्देह समाजवादी समाज कहा जा सकता है। अमेरिकी लोग यह आशा करते है कि सरकार प्राइवेट उद्यमो को इनमे से यथासम्भव अधिकतम लक्ष्यो की प्राप्ति मे सहायता देगी और जो लक्ष्य रह जाएँ उनकी प्राप्ति के लिए सरकारी कार्यक्रम बनायेगी। निस्सन्देह इस अर्थ मे सयुक्त राज्य कम्युनिस्ट राज्यो से भी कही अधिक लोकतन्त्रीय समाजवादी राज्य है।

अमेरिकी प्रणाली मे सरकारी और प्राइवेट सभी सस्थाओ से यह आशा की जाती है कि वे आम जन-कल्याण को समुन्नत करेगी। इस प्रकार की प्रणाली मे प्राइवेट व्यवसाय अपने आपमे कोई लक्ष्य नही है, बल्कि वह सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम रखते हुए जनता की आवश्यकताओ को पूरा करने वाला सबसे प्रभावकारी सगठनात्मक साधन हैं। इस तरह की प्रणाली मे सरकार या शासन भी अपने आप मे कोई लक्ष्य नही है, वह भी उन कार्यो को पूरा करने के लिए सगठित किया गया एक साधन है, जिन्हें प्राइवेट व्यवसाय पूरा नही कर सकते।

इसलिए जहाँ तक पूंजीवाद और समाजवाद के ऐतिहासिक अर्थो का ताल्लुक है, अमेरिकी प्रणाली को इन दोनो मे से किसी भी वर्ग मे नही रखा जा सकता, क्योकि उसमे न राज्य का प्राधान्य है, न प्राइवेट व्यवसाय का और न किसी अन्य अकेले वर्ग का। इसमे सरकारी और प्राइवेट सभी सस्थाएँ पर्याप्त आत्मनिर्धारण और आत्म-उत्तरदायित्व के साथ अपना-अपना काम निभाती है।

तब यह निर्णय कौन करता है कि अन्तत उत्तरदायित्वपूर्ण रीति से काम करने का पैमाना अमुक है ? इस नाजुक प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। यही वजह है कि अमेरिकी प्रणाली की कोई एक निश्चित परिभाषा करना और उसे एक निश्चित वर्ग मे रखना कठिन है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की अधिक से अधिक सही परिभाषा यदि कोई हो सकती है तो वह यही कि अमेरिकी आर्थिक प्रणाली अमेरिकी जनता के राष्ट्रीय हितो को पूरा करती है—और वे राष्ट्रीय हित क्या है, इसकी अभिव्यक्ति लोकतन्त्रीय राजनीतिक प्रक्रियाओ, जन-मत, बहुसख्यक प्राइवेट वर्गो और सगठनो और व्यक्तिगत उपभोक्ता की हैसियत से सभी अमेरिकी नागरिको की पसन्द और रवैयो के जरिये होती रहती है।

'राष्ट्रीय हित' शब्द बहुत अस्पष्ट और अस्थिर धारणा का अभिव्यजक हो सकता है, परन्तु अतीत मे यह धारणा काफी स्पष्ट और सुनिश्चित हो गई है। 'बन्धनहीन व्यवसाय' के सिद्धान्त के समर्थको ने कोई निश्चित आर्थिक स्तर निर्धारित करने के प्रयत्नो का हमेशा विरोध किया है। अर्थात् उपभोग का स्तर क्या हो, आवास-व्यवस्था का स्तर क्या हो या आर्थिक विस्तार की गति कितनी होनी चाहिए—इन सब बातो के निर्धारण के प्रयत्नो पर उन्होने हमेशा नाराजगी जाहिर की है। उनका मत यह रहा है कि यदि हर आदमी केवल अपने हित को पूरा करने का प्रयत्न करे तो उसका जो नतीजा होगा, वही सर्वोत्तम सम्भव परिणाम होगा। लेकिन आज इस बारे मे कुछ निश्चित आदर्श और पैमाने निर्धारित हो रहे है कि आर्थिक गतिविधि के क्या लक्ष्य होने चाहिएँ—उदाहरण के लिए उन सब लोगो को काम मिलना चाहिए जिनमे काम करने की शक्ति और इच्छा है, रोजगार, उत्पादन और मूल्यो मे बहुत उग्र उतार-चढाव नही होने चाहिएँ; लोगो के लिए मजदूरी, मकान, पोषक आहार और स्वास्थ्य सेवाओ की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और आर्थिक अभिवृद्धि की गति ऐसी होनी चाहिए कि विज्ञान और टैकनोलॉजी के क्षेत्र मे हुई प्रगतियो का लाभ उठाते हुए वह देश के भीतर बेरोजगारी को दूर कर सके और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे विश्व की समस्याओ के हल करने के लिए पारस्परिक सहयोग को सहारा दे सके। आज यह बात नही मानी जाती कि यदि हर व्यक्ति को अथवा हर संगठित वर्ग को अपना हित पूरा करने के लिए पूरी छूट दे दी जाय तो उसका जो

परिणाम होगा, वही सर्वोत्तम परिणाम होगा। हर व्यक्ति और वर्ग से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपना स्वार्थ-साधन इस ढग से करेगा कि उससे राष्ट्र का हित-साधन हो।

राष्ट्र-हित के लिए जिन वस्तुओ की आवश्यकता है, उनमे से कुछ ही ऐसी हैं जिन्हे कानून का रूप दिया गया है। शेष वस्तुएँ ऐसी हैं जो या तो 'अलिखित कानून' और परम्परा के रूप मे विद्यमान हैं या उन नर-नारियो के चुनाव पर छोड दी गई है जिन्हे राजनैतिक और आर्थिक निर्णय करने की स्वतन्त्रता है। आम जनता बडे व्यवसायो, बडी ट्रेड यूनियनो और बडे शासन-यन्त्र को तो स्वीकार करती है, परन्तु वह इस बात के लिए राजी नही है कि जनता को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को निर्धारित करने का काम इनमे से किसी के भी हाथ मे हो। जिन लोगो के हाथ मे आज बडे व्यवसायो, बड़ी ट्रेड यूनियनो या बडे प्रशासनिक सगठनो के संचालन का उत्तर-दायित्व है, वे जनता के इस रवैये से परिचित हैं और उसका सम्मान करना अधिकाधिक सीखते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कम्पनी-गुट विरोधी कानूनो मे कम्पनियो के आर्थिक शक्ति के किसी खास दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था न हो, तो भी अलिखित कानून और परम्पराएँ ऐसी बन गई हैं कि इस शक्ति का दुरुपयोग कर जन-हित को नुक्सान पहुँचाने वाली कम्पनियो को सज़ा दी जाती है। यह सज़ा उनके खिलाफ प्रचार के रूप मे हो सकती है, जिनसे उनकी बिक्री पर बुरा असर पड सकता है और यह भी सभव है कि इस प्रकार से उन्हे अपने लिए जिस किस्म के कर्मचारियो की आवश्यकता है वे न मिले। इसके अलावा यह सज़ा काग्रेस (ससद्) द्वारा जाँच के अथवा लोकतन्त्रीय प्रणाली मे असंतोष प्रकट करने के लिए विद्यमान किसी अन्य विधि के रूप मे भी हो सकती है। इसी तरह यदि सरकार पूरी तरह कार्रवाई न करे अथवा ज़रूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करे तो उसके विरुद्ध भी जनता चुनावो मे मतदान के द्वारा अपना असन्तोष व्यक्त करती है।

यह सारी व्यवस्था लचकीली है। आहिस्ता-आहिस्ता कुछ अलिखित कानून लोकतंत्रीय बहस-मुबाहसे के बाद लिखित कानून का रूप धारण कर लेते हैं। किन्तु कानून ही इस व्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण अग नही हैं। एक तरह से वे सिर्फ यह सकेत ही देते है कि किन-किन बातो मे यह व्यवस्था ठीक ढग से नही चल रही थी। यदि प्राइवेट व्यवसायियो ने अपनी आर्थिक सत्ता का कुछ दुरुपयोग न किया होता तो कम्पनी-गुट विरोधी कानून कभी न बनते। अगर मजदूरी की दरे कुछ स्थानो पर एक प्रचलित स्तर से नीची न होती तो मजदूरी-घटा (वेज-अवर) कानून न बनता। अगर औद्योगिक उत्पादन मे गम्भीर शिथिलता और मन्दी न आती तो रोजगार कानून कभी न बनाया जाता। प्राइवेट व्यवसायी सामान्य जन-हित की आवश्यकताओ का जितना ध्यान रखेंगे सरकार द्वारा कानून बनाये जाने और निर्धारित स्तरो को लागू किये जाने की गुजाइश उतनी ही कम होगी।

इस प्रकार सयुक्त राज्य मे जो आर्थिक प्रणाली उभर रही है वह अनेक 'शुद्ध' आर्थिक प्रणालियो की विशिष्टताओ का सम्मिश्रण है और उससे यह आशा रखती है कि वह व्यक्ति की आवश्यकताओ और आधुनिक टैकनोलॉजी की सम्भावनाओ के साथ समन्वय कर सकेगी।

जो लोग यह अनुभव करते है कि अमेरिका मे एक अद्वितीय किस्म की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही हैं, उन्होने इस व्यवस्था के लिए अनेक नाम सुझाये है। यदि यह कहा जाय कि उसके लिए 'आर्थिक लोकतन्त्र' नाम उपयुक्त होगा तो उससे यह अर्थ तो ध्वनित हो जाएगा कि यह व्यवस्था आम लोक-कल्याण का ध्यान रखती है, परन्तु साथ ही 'आर्थिक लोकतन्त्र' से यह अर्थ भी निकलता है कि उसमें श्रमिक और प्रबन्धक मिलकर व्यवसाय की प्रबन्ध-सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित करते हैं, जब कि इस शब्द से हमारा वैसा अभिप्राय नहीं है। कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को 'जनता का पूँजीवाद' कहा जाय, क्योंकि वह पूँजीवादी साधनों से समस्त जनता के कल्याण और प्रतिष्ठा को साधना चाहती है। यह

नाम इस अभिप्राय को सही रूप मे व्यक्त करता है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था कुछ लोगो का ही नही, वल्कि प्राय सभी लोगो का हित-साधन करती है। किन्तु 'जनता का पूंजीवाद' शब्दो का प्रयोग कभी-कभी इस तथ्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है कि साधारण आय वाले करोडो अमेरिकियो के पास वडी-वडी कम्पनियो के शेयर हैं। यह वात सही ज़रूर है, लेकिन इससे ये करोडो अमेरिकी 'पूंजीवाद' शब्द के परम्परागत अर्थ मे, पूंजीवादी नही वन जाते और न ही अमेरिकी व्यवसाय प्रणाली, जैसा कि हमने ऊपर वताया है, इस अर्थ मे पूंजीवादी कही जा सकती है। जो भी नाम चुना जाय, वह ऐसा होना चाहिए कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की मुख्य विशेषताओ को अभिव्यक्त कर सके, उसके व्यक्तिगत स्वतत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के अद्भुत सम्मिश्रण को पूरा कर सके।

हमारे कथन का यह अभिप्राय कदापि नही कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे जो मुख्य विशेषताएँ है वे केवल सयुक्त राज्य की ही अपनी विशेषताएँ है। इनमे से कई महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ ऐसी है जिनका जन्म अन्य देशो मे हुआ, जहाँ की स्वतत्र व्यवसाय वाली अर्थ-व्यवस्था भी अमेरिका के समान ही कायाकल्प मे से गुजरी। इसलिए सयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था को विलकुल सही और सच्चे रूप मे अभिव्यक्त करने वाला कोई एक नाम न होने से हमारा यह सुझाव है कि इसे सिर्फ **अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था** के नाम से व्यक्त किया जाना चाहिए।

अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था—क्या वह अन्य देशों मे भी अपनायी जा सकती है?

हमने अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था का वर्णन करते हुए वहुत गर्व से वताया है कि उसने क्या-क्या सफलताएँ प्राप्त की है और वह कैसे अपने आपको सुधारती और प्रगति की ओर ले जाती है। किन्तु क्या अन्य देश अमेरिका के इस अनुभव से कोई शिक्षा ले सकते है?

क्या यह प्रणाली सम्पूर्ण या आशिक रूप मे अन्य देशो मे भी अपनायी जा सकती है ?

अमेरिकी प्रणाली मे कुछ तत्व ऐसे है जो सभी आर्थिक प्रणालियो मे पाये जाते है और कुछ तत्व उसके अपने विशिष्ट तत्व हैं। एक ओर वह वहुत-से ऐसे बुनियादी मूल्यो और आकाक्षाओ को अभिव्यक्त करती है, जो समस्त मानव-जाति मे समान रूप मे पाये जाते है, और ऐसी आर्थिक विधियो को इस्तेमाल करती है जो ससार मे सभी जगह इस्तेमाल किये जाते है या किये जा सकते है। दूसरी ओर इन मूल्यो को मूर्त्त रूप प्रदान करने वाली विशिष्ट सस्थाएँ पश्चिमी समाज की; जिसमे वे विकसित हुई है, विशिष्ट सस्कृति और परम्पराओ से प्रभावित है। साथ ही ये सस्थाएँ अमेरिका की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियो से कुछ सीमाओ और सम्भावनाओ के दायरे मे भी वधी हुई हैं।

जो दूसरे राष्ट्र की स्वतन्त्रता, न्याय और जन-कल्याण के उन्ही मूल्यो को प्राप्त करना चाहते है, जिन्हे अमेरिकी लोग चाहते है, वे इन उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए अमेरिकी लोगो द्वारा अपनाये जा रहे अनेक रुखो और विधियो को अपनी परिस्थितियो के अनुसार ढालकर अपना सकते है। उदाहरण के लिए, वहुत-से ऐसे देश हैं जो अमेरिका की विचार और कर्म की स्वतन्त्रता और विविधता का आदर करते हैं। काम और कारीगरी, नये आविष्कार और उद्यम, वर्गीय भेद के वावजूद पारस्परिक सहायता और सहयोग, परम्परागत सिद्धान्त के वजाय व्यवहारिक अनुभव के आधार पर कार्य का निश्चय—इन सव के वारे मे अमेरिकी लोगो का जो रुख रहता है वह अन्य देशो के भी अनुकूल है और थोडा-वहुत उनके लोगों मे पाया भी जाता है। इसी प्रकार अमेरिका की उत्पादक तकनीकें और प्रवन्ध विधियाँ, अपनी कार्य-कुशलता के कारण आर्थिक सगठन के विभिन्न रूपो मे सारे संसार मे फैल रही है।

अमेरिका का अनुभव अन्य देशो के लिए खासकर दो कारणों से

बहुत महत्वपूर्ण है

1 वह यह सिद्ध करता है कि बधी-बधाई स्थिर राष्ट्रीय आय का अधिक लोगो मे पुर्नवितरण करने का प्रयत्न समूची जनता के आर्थिक कल्याण को साधने और समाज मे अधिक सामाजिक न्याय की स्थापना करने मे सफल नही हो सकता। इसके विपरीत तेज गति से आर्थिक समृद्धि को बढाना ही उसका अधिक अच्छा और सफल उपाय है।

2 वह यह भी सिद्ध करता है कि व्यक्ति की स्वतत्रता, अभिक्रम और आत्म-उत्तरदायित्व को बलिदान किये बिना भी काफी आर्थिक विकास किया जा सकता है।

वास्तव मे अमेरिकी समाज तीन अशत परस्पर विरोधी मानवीय आदर्शो—आर्थिक कल्याण, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता—मे समन्वय कर रहा है जो इतिहास मे अनुपम है। यह समन्वय बिलकुल पूर्ण कभी नही हो सकता, किन्तु फिर भी सयुक्त राज्य मे वह बहुत-से अन्य देशो की अपेक्षा कही अधिक हुआ है और भविष्य मे उसके और भी आगे बढ जाने की आशा है। यह समन्वय इतनी अधिक मात्रा मे हो सकता है, यह नि सन्देह समूचे मानव-समाज के लिए एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्देश है। यह हो सकता है कि दूसरे देशो को, जिनकी सस्कृतियाँ, परिस्थितियाँ और सम्भावनाएँ भिन्न है, अमेरिका मे प्रचलित प्राइवेट व्यवसाय के कुछ सगठनात्मक रूप अपनी परम्पराओ अथवा वर्त्तमान परिस्थितियो के अनुकूल प्रतीत न हो। इस सक्षिप्त विवरण मे हम यह नही बता सकते कि अलग-अलग परिस्थितियो मे कौन-से अलग-किस्म के आर्थिक सगठन होने चाहिएँ। उदाहरण के लिए एक ओर पश्चिमी सास्कृतिक परम्परा वाले अत्यधिक उद्योग-प्रधान देश के, और दूसरी ओर एक सर्वथा भिन्न सास्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कृषि-प्रधान देश के, आर्थिक सगठनो मे क्या अन्तर होना चाहिए। इसके अलावा, आबादियो मे द्रुत गति से हो रही वृद्धि और निरन्तर बढ रही आर्थिक उन्नति की आशाओ के कारण आज ससार के कुछ देशो को, जिनकी आबादी तो बहुत सघन है परन्तु विकास बहुत अपर्याप्त है, उतना आर्थिक

विकास कुछ दशको के भीतर ही कर लेना होगा, जितना कि सयुक्त राज्य ने एक शताब्दी मे किया। ऐसी परिस्थिति मे यह संभव है कि इन देशो की सरकारे आर्थिक विकास के लिए उससे कही अधिक अभिक्रम करे और उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले जितना कि सयुक्त राज्य की सरकार ने लिया।

इस प्रकार यह आवश्यक है कि अमेरिकी प्रणाली की उन विशेषताओ को, जो अन्य देशो की आवश्यकताओ और सभावनाओ के साथ सगत है, उसकी ऐसी विशिष्टताओ से अलग किया जाय जो उनके अनुकूल नही है। यह भेद न किये जाने के कारण ही अमेरिका मे और अन्य देशो मे अमेरिकी प्रणाली की अन्य देशो के लिए उपयोगिता के प्रश्न पर गलतफहमी पैदा हो जाती है। कुछ अमेरिकी लोगो का ख्याल है कि अन्य देश तभी काफी प्रगति कर सकते है, जब कि वे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की विशिष्ट किस्म की सस्थाओ और उसके रवैये और औद्योगिक विधियो को अपनाएँ। दूसरी ओर अनेक एशियाई और अफ्रीकी लोगो का खयाल है कि अमेरिकी अनुभव मे ऐसी कोई भी बात नही है जो उनकी सर्वथा भिन्न सस्कृतियो और परम्पराओ के साथ संगत होती हो। ये दोनो ही विचार समान रूप मे गलत हैं, क्योकि दोनो मे से कोई भी यह स्वीकार करके नही चलता कि अमेरिकी जनता इस शताब्दी मे मानव-समाज की प्रगति और कल्याण मे जो महत्त्वपूर्ण योग देती रही है, वह स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए उत्पादकता और रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विकसित किये गए रवैयों और तकनीको का एक अद्भुत सम्मिश्रण है।

यह सही है कि कम्युनिस्ट अधिनायकतन्त्र ने भी सोवियत संघ मे आर्थिक विस्तार को असाधारण तीव्र गति से बढाया है, पूंजी-निर्माण मे भारी वृद्धि की है और बहुत तेज रफ्तार से तकनीकी क्षेत्र मे उन्नति की है, और यह सम्भव है कि अन्तत. वह अन्य कम्युनिस्ट देशो मे भी वे सफलताएँ प्राप्त कर सके। लेकिन इसके लिए उसे केवल राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बलिदान ही नही करना पडा है, बल्कि

अपने उत्पादक साधनो को शस्त्रास्त्रो के निर्माण मे लगाना और जन-कल्याण को पूर्णत उपेक्षित भी करना पडा है। हमारा यह दृढ विश्वास है कि आतक और अन्याय का सहारा लिये बिना भी, सन्तुलित आर्थिक अभिवृद्धि सम्भव है और वह भी केवल औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशो मे ही नही, अन्य देशो मे भी।

सारांश

यदि ऐसा कोई एक विषय है, जो समूचे अमेरिकी इतिहास मे चाहे जितने परिवर्त्तन होने पर भी अपरिवर्त्तित रूप से चर्चा का विषय रहा हो तो वह सिर्फ यही है कि हैमिल्टन के आर्थिक प्रगति के विचार का जैफर्सन के स्वतन्त्रता और आत्म-उत्तरदायित्व के आदर्श के साथ समन्वय किया जाय।

अमेरिका ने आर्थिक क्षेत्र मे आशातीत प्रगति की है। आज हर आदमी अपनी आँखो से यह देख सकता है कि राष्ट्र की आय और दौलत मे वृद्धि हुई है, कारखाने और साधन बढे है। वह पुराने युग की और अन्य देशो की आय और दौलत के साथ अमेरिका की आज की आय और दौलत की तुलना कर सकता है। लेकिन प्रगति की इस प्रक्रिया मे जैफर्सन के स्वावलम्बन के आदर्श का बलिदान हुआ है या उसकी रक्षा हुई है, इसे आँकडो से नही नापा जा सकता। किन्तु हमने यह देखा है कि उद्योग, परिवहन और वित्त के क्षेत्रो मे बडी कम्पनियो के प्रभुत्व की आशकाओ को दूर करने और कृषि और छोटे व्यवसायो को सरक्षता देने के लिए अनेक आन्दोलन हुए हैं। इन आन्दोलनो का अमेरिकी कानून पर गहरा असर पडा है और 'आम जनता' पर एव व्यवसायियो, श्रमिको, कृषको और सरकार के वर्त्तमान रुखो पर उसका शायद उससे भी अधिक जबर्दस्त असर पडा है। जैफर्सन के आत्म-उत्तरदायित्व और स्वावलम्बन के आदर्श आज हमारे औद्योगिक समाज मे भी सच्चे अर्थों मे विद्यमान है।

जैफर्सन का यह विश्वास गलत था कि इन आदर्शो की भावना—

जिसे वह अमेरिका का सार कहता था—केवल पारिवारिक फार्मो और कारीगरो के छोटे-छोटे कारखानो मे ही रह सकती है। यह सही है कि जिस जमाने मे उद्यमी उद्योग सचालक यह दावा करते थे कि 'अपने निज के घर मे उन्हे खुद मालिक होने' का पूरा अधिकार है, यानी जिस युग मे उद्योग का अर्थ होता था मजदूरो का शोषण, आर्थिक असुरक्षा, गन्दी रिहायशी व्यवस्था और फलत. दुखपूर्ण पारिवारिक जीवन, उस जमाने मे कारखानो मे पारस्परिक सम्मान की भावना शायद ही सम्भव थी। पर आज वह जमाना नही रहा। आज आधुनिक टैकनोलॉजी और रहन-सहन और काम की आधुनिक परिस्थितियाँ श्रमिको के इतनी अनुकूल हैं कि वे समाज मे अपने स्थान के लिए गर्व अनुभव करते है, और अन्य सभी वर्गो के आदर के पात्र है।

लेकिन इस वात का कोई भरोसा नही है कि यह जैफर्सनवादी भावना, जो आज वहुत प्रबल है, गहरी और औद्योगिक युग के भावी विकास मे भी स्वत जीवित रहेगी। वर्त्तमान सफलताओ और उपलब्धियो ने यह साबित कर दिया है कि पारस्परिक सहयोग और आदर के साथ मिल कर काम करने वाले प्रवन्धको और कर्मचारियो मे यह भावना रह सकती है। वास्तव मे यह भावना सरकारी अधिकारियो मे भी विद्यमान है, जो यह अनुभव करते है कि उनका काम शासन करना नही, वल्कि समस्त जनता के सर्वसामान्य हित को साधना है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पूर्णत. सुनिश्चित न होने पर भी इस वात की वहुत सम्भावना है कि स्वावलम्वी व्यक्तियो को पूर्ण स्वतन्त्रता से काम के अवसर प्रदान करने वाला सप्राण लोकतन्त्र न केवल जीवित रहेगा, वल्कि औद्योगिक समाज के आगामी युग मे और भी शक्तिशाली वनेगा।

अमेरिकी समाज की अतीत और वर्त्तमान उपलब्धियाँ यह सिद्ध करती हैं कि अमेरिका के लोग तर्कवादी है, व्यावहारिक प्रयोजनवादी है और साथ ही आशावादी भी है। यद्यपि ये गुण अमेरिका के भविष्य के लिए वहुत आशा पदा करते हैं तो भी यह असभव नही है कि इन गुणो का उपयोग गलत रीति से किया जाय। एक ओर यह सम्भव है

कि लोग बडे-बडे मधुर स्वप्न लेने लगे, यह मानने लगें कि सभी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएँ मानवीय तर्क-बुद्धि और 'सामाजिक इजिनीयरी' के उपयोग से हल हो सकती है। और दूसरी ओर यह भी असम्भव नही है कि लोग अब तक की उपलब्धियो मे ही पूर्ण सन्तोष मान कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएँ और कोई भी नया परिवर्त्तन और सुधार करने की आवश्यकता अनुभव न करे। अमेरिकी लोगो के लिए इन दोनो चरम रुखो मे से किसी को भी अपनाना घातक होगा।

पिछले दो दशको मे मानव और समाज के स्वरूप और उनकी सम्भावनाओ के बारे मे जो नई और अधिक गहरी अवधारणाएँ विकसित हुई है, उन्होने यह साबित कर दिया है कि इन दोनो चरम मनोवृत्तियो से बचना असम्भव नही है। इन अवधारणाओ मे ये मान्यताएँ विद्यमान है कि मानवीय तर्क-बुद्धि शक्तिशाली होने पर भी सर्वशक्ति-सम्पन्न नही है, मानवीय प्रकृति मे असीम क्षमताएँ है, किन्तु वे अच्छाई की ओर ही नही, बुराई की ओर भी जा सकती है, और समाज को उन्नत किया जा सकता हे, भले ही उसे पूर्णता के स्तर तक कभी न पहुँचाया जा सकता हो। पूर्ण और अन्तिम विजय को असम्भव मानने पर भी उसके लिए उद्योग करना ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा और मानव-कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सबसे अच्छी गारन्टी है।

परिशिष्ट तालिकाएँ

परिशिष्ट तालिका-1

आर्थिक वृद्धि, 1929-1960 (डालर 1960 के मूल्यों के अनुसार)

वर्ष	राष्ट्रीय आय (अरब डालरो मे)	कुल असैनिक कर्मचारी (लाखो मे)	राष्ट्रीय आय प्रति कर्मचारी (डालरो मे)	व्यक्तिगत उपभोग व्यय (अरब डालरो मे)	आवादी (लाखो मे)	उपभोग व्यय (प्रति व्यक्ति)
1929	207·1	476	4351	141·3	1219	1159
1930	187 6	455	4123	132 9	1232	1079
1931	173 4	424	4091	128·8	1241	1037
1932	147·5	389	3792	117 2	1249	938
1933	144 1	388	3714	114·4	1257	910
1934	158 0	409	3866	120 3	1265	951
1935	173·2	423	4095	127 7	1274	1003
1936	197 9	444	4457	140 6	1282	1097
1937	208 2	463	4497	145 6	1290	1129
1938	198 8	442	4498	143·1	1300	1101
1939	215 2	458	4699	151·1	1310	1153
1940	233·	475	4922	159·2	1321	1205
1941	272·6	504	5409	169 7	1334	1272
1942	311·4	538	5788	166·1	1349	1232
1943	350 8	545	6437	170 5	1367	1247

1944	376 3	540	6969	176 6	1384	1276
1945	369 1	528	6991	188 9	1399	1350
1946	321 7	553	5817	211·6	1414	1497
1947	321 1	578	5555	215·3	1441	1494
1948	333 6	591	5645	219 4	1466	1496
1949	334 2	584	5723	225 0	1492	1508
1950	362 3	597	6069	238 7	1517	1574
1951	392 0	608	6447	240 8	1544	1560
1952	406 8	610	6669	247 0	1570	1573
1953	425 5	619	6874	258 9	1596	1622
1954	416 8	609	6844	262 3	1624	1615
1955	449 7	629	7149	282 0	1653	1706
1956	459 2	647	7097	291·3	1682	1732
1957	467 8	650	7197	299 1	1712	1747
1958	459 9	640	7183	301·0	1741	1735
1959	490 6	656	7479	319 3	1771	1803
1960	504 4	667[1]	7562	328 9	1807	1820

1 अलास्का और हवाई भी शामिल हैं (इन दोनों राज्यों को अलग कर देने पर 664)।

परिशिष्ट तालिका-2

कुल राष्ट्रीय आय—स्वतन्त्र संसार के देशों का संक्षिप्त विवरण
(सन् 1959 मे चालू बाजार मूल्यों के अनुसार डालरों में)

	कुल राष्ट्रीय आय (लाख डालरो मे)	राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति (डालरो मे)	1959 के मध्य मे आबादी (लाखो मे)
पश्चिमी यूरोप (ग्रीस और टर्की सहित) ··	29,37,580	838	3,507
अफ्रीका (मिस्र को छोडकर ······	2,76,070	125	2,210
मध्य पूर्व (ग्रीस और टर्की को छोडकर और मिस्र को मिला कर)······	1,39,970	188	745
दक्षिण एशिया······	3,89,470	72	5,413
सुदूर पूर्व······	5,44,250	167	3,260
ओशेनिया·····	1,82,500	1200	152
लैटिन अमेरिका··· ··	5,65,310	285	1,986
संयुक्त राज्य			
महाद्वीपीय संयुक्त राज्य······	48,21.000	2722	1,771
अन्य संयुक्त राज्यीय प्रदेश··· ·	38.560	1205	32
कनाडा···	3,45.930	1983	174
शेष उत्तरी अमेरिका······	130	371	1
कुल योग ···	1,02,40,770	532	19,250

1 1,00,000 से कम

परिशिष्ट तालिका-3

सन् 1909 से 1959 तक विभिन्न वर्षों का प्रति मानव घंटा उत्पादन

(1909=100)

वर्ष	कुल	कृषि	कृषि-भिन्न	निर्माण उद्योग
1909 ·· ···	100 0	100 0	100 0	100 0
1919 ·······	112 8	104 8	114 0	115 0
1929·········	140 3	114 8	142 0	198 1
1938 ···· ··	171 7	138 9	176 5	232 5
1947-49 ·· ·	209 6	184 5	205 8	280 1
1956·········	263 9	252 0	253·9	356 0
1959 · ···	305 6	342 6	281 1	385 5

परिशिष्ट तालिका-4

विभिन्न उद्योगो मे 1947 से 1950 तक प्रति मानव-घण्टा उत्पादन में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत वार्षिक)

निर्माण उद्योग	
डिब्बा वन्द खाद्य पदार्थ	4·2
सीमेंट	4·5
चीनी मिट्टी की वस्तुएँ	2 2
कागज और लुगदी	3·7
धातु प्रद्रावरण और शोधन (ताँबा, सीसा और जस्त)	4·0
रेयन और कृत्रिम वस्त्र	9·6
इस्पात	3·0
खनिज उद्योग	
ऐन्थ्रेसाइट कोयला	6·3
बिट्यूमिनी कोयला	5·8
ताँबा	2·8
लोहा	—·5
सेवाएँ	
रेल परिवहन (यातायात)	4·3
टेलीग्राफ	—1·2

परिशिष्ट तालिका-5

सर्वाधिक आय वाले 5 प्रतिशत अमेरिकी परिवारों और आय-अर्जकों की स्वायत्त आय

वर्ष	आय-अर्जक	परिवार
1914	32 0	
1920	24 0	
1929	33 8	
1939	26 8	
1950	15 8	19 2
1952	15 8	18 2
1058		17 8
1959		17 8

परिशिष्ट तालिका-6

संघीय व्यक्तिगत आय-कर देने से पूर्व और पश्चात् औसत परिवार की व्यक्तिगत आय और पूर्णकालिक कर्मचारी की वार्षिक औसत उपार्जित आय

		प्रति परिवार या परिवार-रहित व्यक्ति औसत व्यक्तिगत आय				औसत वार्षिक आय प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी
		कर देने से पूर्व		कर देने के पश्चात्		
वर्ष	परिवार और परिवार-रहित के व्यक्ति (दस लाखो मे)	चालू मूल्यो हिसाब से (डालर)	1960 के मूल्यों के हिसाब से (डालर)	चालू मूल्यो के हिसाब से (डालर)	1960 के मूल्यो के हिसाब से (डालर)	चालू मूल्यो के हिसाब से (डालर)
1929	36 1	2340	4190	2320	4160	1405
1947	44 7	4130	5370	3720	4840	2589
1948	46 3	4350	5350	4010	4940	2795
1949	47 8	4170	5180	3860	4800	2851
1950	48 9	4440	5440	4070	4980	3008
1951	49·5	4900	5630	4420	5070	3231
1952	50 2	5120	5760	4570	5140	3414

1953	50·5	5390	6000	4810	5350	3587
1954	51 2	5360	5910	4840	5340	3670
1955	52 2	5640	6190	5090	5590	3847
1956	52 8	6010	6490	5400	5830	4036
1957	53 6	6240	6550	5610	5880	4205
1958	54 6	6290	6470	5670	5840	4347
1959	55 3	6610	6730	5930	6040	4553
1960	55 9	6900	6900	6170	6170	4734

परिशिष्ट तालिका-7

विभिन्न उद्योगो में औसत प्रतिघंटा आय, 1939-1960

	डालर प्रतिघण्टा		वृद्धि के सूचक अक	
	1939	1960	1939	1960
कृषि	0·16	0 97	100	606
वस्त्र	0 46	1 62	100	352
लकडी का सामान	0 49	1·99	100	406
फरनीचर	0·52	1·88	100	361
खुदरा व्यापार	0·54	1·78	100	330
कागज और सम्बद्ध उत्पादन	0 59	2·32	100	393
रासायनिक पदार्थ और सम्बद्ध उत्पादन	0 65	2·55	100	393
मशीनरी (बिजली के यन्त्रो को छोडकर)	0 75	2·60	100	347
टेलीफोन	0 82	2 32	100	283
बिट्यूमिनी कोयला खनन	0 89	3·26	100	367
मोटर गाडियाँ	0 93	2·83	100	304
उपभोक्ता मूल्य सूचक अक			100	213

परिशिष्ट तालिका-8

विभिन्न राष्ट्रो मे कितने मिनट की मजदूरी से खाद्य पदार्थों की एक नियत मात्रा खरीदी जा सकती है

वस्तु	सयुक्त राज्य अक्टूबर, 58	फ्रास (पेरिस) अक्टू , 58	जर्मनी अक्टू ,58	इटली अक्टू 58	रूस (मास्को) 15 अगस्त, 1959
गेहूँ का आटा (एक पौड)		15	10	17	अज्ञात
डबलरोटी सफेद (एक पौड)	6	12	13	17	9
गोमास (एक पौंड)	29	153	62	166	82
मछली (एक पौड)	13	32	33	144	अज्ञात
मक्खन (एक पौड)	21	117	81	172	184
दूध (एक क्वार्ट)	7	15	10	23	31
अण्डे (एक दर्जन)	12	108	72	120	144
सेब (एक पौंड)	4	19	10	15	अज्ञात
आलू (एक पौड)	1	5	2	6	12 (जनवरी, 61)
मार्गरीन (एक पौड)	8	42	24	74	अज्ञात
चीनी (एक पौड)	3	15	15	30	64

नोट—हर देश में अलग-अलग खाद्य पदार्थ का अलग-अलग महत्त्व है, इसलिए उसी दृष्टि से इन तुलनाओं से रहन-सहन के स्तर को आंका जाना चाहिए ।

परिशिष्ट तालिका-9

संयुक्त राज्य की गोरी आबादीमे देशजो और विदेशजों की संख्या, 1870—1950

	कुल	देशज और विदेशज कुल विदेशी	विदेशज	विदेशी या देशी-विदेशी मिश्रित माता-पिता से उत्पन्न देशज
		(हजारो मे)		
1870	33589	10818	5494	32
1880	43403	14835	6560	8275
1890	55101	20626	9122	11504
1900	66809	25860	10214	15646
1910	81732	32243	13346	18898
1920	94821	36399	13713	22686
1930	110287	39886	13983	25902
1940	118702	34577	11419	23058
1950	134942	33751	10161	23589
		(कुल गोरी आबादी का प्रतिशत भाग)		
1870	100 0	32.2	16 4	15·9
1880	100 0	34·2	15 1	19·1
1890	100-0	37 4	16·6	20 9
1900	100·0	38·7	15 3	23·4
1910	100·0	39·5	16·3	23 1
1920	100·0	38 4	14·5	23·9
1930	100·0	36·2	12·7	23·5
1940	100 0	29 1	9 6	19 5
1950	100 0	25.0	7·5	17·5

परिशिष्ट तालिका-10

शिक्षा की स्थिति

		शिक्षा संस्थाओ मे भर्ती छात्र, 1957-58		
	अशिक्षित (प्र श.)[1]	सख्या[2] (दस लाखो मे)	कुल आवादी का प्रतिशत भाग	5 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु की आवादी का प्रतिशत भाग
सयुक्त राज्य	2 (1960)	43·2	24	88
पश्चिमी जर्मनी	1–2 (1950)	9·8	19	72
जापान	2 (1950)	21 8	23	72
वेल्जियम	3 (1947)	1·6	18	76
ग्रीस	26 (1951)	1 2	15	56
फिलिपाइन्स	38 (1948)	4 4	18	51
पुर्त्तगाल	42 (1950)	1 0	10	42
इक्वेडर	44 (1950)	0 56	14	अज्ञात
थाईलैंड	46 (1947)	3 7	17	45
ब्राजील	51 (1950)	7 1	11	27
टर्की	65 (1950)	2 6	10	28
स अरब गणराज्य (मिस्र)	75 (1947)	2·8	11	33
भारत	82 (1951)	33 7	8½	अज्ञात
नाइजीरिया	89 (1950)	2 7	8	अज्ञात
हाइटी	89 (1950)	23	7	18

1. इसमें दस वर्ष या इससे अधिक आयु के वे सभी व्यक्ति शामिल किये गए हैं जो लिख या पढ नहीं सकते।

२ इसमें वे सभी छात्र शामिल किये गए है जो पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, टैकनिकल, अध्यापक प्रशिक्षण या माध्यमिकोत्तर किसी भी संस्था और कक्षा में भर्ती हों।

परिशिष्ट तालिका-11

काम बन्द होने के कारण प्रति-कर्मचारी[1] वर्बाद दिन

(वार्षिक औसत, 1950-1954)

सयुक्त राज्य[2]	1·4	कनाडा	·7
फिन लैण्ड	1 8	वेलजियम	·6
न्यूजीलैण्ड	1·2	पश्चिमी जर्मनी	1
आस्ट्रेलिया	·9	नार्वे	1
भारत	9	स्वीडन	·1
इटली	·9	ब्रिटेन	1
फ्रास	·8	डेनमार्क	3
आयर लैण्ड	8	नीदर लैण्डस	3
जापान	8	दक्षिण अफ्रीका	3

1 केवल खनन, वस्तु-निर्माण, भवन-निर्माण और परिवहन उद्योगों के आकडे ।

2. 1958-1960 में सयुक्त राज्य के वर्बाद दिनों का औसत 1·0 दिन था।

3. ·05 दिन प्रति-कर्मचारी से भी कम ।

परिशिष्ट तालिका-12

अमेरिकी निर्माता उद्योगों की कम्पनियों को कर अदा करने से पूर्व मुनाफे की दर (साधारण शेयरों पर प्रतिशत मुनाफा)

वर्ष	2 50 लाख डालर से कम परिसम्पत्तियों वाली कम्पनियाँ	2 5 लाख से 10 लाख डालर तक की परिसम्पत्तियों वाली कम्पनियाँ[1]	एक अरब डालर या इससे अधिक परिसम्पत्तियों[2] वाली कम्पनियाँ
1960	अज्ञात	11 9	17 6
1959	अज्ञात	15 5	!8 3
1958	8 3	11 4	16·3
1957	14 6	14·9	19 5
1956	19 9	15·4	22 0
1955	10 6	16 3	25 9
1954	7 8	12 5	20 7
1953	13 2	16 1	24·5
1952	17 0	12 8	23 0
1951	17 3	22 0	28 8
1950	16 7	22 9	28 6
1949	9 7	14·2	20 3
1948	16 1	23 5	24·7

1. सन् 1959 के बाद इस वर्ग में 10 लाख डालर से कम परिसम्पत्तियों वाली सभी कम्पनियाँ आ जाती हैं।

2. सन् 1957 से पहले के आंकड़े 10 करोड़ डालर या इससे अधिक की परिसम्पत्तियों वाली सभी कम्पनियों के हैं।

परिशिष्ट तालिका-13

विज्ञान और टैकनोलॉजी की उन्नति

वर्ष	असैनिक श्रमिक सख्या (हजारो मे)	कुल (हजारो मे)	असैनिक वैज्ञानिक और इजिनीयर श्रमिक शक्ति का प्र. श भाग
'930	48600	261	·5
1940	52900	378	·7
1950	60000	740	1 2
1956	67500	950	1·4
1959	69400	1100	1·6

परिशिष्ट तालिका-14

अनुसन्धान और विकास के कामों मे लगे वैज्ञानिक और इंजिनीयर

उद्योग	मुख्यत अनुसन्धान और विकास मे लगे वैज्ञानिक और इंजिनीयर		
	जनवरी, 1954	जनवरी, 1959	जनवरी, 1960
सब उद्योगो मे कुल संख्या	**157300**	**277100**	**301000**
खाद्य तथा तत्सम्बन्धी उत्पादन	4000	3700	3700
कपडा और तैयार वस्त्र	1800	1300	1300
कागज और सम्बद्ध उत्पादन	1700	2500	2800
रासायनिक पदार्थ और सम्बद्ध उत्पादन	21500	33900	39000
पेट्रोलियम उत्पादन	6800	9500	10000
पत्थर, चीनी मिट्टी और काच का सामान	2100	2700	2100
धातु उद्योग	3700	5900	6200
धातु निर्मित सैनिक-असैनिक सामान	4600	18600	18500
मशीनरी (बिजली का सामान छोड कर	16300	26900	29000
बिजली की मशीनें	28300	52600	61000
विमान और उनके पुर्जे	27600	60400	64000
वैज्ञानिक और अन्य उपकरण	9100	12300	13000

अन्य वस्तु-निर्माण उद्योग	20400	23800	24500
भवन आदि का निर्माण	1600	1900	2000
परिवहन और अन्य सार्वजनिक सेवाएँ	1200	2300	2600
इंजिनीयरिंग और वस्तु-कला सेवाएँ	6200	7200	8000
अन्य निर्माणेतर उद्योग	6200	11300	126000

परिशिष्ट तालिका-15

अनुसन्धान और विकास के लिए विभिन्न स्रोतो से व्यय की गई राशियो का विवरण (लाख डालरो में) 1959 60

अनुसन्धान और	अनुसन्धान और विकास के काम करने वाले					
विकास के लिए व्यय की गई राशियो के स्रोत	सघीय सरकार	उद्योग	कालेज और विश्व-विद्यालय	लाभ न लेने वाले अन्य सस्थान	कुल	प्रतिशत
सघीय सरकार	18400	54200	7000	1400	81000	64
उद्योग	—	40200	500	500	41200	33
कालेज और विश्वविद्यालय	—	—	2100	—	2100	2
लाभ न लेने वाले अन्य सस्थान	—	—	400	600	1000	1
कुल योग	18400	94400	10000	2500	125300	100
प्रतिशत विभाजन	15	75	8	2	100	

परिशिष्ट तालिका-16

मूल अनुसन्धान के लिए विभिन्न स्रोतो से किये गए व्यय का विवरण (लाख डालरों मे) 1959 60

मूल अनुसन्धान के लिए किये गए व्यय के स्रोत	मूल अनुसन्धान करने वाले					
	सघीय सरकार	उद्योग	कालेज और विश्व-विद्यालय	लाभ न लेने वाले अन्य सस्थान	कुल योग	प्रतिशत
संघीय सरकार	2250	700	3050	400	6400	56
उद्योग	—	2740	200	60	3000	26
कालेज और विश्व-विद्यालय	—	—	1400	—	1400	12
लाभ न लेने नाले अन्य मस्थान	—	—	350	340	690	6
कुल योग	2250	3440	5000	800	11490	100
प्रतिशत विभाजन	19	30	44	7	100	

परिशिष्ट तालिका-17

संयुक्त राज्य मे प्राइवेट विदेशी निवेश—1914 (लाख डालरो मे)

	निवेश के प्रकार			
स्रोत	रेले	अन्य अमेरिकी सिक्यूरिटियाँ	विदेशियो द्वारा नियंत्रित व्यवसाय	कुल
ब्रिटेन	28000	8500	6000	42500
जर्मनी	3000	3500	3000	9500
नीदरलैड्स	3000	2000	1350	6350
फ्रास	2900	750	450	4100
कनाडा	1300	950	500	2750
अन्य	3500	1400	800	5700
	41700	17100	12100	70900

परिशिष्ट तालिका-18

संयुक्त राज्य में ससार के अन्य भागों की विदेशी परिसम्पत्तियाँ और निवेश—1960 दस लाख डालरों में

	कुल	पश्चिमी यूरोप	कनाडा	लैटिन अमेरिका	अन्य	अन्तर्राष्ट्रीय
संयुक्त राज्य मे कुल विदेशी परिसम्पत्ति और निवेश	44682	24048	6196	3726	4837	4965
दीर्घकालिक	18438	13004	3303	1153	858	129
सीधा निवेश	6931	4713	1949	130	139	—
कम्पनी शेयर	9302	6836	1209	728	490	39
कम्पनियो, राज्य सरकारो और म्युनिसिपैलिटियो के बॉड	648	449	5	75	38	81
अन्य	1557	1006	140	220	191	—
अल्पकालिक परिसम्पत्तियाँ और सयुक्त राज्य सरकार की देनदारियाँ	26244	11044	2893	2573	3979	4845

प्राइवेट	12113	4893	1981	2211	2709	319
स० रा० सरकार की देनदारियाँ	14131	6151	912	362	1270	4526
दीर्घकालिक	2276	803	327	141	114	891
अल्पकालिक[1]	11855	5348	585	221	1156	3635

1 इसमें विदेशियों के पास जमा अमेरिकी मुद्रा भी शामिल है जो 1959 में 9060 लाख डालर और 1960 में 9100 लाख डालर थी। ये दोनों राशियां सभी क्षेत्रों का कुल योग हैं।

परिशिष्ट तालिका-19

संयुक्त राज्य का अदायगी सन्तुलन, 1956-1960 (दस लाख डालरों में)

	कैलेंडर वर्ष 1956	1957	1958	1959	1960
क. स० राज्य सरकार द्वारा किये गए लेन-देन					
1. सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्यात	4912	4921	4667	4302	अज्ञात
क. सैनिक अनुदान	2579	2435	2281	1988	अज्ञात
ख. फालतू कृषि उत्पादनों की बिक्री	1078	1233	1023	925	1182
ग अन्य अनुदान और ऋण	1255	1253	1363	1389	1507
सैनिक अनुदान को छोड़कर शेष कुल योग	2333	2486	2386	2314	2689
2. अन्य प्राप्तियाँ	954	1374	1289	1800	1431
क.. ऋण वापसी	479	659	544	1013	605
ख. ब्याज	194	205	307	346	346
ग. सैनिक प्राप्तियाँ	158	372	296	297	326
घ. अन्य	123	138	142	144	154
3. सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अदायगियाँ	—8355	—8833	—8824	—8072	अज्ञात
क. सैनिक अनुदान	—2579	—2435	—2281	—1988	अज्ञात
ख. विदेशों में सैनिक व्यय	—2935	—3165	—3412	—3090	—3034

ग आर्थिक सहायतानुदान	—1733	—1616	—1616	—1623	—1651
घ दीर्घकालिक पूजी	— 545	— 993	—1176	—1018	—1174
ङ विदेशी मुद्रा कोष मे वृद्धि	— 563	— 624	— 339	— 353	— 537
सैनिक अनुदान को छोडकर कुल योग	—5776	—6398	—6543	—6084	—6396
4. अन्य सरकारी अदायगियाँ	— 553	— 670	— 626	— 819	— 845
क सरकार की असैनिक कार्रवाइयाँ	— 264	— 310	— 305	— 322	— 307
ख विदेशियो को दिया गया व्याज	— 154	— 201	— 139	— 281	— 332
ग पेशन और अन्य अन्तरण	— 135	— 159	— 182	— 216	— 206
5 कुल प्राप्तियाँ					
क कुल योग	5866	6295	5956	6102	अज्ञात
ख सैनिक अनुदानो को छोडकर	3287	3860	3675	4114	4120
6 कुल अदायगियाँ					
क कुल योग	8908	9503	9450	8891	अज्ञात
ख. सैनिक अनुदानो को छोडकर	6329	7069	7169	6903	7241
सरकारी खाते का सन्तुलन	—3043	—3208	—3494	—2789	—3121

ख. लेखबद्ध प्राइवेट
संयुक्त राज्यीय लेन देन

1. वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	20897	23532	20194	20363	23631
क. व्यापारिक सामान का निर्यात	15016	16904	13877	13911	16722
ख. सेवाएँ	5851	6628	6317	6452	6909
2. वस्तुओं और सेवाओं का आयात	16476	07247	17197	19867	19630
क. व्यापारिक सामान का आयात	12804	13291	12951	[illegible]	14717
ख. सेवाएँ	3672	3956	4246	4552	4913
3 सामान और सेवाओं का सन्तुलन	+4421	+6285	+2997	+ 496	+ 400
क. सामान का सन्तुलन	+2242	+3613	+ 926	—1404	+ 200
ख. सेवाओं का सन्तुलन	+2179	+2672	+2071	+1900	+ 199
4. संयुक्त राज्य की प्राइवेट पूँजी	—2990	—3175	—3844	—2301	— 352
5. प्राइवेट (निजी) तौर पर विदेशों को भेजी गई रकमें	— 530	— 543	— 540	— 563	— 61
प्राइवेट (गैर सरकारी) सन्तुलन	+ 901	+2567	— 387	—2368	— 137
ग. संयुक्त राज्य सरकार की सिक्यूरिटियों को छोड़कर अन्य वस्तुओं में संयुक्त राज्य में लगी विदेशी पूँजी	+ 530	+ 361	+ 24	+ 548	+ 327
घ. भूल चूक	+ 643	+ 748	+ 380	+ 783	+ 905
ङ. कुल घाटा या लाभ	— 968	+ 468	—3477	—3826	—3836

परिशिष्ट तालिका-20

राष्ट्र का आर्थिक बजट—1929, 1960 और 1970 (संभावित)

(1960 के मूल्यों के हिसाब से अरब डालरों में)

आर्थिक वर्ग	1929 प्राप्तियाँ	1929 व्यय	1929 घाटा या लाभ	1960 प्राप्तियाँ	1960 व्यय	1960 घाटा या लाभ	1970 प्राप्तियाँ	1970 व्यय	1970 घाटा या लाभ
उपभोक्ता									
स्वायत्त व्यक्तिगत आय	83·1	—	—	351·8	—	—	542·0	—	—
व्यक्तिगत उपभोग व्यय	—	79 0	—	—	328·9	—	—	495 9	—
व्यक्तिगत बचत	—	—	+4·1	—	—	+22 9	—	—	+46 1
व्यवसायी									
कुल प्रतिधारित (रिटेण्ड) आय	11·5	—	—	51·7	—	—	78 1	—	—
कुल निजी आन्तरिक निवेश	—	16·2	—	—	72·4	—	—	120 1	—
अतिरिक्त निवेश (—)	—	—	–4 7	—	—	–20·7	—	—	–4 ·0
अन्तर्राष्ट्रीय									
शुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय	—	·7	–·7	1·5	3·0	–1·5	0·8	5·7	–4·9

सरकार (संघीय, राज्यीय और स्थानीय									
कर या अन्य प्राप्तियाँ	11·2	—	—	139·1	—	—	217·9	—	—
अन्तरण, व्याज और अनुपूर्त्तियो की घटाई जाने वाली राशि	1·7	—	—	37·1	—	—	51·0	—	—
शुद्ध प्राप्तियाँ	9 5	—	—	102·0	—	—	166 9	—	—
कुल सरकारी व्यय	—	10·2	—	—	137 2	—	—	217·1	—
अन्तरण, व्याज और अनुपूर्त्तियो की घटाई जाने वाली राशि	—	1 7	—	—	37·1	—	—	51·0	—
शुद्ध सरकारी व्यय	—	8·5	—	—	100 1	—	—	166 1	—
अधिशेष (+)	—	—	+1·0	—	—	+1·9	—	—	+0 8
आकड़ो की भूलचूक	+·3	—	+·3	−2 6	—	−2 6	—	—	—
कुल राष्ट्रीय आय-व्यय	104 4	104 4	—	504·4	504·4	—	787 7	787·7	—

परिशिष्ट तालिका-21

राष्ट्र का मुख्य-मुख्य वर्गों का व्यय, 1960 (अरब डालरो मे)

मद	व्यय	कुल
1. बुनियादी उपभोग्य वस्तुएं		
क खाद्य	70 2	
ख वस्त्र	31 8	
ग आश्रय (मकान)	42 2	
घ घरेलू व्यय	17·2	
कुल योग		161·4
2. उपभोक्ताओं की अन्य आवश्यकताएँ		
क. घरेलू फरनीचर आदि	28 7	
ख व्यक्तिगत व्यावसायिक सेवाएँ	20 6	
ग व्यक्तिगत देखभाल	5 2	
कुल योग		54 5
3 परिवहन		
क नई और पुरानी कारो की खरीद	15 8	
ख. गाडियो के रख रखाव और सचालन का व्यय	21 4	
ग. स्थानीय या नागरिक परिवहन गाडियो की खरीद	3 5	
कुल योग		40·7
4 उपभोग्य विलास और अर्ध-विलास सामग्री		
क सिगरेट और शराब आदि	17 3	
ख टेलीफोन आदि सचार साधन	8 4	
ग. खेल-खिलौने	4 5	

घ. सिनेमा नाटक आदि	2·0	
ङ. अन्य मनोरंजन साधन	4 5	
च. विदेश यात्रा और विदेशों को प्रेषित धन	3·0	
छ जेवर और घड़ियाँ	2 1	
कुल योग		41 8
5. शिक्षा		
क प्राइवेट व्यय	4 5	
ख सरकारी व्यय	18 7	
कुल योग		23.2
6. अनुसन्धान और विकास		
क. राष्ट्रीय सुरक्षा (सैनिक)	7 2	
ख अन्य सरकारी अनुसन्धान	1·3	
ग प्राइवेट अनुसन्धान	4 5	
कुल योग		13 0
7. चिकित्सा और स्वास्थ्य		
क प्राइवेट व्यय	21 3	
ख. सरकारी व्यय	6 3	
कुल योग		27 6
8. प्राइवेट धार्मिक और जन-कल्याण		4 7

9. प्राइवेट पूंजी निवेश		
क उत्पादकों की मशीनरी आदि	27 5	
ख रिहायशी निर्माण	21 1	
ग गैर-रिहायशी भवन	19·6	
घ व्यावसायिक वस्तुओं (इन्वेंटरी) मे परिवर्तन	4·2	
कुल योग		72 4
10 राष्ट्रीय रक्षा व्यय (अनुसन्धान को छोड़कर)		40·4
11 अन्य सरकारी व्यय		
क. सडक निर्माण और परिवहन	9 9	
ख. सार्वजनिक सेवाएँ (बिजली, पानी और डाक सेवा आदि)	1 0	
ग. अन्य सार्वजनिक सेवाएँ	12 5	
कुल योग		23·4
12. शुद्ध विदेशी निवेश		1 5
कुल राष्ट्रीय व्यय		504 4

परिशिष्ट तालिका-22

विभिन्न देशो मे साभाजिक सुरक्षा व्यय—1956-1957
(राष्ट्रीय आय का प्रतिशत भाग)

देश	प्रतिशत
सयुक्त राज्य अमेरिका	6·0%
पश्चिमी जर्मनी	20 8%
फ्रास	18 9%
वेल्जियम	16·3%
इटली	15 2%
स्वीडन	12 9%
ब्रिटेन	12 1%
डेनमार्क	12 0%
यूगोस्लाविया	10 3%
चिली	9 7%
आस्ट्रेलिया	9 1%
कनाडा	8·7%
स्विट्जर लैण्ड	8· %
पोलैण्ड	7 7%
जापान	5 8%
ग्वाटेमाला	3 1%
भारत	1 0%

परिशिष्ट तालिका-23

कुल राष्ट्रीय आय मे से समाज-कल्याण व्यय का प्रतिशत भाग (1889-90 से 1958-59 तक विभिन्न वर्षों का विवरण)

वित्तीय वर्ष	राष्ट्रीय आय (अरब डालरो मे)	कुल राष्ट्रीय आय मे से समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों पर प्रतिशत व्यय						
		कुल	सामाजिक बीमा	सरकारी सहायता	स्वास्थ्य और चिकित्सा	अन्य जन कल्याण	भूतपूर्व सैनिको का पुनर्वास	शिक्षा
1889-90	13 0	2 4	[1]	0 3[2]	0 1	[2]	0 9	1 1
1912-13	39 9	2 5	[1]	·3[2]	4	[2]	5	1 3
1928-29	101 6	4 2	0 3	5[2]	·5	[2]	5	2 4
1934-35	68 7	9 8	6	4 4	8	2	7	3 2
1939-40	95 9	9 3	1 3	3 8	7	·1	·6	2 9
1944 45	212 5	4 2	6	5	·9	·1	·4	1 6
1949-50	264 0	8 7	1 8	9	·9	2	2 5	2 5
1954-55	377 5	8 5	2 6	·8	8	·2	1 2	3 0
1956-57	432 8	9 0	2 9	8	8	2	1 1	3 2
1957-58	438 9	10 2	3 6	·8	8	2	1 1	3 5
1958 59	464 0	10 7	3 9	9	9	2	1 1	3 6
1959-60	494 6	10 8	3 9	8	9	·3	1 0	3 8

1 0 05 प्रतिशत मे कम।

2. इसमें सरकारी सहायता से किये गए जन-कल्याण कार्यक्रम भी शामिल है।

परिशिष्ट तालिका-24

आर्थिक विकास की संभावनाएँ, 1960-70

	वास्तविक 1960	सम्भावित 1970
		(दस लाख मे)
आबादी	180 0	213 8
कुल श्रम शक्ति	73 1	86·6
सशस्त्र सेना	2 5	2 3
असैनिक श्रम शक्ति	70 6	84·3
बेकार व्यक्ति	3 9	3·4
रोजगार पर लगे असैनिक व्यक्ति	66·7	80 9
प्राइवेट	59 7	72·3
कृषि	5 7	5·0
कृषि-भिन्न	54 2	67·3
सरकारी	6 8	8·6
		(दस लाख डालरो मे)
कुल राष्ट्रीय उत्पादन (1960 के मूल्यो मे)	504·4	787·8
प्राइवेट	457·1	717·8
कृषि	21·7	19·5
कृषि-भिन्न	435·4	698·3
सरकारी	47·3	70·0
औसत साप्ताहिक काम के घटे		
प्राइवेट	40·5	38·0
कृषि	45·5	40·9
कृषि-भिन्न	40·0	37·8

		(डालरों में)
प्राइवेट राष्ट्रीय उत्पादन प्रति मानव घण्टा (1960 के मूल्यों के अनुसार)	3 73	5 16
कृषि	1·60	1·84
कृषि-भिन्न	3 95	5·28
औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक (1957=100)	108	175
उपयोगी सेवाएँ	124	26
खनिज	97	153
निर्माण	108	172
कृषि-उत्पादन का सूचक अंक (1957=100)	113	148

परिशिष्ट तालिका-25

राष्ट्रीय आय और व्यय—1960 और 1970 (संभावित)

(1960 के मूल्यों के हिसाब से अरब डालरों में)

	1960	1970 (1)	1970 (2)	1970 (3)
कुल राष्ट्रीय आय	504 4	787 7	787 7	819 5
राष्ट्रीय रक्षा व्यय	45·6	56 4	32 6	86 4
व्यक्तिगत उपभोग व्यय	328·9	495·9	509 0	510 7
प्राइवेट आन्तरिक (देशी) निवेश	72·4	120 1	120·1	118 6
शुद्ध निर्यात	3·0	5 7	5 7	5·7
सरकार की असैनिक खरीद	54·5	109 6	120 3	98 1

(1) बशर्ते कि शस्त्रास्त्रों और सेना के व्यय में कोई कमी न हो।
(2) बशर्ते कि शस्त्रास्त्रों और सेना के व्यय में एक तिहाई कमी हो जाये।
(3) बशर्ते कि शस्त्रास्त्रों और सेना में और भी वृद्धि हो जाये।

परिशिष्ट तालिका-26

सरकार के असैनिक व्यय में सभावित वृद्धि 1959-1970
(1960 के मूल्यों के अनुसार अरब डालरो मे)

	1959	1970	वृद्धि
शिक्षा और स्कूल निर्माण	16 9		19·4
सडके और सचार-परिवहन साधन	8 8	15 4	6·6
सामुदायिक विकास, आवास और सफाई	2 1	14·7	12·6
स्वास्थ्य और अस्पताल	3·9	12 2	8·3
अनुसन्धान	—	4·0	4·0
प्राकृतिक साधन	3·1	6 1	3·0
सामान्य प्रशासन	5 9	10 0	4·1
अन्य	11·3	12·6	10·3
कुल व्यय	52 0	120 3	68·3

परिशिष्ट तालिका-27

विभिन्न उद्योगो मे केन्द्रीकरण (हर उद्योग की चार सबसे बडी कम्पनियो का प्रतिशत अश)

निर्माण उद्योग	लदान का मूल्य 1947	लदान का मूल्य 1954	रोजगार 1950	रोजगार 1954
अधिक केन्द्रीकरण वाले उद्योग				
एल्यूमीनियम धातु उत्पादन	100	100	100	100
जिप्सम के उत्पादन	85	90	89	86
टेलीफोन और टेलीगाफ का सामान	96	89	90	88
एल्युमीनियम का सामान	94	88	89	84
भाप के इजन और टर्वाइन	88	87	87	86
साबुन और ग्लिसरीन	79	85	69	71
सिगरेट	90	82	81	75
टीन के डिब्बे और सामान	78	80	77	78
टायर और ट्यूब	77	79	78	80
ट्रान्सफार्मर	73	78	77	71
मोटर गाडियाँ और पुर्जे	56	75	59	72
गणना आदि के यन्त्र	69	74	70	72
ट्रैक्टर	67	73	76	72
घरेलू धुलाई की मशीनें	40	68	53[1]	60
चीनी शोधन	70	67	69	69
धमन भट्टियाँ	67	65	57[1]	63
इलेक्ट्रानिक ट्यूबें	73	64	64	63
फोटोग्राफी का सामान	61	63	61	61
विमान इजन	72	62	55	51

कोक भट्टियों के उपोत्पादन	53	58	अज्ञात	53
इस्पात का सामान	45	54	55	53
तावे का सामान	60	53	51	54
मोटर और जेनरेटर	59	50	57	47
कम केन्द्रीकरण वाले उद्योग				
मिठाई उद्योग	17	19	12	15
कागज और गत्ता	अज्ञात	19	14	18
भवन-निर्माण और खनन यन्त्र	18	19	16	19
मशीनी औजार	20	19	25	20
रूई के चौडी बुनती के कपडे	अज्ञात	18	15	18
समाचार पत्र	21	18	16	14
चमडा	27	18	18	17
निर्माण और सजावट के काम	23	18	20	16
अण्डे की चीजें	32	17	33[1]	19
वाल्व और फिटिंग	24	17	21	22
गत्ते के डिब्बे	18	16	12	13
धातु पर मुद्रण	17	14	अज्ञात	12
पुरुषों के सूट और कोट	9	11	13	11
व्यावसायिक छपाई	9	10	9	10
लकडी का फरनीचर	7	8	6	7
मशीन वर्कशाप	अज्ञात	8	12	8
प्लास्टिक का सामान	अज्ञात	8	अज्ञात	7
आराकशी और रन्दाकशी	5	7	4	5
स्त्रियों की पोशाकें	अज्ञात	3	अज्ञात	4

1. 1935 के आंकड़े।